गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा पटियाला, श्रीगंगानगर व नेपाल से प्रसारित
साहित्य, शिक्षा, संस्कृति एवं शोध का अंतर्राष्ट्रीय मासिक

ISSN : 2321-8037
May-June 2026
Volume 14, Issue 5-6

Impact Factor :
7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)



Editor :
Dr. Rekha Soni
Chief-Editor :
Dr. Naresh Sihag Adv.



संस्थापक सम्पादिका :
स्मृति शेष
डॉ. विश्वकीर्ति

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

www.ginajournal.com



संस्थापक संरक्षक :
स्मृति शेष
श्री हरविन्द्र कमल चौधरी

वर्ष : 14 अंक : 5–6, भाग–4 मई–जून : 2026 आईएसएसएन : 2321–8037

सम्पादक :
डॉ. रेखा सोनी
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर, राज.

प्रधन सम्पादक :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
सचिव, गीना देवी शोध संस्थान,
भिवानी (हरियाणा)

अंतर्राष्ट्रीय सम्पादक मण्डल :
डॉ. लक्ष्मी जोशी
त्रिभुवन वि.वि. काठमाण्डू।
शिओंग छन श्यू, चीन।
डॉ. ऋतु शर्मा ननंन पाँडे
साहित्यकार, शिक्षाविद, नीदरलैंड।
डॉ. सुनीता शर्मा
हिन्दी साहित्यकार, कवयित्री, संपादक
एवं शिक्षाविद् मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया
डॉ. अनुरुद्ध बायन
मध्य कामरूप कॉलेज, सुभा
जिला बारपेटा, असम।
डॉ. सृष्टि चौधरी
लेक्चरर, इलेक्ट्रानिक्स एंड
कम्युनिकेशन, सरकारी पॉलिटेक्निक
कॉलेज फॉर गर्ल्स, पटियाला, पंजाब।
श्री श्रेष्ठ चौधरी,
सीनियर मैनेजर,
स्टेट बैंक ऑपफ इंडिया, साहिबजादा
अजित सिंह नगर, मोहाली, पंजाब।
कानूनी सलाहकार :
डॉ. रामफल दलाल एडवोकेट,
श्रीमती रूपिन्द्र कौर, एडवोकेट

सलाहाकार समिति (Advisory Committee)

डॉ. सुलक्षणा अहलावत
अंग्रेजी प्रवक्ता, शिक्षा विभाग
नूंह (हरियाणा)

डॉ. अरूणा अंचल
बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय,
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. सुशीला
चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी।

डॉ. अल्पना शर्मा
आईएएसई विश्वविद्यालय सरदारशहर

डॉ. विजय महादेव गाडे
बाबा साहेब चितले महाविद्यालय
भिलवडी (महाराष्ट्र)

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कॉलेज
धारवाड़ (कर्नाटक)

डॉ. रीना कुमारी
दशमेश गर्ल्स कॉलेज,
अल्ला बक्श, मुकेरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती
साहित्यकार, अनुवादक, यूक्रेन।

डॉ. हेमराज न्यौपाने
काठमाण्डु, नेपाल।

डॉ. ममता तनेजा
अबोहर, पंजाब।

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल
बराण, राजस्थान।

डॉ. संदीप
ओम विश्वविद्यालय, हिसार।

डॉ. मधुबाला
राजकीय महाविद्यालय, लाखनमाजरा।

डॉ. पीयूष कुमार द्विवेदी
जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग
विश्वविद्यालय, चित्रकूट, उत्तरप्रदेश

डॉ. हवासिंह ढाका
राजकीय महाविद्यालय, हिन्दुमलकोट,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत प्रवक्ता, शिक्षा विभाग हरियाणा

डॉ. राजेश शर्मा
शिक्षा संकाय, टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. मोहिनी दहिया
माती जीतोजी कन्या महाविद्यालय,
सूरतगढ़ (राजस्थान)

डॉ. मुद्दस्सिर अहमद भट्ट
हिन्दी विभाग,
कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर, कश्मीर

डॉ. सीहेच वी. महालक्ष्मी
सीहेच एसडीएसटी थेरेसा महिला
महाविद्यालय, एलुरू, आंध्र प्रदेश

डॉ. मोरवे रोशन के.
यूनाईटिड किंगडम।

डॉ. अनुपमा, पूर्व प्रोफेसर,
अंकारा विश्वविधालय, अंकारा, टर्की

डॉ. आर.के विश्वास
अध्यक्ष होम्योपैथिक, लखनऊ।

प्रकाशक, स्वामी एवं मुद्रक **डॉ. नरेश सिहाग**, एडवोकेट ने **मनभावन प्रिन्टर्ज**, पुराना बस स्टैण्ड रोड़, नया बाजार, भिवानी से छपवाकर 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी–127021 (हरियाणा) से जारी किया।

संगम SANGAM

बहुभाषिक बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

(Journal of Literature, Arts, Science, Commerece, Culture, Humanities and Social Sciences)

सचिव :

डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,

भिवानी-127021 (हरियाणा)

Email : grngobwn@gmail.com

मो. 09466532152

संगम मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं/लेखों की मौलिकता का दायित्त्व स्वयं रचनाकारों/लेखकों का है। उससे सम्पादक व प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायक्षेत्र केवल भिवानी (हरियाणा) होगा।
सम्पादन और प्रबंधन के सभी पद पूर्ण रूप से अवैतनिक हैं।

Published by :

Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

202, Old Housing Board,

Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA

Email : grsbohal@gmail.com

Facebook.com/bohalshodhmanjusha

Website : www.bohalsm.blogspot.com

WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1300/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

Impact Factor : 7.834

ISSN : 2321-8037

Gina Shodh SANGAM

Peer Reviewed & Refereed Research Journal

International Journal of Literature, Arts, Culture, Humanities and Social Sciences

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

तालिका– 2

शैक्षणिक / शोध अंक की गणना हेतु विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यप्रणाली

(आकलन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए, जैसेः प्रकाशनों की प्रति, परियोजना स्वीकृति पत्र, विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपयोग तथा पूर्णता प्रमाण पत्र, पेटेंट दर्ज कराने संबंधी अभिस्वीकृति और स्वीकृति पत्र, विद्यार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान किए जाने संबंधी पत्र इत्यादि।)

क्रम सं.	शैक्षणिक / शोध क्रियाकलाप	विज्ञान / अभियांत्रिकी / कृषि / चिकित्सा / पशु–चिकित्सा विज्ञान संकाय	भाषा / मानविकी / कला / सामाजिक विज्ञान / पुस्तकालय / शिक्षा / शारीरिक शिक्षा / वाणिज्य / प्रबंधन तथा अन्य संबंधित विधाएं
1	समकक्ष व्यक्ति समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध पत्रों में शोध पत्र	08 प्रति पत्र	10 प्रति पत्र
2	प्रकाशन (शोध पत्रों के अतिरिक्त)		
	(क) लिखी गई पुस्तकें, जिन्हें निम्नवत के द्वारा प्रकाशित किया गया :		
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक	12	12
	राष्ट्रीय प्रकाशक	10	10
	संपादित पुस्तक में अध्याय	05	05
	अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	10	10
	राष्ट्रीय प्रकाशक द्वारा पुस्तक का संपादक	08	08
	(ख) योग्य संकाय द्वारा भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद कार्य		
	अध्याय अथवा शोध पत्र	03	03
	पुस्तक	08	08
3	आईसीटी के माध्यम से शिक्षण ज्ञान– अर्जन, शिक्षण शास्त्र और विषयवस्तु का सृजन तथा नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या का विकास		
	(क) नवोन्मेषी अध्यापन का विकास	05	05
	(ख) नई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को तैयार करना	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम	02 प्रति पाठ्यचर्या / पाठ्यक्रम

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

www.bohalsm.blogspot.com grsbohal@gmail.com 8708822674 9466532152

अनुक्रमाणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. रेखा सोनी	07–07
2.	अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में मजदूरों के संघर्ष	डॉ. आलपाटि भानु प्रसाद	08–10
3.	समस तालाब (झुंझुनूं शहर) के जल की गुणवत्ता का WQI आधारित मूल्यांकन	डॉ. धर्मेन्द्र सिंह	11–15
4.	साम्प्रदायिक सद्भाव की कहानियाँ – हिन्दी कथासाहित्य में मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति	डॉ. तरूण कुमार साहू	16–19
5.	पर्यावरणीय न्याय और मानव अधिकार : भौगोलिक परिप्रेक्ष्य	डॉ. धर्मेंद्र सिंह	20–26
6.	माधव नागदा की कहानियों में सामाजिक परिवर्तन, वर्ग-संघर्ष और मानवीय संवेदना	श्रीमती संगीता देवी, डॉ. राजेश शर्मा	27–34
7.	कोरगर जनजाति : परंपरा, संस्कृति और समकालीन चुनौतियाँ	डॉ. संजीव कुमार. के	35–37
8.	माधव नागदा की कहानियों का कथा-शिल्प – भाषा, संरचना और दृष्टि बिंदु का विवेचन	श्रीमती संगीता देवी, डॉ. राजेश शर्मा	38–44
9.	रामचरित मानस में मानव मूल्य	डॉ. रीनू चतुर्वेदी	45–48
10.	हिंदी कहानी समीक्षा में सुरेंद्र चौधरी का योगदान : एक आलोचनात्मक अध्ययन	भोली रानी	49–53
11.	दलित विमर्श के संदर्भ में 'जूठन' आत्मकथा	डॉ. दर्शना धवल	54–57
12.	अलवर जिले में गिरता भू-जल स्तर और कृषि प्रारूप पर उसका प्रभाव : एक भौगोलिक विश्लेषण	डॉ. सुभाष चंद खटीक	58–60
13.	शिक्षक शिक्षकों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में व्यावसायिक दक्षता एवं व्यावसायिक संतुष्टि के मध्य संबंध का अध्ययन	डॉ. ज्ञान गांधी	61–65
14.	भारतीय संसद एवं महिला सशक्तिकरण : झारखंड राज्य के संदर्भ में	वीरेन्द्र देव, डॉ० प्रीति कुमारी	66–70
15.	भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की भूमिका	डॉ. स्वाति राय	71–74
16.	माध्यमिक स्तर के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं नैतिक मूल्यों में संबंध का एक अध्ययन	कृष्ण बहादुर सिंह, डॉ. राममणि द्विवेदी	75–81
17.	**National Education Policy 2020 & Experiential Learning in School Education**	**Dr. Giriraj Bhojak**	**82-87**
18.	21वीं सदी की हिन्दी कहानियों में नारी चिन्तन व चुनौतियां	डॉ० कमलेश देवी	88–94

19.	ग्रामीण महिलाओं में महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन	सुशीला, डॉ. रेखा खण्डेलवाल	95–98
20.	तारीख-ए-फिरोजशाही--जियाउद्दीन बरनी	आकाश गुप्ता	99–101
21.	राजस्थान की जलवायु	हेमाराम जाट	102–107
22.	**Impact of Competency-Based Assessment under NEP 2020 on Classroom Engagement and Teaching Effectiveness among Secondary School Teachers**	**Pinky Agarwal, Dr. Manju Devi**	**108-112**
23.	ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ	ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ	113-121
24.	ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ : ਇਕ ਅਧਿਐਨ	Dr. Rajbinder Kaur	122-135
25.	संत कबीरदास के माया संबंधी विचार	डॉ. मनोज कुमार	136–139
26.	**Impact of School Environment on Personality Development among Basketball Players : A Comparative Analysis of Government and Private Schools**	**Manish Kumar Sharma, Dr. Surjeet Singh Kaswan**	**140-142**
27.	**Women in Politics and Governance : Constitutional Empowerment and the Road to Viksit Bharat@ 2047**	**Kanika Thakur**	**143-149**
28.	2014 के बाद भारत में राजनीतिक आख्यानों का निर्माण और विकास : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	**Dr. Ekta Chaudhary, Fatima Zohra**	**150-155**
29.	समसामयिक चित्रकला में उभरता नया अध्याय	ध्रुव, डॉ. कृष्ण यादव	156–161
30.	संस्कृत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग : संभावनाएँ, उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ	डॉ. वर्षा रानी	162–167
31.	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में आपदा प्रबन्धन हेतु शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन **Study of Awareness of Disaster Management Education Among Secondary Level Students**	डॉ. नुपूर अग्रवाल	168–174
32.	भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी : ऐतिहासिक विकास, संस्थागत चुनौतियां और भविष्य के नीतिगत आयाम	डॉ. एस.पी. शुक्ला, अंजुलि शुक्ला	175–192
33.	अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का छात्रों की समग्र व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया पर प्रभाव का अध्ययन	लवनीश कुमार, डॉ. रजनीश कुमार कारवारिया	193–201
34.	**Medicinal Plants in Indian Traditional Knowledge**	**Kamini Kumari**	**202-205**
35.	निर्गुण संत कबीर : युवा-वर्ग के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा-स्त्रोत	डॉ. सुधा	206–213

सम्पादक की कलम से.....

ज्ञान, शोध और समाज के मध्य सेतु निर्माण की दिशा में

प्रिय पाठकों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों एवं विद्वान साथियों,

गीना शोध संगम के मई–जून 2026 अंक को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। ज्ञान–विज्ञान के निरंतर विस्तार और बदलते वैश्विक परिदृश्य में शोध की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज का युग सूचना, नवाचार और अंतर्विषयी अध्ययन का युग है, जहाँ केवल जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण, तर्कपूर्ण व्याख्या और समाजोपयोगी निष्कर्षों की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए गीना शोध संगम निरंतर शोध एवं अकादमिक विमर्श को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहा है।

भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने भी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान को विशेष महत्व दिया है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और शोध संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में भारतीय शोध प्रकाशन जगत ने तीव्र विकास किया है तथा शोधार्थियों की संख्या और शोध प्रकाशनों में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। गीना शोध संगम का मूल उद्देश्य केवल शोध पत्रों का प्रकाशन नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शोध संस्कृति का विकास करना है। पत्रिका बहुविषयक शोध को प्रोत्साहित करती है और साहित्य, शिक्षा, समाज विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, संस्कृति, पुस्तकालय विज्ञान, प्रबंधन, विज्ञान एवं अन्य विषयों के शोधार्थियों को एक साझा मंच प्रदान करती है। पत्रिका की समीक्षा प्रक्रिया शोध की गुणवत्ता, मौलिकता और अकादमिक विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल ब्लाइंड समीक्षा प्रणाली जैसे मानकों का अनुसरण शोध प्रकाशन की निष्पक्षता और गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाता है।

आज शोध के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती केवल सामग्री का सृजन नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और सामाजिक प्रासंगिकता है। इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में जानकारी का विस्फोट हुआ है, परंतु सत्य, प्रमाणिकता और नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरने वाला शोध ही समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसलिए शोधकर्ताओं का दायित्व है कि वे अपने अनुसंधान में नैतिक मानकों, संदर्भों की शुद्धता और मौलिक चिंतन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस अंक में प्रकाशित शोध आलेख विभिन्न विषयों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें साहित्यिक समीक्षा, सामाजिक विश्लेषण, सांस्कृतिक अध्ययन, शैक्षिक विमर्श, पर्यावरणीय चिंतन तथा समसामयिक विषयों पर आधारित शोध शामिल हैं। हमें विश्वास है कि ये शोध पत्र पाठकों को नवीन दृष्टि प्रदान करेंगे तथा आगे के अनुसंधान के लिए प्रेरित करेंगे।

हम सभी शोधार्थियों और विद्वानों से आग्रह करते हैं कि वे शोध को केवल पदोन्नति या डिग्री प्राप्ति का माध्यम न मानें, बल्कि समाज, राष्ट्र और मानवता के कल्याण का साधन समझें। शोध की वास्तविक सफलता तभी है जब उसके निष्कर्ष समाज के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हों। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह मानव कल्याण से जुड़ सके।

अंत में, मैं पत्रिका के सभी लेखकों, समीक्षकों, संपादकीय मंडल के सदस्यों तथा पाठकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग से यह अंक संभव हो सका है। आशा है कि गीना शोध संगम का यह अंक शोध और ज्ञान की नई संभावनाओं को उद्घाटित करेगा तथा अकादमिक जगत में सार्थक संवाद को आगे बढ़ाएगा।

–संपादक

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 08–10

अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में मजदूरों के संघर्ष

डॉ. आलपाटि भानु प्रसाद
हिन्दी प्राध्यापक,
यस.आर.आर–सी.वी.आर शासकीय महाविद्यालय (स्वा), विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।

बढ़ती हुई जनसंख्या, पारिश्रामीकरण तथा औद्योगीकरण के कारण समाज में मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा संख्या के अनुरूप ही दिन–ब–दिन उन पर शोषण बढ़ता जा रहा है। अपना श्रम दूसरों को बेचकर रुपये कमाना ही मजदूरी है। पूँजीवाद की अतिशयता से कृषक वर्ग कृषि से दूर होता जा रहा है, अर्थात वह श्रमिक बनता जा रहा है। वर्तमान समय में कृषि पर निर्भर किसानों के समक्ष दो ही विकल्प हैं– पहला विकल्प है, कि वे स्वयं कृषि को बचाए रखने के लिए घाटे में रहकर लगातार खेती करना, परन्तु तमाम कृषकों के लिए यह कदम आत्मघाती साबित होता है। घाटे में रहकर खेती करते रहना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति उन्हें घोर निराशा की ओर ले जा रही है, जिससे वे निकलने की कोशिश करते हैं। पूँजी एवं सत्ता के जाल से निकलने के लिए वे लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। दूसरा विकल्प है कि खेती–किसानी छोड़कर अपने जीवन निर्वाह के लिए रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन करना। अधिकतर किसान दूसरे विकल्प को अपना रहे हैं।

संघर्ष विपरीत परिस्थितियों में या परिस्थितियों को बदलने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्थिति में संघर्ष विपरीत स्थितियों में रहकर उन्हें बदलने के लिए किया जाता है। समाज का निम्न वर्ग मजदूर तथा श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। सर्वहारा मजदूरों का शोषण हमारे ही समाज के उच्च वर्गियों के द्वारा होता जा रहा है। मजदूरों के श्रम चूसनेवालों में मिल मालिक, कारखानेदार आदि लोग प्रमुख रूप से होते हैं। मिल मालिक श्रमिकों द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। पर श्रमिकों को अपने श्रम का उचित मजदूरी न देते। कुछ मजदूर शोषण के विरुद्ध लड़ने के बजाय अपने भाग्य का दोष मानते। पर कुछ मजदूर अपने श्रम का उचित फल पाने की संघर्ष–चेतना दिखाते हैं तथा शोषण के खिलाफ लड़ते हैं।

देश के मजदूरों तथा श्रामिकों को जागृत करते हुए अनेक कवि तथा विद्वान ने अनेक रचना की। कवि छेल बिहारी कण्टक जी भी अपनी रचनाओं में मजदूरों के बारे में वर्णन किया। उनके शब्दों में दया की भीख माँगने के बदले मजदूर अपने दृढ़ आत्मविश्वास से कहता है :–

"यों गुलाम होकर न सहूँगा अब मैं अत्याचार।
मैं जागृत मजदूर माँगता हूँ, अपने अधिकार।।.....
देश के मजदूर-किसान, बहुत दिन सोये लम्बी तान।
उठाये सदियों से अपमान, रहे नंगे-भूखे अनजान।"[1]

अब्दुल बिस्मिल्लाह मूलतः निम्न वर्ग के संघर्ष के कहानीकार है। उन्होंने आजादी के बाद उन्नीस सौ सत्तर के दशक से लेकर इक्कीसवीं सदी के पहले दशक के समाज का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। जिसमें कभी–कभी मध्य वर्ग और अभिजात्य वर्ग के जीवन और समस्याओं की भी झलक दिखलाई पड़ती है। ग्रामीण, कस्बाई और अविकसित शहरी समाज में जीने के लिए मामूली जरूरतों को पूरा करने का संघर्ष इन कहानियों की एक मुख्य चिंता कही जा सकती है। अभाव और भूख अनेक कहानियों के केंद्र में हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में मजदूरों की वेदना तथा शोषण का अद्‌भुत चित्रण किया। अपनी कहानियों के पात्र खाल खींचनेवाला कहानी के भुनेसर, पगलाराजा के भुल्लन, दरबे के लोग कहानी के खुतेजा के वालिद साहब आदि के द्वरा मजदूरों की संघर्ष–चेतना का वर्णन किया गया।

'अतिथि देवभव' कहानी संग्रह की 'खाल खींचने वाला' कहानी का भुनेसर एक खाल खींचनेवाला है। वह बड़ी मेहनत करके बैल का खाल खींच लेता है। उसकी मेहनत के बारे में कहानीकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने इस प्रकार वर्णन किया कि–

''लगभग आधा घंटे बाद वह बैल का एक हिस्सा खालियाने में सफल हुआ। उस वक्त तक आकाश पर बादलों की जगह धूप का एक जलता हुआ तवा तमतमाने लगा था और भुनेसर की कमर अकड़ गई थी। उसकी नंगी पीठ पर अम्हौरियाँ काटने लगी थीं और वह राँपी रखकर बेहया के झाड़ों में घुस गया था। अब उतना काम नहीं होता। फिर यह अकेले का काम तो है नहीं। लेकिन क्या करे। लड़का ही इस लायक होता तो फिर रोना किस बात का। और अगर किसी से मदद लेता है तो उसे भी हिस्सा देने होगा। ऐसी हालत में बचेगा ही कितना उसे। इससे अच्छा तो यही है कि थोड़ी–सी तकलीफ झेलकर अकेला ही निपटा ले। ...भुनेसर बैल के छिले हुए पेट से सटकर बैठ गया और पूरा जोर लगाकर उसे ठेलने लगा। उस पूरी प्रक्रिया में उसे लगा, मानो वह अपनी जिंदगी को ही ठेल रहा है। और हालाँकि उसे पसीना आ गया, अंग–अंग थरथरा उठा, लेकिन कुछ देर बाद बैल उलट गया और उसके साथ ही भुनेसर भी नाले में गिर पड़ा।"[2] कड़ी मेहनत करके बैल का खाल खींचकर उसे बाजार में बेचने के लिए गया। बाजार में एक पढ़े–लिखे व्यापारी बीस रुपये देने को तैयार हो जाता। पर बड़े मियाँ को देखकर सब व्यापारी वहाँ से गायब हो गए। बड़े मियाँ उसे लेकर उचित दाम देने की वादा किया। शाम तक चमड़ों पर नमक लगाने का काम करवाकर केवल पंद्रह रुपया हाथ में रख दिया। आखिर भुनेसर को अपने खाल का सही दाम भी न मिला तथा शाम तक काम करने की मजदूरी भी न मिली। इस प्रकार समाज में बड़े मियाँ जैसे लोग अपने मजदूरों का शोषण करते जा रहे हैं। भुनेसर में संघर्ष से लड़ने की चेतना का अभाव है। उसका संघर्ष आंतरिक ही रह गया। वह मन में सोच लिया कि – "हम लोग तो मुर्दा जानवरों का खाल उतारते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा आदमियों की खाल खींचते हैं और उन्हें दर्द तो दूर, घिन भी नहीं लगती।"[3] लेकिन भुनेसर अपनी मन की वेदना को बाहर न आने देता। क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। क्योंकि समाज में वैसे ही लोगों की जमात थी।

'रैन बसेरा' कहानी संग्रह की 'पगला राजा' कहानी में मजदूरों की संघर्ष–चेतना का चित्रण मिलता है। भुल्लन एक बढ़ई था, जो लकड़ी के काम में बड़ा माहिर है। वह जितना खूबसूरत हल बना सकता है, जो दूसरा बढ़ई नहीं बना सकता। सब लोग भुल्लन से काम करवा कर उनकी भोलेपन का सहारा लेकर पैसे न देते। "गाँव के बहुत बड़े रईस श्री मातादीन शुक्ल ने भुल्लन से अपनी पलंग ठीक कराई और शाम को मजूरी देते वक्त

मुस्कराते हुए कहा, महाराज, हम गरीबों पर दया कीजिए, दो–चार रुपयों से आपका तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। और भुल्लन अपनी पगड़ी को संभालते हुए घर आ गया। चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का संतोष तैर रहा था उस रोज। तब से पूरे पांडेपुर में यह बात प्रसिद्ध हो गई है कि भुल्लन राजा आदमी है एकदम शाही तबियत का । और तभी से भुल्लन प्रजा की तरह काम करता है और मजूरी छोड़कर राजा की तरह घर चला आता है।"[4] इस प्रकार पांडेपुर के सब लोग बिना मजूरी के भुल्लन काम करवाते।

समाज में मातादीन शुक्ल तथा बड़े मियाँ जैसे अनेक अमीर लोग भुल्लन तथा भुनेसर जैसे मजदूरों का शोषण करते रहते हैं। कुछ लोग आगे जाकर मजदूरों की औरतों को भी अपनी काम–वासना की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई अपनी वासना की पूर्ति करने का इनकार के तो उन्हें काम से हटाते या जबर्दस्ती अपनी वासना का पूर्ति कर लेते। इसका वर्णन कहानीकार अब्दुल बिस्मिल्लाह ने अपनी कहानी दरबे के लोग में वर्णन किया।

खुतेजा के वालिद हाजी साहब के दरबे में साड़ियाँ बुनते थे। वह सब से ज्यादा तथा बढ़िया साड़ियाँ बुनते थे। इस बात को स्वयं गिरस्ता हाजी भी एक बार कह चुके थे। पर उसी ने खुतेजा के वालिद को काम से निकाल दिया। निवेदक ने इसके कारण का पता लगाने पर उसे मालूम हुआ, जिसका साधारणतया शायद कोई अर्थ नहीं होता। अर्थात् "कारीगर भैंस का मांस खाते हैं और गिरस्ता लोग औरत का। इन्हें घर की औरत का मांस अच्छा नहीं लगता। कारीगरों के घर की औरतों का मांस अच्चा लगता है। उनकी इस अच्छा लगने वाली वृत्ति को इन दरबों में रहने वाले लोग हमेशा से संतुष्ट करते आए हैं। और जिसने संतुष्ट किया उसे जमाने की सबसे नायाब चीज अर्थात मजदूरी मिलती रही। खुतेजा एक पारसा औरत थी। उसने यह सब पसंद नहीं किया, इसलिए उसके बाप को मजदूरी से ही नहीं, दरबे से भी निकाल दिया गया।"[5] इस प्रकार गिरस्ते लोग कारीगरों के औरतों को अपनी वासना की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते। यदि कोई इनकार करे तो उनको मजदूरी से निकाल देते थे।

उपर्युक्ति वक्तव्य से हमें यह बात समझ में आता है कि मिल मालिक, गिरस्ता लोग हमेशा अपने मजदूरों का शोषण करते रहते हैं। इस शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए सब मजदूर तैयार न होते थे। उनकी संघर्ष–चेतना आंतरिक ही रह जाती। उसे बाहर लाने की परिवेश की कमी है।

संदर्भ :

1. उपन्यासकार अब्दुल बिस्मल्लाह की संघर्ष–चेतना, डॉ. भाऊसाहेब नवले, पृ. 52
2. अतिथि देवोभव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पृ. 59, 60
3. अतिथि देवोभव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पृ. 62, 63
4. ताकी सनद रहे, रैनबसेरा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पृ. 11
5. ताकि सनद रहे, कितने–कितने सवाल, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पृ. 131

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 11–15

समस तालाब (झुंझुनूं शहर) के जल की गुणवत्ता का WQI आधारित मूल्यांकन

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह
सह–आचार्य (भूगोल)
आई.ए.एस.ई. (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय), सरदारशहर, चूरू।

सार :

जल गुणवत्ता का आकलन यह निर्धारित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि कोई जल स्रोत पेयजल एवं घरेलू उपयोगों के लिए उपयुक्त है या नहीं। वर्तमान अध्ययन में राजस्थान के झुंझुनूं शहर में स्थित समास तालाब के जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन जल गुणवत्ता सूचकांक (Water Quality Index – WQI) विधि के माध्यम से किया गया है। तालाब के विभिन्न स्थानों से जल नमूने एकत्रित कर उनका विश्लेषण महत्वपूर्ण भौतिक-रासायनिक मापदंडों जैसे pH, विद्युत चालकता (EC), कुल घुलित ठोस (TDS), घुलित ऑक्सीजन (DO), कुल कठोरता, क्षारीयता, क्लोराइड, नाइट्रेट तथा सल्फेट के लिए किया गया। प्राप्त परिणामों की तुलना भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित पेयजल मानकों से की गई। WQI की गणना के आधार पर जल की समग्र गुणवत्ता का निर्धारण किया गया। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि समास तालाब का जल कुछ स्थानों पर मानकों के भीतर है जबकि कुछ स्थानों पर मानवजनित गतिविधियों के कारण गुणवत्ता में परिवर्तन देखा गया। यह अध्ययन जल संसाधन प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।

मुख्य शब्द : जल गुणवत्ता सूचकांक, समस तालाब, पेयजल, भौतिक-रासायनिक मापदंड, झुंझुनूं।

परिचय :

जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। मानव जीवन, कृषि, उद्योग तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए स्वच्छ जल का होना अत्यंत आवश्यक है। भारत के अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों, विशेष रूप से राजस्थान में, पारंपरिक जल स्रोत जैसे तालाब, बावड़ियाँ तथा झीलें स्थानीय जल आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या, तालाब के चारों ओर स्थानीय बस्ती, सड़कें तथा धार्मिक स्थल स्थित होने के कारण यह क्षेत्र सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। जिसके के कारण जल स्रोत की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सतही जल स्रोतों में घरेलू अपशिष्ट, रसायन, ठोस कचरा तथा अन्य प्रदूषकों के प्रवेश से जल प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है।

जल की गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न भौतिक, रासायनिक तथा जैविक मापदंडों का अध्ययन किया जाता है। इन सभी मापदंडों का संयुक्त विश्लेषण करना जटिल हो सकता है, इसलिए शोधकर्ता जल गुणवत्ता सूचकांक (Water Quality Index – WQI) का उपयोग करते हैं। यह एक सांख्यिकीय विधि है जो विभिन्न मापदंडों को एक ही सूचकांक मान में परिवर्तित कर जल की समग्र गुणवत्ता को दर्शाती है।

झुंझुनूं जिले में स्थित समास तालाब स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों, पशुओं के लिए पानी, तथा कुछ परिस्थितियों में उपचार के बाद पेयजल के रूप में भी किया जाता था। अतः इस तालाब की जल गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक है।

अध्ययन क्षेत्र :

समास तालाब राजस्थान के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित झुंझुनूं शहर के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण पारंपरिक जलाशय है। यह तालाब शेखावाटी क्षेत्र के अर्द्ध-शुष्क जलवायु क्षेत्र में आता है, जहाँ वर्षा सीमित होती है और जल संरक्षण के लिए तालाबों का विशेष महत्व है।

समास तालाब के आसपास धार्मिक एवं आवासीय संरचनाएँ स्थित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जमुवाय माता मंदिर तथा अन्य छोटे मंदिर और आवासीय भवन शामिल हैं। तालाब के चारों ओर स्थानीय बस्ती, सड़कें तथा धार्मिक स्थल स्थित होने के कारण यह क्षेत्र सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है।

ऐतिहासिक दृष्टि से यह माना जाता है कि समास तालाब का निर्माण समस खाँ द्वारा कराया गया था, जिन्होंने झुंझुनूं क्षेत्र में समसपुर गाँव की स्थापना भी की थी। यह तालाब उस समय वर्षा जल संचयन तथा स्थानीय जल आपूर्ति के लिए बनाया गया था।

भौगोलिक दृष्टि से यह तालाब एक मानव निर्मित वर्षा जल संचयन संरचना है, जो मुख्य रूप से वर्षा जल और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले सतही अपवाह से भरता है। तालाब के आसपास सड़क मार्ग तथा आवासीय क्षेत्र होने के कारण जल गुणवत्ता पर मानव गतिविधियों का प्रभाव पड़ सकता है।

इस प्रकार समास तालाब झुंझुनूं शहर में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थानीय जल स्रोत है, जो न केवल जल संरक्षण के लिए बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इसके जल की गुणवत्ता का अध्ययन जल गुणवत्ता सूचकांक (WQI) के माध्यम से करना आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य :

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. समास तालाब के जल के भौतिक-रासायनिक मापदंडों का विश्लेषण करना।
2. प्राप्त मानों की तुलना BIS पेयजल मानकों से करना।
3. जल गुणवत्ता सूचकांक (WQI) की गणना करना।
4. समास तालाब के जल की पेयजल उपयोग हेतु उपयुक्तता का निर्धारण करना।

सामग्री एवं विधि :

नमूना संग्रह :

समास तालाब के विभिन्न स्थानों से स्वच्छ पॉलीएथिलीन बोतलों में जल नमूने एकत्रित किए गए। नमूने संग्रह के समय सावधानी बरती गई ताकि बाहरी प्रदूषण से बचा जा सके। नमूनों को मानक प्रक्रियाओं के अनुसार सुरक्षित रखकर प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया।

विश्लेषित मापदंड

जल के निम्नलिखित भौतिक-रासायनिक मापदंडों का अध्ययन किया गया:

- विद्युत चालकता
- कुल घुलित ठोस
- घुलित ऑक्सीजन
- कुल कठोरता
- क्षारीयता
- क्लोराइड
- नाइट्रेट
- सल्फेट

इन मापदंडों के विश्लेषण के लिए APHA द्वारा सुझाई गई मानक प्रयोगशाला विधियों का उपयोग किया गया।

जल गुणवत्ता सूचकांक (WQI) की गणना :

जल गुणवत्ता सूचकांक की गणना Weighted Arithmetic Method द्वारा की गई।

गुणवत्ता रेटिंग

$Qn=(Vn−Vi)(Sn−Vi)×100Q_n = \frac{(V_n - V_i)}{(S_n - V_i)} \times 100Qn=(Sn−Vi)(Vn−Vi)×100$

जहाँ

Qn = गुणवत्ता रेटिंग

Vn = मापदंड का अवलोकित मान

Vi = आदर्श मान

Sn = मानक अनुमेय मान

इकाई भार

$Wn=KSnW_n = \frac{K}{S_n}Wn=SnK$

जहाँ K एक स्थिरांक है।

अंतिम WQI

$WQI=∑QnWn∑WnWQI = \frac{\sum Q_n W_n}{\sum W_n}WQI=∑Wn∑QnWn$

परिणाम एवं चर्चा :

तालाब के जल के विश्लेषण से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए:

मापदंड	प्रेक्षित मान	BIS मानक
pH	7.4	6.5–8.5
TDS	480 mg/L	500 mg/L
DO	6.2 mg/L	>5 mg/L
कुल कठोरता	220 mg/L	300 mg/L
क्लोराइड	120 mg/L	250 mg/L
नाइट्रेट	35 mg/L	45 mg/L

परिणामों से स्पष्ट है कि अधिकांश मापदंड अनुमेय सीमा के भीतर हैं।

WQI के आधार पर जल गुणवत्ता वर्गीकरण

WQI मान	**जल गुणवत्ता**
0–25	उत्कृष्ट
26–50	अच्छी
51–75	खराब

WQI मान	जल गुणवत्ता
76–100	बहुत खराब
>100	पेयजल के लिए अनुपयुक्त

गणना के आधार पर समास तालाब का जल मध्यम से अच्छा श्रेणी में पाया जा सकता है। हालांकि कुछ मानव गतिविधियों के कारण जल गुणवत्ता में परिवर्तन देखा गया हैं जिसके निम्नलिखित कारण हैं।

जल गुणवत्ता में परिवर्तन के कारण :

जल की गुणवत्ता विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित कारकों से प्रभावित होती है। समास तालाब जैसे छोटे जलाशयों में यह परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है क्योंकि ये मुख्यतः वर्षा जल तथा आसपास के क्षेत्रों से आने वाले सतही अपवाह पर निर्भर करते हैं। जल गुणवत्ता में परिवर्तन के निम्नलिखित प्रमुख कारण हो सकते हैं:

1. घरेलू अपशिष्ट

तालाब के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा उत्पन्न घरेलू कचरा और गंदा पानी कई बार तालाब में पहुँच जाता है। इससे जल में जैविक प्रदूषण बढ़ता है और घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है।

2. ठोस अपशिष्ट का निपटान

कई स्थानों पर तालाबों के आसपास ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, कपड़े और अन्य अपशिष्ट पदार्थ फेंक दिए जाते हैं। यह धीरे-धीरे सड़कर जल की रासायनिक संरचना को प्रभावित करते हैं।

3. सतही अपवाह

वर्षा के दौरान आसपास की भूमि से मिट्टी, धूल, जैविक पदार्थ तथा अन्य प्रदूषक तत्व बहकर तालाब में आ जाते हैं। इससे जल की पारदर्शिता कम हो जाती है तथा TDS और अन्य मापदंडों में वृद्धि हो सकती है।

4. वाष्पीकरण और जलवायु प्रभाव

अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। इससे जल में घुलित लवणों की सांद्रता बढ़ सकती है, जिससे जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

5. धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियाँ

तालाब के आसपास स्थित मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के कारण कई बार पूजा सामग्री, फूल-माला आदि तालाब में डाले जाते हैं। यह पदार्थ सड़ने के बाद जल में जैविक प्रदूषण बढ़ाते हैं।

6. अवसादन

समय के साथ तालाब में मिट्टी और अन्य कणों का जमाव होता रहता है। इससे तालाब की जल धारण क्षमता कम हो जाती है तथा जल की गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकता है।

निष्कर्ष :

इस अध्ययन में समास तालाब के जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन जल गुणवत्ता सूचकांक (WQI) विधि से किया गया। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि जल की गुणवत्ता प्राकृतिक कारकों तथा मानव गतिविधियों दोनों से प्रभावित होती है। अधिकांश मापदंड BIS मानकों के भीतर पाए गए, किन्तु प्रदूषण के संकेत भी मिले।

अतः तालाब के जल को पेयजल के रूप में उपयोग करने से पहले उचित उपचार आवश्यक हो सकता है। जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

सुझाव :

- तालाब के जल की नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
- तालाब के आसपास ठोस अपशिष्ट निपटान पर नियंत्रण होना चाहिए।

- कृषि रसायनों के उपयोग को नियंत्रित करना चाहिए।
- तालाब के आसपास वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए।
- स्थानीय लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

संदर्भ सूचि :

1. R.K. Horton (1965). An Index Number System for Rating Water Quality. Journal of Water Pollution Control Federation, 37(3), 300–306.
2. R.M. Brown, N.I. McClelland, R.A. Deininger, & M.F. O'Connor (1972). A Water Quality Index – Do We Dare? Water & Sewage Works, 117(10), 339–343.
3. American Public Health Association (2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23rd ed.). Washington, D.C.
4. Bureau of Indian Standards (2012). Drinking Water Specification (IS 10500). New Delhi, India.
5. P.C. Mishra & R.K. Patel (2001). Study of the Pollution Load in the Drinking Water of Rairangpur, a Small Tribal Dominated Town of North Orissa. Indian Journal of Environment and Ecoplanning, 5(2), 293–298.
6. R.S. Ayers & D.W. Westcot (1985). Water Quality for Agriculture. FAO Irrigation and Drainage Paper 29.
7. C.G. Smith (1990). A Coding System for the Assessment of Water Quality. Water Research, 24(5), 611–620.
8. World Health Organization (2017). Guidelines for Drinking-water Quality (4th ed.). Geneva.
9. S. Tyagi, B. Sharma, P. Singh & R. Dobhal (2013).Water Quality Assessment in Terms of Water Quality Index. American Journal of Water Resources, 1(3), 34–38.
10. A.K. Bharti & P.K. Katyal (2011). Water Quality Indices Used for Surface Water Vulnerability Assessment. International Journal of Environmental Sciences, 2(1), 154–173.
11. S.K. Gupta & R.C. Gupta (1999). General and Applied Ichthyology (Fish and Fisheries). New Delhi: S. Chand & Company.
12. P. Kannel, S. Lee, S.R. Lee, S. Kanel & S.P. Khan (2007).Application of Water Quality Indices and Dissolved Oxygen as Indicators for River Water Classification. Environmental Monitoring and Assessment, 132, 93–110.

ईमेल : dharamkarwasra@gmail.com

मोबाइल 9414741567

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 16–19

साम्प्रदायिक सद्भाव की कहानियाँ – हिन्दी कथासाहित्य में मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति

डॉ. तरूण कुमार साहू
अतिथि प्राध्यापक शा. रा.लो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम (छ.ग)

प्रस्तावना :

भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश रहा है। यहाँ अनेक धार्मिक समुदायों ने साथ–साथ रहते हुए एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का निर्माण किया है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सहिष्णुता, समन्वयशीलता और बहुलतावादी दृष्टि रही है। किंतु आधुनिक काल में साम्प्रदायिकता भारतीय समाज के सामने एक गंभीर चुनौती के रूप में उभरी है। साम्प्रदायिकता केवल धार्मिक मतभेदों का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक असमानताओं और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से भी जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान का आधार बनाया गया, फिर भी समय–समय पर साम्प्रदायिक तनाव और दंगे सामाजिक एकता को प्रभावित करते रहे हैं।

ऐसी परिस्थितियों में साहित्य ने समाज को नई दिशा देने का कार्य किया है। हिन्दी कहानीकारों ने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध मानवता, प्रेम, सह–अस्तित्व और सामाजिक समरसता के मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ अश्क, निश्तर खानकाही, अब्दुल बिस्मिल्लाह तथा अमिता शीरीं जैसे साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य की पहचान उसके धर्म से नहीं, अपितु उसके मानवीय व्यवहार और संवेदनशीलता से होती है। उनकी रचनाएँ आज भी साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

बीज शब्द : साम्प्रदायिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद, सामाजिक समरसता, हिन्दू–मुस्लिम संबंध, गंगा–जमुनी तहजीब, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकीकरण, सह–अस्तित्व, मानवीय संवेदना।

विष्णु प्रभाकर हिन्दी साहित्य के उन महत्वपूर्ण रचनाकारों में हैं जिन्होंने मानवीय मूल्यों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। उनकी कहानी 'मेरा बेटा' साम्प्रदायिक सद्भाव और मानवीय संबंधों की शक्ति को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी का केंद्र एक ऐसा परिवार है जिसमें पारिवारिक संबंध और धार्मिक पहचान एक–दूसरे से टकराते हुए दिखाई देते हैं। कथा में रामप्रसाद दंगा की चपेट में आ जाता है। दंगा का वातावरण भय, हिंसा और अविश्वास से भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जहाँ लोग एक–दूसरे के धर्म के आधार पर शत्रु बन रहे हैं, वहीं हसन अपनी जान जोखिम में डालकर रामप्रसाद की रक्षा करता है। यह घटना

कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। हसन का यह कार्य केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं है, अपितु साम्प्रदायिक मानसिकता के विरुद्ध मानवता की विजय का प्रतीक है। कहानी यह दर्शाती है कि मनुष्य के भीतर मौजूद प्रेम और करुणा किसी भी धार्मिक विभाजन से अधिक शक्तिशाली होते हैं। कहानी के अंत में पिता का कथन – कि "हसन, मैं उससे पूछेंगा, मैं मुसलमान हो गया तो क्या हुआ, हमारा बाप–बेटे का नाता तो नहीं टूट सकता, आखिर उसकी रगों में अब भी मेरा खून बहता है, इतना ही जितना अनवर की रगों में बहता है, शायद ज्यादा"।[1] मानवीय संबंधों की गहराई को व्यक्त करता है। यह कथन पाठक को सोचने पर विवश करता है कि यदि परिवार और समाज के रिश्ते मानवता के आधार पर बने रहें तो साम्प्रदायिकता की जड़ें स्वतः कमजोर हो जाएँगी।

अमृतलाल नागर हिन्दी कथा–साहित्य में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं के सशक्त रचनाकार माने जाते हैं। उनकी कहानी 'मोती की सात चलनियाँ' साम्प्रदायिक सद्भाव और अंतरधार्मिक संबंधों की समस्या को अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत करती है। इस कहानी में डॉ. निगार सुल्ताना और डॉ. सुरेन्द्र मोहन एक–दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों शिक्षित, आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति हैं। वे धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर विवाह करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन उनका यह निर्णय परिवार और समाज के एक वर्ग को स्वीकार नहीं होता। विशेष रूप से निगार सुल्ताना के पिता और कुछ रिश्तेदार इस विवाह का विरोध करते हैं। उन्हें भय है कि समाज उनकी आलोचना करेगा और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचेगी। यह विरोध वास्तव में उस सामाजिक मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है जो धर्म को मानवीय संबंधों से अधिक महत्व देती है।

कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसका अंत है। विवाह की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। दोनों परिवारों को लगता है कि यह घटना समाज में बड़ी चर्चा का विषय बनेगी। इस तरह "कइयों ने इसे एक खबर के तौर पर पढ़ा और अच्छा कहा। बाकी दुनिया ने पढ़ा, न कुछ सोचा और न कुछ कहा ही। दुनिया यों ही बढ़ती है।"[2] इस समाचार को सामान्य समाचार की तरह पढ़ते हैं और अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। लेखक यहाँ एक महत्वपूर्ण सामाजिक सत्य की ओर संकेत करते हैं कि समाज का बड़ा हिस्सा उतना कट्टर नहीं होता जितना हम समझते हैं। कई बार हमारा भय और पूर्वाग्रह ही समस्याओं को बड़ा बना देता है। इस प्रकार कहानी प्रेम, स्वतंत्रता और सामाजिक समरसता का समर्थन करती है तथा यह संदेश देती है कि मानव संबंध धर्म से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

उपेन्द्रनाथ अश्क की 'टेबल लैंड' कहानी जो विभाजन की त्रासदी को बहुत निकट से देखा था। उनकी कहानी 'टेबल लैंड' विभाजन के बाद की मानसिकता, विस्थापन की पीड़ा और साम्प्रदायिक सोच के परिणामों को अत्यंत संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है।

कहानी में दंगा–पीड़ितों की सहायता के लिए चंदा एकत्र किया जा रहा है। दीनानाथ इस कार्य में सक्रिय है, किंतु उसके भीतर साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह मौजूद हैं। वह मुसलमानों के घर चंदा लेने नहीं जाता। उसे लगता है कि सहायता केवल अपने समुदाय के लोगों के लिए होनी चाहिए। उसका मित्र कासिम इस दृष्टिकोण का विरोध करता है। वह दीनानाथ को समझाता है कि पीड़ा और दुःख का कोई धर्म नहीं होता। यदि सहायता मानवता के नाम पर की जा रही है तो उसमें धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहानी आगे बढ़ते हुए यह दिखाती है कि विभाजन ने केवल हिन्दुओं को ही नहीं, बल्कि मुसलमानों को भी गहरा आघात पहुँचाया था। लाखों

लोग अपने घर, परिवार और स्मृतियाँ छोड़ने के लिए विवश हुए थे। कहानी के अंत में पाकिस्तान से आए एक शरणार्थी को दीनानाथ कहता है "मैं यह चन्दा पंजाब के दुखी शरणार्थियों के लिए इकट्ठा कर रहा था। आप भी पजाब के शरणार्थी हैं और दुखी भी कम नहीं। रुपया ज्यादा नहीं, पर देखिए, यदि इससे आपका कुछ काम निकल सके।"[3] अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, यह बताता है कि जिन लोगों ने स्वयं दुःख सहा है, वे दूसरों की पीड़ा को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अश्क इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि विभाजन की त्रासदी से सीख लेकर समाज को नफरत नहीं, बल्कि सह–अस्तित्व की राह चुननी चाहिए।

निश्तर खानकाही की श्जलता हुआ सवालश साम्प्रदायिकता के विरुद्ध मानवीय प्रश्न है। यह कहानी साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न मानवीय संकट को केंद्र में रखती है। कहानी में लेखक यह प्रश्न उठाते हैं कि धार्मिक उन्माद का सबसे बड़ा शिकार वह साधारण व्यक्ति क्यों बनता है जिसका किसी राजनीतिक या साम्प्रदायिक षड्यंत्र से कोई संबंध नहीं होता। कहानी में दंगों के कारण उत्पन्न भय, असुरक्षा और अविश्वास का चित्रण किया गया है। लेखक दिखाते हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा केवल जान–माल की हानि नहीं करती, बल्कि समाज की नैतिक और मानवीय चेतना को भी क्षति पहुँचाती है। कहानी का केंद्रीय संदेश यह है कि साम्प्रदायिकता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इसका समाधान केवल संवाद, सहिष्णुता और मानवीय विश्वास में निहित है।

अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचनाएँ भारतीय समाज की साझी संस्कृति और गंगा–जमुनी तहजीब की प्रतिनिधि हैं। उनकी कहानी 'दंगाई' साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक सशक्त हस्तक्षेप है। कहानी में लेखक दिखाते हैं कि शहरों में दंगे भड़क रहे हैं, लेकिन गाँव का सामाजिक जीवन अभी भी भाईचारे और सहयोग पर आधारित है। हिन्दू और मुस्लिम मिलकर रामलीला का आयोजन करते हैं। वे एक–दूसरे के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। इस कारण शहरों में फैलने वाली नफरत गाँव तक नहीं पहुँच पाती। कहानी का पात्र डॉ. बशीर रामलीला मंचन का संचालन करते हैं। बड़े उत्साह के साथ लोग रामलीला का आनन्द लेते हुए ईनाम भी भेंट करते हैं। जिसमें डॉ बशीर कहते हैं–"भाइयो, हमारे गाँव के प्रधान श्री दयाशंकर पाण्डेय ने हनुमान के पार्ट पर खुश होकर दो रुपया दिया है और हनुमान के पार्ट पर ही मौलवी जमालुद्दीन साहब ने एक रुपया इनाम दिया है। हमारी रामलीला कमेटी उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती है। बोलो भगवान श्री रामचन्द्र जी की जय!"[4] कहानी यह संदेश देती है कि साम्प्रदायिकता बाहर से थोपी गई मानसिकता है, जबकि भारतीय समाज की मूल चेतना सह–अस्तित्व और साझी संस्कृति पर आधारित है।

अमिता शीरीं की आत्मकथा साम्प्रदायिक सद्भाव का अत्यंत भावनात्मक और वास्तविक उदाहरण प्रस्तुत करती है। वे अपने बचपन और पारिवारिक अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताती हैं कि उनकी माँ किसी भी मुसलमान–विरोधी टिप्पणी को सुनकर आक्रोशित हो जाती थीं। इसका कारण एक गहरा मानवीय अनुभव था। बचपन में अमिता की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई थीं। उस समय एक मुस्लिम युवक ने रक्तदान करके उनकी जान बचाई थी। यह घटना केवल चिकित्सा सहायता का उदाहरण नहीं थी, बल्कि मानवता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी।

इस अनुभव ने पूरे परिवार की सोच को प्रभावित किया। उनकी माँ के लिए मुसलमान कोई अलग समुदाय नहीं था, अपितु वह व्यक्ति था जिसने उनको नया जीवन दिया था। लेखिका कहती हैं –"अब मुझे इस बात का शिद्दत से अहसास होने लगा है कि अब आने वाली पीढ़ियों का बचपन मेरी तरह कभी नहीं होगा। मेरी

माँ की रगों में बहता जो मुस्लिम खून हमारे जहन में उतर गया था. वह खून अब मुल्क की सड़कों पर बह रहा है..."[5] आत्मकथा का यह प्रसंग बताता है कि मानवीय संवेदना और करुणा किसी भी धार्मिक पहचान से कहीं अधिक बड़ी होती है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त रचनाओं के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हिन्दी कथा–साहित्य ने साम्प्रदायिक सद्भाव की स्थापना तथा मानवीय मूल्यों के संवर्धन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन सभी रचनाओं में मानवता को धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर स्थान दिया गया है। विष्णु प्रभाकर की 'मेरा बेटा' पारिवारिक संबंधों और मानवीय करुणा की शक्ति को रेखांकित करती हैय अमृतलाल नागर की 'मोती की सात चलनियाँ' अंतरधार्मिक प्रेम तथा सामाजिक स्वीकृति का समर्थन करती हैय उपेन्द्रनाथ अश्क की 'टेबल लैंड' विभाजन की त्रासदी के बीच मानवता की खोज प्रस्तुत करती हैय निश्तर खानकाही की 'जलता हुआ सवाल' साम्प्रदायिक हिंसा के दुष्परिणामों को उजागर करती हैय जबकि अब्दुल बिस्मिल्लाह और अमिता शीरीं की रचनाएँ साझा संस्कृति, गंगा–जमुनी तहजीब तथा मानवीय एकता के मूल्यों को प्रतिष्ठित करती हैं।

इन समस्त रचनाओं का सामूहिक संदेश यह है कि भारतीय समाज की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता, सहिष्णुता, समन्वयशीलता तथा मानवीय संवेदनाओं में निहित है। साहित्य यह स्थापित करता है कि धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद मानवता, प्रेम, करुणा और सह–अस्तित्व ही सामाजिक सद्भाव के आधार हैं। अतः जब तक मानवता को धर्म से ऊपर स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक स्थायी सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की स्थापना संभव नहीं हो सकेगी। इस दृष्टि से हिन्दी कथा–साहित्य न केवल सामाजिक यथार्थ का दर्पण है, बल्कि साम्प्रदायिक सद्भाव और मानवीय मूल्यों का सशक्त संवाहक भी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. अग्रवाल. गिरिराज शरण. सामाजिक सद्भाव की कहानियां. प्रभात प्रकाशन दिल्ली. प्रथम संस्करण. 1996. पृ. 159.
2. वही, पृ. 29
3. वही, पृ. 53
4. वही, पृ. 39
5. कथा देश सितंबर 2025, अंक, पृ. 65

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 20-26

पर्यावरणीय न्याय और मानव अधिकार : भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

डॉ. धर्मेंद्र सिंह
सह –आचार्य (भूगोल),
आई.ए.एस.ई. (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), सरदारशहर, चूरू।

सार :

वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के तीव्र विस्तार ने पर्यावरणीय संसाधनों पर भारी दबाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप वायु, जल, मिट्टी और ध्वनि प्रदूषण में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन पर्यावरणीय परिवर्तनों का प्रभाव सभी पर समान रूप से नहीं पड़ता, बल्कि सामाजिक–आर्थिक रूप से कमजोर, हाशिए पर स्थित तथा वंचित समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पर्यावरणीय न्याय (Environmental Justice) का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, स्वस्थ पर्यावरण में रहने का समान अधिकार रखता है। भौगोलिक अध्ययन इन असमानताओं को स्थानिक (Spatial), सामाजिक तथा आर्थिक आयामों में समझने का एक सशक्त माध्यम है। यह शोध–पत्र प्रदूषण, कचरा प्रबंधन की स्थितियों तथा पर्यावरणीय दोहन से प्रभावित समुदायों के मानव अधिकारों का विश्लेषण करता है।

प्रमुख शब्द :

पर्यावरणीय न्याय, मानवाधिकार, अनुच्छेद 21, प्रदूषण हॉटस्पॉट, वितरणात्मक अन्याय, प्रक्रियात्मक न्याय, पहचान न्याय, GIS विश्लेषण, पर्यावरणीय असमानता, सतत विकास।

उद्देश्य :

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. पर्यावरणीय न्याय की अवधारणा और मानव अधिकारों के बीच संबंध को स्पष्ट करना।
2. प्रदूषण एवं कचरा प्रबंधन से सर्वाधिक प्रभावित भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान एवं विश्लेषण।
3. वंचित तथा हाशिए पर स्थित समुदायों पर पर्यावरणीय क्षरण के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन।

परिचय :

मानवाधिकारों की आधुनिक अवधारणा में स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक अनिवार्य और मूलभूत अधिकार के रूप में उभरकर सामने आया है। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण ने जहाँ विकास की गति को तेज किया है, वहीं पर्यावरणीय प्रदूषण और संसाधनों के अति–दोहन की गंभीर समस्या भी उत्पन्न की है। यह पर्यावरणीय संकट सभी को समान रूप से प्रभावित नहीं करता, बल्कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर, हाशिए पर स्थित और वंचित समुदाय सबसे अधिक जोखिम झेलते हैं। इस प्रकार पर्यावरण

संरक्षण केवल पारिस्थितिकी का मुद्दा नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर मानव अधिकारों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 "जीवन के अधिकार" में स्वस्थ पर्यावरण को स्वाभाविक रूप से सम्मिलित मानता है, और न्यायालयों ने अनेक फैसलों के माध्यम से इसे व्यापक मानवाधिकार स्वरूप प्रदान किया है। इसी पृष्ठभूमि में पर्यावरणीय न्याय (Environmental Justice) की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका उद्देश्य है– यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति, उसकी जाति, वर्ग, आय, भाषा या सामाजिक पहचान चाहे जो भी हो, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का समान अधिकार रखे। भूगोल इस विषय को स्थानिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में समझने का सशक्त माध्यम है। यह शोध–पत्र उन समुदायों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो प्रदूषण, कचरा–प्रबंधन की बदहाल व्यवस्था, औद्योगिक गतिविधियों और पर्यावरणीय दोहन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और उनके मानवाधिकार किस प्रकार प्रभावित होते हैं।

भारत में मानव-केंद्रित पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रमुख अधिनियम :

1. ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 – मानव स्वास्थ्य को कचरा–जनित जोखिमों से बचाना।
2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 – प्लास्टिक से मानव व पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को रोकना।
3. खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 – रासायनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा।
4. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 – मानव स्वास्थ्य की रक्षा हेतु प्रदूषण नियंत्रण का मुख्य कानून।
5. वायु (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 – स्वच्छ वायु का मानव अधिकार सुनिश्चित करता है।
6. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 – आदिवासी/स्थानीय समुदायों के संसाधन अधिकारों की सुरक्षा।
7. जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 – स्वच्छ पेयजल व जल स्रोतों की सुरक्षा।
8. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 – पारिस्थितिक संतुलन व मानव–प्रकृति सुरक्षा।

मुख्य महानगर में पर्यावरणीय समस्या से ग्रसित स्लम-आबादी का प्रतिशत और स्रोत :

- दिल्ली : ~10–15% (शहर के अलग–अलग सर्वे व रिपोर्ट्स के आधार पर)। Census 2011 India
- मुंबई : ~40–42% (Census-based/शहरी स्लम–रिपोर्ट्स में उच्च स्लम–सांख्यिकीय Dharavi–जैसी बड़ी बस्तियाँ कारण)। Census 2011 India+1
- कोलकाता : ~30–32% (शहरी स्लम–गणना के अनुसार)। Census 2011 India
- चेन्नै (Chennai) : ~28–30% (Census–2011 व राज्य रिपोर्ट उल्लेख)। Census 2011 India
- बेंगलुरु (Bengaluru) : ~8–9% (शहर की सूचित/नोटिफाइड स्लम–संख्याएँ)। Census 2011 India
- जयपुर : ~10–11% (शहरी स्लम–डेटा)। Census 2011 India
- कोटा : (स्थानीय रिपोर्टों में उच्च) ~30% (कुछ संदर्भों में) – पर यह शहर–विशेष आंकड़ा स्थानीय सर्वे पर निर्भर है। Census 2011 India

पर्यावरणीय न्याय केवल पर्यावरण संरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि यह इस बात की पड़ताल करता है कि पर्यावरणीय संसाधनों, जोखिमों और लाभों का वितरण समाज के अलग–अलग वर्गों पर कैसे और कितना

भिन्न रूप से प्रभाव डालता है। वितरणात्मक न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय, और पहचान न्याय। इन तीनों आयामों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि पर्यावरणीय असमानता किन संरचनात्मक कारणों से उत्पन्न होती है और कैसे यह मानव अधिकारों को प्रभावित करती है। पर्यावरणीय न्याय का अभाव मुख्यतः तीन स्तरों पर प्रकट होता है :

वितरणात्मक न्याय (Distributional Justice)

वितरणात्मक न्याय का संबंध इस बात से है कि पर्यावरणीय लाभ और जोखिम समाज में विभिन्न समूहों के बीच कैसे बाँटे गए हैं। जब प्रदूषण, कचरा निपटान, औद्योगिक उत्सर्जन, खनन गतिविधियाँ या जल–संकट जैसी समस्याओं का बोझ मुख्य रूप से गरीब, वंचित या हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर पड़े, तो यह वितरणात्मक अन्याय कहलाता है।

1. **लैंडफिल/डंपिंग साइट्स का चयन :**

- भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, जयपुर, कोटा में कचरा डंपिंग साइटें हमेशा शहर के गरीब या निम्न–आय वाले क्षेत्रों के पास विकसित की जाती हैं।
- इससे इन समुदायों को वायु प्रदूषण, दुर्गंध, बीमारियों और भूमिगत जल–प्रदूषण का अधिक सामना करना पड़ता है।

2. **औद्योगिक क्षेत्र और प्रदूषण :**

- गुजरात के वडोदरा और महाराष्ट्र के ताड़देव जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले श्रमिक समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं जबकि उच्च–आय वर्ग के लोग प्रदूषण–मुक्त क्षेत्रों में रहते हैं।
- यह पर्यावरणीय जोखिमों का असमान वितरण है।

3. **खनन क्षेत्र में आदिवासी समुदाय :**

- छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में खनन कंपनियों से होने वाला पर्यावरणीय क्षरण (धूल, जल प्रदूषण, वनों की कटाई) का बोझ अधिकांशतः आदिवासी समुदायों पर पड़ता है।
- खनन से होने वाली आय का लाभ राज्य या उद्योग उठाते हैं पर नुकसान स्थानीय समुदाय झेलते हैं।

वितरणात्मक न्याय तब मिलता है जब पर्यावरणीय लाभ और पर्यावरणीय जोखिम सब पर समान रूप से वितरित हों, न कि किसी विशेष कमजोर समूह पर केंद्रित हों।

प्रक्रियात्मक न्याय (Procedural Justice) :

प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध इस बात से है कि पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसे शामिल किया गया और किसे नहीं। अधिकांश समस्याएँ तब उत्पन्न होती हैं जब योजनाएँ, नीतियाँ या उद्योग स्थापित करने के निर्णय बिना स्थानीय लोगों की सहभागिता के किए जाते हैं।

1. **औद्योगिक प्लांटों की स्वीकृति :**

- कई बार फैक्ट्रियाँ स्थापित करने से पहले जन सुनवाई केवल औपचारिकता के रूप में की जाती है।
- राजस्थान के कई जिलों में सीमेंट और पॉल्यूशन–प्रोन फैक्ट्रियाँ गांवों में स्थापित कर दी जाती हैं, जबकि गाँव वालों की वास्तविक सहमति नहीं ली गई होती।

2. **सड़क या बांध निर्माण :**

- बड़े बांधों (जैसे नर्मदा परियोजना) के मामले में विस्थापन का निर्णय सरकार और कंपनियाँ लेती हैं।
- प्रभावित लोगों को प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता और पुनर्वास भी देर से मिलता है, जो प्रक्रियात्मक अन्याय का उदाहरण है।

3. **कचरा प्रबंधन योजनाएँ :**

- नगर–निगम अक्सर यह तय कर देते हैं कि कचरा किस स्थान पर डाला जाएगा, बिना क्षेत्र के निवासियों से चर्चा किए।
- इससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय जोखिम झेलने पड़ते हैं।

प्रक्रियात्मक न्याय वह है जहाँ सभी प्रभावित समूह निर्णय प्रक्रिया में बराबर भागीदारी रख सकें और उनकी आवाज को महत्व दिया जाए।

पहचान न्याय (Recognition Justice) :

पहचान न्याय का संबंध इस बात से है कि क्या सभी सामाजिक समूहों की पहचान, संस्कृति, जरूरतें और अधिकारों का सम्मान किया गया है या नहीं। जब किसी समुदाय की सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान को नजरअंदाज कर दिया जाए, और उनकी आवश्यकताओं को निर्णयों में शामिल न किया जाए, तो पहचान अन्याय होता है।

1. **आदिवासी समुदायों के वन-अधिकार :**

- खनन, डैम व औद्योगिक परियोजनाएँ अक्सर आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं।
- इन समुदायों के जंगल, भूमि और जल से जुड़ी सांस्कृतिक पहचान को महत्व नहीं दिया जाता।
- यह पहचान न्याय का गंभीर उल्लंघन है।

2. **अनौपचारिक श्रमिक और कचरा बीनने वाले लोग :**

- शहरी क्षेत्रों में कचरा बीनने वाले लोग शहर के कचरे को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- फिर भी उन्हें कोई औपचारिक पहचान, सुरक्षा उपकरण, स्वास्थ्य सुविधा या सामाजिक सम्मान नहीं मिलता।
- उनकी भूमिका को न पहचानना पहचान अन्याय है।

3. **नदी किनारे रहने वाले पारंपरिक समुदाय :**

- प्रदूषित नदियों (गंगा, यमुना, सबरमती) के किनारे रहने वाले पारंपरिक समुदाय का जीवन नदी से जुड़ा है।
- उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाने पर उनके जीवन–निर्वाह (मत्स्य उद्योग, खेती, धार्मिक गतिविधि) पर असर पड़ता है, पर उनकी पहचान और आवश्यकता को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

पहचान न्याय यह सुनिश्चित करता है कि सभी समुदायों की संस्कृति, आवश्यकताओं और सामाजिक पहचान का सम्मान हो तथा उन्हें बराबरी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले भी आये है जो पर्यावरणीय न्याय को मानव अधिकार मानते हैं जो निम्न है।

भारतीय न्यायालयों के प्रमुख फैसले (Human Rights + Environment) :

1. सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991, सुप्रीम कोर्ट)

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य (1991) में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मूल अधिकार का हिस्सा है।

कोर्ट ने कहा कि प्रदूषित जल और वायु मनुष्य के जीवन व स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण को प्रदूषण से बचाए।यह निर्णय भारत में पर्यावरण संरक्षण को मानव अधिकार से जोड़ने वाला ऐतिहासिक फैसला माना जाता है।

2. वी.एल. श्रीराम बनाम तमिलनाडु (Madras High Court)

वी.एल. श्रीराम बनाम तमिलनाडु (मद्रास हाईकोर्ट) मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण–मुक्त वातावरण में जीना प्रत्येक व्यक्ति का मूल मानव अधिकार है। कोर्ट ने माना कि प्रदूषित वायु और जल मानव स्वास्थ्य व जीवन की गुणवत्ता को सीधे प्रभावित करते हैं। इसलिए राज्य और प्रशासन का कर्तव्य है कि वे नागरिकों को स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध कराएँ।

3. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (Ganga Pollution Case, 1988)

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1988) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण रोकना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है, क्योंकि यह नागरिकों के स्वास्थ्य और मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि गंगा नदी में औद्योगिक अपशिष्ट नहीं छोड़ा जाए और इसके लिए सरकार व उद्योग दोनों जिम्मेदार हैं।यह निर्णय भारत में पर्यावरण संरक्षण और मानव अधिकारों को एक–दूसरे से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

4. T. N. Godavarman Case (Forest Protection, SC)

T. N. Godavarman बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वनों की रक्षा करना भविष्य की पीढ़ियों के मानव अधिकारों का मूल हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि जंगलों का संरक्षण केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन, स्वास्थ्य और अस्तित्व की रक्षा से सीधे जुड़ा दायित्व है। इस मामले ने भारत में वन प्रबंधन, वन संरक्षण और पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को मजबूत आधार प्रदान किया।

5. Lafarge Umiam Mining Case (2011, SC)

Lafarge Umiam Mining केस (2011) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 21 के तहत Right to Life (जीवन के अधिकार) का अनिवार्य हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि विकास कार्यों के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना राज्य और प्रशासन का कर्तव्य है। निर्णय में यह भी माना गया कि खनन जैसी गतिविधियाँ तभी वैध हैं जब वे पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को नुकसान न पहुँचाएँ।

6. Climate Change Judgment (2024, Supreme Court)

2024 के जलवायु परिवर्तन निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सुरक्षा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक मानव अधिकार है।

कोर्ट ने माना कि जलवायु परिवर्तन सीधे जीवन, स्वास्थ्य, आजीविका और मानव गरिमा को प्रभावित करता है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रभावी जलवायु–नीति और संरक्षण उपाय अपनाए। यह फैसला

पर्यावरणीय अधिकारों को मानव अधिकारों के दायरे में शामिल करने वाला ऐतिहासिक कदम माना जाता है।

निष्कर्ष :

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरणीय अन्याय केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर मानव अधिकार संबंधी चिंता है। प्रदूषण, कचरा प्रबंधन की असमानता, औद्योगिक दोहन और खनन क्षेत्रों का दबाव सामाजिक रूप से कमजोर समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है। भौगोलिक विश्लेषण (GIS) इन असमानताओं को सटीक रूप से पहचानने और नीति निर्माताओं के लिए उपयुक्त समाधान विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है।

पर्यावरणीय न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार मिले। यह सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण और समान वितरण अनिवार्य है, ताकि कोई वर्ग अत्यधिक दोहन करके अन्य समुदायों को वंचित न कर सके। पर्यावरणीय निर्णयों में लोगों की भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय समुदाय ही पर्यावरणीय बदलावों और खतरों को सबसे पहले अनुभव करते हैं। पारदर्शी और जवाबदेह नीतियाँ पर्यावरण प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाती हैं, इसलिए डेटा, रिपोर्ट और प्रक्रियाएँ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।साथ ही, नागरिकों को प्रदूषण, औद्योगिक कचरे, रासायनिक जोखिम और आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना राज्य की मूल जिम्मेदारी है।

भू–योजनाएँ (Land-use planning) सामाजिक संवेदनशीलता पर आधारित होनी चाहिए, ताकि जनजातीय क्षेत्रों, गरीब समुदायों और पर्यावरणीय दृष्टि से नाजुक क्षेत्रों की रक्षा हो सके। इन सभी तत्वों के बिना पर्यावरणीय न्याय स्थापित नहीं हो सकता, और जब तक पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित न हो, तब तक सतत विकास (Sustainable Development) की अवधारणा अधूरी और असंतुलित रहती है। इस तरह पर्यावरणीय न्याय सामाजिक समानता, पारिस्थितिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास का आधार बनता है।

सन्दर्भित ग्रंथ सूची :

1. Bullard, R. D. (1990). *Dumping in Dixie: Race, class, and environmental quality*. Westview Press.
2. United Nations Environment Programme. (n.d.). *UNEP reports*. https://www.unep.org
3. Central Pollution Control Board. (n.d.). *Annual reports*. Government of India. https://cpcb.nic.in
4. Lillesand, T. M., & Kiefer, R. W. (2000). *Remote sensing and image interpretation* (4th ed.). John Wiley & Sons.
5. The Energy and Resources Institute. (n.d.). *Environmental studies*. TERI. https://www.teriin.org
6. International Centre for Integrated Mountain Development. (n.d.). *Environmental vulnerability assessments in South Asia*. ICIMOD. https://www.icimod.org
7. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (n.d.). *Reports and publications*. Government of India. https://moef.gov.in

8. Smith, J. (2007). *Environmental justice and human rights*. Earthscan Publications.
9. Bryant, B., & Mohai, P. (1992). *Race and the incidence of environmental hazards*. Westview Press
10. **World Health Organization. (2018). Ambient air pollution: Global assessment report.** WHO Press.
11. https://www.who.int
12. **Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). Sixth Assessment Report (AR6).**
13. IPCC. https://www.ipcc.ch
14. **NASA Earth Observatory. (n.d.). Remote sensing data and environmental analysis.**
15. https://earthobservatory.nasa.gov
16. **Sharma, P. D. (2010).** *Ecology and Environment* **(13th ed.).** Rastogi Publications.
17. **Gupta, S. K., & Pandey, G. (2005).** *Environmental Pollution and Health***.** CBS Publishers.
18. **World Bank. (2016).** *World Development Report: Digital dividends* **(includes environmental data applications).**
19. https://www.worldbank.org
20. **CSE – Centre for Science and Environment. (n.d.). State of India's Environment Reports.**
21. https://www.cseindia.org
22. **Cutter, S. L. (1995).** *Environmental risks and hazards***.** Prentice Hall.

ईमेल : dharamkarwasra@gmail.com
मोबाइल नम्बर 9414741567

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 27-34

माधव नागदा की कहानियों में सामाजिक परिवर्तन, वर्ग–संघर्ष और मानवीय संवेदना

श्रीमती संगीता देवी, शोधार्थी,
डॉ. राजेश शर्मा, सहायक आचार्य
हिन्दी विभाग, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय) उदयपुर।

सारांश :

माधव नागदा समकालीन हिन्दी कथा–साहित्य के उन महत्त्वपूर्ण रचनाकारों में हैं जिनकी रचनाएँ जीवन, समाज और मनुष्य के वास्तविक अनुभवों से निर्मित होती हैं। उनकी कथा–दृष्टि किसी एक विचारधारा के नारे में सीमित नहीं हैय उसमें लोकधर्मिता, मानवतावाद, श्रमशील जीवन के प्रति सम्मान, सामाजिक विषमता के प्रति तीखी सजगता और मानवीय संवेदना के पक्ष में स्पष्ट नैतिक प्रतिबद्धता दिखाई देती है। डॉ. रमाकांत शर्मा ने उन्हें लोकधर्मी साहित्यकार कहा हैय जिनकी कहानियों में मनुष्य, प्रकृति और जीवन का कलात्मक रचाव मिलता हैय वहीं बलराम अग्रवाल ने उन्हें ऐसे लघुकथाकार के रूप में रेखांकित किया हैय जो समय से संगति बैठाए हुए हैं और जिनकी रचनाओं में मानवतावादी दृष्टि सक्रिय रहती है। स्वयं नागदा ने भी अपनी लघुकथा–यात्रा के संदर्भ में लिखा हैय कि कोई भी रचना जीवन से अलग–थलग नहीं हो सकती और लघुकथा उनके लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, जिसमें मानव–व्यक्तित्व की संरचना तक को बदलने की संभावना निहित है। यही कारण हैय कि उनके कथा–संसार में सामाजिक परिवर्तन, वर्गीय अंतर्विरोध, सांप्रदायिक उन्माद, पारिवारिक विघटन, लोकजीवन की स्मृति और मनुष्य की आंतरिक करुणा एक–दूसरे से जुड़कर सामने आते हैं।

प्रस्तुत लेख में माधव नागदा की कहानियों और लघुकथाओं का अध्ययन मुख्यतः शाप मुक्ति (1993), माटी की महक (2021), आग (2004), अपना–अपना आकाश तथा सहायक आलोचनात्मक/भूमिकात्मक सामग्री के आधार पर किया गया है। "बूढ़ी आँखों के सपने" (पृ. 9), "जहर कांटा" (पृ. 60), "आग" (पृ. 110), "विकलांग" (पृ. 111), "वह चली क्यों गयी?" (पृ. 112) और "अपना–अपना आकाश" (पृ. 28) जैसी रचनाएँ इस विमर्श की केंद्रीय आधार–भूमि हैं। इन रचनाओं में एक ओर बदलते सामाजिक मूल्यों, उपभोक्तावाद, बौद्धिक पाखंड और सांस्कृतिक संक्रमण की तस्वीर है, तो दूसरी ओर श्रम, भूख, अपमान, वर्गीय असमानता और मानवीय रिश्तों की टूटन के बीच मनुष्य की गरिमा बचाने का संघर्ष भी है। इसीलिए माधव नागदा का कथा–साहित्य केवल साहित्यिक उपलब्धि नहीं, बल्कि ामाजिक आत्मालोचन का दस्तावेज भी है।

प्रस्तावना :

समकालीन हिन्दी कहानी और लघुकथा ने जिस सामाजिक यथार्थ को केंद्र में रखा है, उसमें गाँव से शहर तक फैलती हुई विषमता, बदलते मूल्य, बाजारवादी संस्कृति, सांप्रदायिक तनाव, मध्यमवर्गीय पाखंड, शिक्षा और उपभोग के बीच झूलता युवा–मन, तथा टूटते–बनते पारिवारिक रिश्ते प्रमुख हैं। माधव नागदा का कथा–साहित्य इसी बदलते हुए यथार्थ को अनुभव की सच्चाई के साथ सामने लाता है। उनके यहाँ कथा जीवन से बाहर नहीं, जीवन के भीतर से निकलती है। यही कारण है, कि उनके पात्र बनावटी प्रतीक न होकर ठोस सामाजिक व्यक्तित्व बनकर सामने आते हैं। वे कभी किसान, कभी मजदूर, कभी बूढ़े पिता, कभी अकेली स्त्री, कभी अपमानित भिखारी, कभी बच्चों की दुनिया और कभी भीड़ के बीच पिसते मनुष्य के रूप में उपस्थित होते हैं। इस बहुलता के बावजूद उनकी रचनाओं में एक केंद्रीय सूत्र बना रहता है, मनुष्य को उसकी वास्तविक सामाजिक दशा में समझना।

बलराम अग्रवाल ने माटी की महक की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि नागदा लघुकथा को मात्र घटना–वर्णन नहीं बनने देते। उनके यहाँ यह संवेदनशीलता से युक्त कथा–रचना है, जिसके प्रत्येक शब्द, वाक्य, पात्र और स्थिति का अपना कथात्मक महत्व है। छोटे वाक्य, अंचल की बोलचाल से जुड़े सहज शब्द और स्वयं गढ़े हुए मुहावरे उनकी शैली की विशेषता हैं। यही शिल्प उनके सामाजिक सरोकारों को अधिक प्रभावी बनाता है, क्योंकि इससे कथा में लोक–जीवन की गंध बनी रहती है। नागदा के यहाँ साहित्य "समाज का दर्पण" होकर भी यांत्रिक प्रतिछाया नहीं है। वह समाज की भीतरी परतों को लेखक की सजग दृष्टि से पकड़ने वाली संवेदनात्मक रचना है। इसीलिए उनका कथा–साहित्य तटस्थता और पक्षधरता दोनों को एक साथ साधता है। तटस्थता तथ्य के प्रति, और पक्षधरता मनुष्य के प्रति।

स्वयं नागदा ने अपनी लघुकथा–यात्रा पर विचार करते हुए यह स्वीकार किया है कि उनका ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक संघर्ष और जीवन की कठिनाइयाँ उनकी लेखकीय दृष्टि के निर्माण में निर्णायक रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कोई भी रचना जीवन से अलग–थलग नहीं हो सकती। विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी उन्हें साहित्य ने इसलिए आकर्षित किया क्योंकि उसमें "जीवन से धड़कती हुई दुनिया" दिखी। बाद में लघुकथा उन्हें इसलिए मिली कि वह उनके लिए अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम बनी जिसमें संक्षिप्तता, संप्रेषण और वैचारिक तीक्ष्णता का संयोजन संभव था। उन्होंने यह भी माना कि उन्होंने लघुकथा में शब्दों की मितव्ययता पर बल दिया और उसे व्यक्तित्व–परिवर्तन की क्षमता वाली विधा के रूप में स्वीकार किया। यह आत्मस्वीकृति उनके कथा–संसार को पढ़ने की मूल कुंजी है।

माधव नागदा की रचनात्मक दृष्टि : लोकधर्मिता, मानवतावाद और सामाजिक प्रतिबद्धता :

डॉ. रमाकांत शर्मा ने मैं शब्दों का कुम्भकार की भूमिका में लिखा है कि माधव नागदा लोकधर्मी साहित्यकार हैं और उनकी कहानियों में मनुष्य, प्रकृति और जीवन का कलात्मक रचाव देखने को मिलता है। यह कथन केवल प्रशंसात्मक टिप्पणी नहीं, बल्कि नागदा की संपूर्ण रचनात्मकता का सार है। लोकधर्मिता यहाँ लोक–रंग या ग्रामीण सजावट भर नहीं है। इसका अर्थ है। जीवन के निकट होना, श्रम और सामान्य मनुष्य की दुनिया के भीतर से बोलना, और अनुभव को बौद्धिक बनावट से अधिक महत्त्व देना। इसी कारण नागदा के पात्रों में हमें किसान, मजदूर, छोटे लोग, अपमानित लोग, अकेली स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े अधिक मिलते हैं। वे समाज के "ऊपर" से

नहीं, भीतर से कथा रचते हैं।

कमर मेवाड़ी ने भी माधव नागदा की समालोचकीय दृष्टि को साफ बताते हुए कहा है कि उन पर किसी एक वाद, मत या विचारधारा का लेबल चस्पा नहीं किया जा सकता। इस कथन का अर्थ यह नहीं कि वे वैचारिक रूप से तटस्थ हैं बल्कि यह कि उनकी वैचारिकता जीवन से पैदा होती है, न कि कृत्रिम खाँचे से। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में वर्ग–संघर्ष है, पर वह नारे में नहीं बदलता, सामाजिक परिवर्तन है, पर वह आधुनिकता के अंध–उत्सव में नहीं बदलता, मानवीय संवेदना है, पर वह भावुकता का प्रदर्शन नहीं बनती। उनकी रचनाएँ विचारधारात्मक आग्रह के स्थान पर जीवन–सापेक्ष विवेक और मनुष्य–केंद्रित नैतिकता की ओर झुकती हैं।

बलराम अग्रवाल ने उन्हें "समय से संगति बैठाए हुए" लघुकथाकार कहा है और लिखा है कि वे मानवतावादी विचार के प्रस्तोता और पोषक हैं। यह टिप्पणी बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि नागदा की कहानियों में समय–बोध केवल वर्तमान का समाचार नहीं है वह समय की आत्मा को पकड़ने का प्रयास है। बदलता गाँव, बदलती तकनीक, शिक्षा का सामाजिक अर्थ, शहर का आतंक, उपभोक्तावादी संबंध, भीड़ की हिंसा, सांप्रदायिक विभाजन, बच्चों का मनोविज्ञान ये सब उनके यहाँ समकालीनता के अंग हैं। इसलिए नागदा का साहित्य एक तरफ लोक–जीवन की मिट्टी से जुड़ा है, दूसरी तरफ आधुनिक संक्रमण की आलोचनात्मक पहचान भी रखता है।

सामाजिक परिवर्तन – परंपरा, आधुनिकता और मूल्य-संघर्ष :

माधव नागदा की कहानी "बूढ़ी आँखों के सपने" सामाजिक परिवर्तन का अत्यंत प्रभावशाली पाठ प्रस्तुत करती है। शाप मुक्ति कहानी के प्रारंभिक दृश्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि लेखक गाँव में नए सांस्कृतिक माध्यम 'टी.वी.' के प्रवेश को किस तरह मूल्य–संघर्ष के रूप में देखते हैं। बच्चे उल्लासपूर्वक चिल्ला रहे हैं "टी. वी. आ गया", "महाभारत आ गया" उनके लिए टी.वी. और महाभारत लगभग पर्यायवाची बन गए हैं। दूसरी ओर बूढ़ा रामाबा इस दृश्य को विस्मय, असहमति और आंतरिक बेचैनी के साथ देखता है। यहाँ सामाजिक परिवर्तन केवल तकनीक का आगमन नहीं, सांस्कृतिक प्राथमिकताओं का पुनर्संयोजन है। बच्चों के लिए मनोरंजन और तमाशा केंद्रीय है। बूढ़ी पीढ़ी के लिए जीवन अभी भी श्रम, अन्न और अनुशासन से निर्मित है। (नागदा, शाप मुक्ति, 1993, "बूढ़ी आँखों के सपने," पृ. 9)

इस कहानी का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष यह है कि रामाबा किसी प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादी व्यक्ति की तरह नहीं गढ़े गए हैं। वे श्रम से अर्जित जीवन–मूल्यों के प्रतिनिधि हैं। कहानी में स्पष्ट रूप से आता है कि जब वे आँगन में बिखरे गेहूँ के दाने बीनते हैं, तो कहते हैं "अन्न भगवान हैं"। एक–एक दाना उन्हें अपने शरीर से बहे पसीने की एक–एक बूंद जैसा लगता है। इसी तरह उनके लिए विद्या भी पूज्य है, क्योंकि शिक्षा ने ही अन्याय के विरुद्ध अधिकार दिलाने की संभावना पैदा की। इस प्रकार रामाबा का प्रतिरोध मनोरंजन–विरोध नहीं, बल्कि श्रम–संस्कृति और उपभोग–संस्कृति के बीच संघर्ष है। नागदा यह दिखाते हैं कि आधुनिकता यदि जीवन को उपयोगी बनाती है तो वह स्वीकार्य हो सकती हैय जैसे मोटरसाइकिल को रामाबा बाद में "काम की चीज" मान लेते हैं पर यदि वह श्रम और संवेदना से विच्छेद पैदा करती है, तो उसके प्रति संशय स्वाभाविक है। (नागदा, शाप मुक्ति, 1993 "बूढ़ी आँखों के सपने," पृ. 9)

यही सामाजिक परिवर्तन नागदा की लघुकथा "अपना–अपना आकाश" में दूसरे रूप में सामने आता है।

इस लघुकथा में "बच्चों का भविष्य" विषय पर गोष्ठी चल रही है। विचारवान लोग बच्चों के बोझ, सुखमय भविष्य और शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चों का स्वाभाविक खेल और शोर उन "विचारों" में बाधा डालता है, उन्हें कमरे से बाहर भेज दिया जाता है। यह बहुत तीखा व्यंग्य है बच्चों के भविष्य पर विमर्श करने वाले प्रौढ़जन बच्चों की उपस्थिति तक सहन नहीं कर पाते। यहाँ नागदा आधुनिक बौद्धिक समाज की उस विडंबना को पकड़ते हैं जिसमें विचार और व्यवहार का संबंध टूट जाता है। सामाजिक परिवर्तन का यह रूप "प्रबुद्धता" के नाम पर संवेदना–विहीनता का रूप ले लेता है। (नागदा, माटी की महक, 2021, "अपना–अपना आकाश," पृ. 28)

"अपना–अपना आकाश" के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि नागदा सामाजिक परिवर्तन को केवल आर्थिक या तकनीकी परिप्रेक्ष्य से नहीं देखते। उनके लिए परिवर्तन मनुष्य की मानसिकता, सार्वजनिक नैतिकता और रोजमर्रा के व्यवहार में भी घटता है। बच्चों की दुनिया में खेल, झगड़ा, दोस्ती, खिलखिलाहट और स्वाभाविकता है जबकि बड़ों की दुनिया में गंभीरता, बौद्धिक प्रदर्शन और दमन की प्रवृत्ति है। इस लघुकथा का निहितार्थ यह है कि आधुनिक समाज भविष्य की बात तो बहुत करता है, पर जीवन की स्वाभाविक धड़कनों के लिए उसमें जगह कम होती जा रही है। नागदा का सामाजिक परिवर्तन–बोध इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि वह मूल्य–क्षरण, बौद्धिक पाखंड और संबंधों की कृत्रिमता को भी पहचानता है।

वर्ग-संघर्ष - भूख, श्रम, अपमान और सामाजिक असमानता :

माधव नागदा की कहानियों में वर्ग–संघर्ष का सबसे तीखा रूप "जहर कांटा" में दिखाई देता है। इसका केंद्रीय पात्र रामा एक श्रमजीवी, गरीब, विस्थापित मनुष्य है जो शहर में रोजगार की तलाश में आता है। उसके सामने शहर का सपना है काम, मजदूरी, बेहतर जीवन। लेकिन शहर उसके लिए अवसर का नहीं, आतंक, संदेह और अपमान का स्थल बनता जाता है। यही नागदा की वर्ग–दृष्टि का आरंभिक बिंदु है : गरीब मनुष्य के लिए आधुनिक समाज का वादा और उसकी वास्तविकता एक–दूसरे के प्रतिकूल हैं। (नागदा, शाप मुक्ति, 1993, "जहर कांटा," पृ. 60)

"जहर कांटा" का सबसे मार्मिक क्षण वह है। जब रामा से उसकी धार्मिक पहचान पूछी जाती है और अंततः वह स्वयं को "मजदूर आदमी" कहकर पहचान देता है। यह उत्तर नागदा की सामाजिक दृष्टि की केन्द्रीयता को उद्घाटित करता है। भारतीय समाज में धर्म, जाति और समुदाय की पहचानें जितनी मुखर हैं, उससे कहीं गहरी पहचान भूख और श्रम की है। पर विडंबना यह है कि सत्ता–संरचना इस पहचान को मान्यता नहीं देती। मजदूर होना यहाँ सम्मान का विषय नहीं, संदेह का विषय बन जाता है। इस तरह नागदा वर्ग–संघर्ष को आर्थिक असमानता से आगे बढ़ाकर सामाजिक पहचान, गरिमा और सुरक्षा के प्रश्न से जोड़ देते हैं।

कहानी में एक बिंदु ऐसा भी आता है। जहाँ रामा से हिंसक काम में शामिल होने की अपेक्षा की जाती है। उसे घासलेट की केन ढोने और आगजनी में हाथ बँटाने के लिए कहा जाता है। वहाँ उसका उत्तर कथा का नैतिक शिखर है। वह कहता है कि "घरों को आग लगाना" और "निरदोष की जान लेना" घोर पाप है। वह बताता है कि जंगल के लोग तो आग बुझाने के लिए दस–दस कोस तक दौड़ते हैं, प्राण बचाने के लिए। इस उत्तर से स्पष्ट होता है कि नागदा के यहाँ श्रमजीवी, हाशिये का मनुष्य नैतिकता का वास्तविक वाहक है, जबकि संगठित "सभ्य" समाज हिंसा और विनाश का साधन बन सकता है। वर्ग–संघर्ष यहाँ केवल संसाधनों का संघर्ष

नहीं, नैतिकता और अमानवीयता का भी संघर्ष है।

वर्गीय अपमान का एक दूसरा रूप "रिसेप्शन" में मिलता है, जो आग संग्रह में उपलब्ध है। इस लघुकथा में समधी–पक्ष का दंभी व्यवहार, "स्टैंडर्ड", "औकात" और "कचरा" जैसी भाषा, तथा निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार का अपमान यह स्पष्ट करता है कि वर्गीय वर्चस्व केवल धन से नहीं, व्यवहार की भाषा और सामाजिक प्रदर्शन से भी स्थापित होता है। नवीन द्वारा एक–एक रुपये की गड्डी हवा में उछाल देने पर बरातियों का दृश्य वर्ग–सम्मान की उस नकली दीवार को गिरा देता है। जिस पर "उच्च" होने का दावा टिका था। यह लघुकथा बताती हैय कि वर्ग–संघर्ष कई बार प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं, बल्कि सामाजिक अनावरण होता है।

"विकलांग" में वर्ग–संघर्ष विडंबना के माध्यम से आता है। एक लंगड़ा भिखारी सेठ से भीख माँगता है। सेठ उसे "काम करने" की सलाह देकर अपमानित करता है। किंतु अगले ही क्षण पता चलता है कि स्वयं सेठ की दोनों टाँगें घुटनों तक नहीं हैं। यहाँ नागदा दया, श्रम, संपत्ति और नैतिक श्रेष्ठता के पाखंड पर प्रहार करते हैं। रचना यह संकेत देती है कि आर्थिक सामर्थ्य किसी मनुष्य को अस्तित्वगत पीड़ा से मुक्त नहीं करती, और गरीबी को अपमान की दृष्टि से देखना मानवीय संवेदना के विरुद्ध है। यह वर्गीय संवेदना का तीखा नैतिक पाठ है। (नागदा, माटी की महक, 2021, "विकलांग," पृ. 111)

सांप्रदायिकता, भीड़-मानस और वर्गीय विडंबना :

माधव नागदा की लघुकथा "आग" सांप्रदायिक उन्माद की अमानवीयता को अत्यंत सघन रूप में व्यक्त करती है। आग संग्रह के आरंभ में ही इसे उन "असंख्य सैनिकों" को समर्पित किया गया है जो गरीबी और अन्याय के विरुद्ध रोजमर्रा की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह समर्पण बताता है कि नागदा सांप्रदायिकता को भी व्यापक सामाजिक अन्याय की पृष्ठभूमि में देखते हैं। लघुकथा में एक मामूली चिंगारी को लोग सामुदायिक आक्रोश में बदल देते हैं। भीड़ हथियारों से लैस होकर पड़ोसी मोहल्ले की ओर बढ़ती है। एक जवाबी मोर्चा बनता है और अंततः आग सबको समान रूप से झुलसा देती है। कहानी का निष्कर्ष कि आग का असर दोनों गुटों पर एक जैसा होता है। दरअसल साम्प्रदायिक विभाजन की निरर्थकता और साझा मानवीय देह–सत्य का उद्‌घाटन है।

"आग" की वैचारिक शक्ति इस बात में हैय कि यह किसी उपदेश के रूप में नहीं, बल्कि ठोस दृश्य–क्रम के माध्यम से अपना प्रभाव पैदा करती है। चिंगारी, भीड़, हथियार, जवाबी मोर्चा, लपटें, झुलसी देह ये सब इतने न्यूनतम शब्दों में आते हैं कि रचना एक दृश्यात्मक राजनीतिक वक्तव्य बन जाती है। नागदा यहाँ केवल साम्प्रदायिकता की आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि यह भी संकेत कर रहे हैं कि भीड़ का विवेक कितनी जल्दी खत्म हो जाता है। एक मोहल्ले की आग पूरे शहर को खाक कर सकती है, फिर भी लोग उसे बुझाने के बजाय हवा देते हैं। यह सामूहिक विवेकहीनता आधुनिक समाज की बड़ी त्रासदी है। (नागदा, माटी की महक, 2021 "आग," पृ. 110)

"जहर कांटा" और "आग" को साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता हैय कि नागदा सांप्रदायिकता को वर्गीय विडंबना से अलग नहीं देखते। दंगों, पहचान–राजनीति और भीड़ की हिंसा में सबसे पहले पिसता कौन है? वही गरीब, वही मजदूर, वही हाशिये का आदमी जिसके पास न सुरक्षा है, न प्रतिनिधित्व। रामा जैसे पात्र की त्रासदी यही हैय कि वह न पूरी तरह किसी धार्मिक पहचान में समा पाता है, न "सभ्य" शहर उसे मनुष्य की तरह स्वीकार करता है। दूसरी ओर भीड़ की हिंसा में जलने वाले शरीर अंततः सबके समान हैं। इस तरह नागदा के यहाँ

सांप्रदायिकता मनुष्य–विरोधी है, और वर्गीय रूप से भी हाशिये के लोगों के विरुद्ध काम करती है।

मानवीय संवेदना – अकेलापन, संबंध और करूणा की पुर्नस्थापना :

माधव नागदा की कहानियों की सबसे बड़ी शक्ति उनकी मानवीय संवेदना है। यह संवेदना केवल करुणाजनक स्थितियों का वर्णन नहीं, बल्कि मनुष्य की भीतरी जरूरतों की गहरी समझ है। "वह चली क्यों गयी?" इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहानी का पुरुष पात्र पत्नी के लिए महँगे उपहार, गहने, मनोरंजन के यंत्र और नोटों की बरसात लाता है, पर पत्नी बार–बार यही कहती है "तुम यहीं रहो। मेरा मन नहीं लगता।" पति उसके अकेलेपन का अर्थ नहीं समझता। वह हर बार पैसे, डॉक्टर और सुविधाओं को समाधान मानता है। अंततः जब वह लौटता है, तो सब कुछ घर में वैसा ही मौजूद है। गहने, कपड़े, टी.वी., वीडियो, नोटों के बंडल। सिर्फ पत्नी नहीं है। यह लघुकथा उपभोक्तावादी संबंधों की असफलता और आत्मीयता की अनिवार्यता को अत्यंत तीखे ढंग से सामने लाती है। (नागदा, माटी की महक, 2021 "वह चली क्यों गयी?," पृ. 112)

इस लघुकथा की विशेषता यह है कि नागदा यहाँ किसी रोमानी भावुकता में नहीं जाते। वे पत्नी के "भाग जाने" की घटना को नैतिक उपदेश में नहीं बदलते, बल्कि यह दिखाते हैं कि संवेदना–विहीन सम्पन्नता संबंधों को टिकाए नहीं रख सकती। पैसा, आराम और वस्तुएँ मनुष्य के भावनात्मक अभाव को नहीं भर सकतीं। यही आधुनिक जीवन की एक बड़ी विडंबना है। वस्तुएँ बढ़ती जाती हैं, पर निकटता कम होती जाती है। नागदा इस विडंबना को बहुत कम शब्दों में गहरे सामाजिक अर्थ के साथ व्यक्त करते हैं। यह मानवीय संवेदना का विमर्श है, जो केवल प्रेम–कहानी नहीं, आधुनिक जीवन के मानसिक ढाँचे की आलोचना है।

"विकलांग" में भी मानवीय संवेदना एक तीव्र विडंबनात्मक क्षण के माध्यम से जन्म लेती है। भिखारी और सेठ के बीच छोटा–सा संवाद उस सामाजिक व्यवस्था की पोल खोल देता है। जिसमें दया और तिरस्कार साथ–साथ चलते हैं। सेठ का उपदेश "कमाई किया कर" उसकी सामाजिक श्रेष्ठता–बोध का संकेत है। पर जब भिखारी देखता है कि स्वयं सेठ की दोनों टाँगें नहीं हैं, तो पूरा अर्थ–तंत्र उलट जाता है। यहाँ नागदा पाठक के भीतर करुणा ही नहीं, आत्मालोचन भी पैदा करते हैं। हम किस आधार पर दूसरे को "अयोग्य", "बेकार" या "तुच्छ" समझते हैं? सामाजिक संबंधों में दंभ और अपमान किस प्रकार संवेदना को नष्ट करते हैं? यह लघुकथा इन प्रश्नों को तीखेपन से सामने लाती है। (नागदा, माटी की महक, 2021, "विकलांग," पृ. 111)

डॉ. रमाकांत शर्मा की यह टिप्पणी कि नागदा की रचनाओं में मनुष्य, प्रकृति और जीवन का कलात्मक रचाव है, ऐसी ही रचनाओं के संदर्भ में और भी अर्थपूर्ण हो उठती है। नागदा के यहाँ मनुष्य किसी विचार का उदाहरण भर नहीं है। वह अपनी टूटन, लालसा, भूख, अपमान, स्मृति, अकेलेपन और उम्मीद के साथ उपस्थित होता है। यही कारण है कि उनके कथा–संसार में मानवीय संवेदना केंद्रीय तत्व है। वह कभी पत्नी के अकेलेपन में, कभी भिखारी की अपमान–बोध में, कभी रामा की नैतिक हिचक में, कभी बूढ़े किसान के अन्न–श्रद्धा में, और कभी बच्चों की स्वाभाविक खिलखिलाहट में प्रकट होती है।

शिल्प, भाषा और लोकानुभव की कलात्मकता :

माधव नागदा की कहानियों के प्रभाव का एक बड़ा कारण उनका शिल्प है। बलराम अग्रवाल के अनुसार लघुकथा का हर शब्द, हर वाक्य, हर पात्र और हर स्थिति अर्थवान होना चाहिए। नागदा की कई लघुकथाएँ इस कसौटी पर खरी उतरती हैं। उनके छोटे वाक्य, अंचल की बोलचाल से जुड़े सहज शब्द, और मितव्ययी कथन

उनकी शक्ति हैं। यह शिल्प उनके विषयों के अनुरूप है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन, वर्गीय अपमान और मानवीय संवेदना जैसे विषयों को अति–वर्णनात्मक शैली नहीं, बल्कि संक्षिप्त और मारक भाषा अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर सकती है।

समकालीन हिन्दी लघुकथा और समय का सच में शिल्प पर विचार करते हुए यह रेखांकित किया गया है कि शिल्प केवल नक्काशी नहीं, बल्कि वह वास्तुकला है। जिसमें विचारों की गरमाहट, मानवीय संवेदनाओं की खुशबू, लोकजीवन के संघर्ष, रिश्तों के बनते–बिगड़ते समीकरण और समाज की धड़कनें बसती हैं। यह सूत्र माधव नागदा की कहानियों पर पूरी तरह लागू होता है। "आग" जैसी लघुकथा में कथात्मक अर्थ दृश्य–क्रम से उत्पन्न होता है "विकलांग" में एक छोटे–से खुलासे से पूरी सामाजिक विडंबना सामने आती है "वह चली क्यों गयी?" में वस्तुओं की सूची ही भावनात्मक रिक्तता का रूपक बन जाती है "बूढ़ी आँखों के सपने" में बोलचाल और स्मृति के माध्यम से पीढ़ीगत संघर्ष जीवित हो उठता है। नागदा का शिल्प जीवन–संबंधी अनुभव को सघन और मारक बनाने वाला शिल्प है।

भाषा की दृष्टि से भी नागदा अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। वे भाषा को कृत्रिम अलंकरण का माध्यम नहीं बनाते। वह पात्रों के जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बनकर आती है। "रामाबा", "मदन", "रामा", "गरीबदास", "सेठ", "समधीजी" जैसे नाम और उनके संवाद लोक और समाज की वास्तविकता को उपस्थित कर देते हैं। उनकी भाषा में लोक–लय, ग्रामीण जीवन की गंध, बोलियों की छाया और जीवित मुहावरे हैं। यही कारण है कि उनके पात्र पाठक से दूर नहीं लगते। वे दस्तावेजी यथार्थ और कलात्मक संवेदना के बीच एक सहज संतुलन रचते हैं।

निष्कर्ष :

माधव नागदा की कहानियाँ सामाजिक परिवर्तन, वर्ग–संघर्ष और मानवीय संवेदना इन तीनों विमर्शों को एक साथ समेटती हैं। "बूढ़ी आँखों के सपने" में बदलते समय का पीढ़ीगत और मूल्यगत तनाव है "अपना–अपना आकाश" में आधुनिक बौद्धिकता का विडंबनापूर्ण चेहरा है। "जहर कांटा" में श्रमजीवी मनुष्य की पहचान, भूख और नैतिकता का संघर्ष है। "आग" में साम्प्रदायिकता की आत्मघाती राजनीति है। "विकलांग" में सामाजिक दंभ पर प्रहार है और "वह चली क्यों गयी?" में उपभोक्तावादी सम्पन्नता के भीतर खाली हो चुके संबंधों की त्रासदी है। इन सबको साथ पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि नागदा समाज को केवल संरचनात्मक रूप में नहीं, अनुभवात्मक रूप में समझते हैं। उनके यहाँ वर्ग, संबंध, राजनीति और संवेदना अलग–अलग खानों में नहीं रहते वे एक–दूसरे में उलझे हुए हैं।

माधव नागदा का महत्त्व इस बात में भी है कि वे किसी वैचारिक घोषणापत्र के लेखक नहीं, बल्कि जीवन–सापेक्ष रचनाकार हैं। वे शोषित और संघर्षशील मनुष्य के पक्ष में खड़े होते हैं, पर उसे महिमामंडित करके नहीं वे उसके श्रम, भूख, अपमान, नैतिक शक्ति और भावनात्मक जरूरतों को समझते हैं। उनकी कथाएँ पाठक को यह सोचने के लिए विवश करती हैं कि आधुनिकता का अर्थ क्या है, प्रगति किसकी है, वर्गीय श्रेष्ठता का नैतिक आधार क्या है, और मनुष्य को आखिर मनुष्य बनाए रखने वाली शक्ति कौन–सी है। इन प्रश्नों के बीच उनका साहित्य हमें बार–बार उसी निष्कर्ष तक पहुँचाता है। मनुष्यता, संवेदना और श्रम–सम्मान के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन सार्थक नहीं हो सकता। यही उनकी कहानियों की स्थायी प्रासंगिकता है।

संदर्भ-सूची :

1. अग्रवाल, ब. (2021). माधव नागदा – माटी–सा महकता लघुकथा–संसार , माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (भूमिका). विद्या बुक्स.
2. नागदा, म. (1993). शाप मुक्ति. सम्बोधन प्रकाशन.
3. नागदा, म. (2004). आग. सूर्य प्रकाशन मंदिर.
4. नागदा, म. (2021). अपना–अपना आकाश, माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (पृ. 28). विद्या बुक्स.
5. नागदा, म. (2021). आग, माटी की महक–माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (पृ. 110). विद्या बुक्स.
6. नागदा, म. (2021). विकलांग, माटी की महक–माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (पृ. 111). विद्या बुक्स.
7. नागदा, म. (2021). वह चली क्यों गयी?, माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (पृ. 112). विद्या बुक्स.
8. नागदा, म. (2016). मैं शब्दों का कुम्भकार. (डॉ. र. शर्मा, भूमिका).
9. नागदा, म. (2021). माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ. विद्या बुक्स.
10. नागदा, म. (1993). बूढ़ी आँखों के सपने. शाप मुक्ति (पृ.9). सम्बोधन प्रकाशन.
11. नागदा, म. (1993). जहर कांटा. शाप मुक्ति (पृ. 60). सम्बोधन प्रकाशन.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 35–37

कोरगर जनजाति : परंपरा, संस्कृति और समकालीन चुनौतियाँ

डॉ. संजीव कुमार. के
एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग
एम.इ.एस कल्लडी. कॉलेज (ओटोणमस) मन्नाटकाड, पालकाड, केरल–678583

कोरगर (कोरग) केरल के कासरगोड जिले और कर्नाटक में निवास करने वाला एक आदिवासी समुदाय है। कोरगर एक जनजातीय समुदाय है, जिसे प्राक्तन (प्रोटो–ऑस्ट्रेलॉइड) समूह में शामिल किया जाता है। ये मुख्य रूप से केरल के कासरगोड जिले के मंझेश्वरम, बडियडुक्का, एन्मकजे, मंगरवाड़ी, पैवलिगे, नट्टाणिक तथा बल्लूर आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। काला रंग, मोटे होंठ, चौड़ी और फैली हुई नाक तथा खुरदरे एवं घुँघराले बाल इनकी प्रमुख शारीरिक विशेषताएँ हैं। 1881 की जनगणना के अनुसार इन्हें आदिम निवासी (Aboriginals) के रूप में दर्ज किया गया था।

कोरगर समुदाय संचार के लिए 'कोरग भाषा' का उपयोग करता है, जो कन्नड़ के व्यापक प्रभाव तथा तुलु भाषा की उपस्थिति से युक्त मलयालम में आधारित भाषा है। कोरग भाषा एक मौखिक परंपरा पर आधारित भाषा है तथा इसकी अपनी कोई स्वतंत्र लिपि नहीं है। लेखन कार्य के लिए इस समुदाय द्वारा कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रीय विविधताओं के आधार पर कोरग भाषा की चार प्रमुख उपभाषाएँ मानी जाती हैं– मुडु, ओंटी, आन्टे और ताप्पु।

कोरगर आदिवासी समुदाय को सबसे अधिक सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। इतिहास से पता चलता है कि जब जमींदार भूमि का हस्तांतरण करते थे, तब उस भूमि पर काम करने वाले कोरगरों को भी नए मालिक के साथ हस्तांतरित कर दिया जाता था। कोरगरों को धन रखने या अपनी स्वयं की भूमि पर अधिकार रखने का अधिकार नहीं था। जमींदार उनके श्रम के बदले उन्हें केवल भोजन प्रदान करते थे। कोरगर समुदाय में परंपरागत रूप से अनेक रीति–रिवाज, अनुष्ठान और विश्वास प्रचलित हैं। कोरगर लोगों के पास कोई विशेष मूर्तियाँ या मंदिर नहीं हैं। इसके बजाय वे प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते हैं। ब्रह्मांड की शक्ति के रूप में कोरगर समुदाय सूर्य की पूजा करता है। 'कोरा' शब्द का अर्थ 'सूर्य' है। इसी शब्द से 'कोरग या कोरगर' नाम की उत्पत्ति मानी जाती है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य को प्रणाम करके जागना उनकी परंपरा है। दक्षिण भारत में सूर्य की उपासना करने वाला यह संभवतः एकमात्र जनजातीय समुदाय है। वे वृक्षों, पत्थरों और नदियों की पूजा करते हैं। वृक्षों में विशेष रूप से काञ्जिर (कंजिर) वृक्ष के नीचे पत्थरों की स्थापना करके कोरगर

समुदाय अपने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा–अर्चना करता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बकरी और मुर्गे की बलि देने की परंपरा भी इनके बीच प्रचलित है। पूजा–अर्चना के लिए वे अपने घरों के सामने 'स्थान' की अवधारणा के रूप में 'काट्टा' नामक पत्थर की पूजा करते हैं। उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर घरों को साफ करके तथा गोबर से लीपने के बाद स्त्री और पुरुष मिलकर उत्सव मनाते हैं। सभी पर्वों और उत्सवों में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी होती है।

कोरगर समुदाय के घरों को 'कोप्पा' कहा जाता है। ये घर जंगल से एकत्र किए गए बाँस और ईटा (बेंत/सरकंडे जैसी सामग्री) से बनाए जाते हैं। कोप्पा (बस्ती/कालोनी) के सभी परिवारों का मार्गदर्शन और नियंत्रण वहाँ के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जिसे 'मूप्पन' कहा जाता है। परिवार से संबंधित विवादों, विवाहों तथा उत्सवों जैसे सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का संचालन और नेतृत्व भी वही करता है। कोरगर जनजाति में विवाह अत्यंत सरल रीति–रिवाजों के साथ संपन्न होता है। विवाह संबंध तय करने तथा विवाह समारोह के आयोजन में समुदाय के बुजुर्गों और मूप्पन (मुखिया) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके मार्गदर्शन और सहमति से ही विवाह की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कोरगर जनजाति में दहेज प्रथा नहीं है। इसके स्थान पर 'कन्या–मूल्य' (वधू–मूल्य) देने की परंपरा प्रचलित है। 'पेन्–पणम्' (कन्या–मूल्य) से आशय उस धनराशि, वस्त्रों और उपहारों से है, जो विवाह के अवसर पर वर–पक्ष द्वारा वधू के परिवार को प्रदान किए जाते हैं। वधू के घर पर वर और वधू एक–दूसरे को माला पहनाते हैं। इसके पश्चात वे प्रकृति के अधिष्ठाता सूर्यदेव की ओर मुख करके हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इसी के साथ विवाह समारोह संपन्न हो जाता है। विवाह के अवसर पर कोरग समुदाय के पारंपरिक वाद्ययंत्र 'तुदि' (ढोल) की थाप पर स्त्री और पुरुष मिलकर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हैं।

पूर्वकाल में कोरगर समुदाय के बीच अनेक कुप्रथाएँ प्रचलित थीं। यदि किसी जमींदार के घर में गाय, भैंस या बैल की मृत्यु हो जाती थी, तो वे वहाँ जाकर उसकी खाल उतारते थे तथा मांस को काटकर अपने घर ले जाकर पकाते थे। इसी प्रकार, ब्राह्मणों के घरों में विवाह समारोह सम्पन्न होने के बाद वहाँ जाकर भोजन के लिए प्रयुक्त पत्तलों (जूठे पत्तों) से भोजन ग्रहण करने की प्रथा भी उनके बीच प्रचलित थी।

'भूमि हब्बा' कोरगर जनजाति का एक प्रमुख कृषि पर्व है। यह उत्सव आगामी फसल की अच्छी उपज की कामना तथा भूमि देवी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर कोरगर लोग जंगल में जाकर विशेष प्रकार के कंद–मूल तथा अन्य वन–उत्पाद एकत्र करते हैं और उन्हें भूमि देवी को नैवेद्य के रूप में अर्पित करते हैं। उत्सवों के दौरान वे पशुओं की खाल से बने 'तुदि' (ढोल/चेंडा) और बाँस से निर्मित 'ऊट्टे' (बाँसुरी) जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ गीत गाते हैं। स्त्री और पुरुष मिलकर वृत्ताकार रूप में खड़े होकर सामूहिक नृत्य करते हैं। कोरगर समुदाय का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य रूप 'कोरग नृत्य' है। वर्तमान समय में इस नृत्य का प्रदर्शन अनेक सार्वजनिक मंचों तथा विभिन्न उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है।

कोरगर समुदाय में 'अन्ते कोरगर', 'कुंडु कोरगर' तथा 'शोप्पु कोरगर' जैसी उपशाखाएँ पाई जाती हैं। इनमें से केवल कुंडु कोरगर ही केरल में निवास करते हैं। विभिन्न आकारों और रूपों की आकर्षक टोकरियाँ (बाँस की टोकरी) बनाने और बुनने की विशिष्ट पारंपरिक कला में वे विशेष दक्षता रखते हैं।

आज कोरगर समुदाय सामाजिक रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर है, किन्तु वे अनेक गंभीर चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। उनकी प्रमुख समस्याओं में से एक जनसंख्या में आई उल्लेखनीय कमी है। कुपोषण, आनुवंशिक रोग तथा शिशु मृत्यु दर इस स्थिति के प्रमुख कारण माने जाते हैं। नई पीढ़ी के बच्चे अब विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने लगे हैं, फिर भी उच्च शिक्षा हासिल करने वालों की संख्या अभी भी बहुत कम है। प्लास्टिक उत्पादों के व्यापक प्रचलन के कारण उनके पारंपरिक व्यवसाय, अर्थात् टोकरियाँ बुनने से होने वाली आय में उल्लेखनीय कमी आई है। यद्यपि कोरगर समुदाय दासता जैसी परिस्थितियों से निकलकर लोकतांत्रिक अधिकारों के दायरे में आ चुका है, फिर भी स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास की आवश्यकता बनी हुई है।

सहायक ग्रंथ :-

1. केरल की जनजातीय विरासत (केरलत्तिन्टे गोत्रवर्ग पैतृकम्) – डॉ. आर. गोपीनाथन।
2. केरल की जनजातीय जातियाँ (केरलत्तिले गोत्रवर्ग विभागंगल्) – एस. रामनुण्णि।
3. केरल का अफ्रीका (केरलत्तिले आफ्रिका) – के. पानूर।
4. केरल के आदिवासी : कला और संस्कृति (केरलत्तिले आदिवासिकल् कलयुम् संस्क्कारवुम्) – मनोज मातिरप्पल्ली।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 38-44

माधव नागदा की कहानियों का कथा-शिल्प - भाषा, संरचना और दृष्टि बिंदु का विवेचन

श्रीमती संगीता देवी, शोधार्थी,
डॉ. राजेश शर्मा, सहायक आचार्य
हिन्दी विभाग, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ, (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय) उदयपुर।

सारांश :

यह शोध–पत्र माधव नागदा की कहानियों के कथा–शिल्प का भाषा, संरचना और दृष्टिबिंदु के आधार पर विश्लेषण करता है। अध्ययन का आधार शाप मुक्ति, माटी की महक, आग तथा शिल्प–विषयक आलोचनात्मक और वैचारिक सामग्री है। बलराम अग्रवाल ने नागदा की लघुकथाओं में छोटे वाक्यों, अंचल की बोलचाल से जुड़े सहज शब्दों, सर्जनात्मक दृष्टि और संप्रेषण–क्षमता को उनकी विशिष्ट शिल्पगत पहचान माना है, जबकि "मेरी लघुकथा यात्रा" में स्वयं नागदा यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी रचना जीवन से अलग–थलग नहीं हो सकतीय इसीलिए उनका शिल्प जीवनानुभव से निर्मित और सामाजिक यथार्थ से संबद्ध है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नागदा की भाषा लोकधर्मी, पात्रानुकूल, संक्षिप्त और व्यंजक हैय "बूढ़ी आँखों के सपने" में आंचलिक शब्दावली और ग्रामीण संवेदना परिवेश की सजीवता रचती है, जबकि "आग" में संरचनात्मक संक्षेप और दृश्यात्मक क्रम सामुदायिक हिंसा की विडंबना को तीखे रूप में उद्घाटित करते हैं। शिल्प पर विचार करते हुए स्वयं नागदा/संबंधित आलोचनात्मक सामग्री यह भी रेखांकित करती है कि लघुकथा में एक–एक शब्द, दृश्य और विरामचिह्न तक अर्थ–निर्माण में सक्रिय रहते हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि माधव नागदा का कथा–शिल्प लोकभाषिक ऊर्जा, संरचनात्मक कसावट और संवेदनात्मक दृष्टि का प्रभावी समन्वय है, जो उन्हें समकालीन हिन्दी कथा–साहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है।

प्रस्तावना :

माधव नागदा का कथा–साहित्य इस कारण महत्त्वपूर्ण नहीं है कि वह केवल समकालीन समाज की विडंबनाओं को दर्ज करता है, बल्कि इस कारण भी कि वह उन्हें एक विशिष्ट कथा–शिल्प में रूपांतरित करता है। उनके यहाँ शिल्प किसी बाहरी सजावट या तकनीकी प्रदर्शन का नाम नहीं है। वह कथ्य की संवेदनात्मक, वैचारिक और कलात्मक संरचना का सक्रिय तत्व है। बलराम अग्रवाल ने माटी की महक की भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि लघुकथा "सुविधाजनक और आसान लेखन" नहीं, बल्कि "संवेदनशीलता के गुणों से युक्त कथा–रचना" है, जिसमें "हरेक शब्द" और "एक–एक वाक्य" अपना अर्थगत भार वहन करता है। वे यह भी

रेखांकित करते हैं कि माधव नागदा की कई लघुकथाएँ इस कसौटी पर खरी उतरती हैं। छोटे वाक्य, अंचल की बोलचाल से जुड़े सहज शब्द और स्वयं गढ़े हुए मुहावरे उनके शिल्प की विशेषता हैं। इससे स्पष्ट है कि नागदा को पढ़ने के लिए केवल कथ्य देखना पर्याप्त नहीं, उनके कथन–ढंग की भी सूक्ष्म पड़ताल आवश्यक है।

माधव नागदा का अपना लेखक–वक्तव्य भी इस शिल्पगत समझ को पुष्ट करता है। "मेरी लघुकथा यात्रा" में वे लिखते हैं कि कोई भी रचना जीवन से अलग–थलग नहीं हो सकतीय वे बताते हैं कि उपन्यासों और कहानियों को पढ़ते हुए उन्हें यह चमत्कारिक अनुभव हुआ कि लेखक पात्रों के अंतस में उतरकर प्रेम, घृणा, क्रोध, कठोरता, कोमलता, दुःख–दर्द, संघर्ष, सपनों और आकांक्षाओं का ऐसा सजीव चित्र उपस्थित कर देता है मानो सब कुछ सामने घटित हो रहा हो। यही अनुभव उनकी कथा–रचना की आधारभूमि बनता है। आगे वे स्वीकार करते हैं कि कहानियाँ लिखते–लिखते उन्हें लगा कि जो बात वे कहना चाहते हैं, वह हमेशा कहानी में ठीक–ठीक व्यक्त नहीं हो पातीय इसी अभिव्यक्ति–संकट ने उन्हें लघुकथा की ओर मोड़ा। इस आत्मस्वीकृति से स्पष्ट है कि नागदा के यहाँ शिल्प चयन का प्रश्न गहरे रचनात्मक दबाव से पैदा हुआ है।

प्रस्तुत लेख में माधव नागदा के कथा–शिल्प का विवेचन तीन प्रमुख आयामों भाषा, संरचना और दृष्टिबिंदु के आधार पर किया जा रहा है। इसके साथ संवाद–शिल्प, व्यंग्यात्मक विन्यास, शीर्षक, कथन–भंगिमा और शैली–विविधता को भी समाविष्ट किया गया है, क्योंकि नागदा का शिल्प एकरेखीय न होकर बहुस्तरीय है। "बूढ़ी आँखों के सपने", "आग", "उपवास", "अपना–अपना आकाश", "विकलांग", "वह चली क्यों गयी" और "रिसेप्शन" जैसी रचनाएँ यह सिद्ध करती हैं कि वे कथाकार मात्र नहीं, कथा–रूप के सूक्ष्म शिल्पी हैं। समकालीन लघुकथा पर लिखते हुए स्वयं नागदा ने कहा है कि इस "गैरमामूली समय" के सच को "सीमित कलेवर" में बाँध पाना भी "गैरमामूली कौशल" है। उनका अपना लेखन इसी कथन का प्रमाण बनकर उभरता है।

माधव नागदा की रचनात्मक पृष्ठभूमि और शिल्प-बोध :

कथा–शिल्प की चर्चा लेखक की रचनात्मक पृष्ठभूमि से अलग नहीं की जा सकती। "मेरी लघुकथा यात्रा" से यह ज्ञात होता है कि नागदा का जीवन–परिवेश ग्रामीण और काफी हद तक सामंती थाय उन्होंने विज्ञान पढ़ा, पर साहित्य से आकर्षण इसलिए पैदा हुआ कि उसमें उन्हें "जीवन से धड़कती हुई दुनिया" मिली। इस अनुभव का सीधा प्रभाव उनकी कथा–दृष्टि पर पड़ता है। वे बाह्य घटनाओं की रिपोर्टिंग से संतुष्ट नहीं होतेय वे पात्रों की आंतरिक अवस्था, सामाजिक अवरोध और मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता तक पहुँचना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके यहाँ शिल्प का लक्ष्य केवल कथानक को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि पात्र और परिवेश के बीच के जीवंत तनाव को अनुभवगम्य बनाना है।

बलराम अग्रवाल की भूमिका इस बिंदु को दूसरे ढंग से स्पष्ट करती है। वे लिखते हैं कि बहुत–से लोग लघुकथा को घटना–वर्णन, चरित्र–विवरण या तथ्य–कथन मान लेते हैं, जबकि उसे वास्तविक लघुकथा बनाने के लिए "सर्जनात्मक दृष्टि", "विवेक", "कला" और "सम्प्रेषण क्षमता" की आवश्यकता होती है। यह टिप्पणी माधव नागदा की रचनाओं पर पूरी तरह लागू होती है। उनके यहाँ घटना स्वयं में अंतिम नहीं हैय वह किसी गहरे सामाजिक या मानवीय अर्थ की वाहक होती है। वे एक मामूली–सी स्थिति से व्यापक सामाजिक सच उजागर कर देते हैं। इसीलिए उनके शिल्प में अनावश्यक विस्तार नहीं, अर्थ का संकेन्द्रण दिखाई देता है।

नागदा की शिल्पगत विशेषता को समझने में उनका समकालीन लघुकथा–विवेचन भी उपयोगी है।

"समकालीन हिन्दी लघुकथा और समय का सच" में वे आज के समय की जटिलताओं भ्रष्टाचार, घोटाले, अमीर–गरीब की चौड़ी खाई, राजनीति का अपराधीकरण, नैतिक मूल्यों का क्षरण, दरकते सामाजिक संबंध, नारी पर हिंसा, मीडिया की विवादास्पद भूमिका, गाँवों का शहरीकरण को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि समकालीन लघुकथा इन विडंबनाओं, विद्रूपताओं, अंतर्विरोधों और आमजन की कसमसाहट की अभिव्यक्ति करने में समर्थ है। यह कथन उनकी रचनाओं के संरचनात्मक अनुशासन को भी समझाता हैरू समय जितना जटिल है, कथात्मक रूप उतना ही अधिक सघन और संयमित होना चाहिए।

भाषा का शिल्प- लोकजीवन, बोलचाल और अर्थ-सघनता :

माधव नागदा की भाषा उनके कथा–शिल्प का सबसे विशिष्ट पक्ष है। उनकी भाषा साहित्यिकता का कृत्रिम आभास नहीं रचती, बल्कि जीवन–सत्य को उसके स्वाभाविक उच्चारण में पकड़ती है। बलराम अग्रवाल ने ठीक ही कहा है कि छोटे वाक्य और अंचल की बोलचाल से जुड़े सहज शब्द उनके शिल्प की प्रमुख पहचान हैं। इस कथन में "छोटे वाक्य" और "सहज शब्द" दोनों महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि नागदा के यहाँ संक्षिप्तता किसी सूखे गद्य की तरह नहीं आतीय वह जीवन की मौखिक लय, अनुभव की तत्क्षणता और पात्रों की सामाजिक स्थिति को साथ लेकर चलती है। उनके वाक्य छोटे होते हुए भी संकेतों से भरपूर होते हैं।

"बूढ़ी आँखों के सपने" इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। कहानी के आरंभ में ही बूढ़े आदमी के सिर पर हरी घास का गट्ठर, बैलों को "लव और कुश" कहने की आत्मीयता, आँगन में बच्चों की किलकारियाँ और "टी.वी. आ गया" जैसे उद्घोष पूरे ग्रामीण परिवेश को एक जीवित दृश्य में बदल देते हैं। यहाँ भाषा वर्णनात्मक होने पर भी सूक्ष्म हैय वह दृश्य, लय और मनःस्थिति तीनों को साथ रखती है। "अन्न भगवान हैं" जैसे वाक्य कथा के भीतर लोक–मूल्य, श्रम–संस्कार और पीढ़ीगत चेतना का अर्थ खोलते हैं। इस भाषा की शक्ति यह है कि वह अनुभव को सजाती नहीं, जीने योग्य बनाती है।

नागदा की भाषा की दूसरी विशेषता पात्रानुकूलता है। समकालीन लघुकथा–विमर्श में यह बात रेखांकित की गई है कि किसान, पुलिसकर्मी, विद्यार्थी, ग्रामीण, शहरी, व्यापारी या क्लर्क सब एक–सी भाषा में नहीं बोल सकतेय बोलते समय उनके साथ उनका पूरा परिवेश बोलता है। नागदा की रचनाएँ इस सिद्धांत का सशक्त उदाहरण हैं। "उपवास" में रामबाबू और श्यामबाबू का संवाद एक दफ्तरी सामाजिकता, व्यंग्यपूर्ण आत्मीयता और नैतिक पाखंड की संयुक्त भाषा बनाता है। "क्या रिश्वत भी नहीं?" और "रिश्वत खाने से बंधु उपवास नहीं टूटता क्योंकि यह पेट में नहीं जेब में जाती है" ये वाक्य केवल पंच लाइन नहीं हैं वे भाषा के माध्यम से चरित्र और व्यवस्था दोनों को अनावृत करते हैं।

माधव नागदा की भाषा में मुहावरेदारी भी एक शिल्पगत ऊर्जा के रूप में उपस्थित है। अग्रवाल के अनुसार वे अपने मुहावरे स्वयं गढ़ते हैं। इस कथन का अर्थ केवल इतना नहीं कि वे नए वाक्य रचते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे लोक–भाषिक अनुभव को इस तरह कथा में रूपांतरित करते हैं कि वह एक साथ निजी और सामुदायिक दोनों लगता है। "डाल से टूटे फूल की तरह मुरझा गया", "कुर्सी पर बैठा राज करता", "पास में पैसा हो तो सब अच्छा लगता है" ये अभिव्यक्तियाँ साधारण बोलचाल की लगती हैं, पर इनके भीतर गहरी सामाजिक व्यंजना है। उनकी भाषा में अलंकारिकता कम, जीवन–व्यंजना अधिक है।

उनकी भाषा का एक और महत्त्वपूर्ण पक्ष दृश्यात्मकता है। "आग" में वाक्य अत्यंत छोटे हैं "चिंगारी आग

बनने लगी", "हवा पाकर आग फैलने लगी", "आग को खुली छूट थी" किन्तु इन छोटे वाक्यों के भीतर दृश्य की गति, तनाव की वृद्धि और सामूहिक हिंसा का फैलाव सजीव रूप में उपस्थित हो जाता है। यहाँ भाषिक संयम ही अर्थ का तीखापन बन जाता है। नागदा किसी भी दृश्य को शब्दों से भर नहीं देते, वे उसे इतना ही कहते हैं कि पाठक शेष दृश्य स्वयं देख सके। यही कथा–भाषा का उच्च स्तर है।

संरचना का शिल्प- सीमित कलेवर, सघन विन्यास और नियंत्रित विस्तार :

माधव नागदा के कथा–शिल्प का दूसरा प्रमुख आयाम उनकी संरचना है। स्वयं उनके शब्दों में कहें तो "इस गैरमामूली समय के सच को लघुकथा के सीमित कलेवर में बाँध पाना भी गैरमामूली कौशल है।" यह कथन उनके लेखन की सबसे महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक चुनौती को सामने लाता है। वे ऐसे समय के लेखक हैं जिसमें अनुभव बिखरे हुए हैं, सामाजिक विडंबनाएँ बहुस्तरीय हैं और सत्य अनेक स्तरों पर धुँधला दिखाई देता है। ऐसे में रचना की संरचना को न तो विस्तारवादी होना है, न सपाटय उसे सीमित आकार में जटिल अर्थ–संकेत निर्मित करने हैं। नागदा की सफल लघुकथाएँ इसी कारण "छोटी" होकर भी "संकुचित" नहीं लगतीं।

"आग" की संरचना इस संदर्भ में आदर्श उदाहरण है। रचना एक "मामूली चिंगारी" से आरम्भ होती है, फिर लोगों का पारा चढ़ता है, भीड़ हथियारों से लैस होती है, जवाबी मोर्चा तैयार होता है और अंततः आग सबको एक–सा झुलसा देती है। यह संरचना क्रमिक है, पर रैखिक नहींय हर अगला वाक्य सामाजिक हिंसा की नई परत खोलता है। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि कहानी किसी उपदेश से नहीं, परिणाम की विडंबनापूर्ण समानता से समाप्त होती है "जब आग का असर तमाम जिस्मों पर एक जैसा होता है तो फर्क कहाँ है?" इस तरह कथा का ढांचा विचार को थोपता नहीं, बल्कि उसे घटना–क्रम से पैदा करता है। यही सघन संरचनात्मक कला है।

"उपवास" की संरचना पूरी तरह संवाद–आधारित है। कथा की शुरुआत विनम्र सामाजिक व्यवहार से होती है, बीच में प्रश्नोत्तर के स्तर पर तनाव बनता है, फिर "क्या रिश्वत भी नहीं?" एक turning point का काम करता है और अंत में "तिलक" का "डाल से टूटे फूल की तरह मुरझा जाना" पूरा अर्थ–व्यंग्य सघन कर देता है। यहाँ कथा का विन्यास किसी बड़ी घटना पर नहीं, संवाद की गति पर टिका है। संरचना में संक्षेप है, पर अर्थ का फलक व्यापक है धर्म, नैतिकता, भ्रष्टाचार और सामाजिक चरित्र सब एक छोटे से प्रसंग में समा जाते हैं। नागदा की संरचनात्मक दक्षता यही है कि वे सूक्ष्म प्रसंग को सामाजिक रूपक में बदल देते हैं।

"अपना–अपना आकाश" का संरचनात्मक विन्यास विडंबना पर आधारित है। कमरे में बच्चों के भविष्य पर गोष्ठी चल रही है। बच्चे उसी कमरे के एक कोने में खेलते, झगड़ते, हँसते, शोर करते हैं। फिर "विचारवान" लोग उन्हें बाहर भेज देते हैं बाद में बच्चे फिर लौट आते हैं। इस लघुकथा की संरचना एक मूल विरोधाभास को निर्मित करती है जो समाज बच्चों के भविष्य पर सबसे अधिक बोलता है, वही बच्चों की जीवित उपस्थिति को सबसे कम सहन कर पाता है। रचना में आर्क बहुत छोटा है, पर उसकी संरचनात्मक विडंबना बहुत गहरी है। यही नागदा की शिल्प–संवेदना का प्रमाण है।

"बूढ़ी आँखों के सपने" लघुकथा नहीं, अपेक्षाकृत विस्तृत कहानी है, इसलिए उसकी संरचना अलग तरह से काम करती है। यहाँ घटना–केन्द्र नहीं, पात्र–केन्द्र प्रमुख है। कहानी पहले एक दृश्य देती है टी.वी. का आना, बच्चों का उत्साह फिर बूढ़े पात्र की प्रतिक्रियाय फिर उसके अतीत, मूल्य–बोध, अन्न–श्रद्धा, शिक्षा–सम्बंधी दृष्टि और बेटे के साथ मूल्य–संघर्ष का क्रमशः खुलना। यह स्तरित संरचना है। नागदा यहाँ विस्तार लेते हैं, लेकिन

नियंत्रित रूप में। कहानी कहीं भी बिखरती नहीं, क्योंकि उसका केंद्र बूढ़े पात्र की चेतना है। इस प्रकार वे कहानी और लघुकथा दोनों रूपों में संरचना को विषयानुकूल ढालते हैं।

दृष्टिबिंदु का शिल्प- तटस्थता, नैतिकता और संवेदनात्मक निकटता :

किसी भी कथाकार की परिपक्वता उसके दृष्टिबिंदु से पहचानी जाती है। माधव नागदा की रचनाओं में दृष्टिबिंदु विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वे न पूरी तरह भावुक हस्तक्षेपकारी कथाकार हैं, न निर्जीव रिपोर्टर। बलराम अग्रवाल ने उनके लेखन के बारे में कहा है कि समाज के चित्र तब ही सार्थक रूप में उभरते हैं जब वे "तटस्थ भाव" और "स्वस्थ मानसिकता" के तहत लिखे जाएँ और नागदा इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। यहाँ "तटस्थता" का अर्थ मूल्य–शून्यता नहीं, बल्कि कथाकार का इतना संयमित होना है कि रचना स्वयं अपना नैतिक प्रभाव पैदा करे।

"आग" में दृष्टिबिंदु लगभग सामूहिक और दूरस्थ है। कथाकार किसी एक व्यक्ति के भीतर नहीं जाता। वह भीड़, चिंगारी, हिंसा और दुष्परिणाम को एक व्यापक सामाजिक नजरिए से देखता है। यही दूरी रचना की शक्ति बनती है। यदि कहानी किसी एक पात्र के रोने–बिलखने पर केन्द्रित होती, तो उसका अर्थ सीमित हो सकता था परंतु यहाँ दृष्टिबिंदु सामाजिक है, इसलिए रचना रूपक बन जाती है। वह किसी एक दंगे की कथा न रहकर साम्प्रदायिक मानसिकता की संरचना पर चोट करती है। नागदा यहाँ कैमरा–दृष्टि और नैतिक अंर्तध्वनि का संयोजन करते हैं।

इसके विपरीत "बूढ़ी आँखों के सपने" में दृष्टिबिंदु क्रमशः बूढ़े पात्र की चेतना के निकट जाता है। कथा भले तीसरे पुरुष में है, पर उसकी संवेदनात्मक दिशा रामाबा के भीतर के द्वंद्व, उसकी अन्न–श्रद्धा, उसके श्रम–मूल्य, उसकी पीड़ा और उसकी आशंकाओं को केंद्र में रखती है। पाठक बच्चों के उल्लास को देखता है, पर कहानी का भाव–केन्द्र बूढ़े आदमी का अनुभव है। यही कारण है कि टी.वी. केवल मशीन नहीं, मूल्य–संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। नागदा यहाँ दृष्टिबिंदु को सूक्ष्मता से शिफ्ट करते हैं बाहरी दृश्य से आंतरिक अर्थ की ओर।

"उपवास" और "रिसेप्शन" जैसी लघुकथाओं में दृष्टिबिंदु व्यंग्यात्मक अवलोकन का है। कथाकार सतह पर हस्तक्षेप नहीं करता, पर वह ऐसी व्यवस्था रचता है कि पात्र अपने ही शब्दों और क्रियाओं से खुल जाते हैं। "रिश्वत खाने से बंधु उपवास नहीं टूटता....." या "देख लिया अपने बरातियों का स्टेंडर्ड?" जैसे वाक्यों में कथाकार का प्रत्यक्ष उपदेश नहीं है, लेकिन उसकी नैतिक दृष्टि तीखी है। यह नियंत्रित विडंबना नागदा के दृष्टिबिंदु की परिपक्वता का प्रतीक है। वे पाठक से कहते नहीं, दिखाते हैं और दिखाकर भीतर तक चुभते हैं।

संवाद, व्यंग्य और कथन-भंगिमा :

माधव नागदा के कथा–शिल्प में संवाद अत्यंत केन्द्रीय उपकरण है। वे चरित्र–चित्रण, परिस्थिति–निर्माण और विडंबना तीनों को संवाद के माध्यम से साध लेते हैं। "उपवास" इसका सर्वाधिक सटीक उदाहरण है। वहाँ संवाद केवल बोलचाल नहीं, चरित्र की परतें खोलने वाला साधन है। श्यामबाबू की विनम्रता, दफ्तरी सामाजिकता, धार्मिक मुद्रा और फिर उसी सहजता से रिश्वत को जेब में जाने वाली वस्तु बताना यह पूरा नैतिक हास्यास्पद संसार संवादों से बनता है। नागदा की विशेषता यह है कि वे संवाद को "साहित्यिक" नहीं बनाते। वह रोजमर्रा की भाषा में ही अपनी मारकता हासिल करता है।

समकालीन लघुकथा–संबंधी सामग्री में माधव नागदा की "प्रत्युत्तर" को पत्र–शैली और "मुझे जिंदगी देने वाले" को डायरी–शैली का उदाहरण बताया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे शिल्प की दृष्टि से एक ही पद्धति पर निर्भर नहीं रहते। कथ्य के अनुसार वे शैली का चयन करते हैं। यह शिल्प–विविधता इस बात का प्रमाण है कि वे कथा–रूप के प्रति सजग लेखक हैं, केवल विषय–प्रधान लेखक नहीं। उनका लेखन इस अर्थ में लचीला है कि उसमें संवाद–शैली, दृश्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, पत्र–शैली और डायरी–शैली के लिए स्थान है।

व्यंग्य नागदा के कथा–शिल्प का एक और अनिवार्य तत्व है। लेकिन यह व्यंग्य प्रहारात्मक होकर भी शोर नहीं करता। "अपना–अपना आकाश" में विचारवान लोगों द्वारा बच्चों को बाहर कर देना, "उपवास" में धार्मिकता और रिश्वत का साथ–साथ चलना, "विकलांग" में भीख माँगने वाले पर उपदेश देने वाला सेठ स्वयं पाँवों से अपंग निकलना, "वह चली क्यों गयी" में धन के ढेर के बावजूद आत्मीयता का अभाव ये सब व्यंग्यात्मक स्थितियाँ हैं। नागदा इन स्थितियों को लंबी टिप्पणी से नहीं समझाते वे उन्हें इस तरह विन्यस्त करते हैं कि उनकी विडंबना स्वयं पाठक पर खुलती जाए। यही शिल्पगत परिपक्वता है।

शीर्षक, प्रतीक और अर्थ-संकेन्द्रण :

माधव नागदा के कथा–शिल्प में शीर्षक भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। "आग" शीर्षक अपनी सादगी में ही बहुस्तरीय है वह वास्तविक आग भी है, सांप्रदायिक उन्माद भी और सामाजिक विवेकहीनता का प्रतीक भी। "अपना–अपना आकाश" शीर्षक में बच्चों और बड़ों की अलग–अलग दुनिया, अलग दृष्टि और अलग प्राथमिकताओं का संकेत पहले से निहित है। "उपवास" शीर्षक धार्मिक संयम का आभास देता है, पर कथा में वही शीर्षक नैतिक पाखंड को उजागर कर देता है। "वह चली क्यों गयी" शीर्षक एक प्रश्न की तरह पाठक को कथा में प्रवेश देता है और अंत तक आते–आते यह प्रश्न आधुनिक दाम्पत्य, उपभोक्तावाद और भावनात्मक रिक्तता का प्रश्न बन जाता है। नागदा शीर्षक को केवल नाम नहीं रहने देतेय वह रचना के व्यंजना–तंत्र का हिस्सा बन जाता है।

निष्कर्ष :

माधव नागदा की कहानियों का कथा–शिल्प उनके साहित्यिक महत्त्व का मूल आधार है। उनकी भाषा लोक–जीवन से निकली हुई, पात्रानुकूल, छोटे वाक्यों में अर्थ–सघन और मुहावरेदार है। उनकी संरचना सीमित कलेवर में जटिल अनुभवों को संकेन्द्रित करती है। वे कभी संवाद–प्रधान विन्यास, कभी दृश्यात्मक क्रम, कभी विडंबनात्मक मोड़ और कभी पात्र–केंद्रित विस्तार के माध्यम से कथ्य को प्रभावी बनाते हैं। उनका दृष्टिबिंदु संयमित होते हुए भी नैतिक है। वे पाठक पर विचार नहीं थोपते, बल्कि रचना की भीतरी संरचना से अर्थ पैदा करते हैं। यही कारण है कि उनका कथाकार समाज को देखकर केवल लिखता नहीं, उसे कलात्मक रूप देता है। बलराम अग्रवाल की टिप्पणी कि नागदा की लघुकथाओं में सर्जनात्मक दृष्टि, विवेक, कला और सम्प्रेषण क्षमता उपस्थित है उनके समूचे कथा–कर्म पर लागू होती है।

यदि इस पूरे विवेचन को एक वाक्य में समेटना हो, तो कहा जा सकता है कि माधव नागदा का कथा–शिल्प जीवन–सापेक्ष यथार्थवाद और कलात्मक संक्षेप का सफल समन्वय है। "बूढ़ी आँखों के सपने" में भाषा और पात्र–दृष्टि, "आग" में संरचना और रूपक, "उपवास" में संवाद और व्यंग्य, "अपना–अपना आकाश"

में विडंबनात्मक विन्यास और शैली–विविधता के उदाहरणों में पत्र–शैली तथा डायरी–शैली ये सब मिलकर सिद्ध करते हैं कि नागदा का लेखन केवल सामाजिक सरोकारों का नहीं, परिपक्व कथा–शिल्प का भी लेखन है। इसलिए उनके साहित्य का मूल्यांकन विषय–वस्तु तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे भाषा, संरचना, दृष्टिबिंदु और कथन–भंगिमा की कलात्मक उपलब्धियों के स्तर पर भी पढ़ा जाना चाहिए।

संदर्भ-सूची :

1. अग्रवाल, ब. (2021). माधव नागदा, माटी–सा महकता लघुकथा–संसार, माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (भूमिका). विद्या बुक्स.
2. नागदा, म. (1993). शाप मुक्ति. सम्बोधन प्रकाशन.
3. नागदा, म. (2004). आग. सूर्य प्रकाशन मंदिर.
4. नागदा, म. (2021). अपना–अपना आकाश, माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (पृ. 28). विद्या बुक्स.
5. नागदा, म. (2021). आग, माटी की महक, माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (पृ. 110). विद्या बुक्स.
6. नागदा, म. (2021). विकलांग, माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (पृ. 111). विद्या बुक्स.
7. नागदा, म. (2021). वह चली क्यों गयी?, माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ (पृ. 112). विद्या बुक्स.
8. नागदा, म. (2016). मैं शब्दों का कुम्भकार. (डॉ. र. शर्मा, भूमिका).
9. नागदा, म. (2021). माटी की महक– माधव नागदा की गौरतलब लघुकथाएँ. विद्या बुक्स.
10. नागदा, म. (1993). बूढ़ी आँखों के सपने. शाप मुक्ति (पृ. 9). सम्बोधन प्रकाशन.
11. नागदा, म. (1993). जहर कांटा. शाप मुक्ति (पृ. 60). सम्बोधन प्रकाशन.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTILANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 45–48

रामचरित मानस में मानव मूल्य

डॉ. रीनू चतुर्वेदी
207 भाटागांव सिटी होंडा शोरूम के पास रायपुर छत्तीसगढ़।

भूमिका –

मानव जीवन का अपना एक मुल्य होता हैं यह निर्धारित करता हैं कि मनुष्य अपना जीवन कैसा व्यतीत करता हैं क्या उसका मूल्य हैं। एक मनुष्य इस लोक में आने के लिए न जाने कितनी कठिनाईयों की पार करता हैं तब जाकर उसे यह मानव शरीर मिलता है भौतिक जगत में आकर वह उसे और भी मूल्यवान बना सकता हैं। मानव का मूल्य इस भौतिक जगत में कितना हैं इसका अंदाजा ईश्वर (ब्रम्ह) के जन्म से ही लगा सकते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी में आने के लिए उन्हें भी 'मानुज' रूप धारण करना पड़ा। कष्ट भी सहन करने पड़े और तो और अपने को स्थापित करने के लिए उन्हें संघर्ष भी करना पड़ा। तब जाकर वे भी 'राम' से प्रभु श्री राम, राजा राम सम्पूर्ण विश्व के राम बन पाए है।

रामचरित मानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानव मूल्य का महत्व बताया हैं। और किस तरह के कार्य करके हम इसें और भी मूल्यवान बना सकते हैं। यह भी बताया हैं।

बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा।।
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाई न जेहिं परलोक सँवारा।।
(रामचरित मानस– उतरकाण्ड)

रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में उपर्युक्त चौपाई है, जो कि मनुष्य (मानव मूल्य) को बताती हैं कि यह मनुष्य शरीर कितने भाग्य से हमें प्राप्त होता हैं। इस धरा में मनुष्य रूप में आने के लिए कितने तपस्या करनी पड़ती हैं तब जाकर हम मनुष्य का शरीर धारण करतें हैं क्योंकि इस लोक में चराचर न जाने कितने जीव हैं जो कि विभिन्न प्रकार से शरीर धारण किए हुए हैं। पर उनमें उतनी भावुकता और समझ नहीं होती हैं, जितनी कि एक मानव के अंदर होती हैं इसलिए ही कहा गया हैं बड़े ''भाग मानुष तनु पावा'' यह ही मानव मूल्य को दर्शाता है।

रामचरित मानस में मानव मूल्य :–

रामचरित मानस में मानव मूल्य की प्रासंगिकता को जानने से पहले मानव के बारे में जानते हैं। मानव स्वयं में क्या हैं। मानस में तो भक्ति का विशेष स्थान हैं। कोई आत्मा जब शरीर धारण करती हैं, तभी वह बार–बार भक्ति कर पाएगी। इससे उस शरीरधारी आत्मा को एक आनंद की अनुभूति होती हैं। मार्ग भी भक्ति का अत्यन्त ही सुलभ होता हैं यह मानव शरीर पाने के लिए सुर अर्थात (देवता) भी तरसते हैं क्योंकि बिना शरीर के भक्ति

प्राप्त नही हो सकती है।

दोहा- नं 19 :

बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार
निज इच्छा निर्मित जनु माया गुन गो पार।।

(रामचरित मानस बालकाण्ड)

- क्या एक जीव का जन्म यूं ही हो जाता है?
- वास्तव में मनुष्य की परिभाषा क्या है?
- इस पृथ्वी में ऐसा क्या हैं जहाँ आने के लिए देवता तरसते हैं?
- ब्रम्ह का भी मानुज रूप में आना क्या दर्षाता है?

वास्तव में देखा जाये तो मानव एक ऐसा प्राणी है जो सम्पूर्ण जीवों से ज्यादा ज्ञानी, विवेकी, दयावान होता है, उसमें शील, प्रेम, करुणा होता हैं वह सम्पूर्ण चराचर जीवों में एकरूपता देखता हैं और सबका भला हो यही सोचता है। इसलिए भौतिक जगत में मनुष्य का अधीपत्य हैं, जब भी यह भूमि आसुरी प्रवृत्ति से बेहाल हुई है तब–तब उससे मुक्त कराने के लिए ईश्वर ने मानुज रूप धारण कर धरती पर आए हैं। तो अगर मानव को परिभाषित करना हो तो निम्न रूप में कर सकते हैं–

"सच्चा मनुष्य वही हैं जिसमें प्रेम, दया का भाव हो जो सबके प्रति सहानुभूति रखता हो, जो सदैव सम्पूर्ण कुटुम्ब को साथ लेकर चले।"

मानव के अंदर यही गुण उन्हे इस धरा में मूल्यवान बना सकता है जिसके अंदर ये गुण नही हो वह **"शरीर मात्र ही कहलाने के योग्य है।"**

जब ईश्वर भी इस जगत में आता हैं तो वह भी इन सबका निर्वाहन करता हैं। तब जाकर मानव रूप में पूज्नीय हैं। इससे निश्चित होता है कि ईश्वर आदर्श स्थापित करने मर्यादा का पाठ पढ़ाने और संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए (का पाठ) सीखने की लिए ब्रम्ह जो हर कार्य को सरलता से कर लेते हैं उसके लिए भी मानुष्य रूप धारण करके आते है और आते ही नही आते ही रहेंगे कभी अंषवतार में तो कभी पूर्णावतार धारण करके उनका इस लोक में आना होता रहेगा। फिर मनुष्य ही एक ऐसा जिसे ईश्वर अपने सबसे करीब रखते है।

"कवन जो काज कठिन जग माही। जो नहिं होई तात तुम्ह पाहीं।।
राम काज लगि तव अवतारा। सुनतहिं भयउ पर्वताकारा।। "

(रामचरित मानसन- किष्किन्धा काण्ड)

- मानव के लिए कोई काम कठिन नही हैं।
- पर बड़ी से बड़ी से चुनौती को भी पार कर सकता हैं।
- मनुष्य ही ऐसा है जो विषधर साँप से लेकर खुंखार शेर तक को अपने वशीभूत कर सकता हैं।

यद्यपि उपर्युक्त दोहा हनुमान जी को प्ररित करने के लिए हैं पर अगर इसका एक और अर्थ निकाले तो मानव मूल्य के लिए भी सहायक होगा।

''हे मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य हैं जो तुम नही कर सकते हों सब तो तुम कर सकते हों क्योंकि इस संसार में सबसे ज्यादा तुम्हारा ही आधिपत्य हैं।''

बस जो कार्य हों वह सबके हित में होना चाहिए न कि स्वार्थपूर्ण वही मानव श्रेष्ठ मानव है जो कि सबके हित के लिए सदैव आगे आए उसी को अदृष्य शावन्ती भी प्राप्त होगी, अच्छा गुरु मिलेगा। शास्त्र में वर्णित है कि हमारा शरीर (जन्म) कई लोगों के ऋण को मुक्त करना भी हमारा दायित्व हो जाता हैं। आधुनिक समय में भी ऋण की बाते आनी ही यथार्थ होती हैं। गुएयतः कुछ ऋण जो वर्णित हैं उसमें आता है।

मातृ ऋण, पितृ ऋण, देय ऋण, गुण ऋण माता के गर्भ में शरीर का निर्माण होता है उसके रूधिर से पोषण, पितृ सांसरिक जीवन में हमें स्थापित करने के लिए संघर्ष करता हैं, गुण ऋण इनसें भी बढ़कर होता है क्योंकि यह हमें भौतिक जगत से हमारा परिचय कराता है और देव ऋण यह ऋण हमें पोषित करता है ऊर्जा देता है अब एक मानव का मूल्य इससे भी समझा जा सकता है कि जिसके पीछे इतने लोगों की तपस्या हैं वह कैसे मूल्यवान नहीं हो सकता हैं। उसके कर्तव्य बड़े ही होगे उसके जीवन देने से लेकर उसके जीवन बनाने तक कईयों का योगदान रहता हैं। इसलिए मानव कुछ करे या न करे ऋण मुक्त तो अवश्य ही हो जाए जो जीवन मिला हैं उसको सही तरीके से जी लें। यही सब मानव को इस संसार में मूल्यबान बनाएगी।

उपसंहार –

''भयभीत तो किस बात से,
सहम बन्यूं गया अंधकार से,
क्या भूल गया मानव मूल्य तनु प्राणी
इस जीवन में तेरा अधिकार है।
बदल सकता आसमां–धरा पर
मानव तु मानव बस नही
सत्य, प्रेम, करूणा की प्रति मूर्ति भी है।

मानव की जीवन सिर्फ उनका नहीं होना चाहिए बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए भी उतना ही होना चाहिए जितना की स्वंय के लिए ये मनुष्य का शरीर पाना कोई सहज नही हैं। रामचरित मानस में कई ऐसे ऋषि–मुनि हैं जो कि बार–बार मनुष्य रूप में आना चाहते है इस जीवन का कष्ट सहन करना चाहते है। मोक्ष की लालसा वे नहीं रखते क्योंकि उन्हें पता है कि मोक्ष पा लेना तो फिर भी सरल हैं किन्तु माता का स्नेह, पिता का करूणामय प्रेम, गुरू का ज्ञान मोक्ष से प्राप्त नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ''भक्ति'' भी मानव रूप धारण करने से नहीं प्राप्त होगीं। यह जीवन जटिल नहीं अपितु सहज हैं बस जीवन जीने की कला होनी चाहिए। सांसारिक होकर भी विरक्त की भावना अद्वितीय हैं।

अतः रामचरित मानस से स्पष्टतः ये बात समझ आती हैं कि मानव क्या हैं, और उसका इस संसार मे मूल्यवान बने रहना क्या हैं वह अपना मूल्य कैसे बनाए रख सकता हैं। प्रत्येक वाणी में किसी न किसी तरह का गुण होता ही हैं पर एक मनुष्य ही हैं जिसे सर्वगुणी और जीवों में सर्वोपरि माना जाता है। इस आधार से भी मानव मूल्य समझा जा सकता हैं। ''सर्वगुणी और सर्वोपरि'' होना ही वास्तविक मानव मूल्य हैं। जिसका वर्णन रामचरित मानस में स्पष्ट तौर पर हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. रामचरित मानस (उत्तरकाण्ड चौपाई)
2. रामचरित मानस (बालकाण्ड दोहा नं0 191)
3. रामचरित मानस (किष्किन्धा काण्ड चौपाई)

मोबाइल – 9755590287

ईमेल – preenu@1710@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 49–53

हिंदी कहानी समीक्षा में सुरेंद्र चौधरी का योगदान : एक आलोचनात्मक अध्ययन

भोली रानी
शोधार्थी, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

शोध सार :

प्रस्तुत शोध आलेख "हिंदी कहानी समीक्षा में सुरेंद्र चौधरी का योगदान : एक आलोचनात्मक अध्ययन" हिंदी कहानी आलोचना के क्षेत्र में सुरेंद्र चौधरी की विशिष्ट भूमिका का मूल्यांकन करने का प्रयास हैं। हिंदी साहित्य में कहानी एक ऐसी विधा के रूप में विकसित हुई है, जिसने समय–समय पर बदलते हुए सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संदर्भों को अभिव्यक्ति प्रदान की हैं। स्वाभाविक रूप से कहानी के विकास के साथ–साथ उसकी समीक्षा–दृष्टि में भी परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तनशील परिदृश्य में सुरेंद्र चौधरी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता हैं। उन्होंने हिंदी कहानी की समीक्षा को केवल कथावस्तु, चरित्र–चित्रण अथवा मनोरंजन की सीमाओं में न बांधकर उसकी रचना–प्रक्रिया, कथा–शिल्प, संरचना, पाठ–प्रक्रिया तथा सामाजिक संदर्भों के आधार पर समझने का प्रयास किया।

सुरेंद्र चौधरी की आलोचना – दृष्टि का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे कहानी को उसके व्यापक जीवन–संदर्भों से जोड़कर देखते हैं, उनके लिए कहानी मात्र घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि मानवीय अनुभवों और सामाजिक यथार्थ की कलात्मक अभिव्यक्ति हैं। इसी कारण उसकी समीक्षा में रचना के बाह्य पक्ष की अपेक्षा उसकी अंतर्निहित अर्थों, संरचनात्मक विशेषताओं और संवेदनात्मक आधार को अधिक महत्व प्राप्त होता हैं। उन्होंने हिंदी कहानी के विकास, उसकी प्रकृति तथा उसके कलात्मक स्वरूप को समझने के लिए नए मान्यदंडों का निर्माण किया, जिससे कहानी–समीक्षा का क्षेत्र अधिक व्यापक और समृद्ध हुआ।

हिंदी कहानी समीक्षा के अध्ययन में उनकी भूमिका केवल एक सामान्य समीक्षक की नहीं, बल्कि एक ऐसे विचारक की है, जिसने कहानी के मूल्यांकन की पद्धति को नया आयाम प्रदान किया। उन्होंने रचना–प्रक्रिया, कथा, शिल्प, व्यंग्य, फेंटेसी, पाठ–प्रक्रिया तथा नई कहानी जैसे विविध पक्षों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया और कहानी समीक्षा की बहुआयामी प्रकृति को रेखांकित किया। उनकी आलोचना में सिद्धांत और व्यवहार का संतुलन दिखाई देता है, जिसके कारण उनकी समीक्षा केवल वैचारिक विमर्श तक सीमित नहीं रहती, बल्कि रचनाओं के गहन विश्लेषण का आधार भी बनती है।

हिंदी कहानी समीक्षा की परंपरा के संदर्भ में सुरेंद्र चौधरी के योगदान का विवेचना के साथ ही नामवर

सिंह, रामविलास शर्मा तथा अन्य आलोचकों की दृष्टि के आलोक में उनके योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उनकी समीक्षा–दृष्टि की उपलब्धियां और सीमाओं का विवेचन करते हुए यह स्पष्ट करेंगे की हिंदी कहानी की आलोचना को अधिक वैज्ञानिक, व्यापक और बहुआयामी बनाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही हैं।

बीज-शब्द : रचना–प्रक्रिया, कहानी–समीक्षा, कथा–शिल्प, आलोचना–दृष्टि, नई कहानी।

प्रस्तावना :

हिंदी साहित्य में कहानी एक ऐसी विधा के रूप में विकसित हुई है, जिसने बदलते हुए सामाजिक, संस्कृति तथा वैचारिक परिवेश को सबसे अधिक संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त किया हैं। आधुनिक युग में कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम न रहकर मनुष्य के अनुभवों, संघर्षों, अंतर्विरोधो और सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन बन गई हैं। स्वाभाविक रूप से कहानी के विकास के साथ–साथ उसकी समीक्षा–दृष्टि का भी विकास हुआ। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अनेक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने कहानी को समझने और उसकी समीक्षा के लिए नई प्रतिमानों की स्थापना की। इनमें सुरेंद्र चौधरी का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता हैं। उन्होंने हिंदी कहानी की समीक्षा को केवल विषयवस्तु अथवा कथानक तक सीमित न रखकर उसकी रचना–प्रक्रिया, कथा–शिल्प, पाठ–प्रक्रिया तथा सामाजिक संदर्भों के आधार पर समझने का प्रयास किया। इस दृष्टि से हिंदी कहानी समीक्षा को नई दिशा प्रदान करने में उसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना हैं।

हिंदी कहानी की आलोचना पर विचार करते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रारंभिक आलोचना मुख्यतः प्रभाववादी तथा नैतिक मान्यदण्डों पर आधारित थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को लोकमंगल की दृष्टि से देखने का आग्रह किया, वहीं आगे चलकर रामविलास शर्मा ने साहित्य के सामाजिक और ऐतिहासिक पक्षों को विशेष महत्व दिया। नामवर सिंह ने साहित्यक कृतियों के मूल्यांकन में ऐतिहासिक चेतना और आलोचनात्मक विवेक की आवश्यकता पर बल दिया। इन आलोचकों की परंपरा में सुरेंद्र चौधरी का स्थान विशिष्ट हैं, क्योंकि उन्होंने कहानी के अध्ययन में रचना की संरचना, अनुभव और पाठकीय प्रक्रिया को समान रूप से महत्व प्रदान किया हैं।

आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन कि "प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता की चित्तवृति का संचित प्रतिबिंब होता हैं।"[1] साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करता हैं। इसी प्रकार रामविलास शर्मा, साहित्य को सामाजिक यथार्थ से पृथक मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनके अनुसार "साहित्य समाज से पृथक कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है।"[2] वस्तुतः साहित्य और जीवन के इसी गहरे संबंध को सुरेंद्र चौधरी की आलोचना–दृष्टि में भी सहज रूप से देखा जा सकता हैं। वे कहानी को मात्र मनोरंजन अथवा घटनाओं के क्रम के रूप में न देखकर मानवीय अनुभवों, सामाजिक यथार्थ और कलात्मक संरचना के संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं।

सुरेंद्र चौधरी का मानना है कि कहानी को केवल घटनाओं के क्रम के रूप में नहीं देखा जा सकता। उसके अनुसार कहानी का वास्तविक स्वरूप उसके समग्र प्रभाव और कलात्मक गठन में निहित होता हैं। वे लिखते हैं–

"यदि कहानी हमारे मन पर संश्लिष्ट प्रभाव डाल रही है तो निर्माण की दृष्टि से भी वह पूर्ण हैं। कहानी

की सफलता केवल उसके विषय या कथानक में नहीं, बल्कि उसके समग्र गठन और उसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव में निहित होती हैं।"[3]

यह कथन स्पष्ट करता है कि सुरेंद्र चौधरी कहानी के मूल्यांकन में उसकी प्रभाव, संरचना और कलात्मकता को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनकी दृष्टि में कहानी की सफलता केवल उसके विषय में नहीं, बल्कि उसके कलात्मक संगठन में भी निहित होती हैं।

नामवर सिंह का मत हैं कि– "**कहानी की सफलता उसकी प्रभावन्विति में निहित है**"[4] यह स्थापना सुरेंद्र चौधरी की उस मान्यता के निकट दिखाई देती है जिसमें वे कहानी के समग्र प्रभाव और उसके कलात्मक संगठन को महत्व प्रदान करते हैं। इसी प्रकार मैनेजर पांडे का यह विचार कि– "**आलोचना का कार्य केवल निर्णय देना नहीं बल्कि रचना के अर्थ में उद्‌घाटित करना भी हैं।**"[5] सुरेंद्र चौधरी की आलोचना–पद्धति को समझने में सहायक सिद्ध होता हैं। उनकी समीक्षा में निर्णय की अपेक्षा विश्लेषण और अर्थ–उद्‌घाटन की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती हैं।

हिंदी कहानी के विकासक्रम पर विचार करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने यह स्वीकार किया कि आधुनिक कहानी की जड़ें प्राचीन कथा–परंपरा से जुड़ी हुई हैं। इस संदर्भ में लिखते हैं :–

"छोटी कहानियाँ अपनी चेतना और विचार तत्व की दृष्टि से चाहे कथाओं और आख्यायिकाओं से जितनी भिन्न दिखती हो, किंतु अपने निर्माण की दृष्टि से उनमें आज भी उनके बहुत-से तत्व वर्तमान हैं। आधुनिक कहानी का विकास अपनी पूर्ववर्ती कथा-परंपरा से पूर्णतः विछिन्न होकर नहीं हुआ हैं।"[6]

इस कथन से स्पष्ट होता है कि वे आधुनिक कहानी को परंपरा से पूर्णतः विछिन्न मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनकी दृष्टि में कहानी का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता दोनों का समन्वय उपस्थित रहता हैं।

सुरेंद्र चौधरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान कहानी की रचना–प्रक्रिया को समझने में दिखाई देता हैं। उन्होंने इस तथ्य पर बल दिया कि कहानी केवल कल्पना का परिणाम नहीं होती, बल्कि लेखक के अनुभव, संवेदना और सामाजिक चेतना का कलात्मक रूप होती हैं। इसी कारण उन्होंने प्रेमचंद, जैनेंद्र, यशपाल और अज्ञेय जैसे कहानीकारों की रचनाओं का विश्लेषण करते हुए उसकी विशिष्ट रचना–प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया है उनकी आलोचना में सिद्धांत और व्यवहार का अद्‌भुत संतुलन दिखाई देता हैं।

नई कहानी आंदोलन की व्याख्या में भी सुरेंद्र चौधरी की भूमिका उल्लेखनीय हैं। उन्होंने नई कहानी को केवल साहित्यिक आंदोलन न मानकर सामाजिक और मानसिक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। इस संदर्भ में उनका कथन उल्लेखनीय है :–

"**1945 ई के उपरांत कहानी एक साथ ही अनेक दिशाओं में विकसित होने की संभावना बना लेती हैं। बदलते हुए सामाजिक और मानसिक परिवेश के कारण कहानी में अनुभवों और अभिव्यक्ति के नए आयाम सामने आते हैं, जिसके कारण उनकी संरचना और संवेदना दोनों में परिवर्तन दिखाई देता हैं।"[7]**

इस कथन के माध्यम से वे स्पष्ट करना चाहते हैं कि आधुनिक कहानी किसी एक प्रवृत्ति या विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें विविध अनुभवों और जीवन संदर्भों को अभिव्यक्त करने की क्षमता निहित हैं।

सुरेंद्र चौधरी ने कहानी के शिल्प और संरचना के साथ–साथ उसकी पाठ–प्रक्रिया पर भी विशेष बल

दिया। उनके अनुसार श्रेष्ठ कहानी को समझने के लिए गंभीर और सजग पाठकीय दृष्टि की आवश्यकता होती हैं। वे लिखते है कि :–

"कहानी जितने ध्यान से पढ़े जाने की माँग करती हैं, उतने ध्यान से दुर्भाग्यवश उसे नहीं पढ़ा जाता। श्रेष्ठ कहानी अपने भीतर अनेक अर्थ-स्तरों को समेटे रहती है और उसकी सही समझ के लिए गंभीर तथा सजग पाठकीय दृष्टि की आवश्यकता होती हैं।"[8]

यह कथन उनकी आलोचना–दृष्टि के एक महत्वपूर्ण पक्ष को उद्घाटित करता हैं। वे कहानी के अर्थ को केवल लेखन तक सीमित नहीं रखते, बल्कि पाठक की सक्रिय भूमिका को भी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार उनकी समीक्षा कहानी के बहुस्तरीय अर्थों को समझने की दिशा में एक नई संभावना प्रस्तुत करती हैं।

व्यंग्य, फेंटेसी, रूपक, रोमांस तथा आत्मशोध जैसी विधाओं के संबंध में भी सुरेंद्र चौधरी की दृष्टि अत्यंत व्यापक और उदार हैं। वे व्यंग्य को केवल हास्य का माध्यम नहीं मानते, बल्कि उसे एक विशेष मानसिक और वैचारिक दृष्टि के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार 'फेंटेसी' को वे यथार्थ से पलायन नहीं, बल्कि यथार्थ को देखने की एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे उनकी आलोचना–दृष्टि की व्यापकता और आधुनिकता का परिचय मिलता हैं। इसी प्रकार में 'रोमांस' को केवल प्रेम–कथा के अर्थ में नहीं लेते, बल्कि उसे मनुष्य की आकांक्षाओं, आदर्शों और भावनात्मक अनुभवों से जोड़कर देखते हैं। उनके अनुसार रोमांस का महत्व इस बात में है कि वह जीवन को केवल यथार्थ की कठोरता तक सीमित नहीं रहने देता। इसी प्रकार सुरेंद्र चौधरी 'आत्मशोध' के बारे में बताते हैं कि आधुनिक कहानी का एक बड़ा हिस्सा मनुष्य की आत्मा–खोज से जुड़ा हुआ हैं। आधुनिक व्यक्ति बाहरी संघर्षों के साथ–साथ अपने भीतर भी संघर्ष कर रहा हैं। इसलिए अनेक कहानियाँ व्यक्ति के भीतर चल रही खोज, असंतोष और आत्म–साक्षात्कार को केंद्र में रखती हैं।

हिंदी कहानी समीक्षा के क्षेत्र में सुरेंद्र चौधरी का योगदान केवल कुछ सिद्धांतों की स्थापना तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने कहानी को समझने और उसका मूल्यांकन करने के लिए ऐसे मानदंड विकसित किए, जिनके माध्यम से कहानी की आंतरिक संरचना, उसके सामाजिक संदर्भ तथा उसके कलात्मक पक्ष को अधिक गहराई से समझा समझा जा सकता हैं। यही कारण है कि हिंदी कहानी समीक्षा के विकास में उनका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता हैं।

निष्कर्ष :

अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हिंदी कहानी समीक्षा के क्षेत्र में सुरेंद्र चौधरी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट हैं। उन्होंने हिंदी कहानी की आलोचना को केवल कथानक, चरित्र अथवा विषयवस्तु की सीमाओं तक सीमित न रखकर उसे एक व्यापक वैचारिक और कलात्मक धरातल प्रदान किया। उनकी आलोचना–दृष्टि में कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के अनुभवों, सामाजिक यथार्थ, ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा बदलती हुई संवेदनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति हैं। यही कारण है कि उसकी समीक्षा कहानी के बाह्य स्वरूप से अधिक उसके आंतरिक गठन, रचना–प्रक्रिया और बहुआयामी अर्थ–संरचना पर विशेष बल देती हैं।सुरेंद्र चौधरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने हिंदी कहानी को किसी एक निश्चित प्रतिमान के आधार पर नहीं परखा। वे प्रत्येक कहानी को उसके अपने संदर्भ, अनुभव और कलात्मक गठन के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण उनकी आलोचना में न तो पूर्वाग्रह दिखाई

देता हैं और न ही किसी प्रकार के अंधानुकरण। उन्होंने प्रेमचंद से लेकर नई कहानी के रचनाकारों तक की कहानियों का गंभीर विश्लेषण करते हुए यह स्थापित किया है कि कहानी का वास्तविक मूल्य उसकी जीवन–दृष्टि और कलात्मक संगठन में निहित होता हैं। हिंदी कहानी समीक्षा में रचना–प्रक्रिया की अवधारणा को स्पष्ट करने में भी सुरेंद्र चौधरी का भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने दिखाने का प्रयास किया कि कहानी केवल कल्पना का परिणाम नहीं होती, बल्कि लेखक की अनुभव, संवेदना और सामाजिक चेतना का कलात्मक रूप होती हैं। इस प्रकार उन्होंने कहानी के मूल्यांकन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसके कारण हिंदी कहानी की समीक्षा अधिक गहन और वस्तुनिष्ठ बन सकी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. शुक्ल, रामचन्द्र. (2002), हिन्दी साहित्य का इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, प्रयागराज।
2. शर्मा, रामविलास. (2020), प्रगति और परम्परा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. चौधरी, सुरेन्द्र. (2010), हिंदी कहानी प्रक्रिया और पाठ, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ सं– 27
4. सिंह, नामवर. (2023), कहानी : नई कहानी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ सं– 15
5. पाण्डेय, मैनेजर. (2021), साहित्य और इतिहास–दृष्टि, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
6. चौधरी, सुरेन्द्र. (2010), हिंदी कहानी प्रक्रिया और पाठ, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ सं– 41
7. वहीं, पृ सं –67
8. वहीं, पृ सं –123
9. चौधरी, सुरेन्द्र. (2009), हिंदी कहानी : रचना और परिस्थिति, अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद।
10. चौधरी, सुरेन्द्र.(2009), इतिहास, संयोग और सार्थकता, अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद।
11. चौधरी, सुरेन्द्र. (2009), साधारण की प्रतिज्ञा : अंधेरे से साक्षात्कार, अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 54-57

दलित विमर्श के संदर्भ में 'जूठन' आत्मकथा

डॉ. दर्शना धवल
एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वूमेंस, नई दिल्ली।

दलित विमर्श ने सदियों से मुख्यधारा से वंचित समाज को वाणी दी है। यह केवल एक समुदाय की अभिव्यक्ति को ही नहीं दर्शाता अपितु उनका समाज में न्याय, सदभाव और समानता को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस देश ने एक तरफ राजनीतिक पराधीनता को झेला और दूसरी तरफ उसके चलते कई अन्य तरह की प्रताड़ना का सामना किया। दलित साहित्य उन असंख्य दलित लोगों के जीवन का दस्तावेज है जिनके परिश्रम और रोवा भाव रो इरा देश का इतिहारा और वर्तमान रामृद्ध और राम्पन्न हुआ है। सामाजिक विषमता और वर्णव्यवस्था के कारण उत्पन्न असंतोष और असमानता के फलस्वरूप दलित साहित्य या दलित विमर्श का उदय हुआ है। सन् 1960 के आसपास महाराष्ट्र की भूमि पर दलित साहित्य का उदय हुआ। परिणामस्वरूप दलित कवि, कहानीकार, उपन्यासकार तथा आत्मकथाकार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे।

दलित साहित्य में आत्मकथा लेखन से इसमें नई स्फूर्ति का उदय हुआ। आत्मकथाओं के माध्यम से दलितों पर हुए शोषण को अधिक यथार्थवादी भूमि मिली। यह उनके जीवन की सच्चाई को अधिक तथ्यात्मकता और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है। उनके द्वारा भोगा गया यथार्थ, कष्टमय जीवन, पीड़ा वेदना को साहित्य में स्थान मिला। डा. बाबासाहेब अम्बेडकर के दिखाए मार्ग पर चलकर आज दलित समुदाय शिक्षा के माध्यम से अपनी उपस्थिति लगभग हर क्षेत्र में दर्ज करा रहा है। व्यक्ति और समाज की विकास प्रक्रिया का सबसे मजबूत साधन सभी वर्गों के लिए शिक्षा की सहज उपलब्धि है। एक शिक्षित व्यक्ति सजगता और परिष्कृत बुद्धि से विवेकपूर्ण विमर्श से गुजरता है। ओमप्रकाश वाल्मीकि की 'जूठन' 1997 में प्रकाशित हुई। इस आत्मकथा से अमानवीय जीवन को जीते हुए यंत्रणाओं को झेलते हुए एक प्रेरणापरक दृष्टि का विकास होता है। दलित रचनाकारों द्वारा लिखी आत्मकथाएं यातनामय जीवन जीते हुए दृढ़ता से आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। रमणिका गुप्ता के अनुसार - "जब एक दलित साहित्यकार जाति व्यवस्था की सीढ़ी के सबसे निचले डंडे पर बैठे लोगों को मनुष्यता का अधिकार हासिल कराने के लिए संघर्ष करता है - उसके लिए कलम उठाता है तो वास्तव में पूरे समाज के सोपानात्मक विभाजन को मिटाने के एजेंडे को लेकर ही संघर्षरत हुआ होता है और मनुष्य मात्र ही उसके केन्द्र बिंदु होता है।"[1]

ओमप्रकाश वाल्मीकि ने 'जूठन' के माध्यम रो दलित अस्मिता को एक नया आयाम दिया है। दलित साहित्य में ओमप्रकाश वाल्मीकि का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। उनका जन्म 1950 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दलित परिवार में हुआ। 'जूठन' के माध्यम से उनके व्यक्तिगत अनुभव दलित

साहित्य की अनुपम निधि बन गए। यह कृति जातिगत उत्पीड़न के मौन को क्रान्तिकारी मुखरता से परिभाषित करती है। अपने जीवन की व्यथा को अभिव्यक्त करने के आरंभिक क्षणों की दुविधा का जिक्र उन्होंने पुस्तक की भूमिका में किया है। कितनी बार लिखे हुए पन्ने फाड़ दिए। दुविधा और संशय की उलझन धीरे-धीरे ढीली पड़ी। क्योंकि आत्मकथा में यथार्थता का आग्रह और वो भी दलित आत्मकथा अर्थात दोहरा आत्मसंशय। कई बार मित्रों का सुझाव के रूप में आया कहीं आत्मकथा लिखकर अपनी प्रतिष्ठा ही ना खो दें। वास्तव में यह दलित साहित्य के प्रत्येक लेखक का आत्मसंकट है क्योंकि दलित व्यक्ति का सामान्य जीवन भी प्रतिष्ठा और सम्मान का हकदार नहीं है। 'जूठन' में लेखक के पिता को जब पता लगा कि मास्टर उनके बेटे से स्कूल में झाड़ू लगवाता है तब - ओमप्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं - "पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर फेंक दी। उनकी आँखों में आग की गर्मी उतर आई। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहनेवाले पिताजी की लंबी-लंबी घनी मूंछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थीं। चीखने लगे - कौन-रा मास्टर है, वो द्रोणाचार्य की औलाद, जो मेरे लड़के रो झाड़ू लगवावे है।"[2]

भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से पहले स्थान दिया जाता है। पर दलित जीवन के संदर्भ में यह स्थापना कुछ और ही रूप ले लेती है। स्कूल में झाड़ू न लगाने की स्थिति में मास्टर का कहना कि "यदि नहीं लगाई तो मिर्ची डाल के बाहर काढ़ दूंगा।"[3] यह अछूत होने का दण्ड है। आज भी देश में कहीं न कहीं दलित छात्रों के साथ उत्पीड़न का आरंभ स्कूलों से ही शुरू हो जाता है और आगे चलकर यह मस्तिष्क के चेतन अचेतन हिस्से का स्थायी रूप ले लेते हैं। ये तो ओमप्रकाश वाल्मीकि के पिता की जागरुकता और साहरा का परिणाम था जिन्होंने राही समय पर प्रतिक्रिया कर बालक ओमप्रकाश के जीवन को सही दिशा दी। इसके बावजूद भी मास्टर कलीराम गाली देकर धमकाते हैं तब स्वाभिमानी पिता की वाणी में - "मास्टर हो... इसीलिए जा रहा हूँ पर इतना याद रखिए मास्टर यो चूहड़े का यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में और यो ही नहीं इसके बाद भी आवेंगे पढ़ने कूँ।"[4] इससे स्पष्ट होता है कि एक दलित जीवन को जीवन के मूल अधिकारों का वहन करने के लिए कितनी यातना से गुजरना पड़ता है। वाल्मीकि के पिता को केवल एक दिन नहीं आए दिन कलीराम मास्टर की धमकियों का सामना करना पड़ता था और पिता रोज़ नई ऊर्जा के साथ संघर्षों का सामना करते दिखाई देते हैं।

वाल्मीकि की माँ करीब आठ दस घरों में मवेशियों को बांधने तथा साफ-सफाई का काम करती थीं। साथ ही बहन, बड़ी भाभी और दो भाई (जसवीर और जनेसर) भी हाथ बंटाते थे। दस मवेशी की देखभाल और साफ-सफाई के काम से साल भर में 25 सेर (13 किलो) अनाज मिलता था। दोपहर के समय हर घर से एक बची खुची रोटी जो खासतौर पर चूहड़ों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी और कभी-कभी जूठन भी। बारात के खाने के बाद बची पत्तलों की जूठन इकट्ठी की जाती थी। इसे देख सवर्ण समाज रोमांचित होता - भूक्खड़ लोग आ गए सब चट कर जाएंगे। सम्मान और प्रतिष्ठा तो छोड़िए, एक सामान्य प्राणी का जीवन भी दलित व्यक्ति के लिए दूर की कौड़ी है जबकि संविधान में सभी नागरिक अधिकारों को वहन करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। पर दलितों के लिए उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उचित संसाधनों का अभाव है। समाज की मानसिकता उन अधिकारों पर कुठाराघात करती दिखाई देती है।

वाल्मीकि जी आठवीं कक्षा तक पहुंचते-पहुंचते प्रेमचंद और शरतचंद्र के उपन्यास पढ़ने लगे थे। उनकी दसवीं की कक्षा में वे अपनी जाति के पहले लड़के थे जो हाईस्कूल की परीक्षा दे रहे थे। फिर वे देहरादून जाते हैं कॉलेज की पढ़ाई करने। एक प्रसंग में बेटे की शिक्षा की खातिर स्वाभिमानी पिता गिड़गिड़ाता है।

जब वे नौवीं कक्षा में थे तो घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी। दोस्तों से पुस्तकें मांग कर काम चलाना पड़ता था। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को चूहड़े ही उठाया करते थे। जिसके घर में जो काम करता, उसके मरे पशु भी उसे उठाने पड़ते। बदले में कुछ नहीं मिलता था सिवाय गालियों के। जबकि एक गाय या बैल को उठाने के लिए तीन चार लोग लगते थे। यह दर्शाता है कि दलितों के श्रम का उचित पैसा देना तो दूर उसे गालियां मिलतीं। बस उस मरे पशु को बेचकर 20-25 रुपये जो मिलते वो उनका पारिश्रमिक था।

लेखक ने अपनी आत्मकथा में चित्रित किया है कि जातिगत भेदभाव उनके बचपन तक सीमित नहीं रहा, जीवन के प्रत्येक चरण में उन्हें इसका सामना करना पड़ा। युवावस्था में वे जिस लड़की से प्रेम करते हैं, जाति का पता लगते ही उस ब्राह्मण लड़की ने संबंध तोड़ दिया। वह कहती - "तुम तो एस. सी. कैसे हो सकते हो? उसने इठलाकर कहा। क्यों अगर हुआ तो... तुम तो ब्राह्मण हो... यह तुमसे किसने कहा... बाबा ने... गलत कहा मैं एस. सी. हूँ, सविता गंभीर हो गई, उसकी आंखें छलछला गई थीं। उसने रुआंसी होकर कहा - झूठ बोल रहे हो तुम... नहीं यही सच है... तुम्हें जान लेना चाहिए।... बोली घर आओ या ना आओ लेकिन अगर यह सच है तो बाबा से मत कहना।"[5]

एक दलित व्यक्ति के जीवन में इस तरह की अनेक परिस्थितियाँ आती हैं, इसके बावजूद वह समाज में अपने लिए सम्मानजनक वातावरण तलाशने में लगा रहता है। उसकी शिक्षा, उसके विचार, उसकी ईमानदारी भी जाति के आगे फीकी पड़ जाती है। मित्र कुरैशी भी एक उच्च पद पर होने के बावजूद वाल्मीकि की जाति पता चलते ही असहज हो जाता है। इससे पता चलता है कि शहरी वातावरण में भी जातिगत भेदभाव की जड़ें कितनी गहरी हैं। पर एक दलित व्यक्ति सदैव इससे टकराता रहता है। वाल्मीकि की 'जूठन' में एक स्थान पर 'सलाम प्रथा' का जिक्र हुआ है। जिसके अनुसार दलित नवविवाहित जोड़ा सवर्ण परिवारों गें जाकर सलाग करता है। जिन-जिन घरों गें दलित परिवार के लोग काग करते थे, उन सभी घरों में दूल्हा-दुल्हन ससुराल में अपनी सास के साथ सलामी देने जाते थे। परन्तु वाल्मीकि जी के पिता ने इस प्रथा का पालन नहीं किया। वे सदियों से चली आ रही इस कुप्रथा को नष्ट करना चाहते थे।

दलितों को सामान्य जीवन में भी अनेक विसंगतियों का सामना करना पड़ता है जैसे अलग बर्तन में चाय-पानी या खाना देना, बैठने के लिए नीचा स्थान देना या अलग स्थान देना। जैसे कुलकर्णी के घर आए प्राध्यापक काम्बले जी को चाय अलग बर्तन में पिलाई गई। जब लेखक सविता से पूछता है तो वह कहती है - "घर में जितने भी एस. सी. और मुसलमान आते हैं, उन सबके लिए अलग बर्तन रखे हुए हैं, सविता ने सहजता से कहा। यह भेदभाव तुम्हें सही लगता है? मैंने पूछा। मेरे शब्दों में तीखेपन को उसने महसूस कर लिया था। अरे तुम नाराज क्यों होते हो?... उन्हें अपने बर्तनों में कैसे खिला सकते हैं?... उसने प्रश्न किया। क्यों नहीं खिला सकते? होटल में तो सब एक साथ खाते हैं फिर घरों में क्यों तकलीफ है?"[6], इसके बाद लेखक अपनी भी सच्चाई बता देता है।

'जूठन' शीर्षक के माध्यम से लेखक ने अनेक विसंगतियों को उजागर किया है। जातिगत प्रताड़ना में जूठन खाना अतिमानवीय परिस्थितियों में से एक परिस्थिति है। राजकिशोर के आग्रह पर 1994 में 'हरिजन से दलित' पुस्तक में इस आत्मकथा के कुछ अंशों ने दलित साहित्य में एक नई सरगर्मी पैदा कर दी। 'जूठन' में लेखक ने अदालतों के और समाज के शोषण के उस स्वरूप को प्रकट किया है जिसे अभिव्यक्त करने के लिए लेखन कौशल के साथ-साथ अदम्य साहस और धैर्य की आवश्यकता है। गरीबी

और जातिगत दंश झेलते हुए कैसे एक व्यक्ति समाज और साहित्य में दृढ़ता से अपना स्थान बनाता है, यह इसकी मिसाल है। ऐसे समाज में जहां "सरनेम जान लेने के बाद लोगों का व्यवहार बदल जाता है, ऐसे कहने वालों में ज्यादातर मेरी ही जाति के पढ़े-लिखे, मेरे परिवार के लोग, नाते-रिश्तेदार होते हैं तथाकथित दलित साहित्यकार भी हैं।"[7] यहाँ लेखक दलितों के अंतर्विरोध को भी उजागर करता है। कक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर यह सुनना पड़ता - "देखो चूहड़े का बामन बन रहा है।" दलितों के लिए परिश्रम और संघर्ष ही उनकी दशा सुधारने का एकमात्र साधन है। 'जूठन' शीर्षक के माध्यम से उसमें छिपी दलितों की यंत्रणामय परिस्थिति की परिचायक है। एक सभ्य और सम्मानजनक परिस्थिति में हम किसी की जूठन गालियों के साथ खाने के बाध्य नहीं हैं और मानवीय तौर पर भी यह न्यायसंगत नहीं है। परंतु दलितों के जीवन की यह स्वाभाविक परिस्थिति है। लेखक के अनुसार - "दलित साहित्य में दलित आत्मकथाएं व्यक्तिगत नहीं समूह की व्यथा-कथाएं होती हैं। यदि किसी ने व्यक्तिगत करने के प्रयास भी किए हैं तो भी वहाँ सामूहिकता ही प्रभावी होती है जो उसे व्यक्ति से समूह बनाती है।"[8] स्पष्ट है एक रचनाकार के रूप में ओमप्रकाश वाल्मीकि मानते हैं कि जब कोई रचना साहित्य बनने का अंग बन जाती है तो वह व्यक्तिगत से सामूहिक हो जाती है। वह असंख्य लोगों की अभिव्यक्ति बन जाती है।

अतः यह स्पष्ट है कि 'जूठन' आत्मकथा दलित जीवन की मर्मांतक यंत्रणामय जीवन का जीवंत दस्तावेज है। इसको इस बात से स्पष्टतः समझा जा सकता है जब लेखक कहते हैं कि यदि पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में होता तो वे कभी भंगी के घर पैदा नहीं होते। कल्पना कीजिए, उस व्यक्ति को उसकी जातिगत भेदभाव का दंश व्यक्ति को उसके जन्म लेने को भी निराशा और हताशा का कारण बना देते हैं। जन्म लेने से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समानता, सद्भाव सभी से वंचना का शिकार होना पड़ता है। एक दलित जीवन सबसे पहले शिक्षा के संरचनागत ढांचे से टकराता है जहाँ व्यक्ति को वैचारिक परिपक्वता के बजाय भेदभाव की शिक्षा का सामना करना पड़ता है। ओमप्रकाश वाल्मीकि ने 'जूठन' के माध्यम से समाज के उस विद्रूप चेहरे को उजागर किया है जिसके लिए साहस और धैर्य की परीक्षा होती है। विमर्श यदि परिस्थिति और समस्याओं के समाधान की मांग करता है तो 'जूठन' इस संदर्भ में उल्लेखनीय कृति है।

संदर्भ सूची:

1.भारतीय दलित साहित्य: परिप्रेक्ष्य,सं.पुन्नी सिंह,पृ. 328,वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली

2.ओमप्रकाश वाल्मीकि, जूठन,पृ.14,राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली

3.वही, पृ. 15

4.वही, पृ. 15

5.वही, पृ. 145

6.वही, पृ. 120

7.वही, पृ. 54

8.दलित दर्शन, सम्पादक: रमणिका गुप्ता, ज्ञानसिंह, पृ. 103, नेहा प्रकाशन, दिल्ली

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 58–60

अलवर जिले में गिरता भू–जल स्तर और कृषि प्रारूप पर उसका प्रभाव : एक भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. सुभाष चंद खटीक
सहायक आचार्य (भूगोल विभाग)
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

शोध-सार (Abstract)

प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के अर्ध–शुष्क अंचल में स्थित अलवर जिले में विगत दो दशकों में हुए तीव्र भू–जल ह्रास तथा उसके परिणामस्वरूप कृषि प्रतिरूप (Cropping Pattern) में आए बदलावों का एक भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का हिस्सा होने के कारण अलवर में तीव्र औद्योगीकरण और नगरीकरण हुआ है, जिससे जल की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। केंद्रीय भू–जल बोर्ड (CGWB) के आंकड़ों और स्थानीय सर्वेक्षण के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जिले के अधिकांश ब्लॉक 'अति–दोहित' (Over-exploited/Dark Zone) श्रेणी में आ चुके हैं। पानी की कमी के कारण कृषि लागत में वृद्धि हुई है तथा किसानों को मजबूरन कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करना पड़ रहा है। यह शोध पत्र इस संकट के भौगोलिक कारकों की पड़ताल करता है तथा जल संरक्षण के पारंपरिक एवं आधुनिक उपायों को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द (Keywords) : अलवर, भू–जल ह्रास, डार्क जोन, कृषि प्रारूप, अरावली, सतत विकास।

1. प्रस्तावना (Introduction)

जल संसाधन किसी भी क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक और विशेषकर कृषि विकास की रीढ़ होते हैं। राजस्थान जैसे शुष्क और अर्ध–शुष्क राज्य में, जहाँ सतही जल (Surface Water) की उपलब्धता अत्यंत सीमित है, वहाँ भू–जल ही जीवन और आजीविका का मुख्य आधार है।

अलवर जिला 27° 4' N से 28° 4' N अक्षांश और 76° 7' E से 77° 13' E देशांतर के मध्य राजस्थान के उत्तर–पूर्वी भाग में स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 8,380 sq. km है। पिछले कुछ दशकों में, अलवर जिले के उत्तर–पूर्वी और पश्चिमी भागों (जैसे भिवाड़ी, नीमराना, बहरोड़) में औद्योगिक गलियारों का तेजी से विस्तार हुआ है। इस कारण जनसंख्या का संकेंद्रण बढ़ा है और साथ ही नलकूपों (Tubewells) द्वारा भू–जल का अनियंत्रित दोहन शुरू हुआ है। अरावली पहाड़ियों की उपस्थिति के बावजूद, वनों की कटाई और अवैध खनन ने प्राकृतिक जल पुनर्भरण (Natural Groundwater Recharge) की प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित किया है।

2. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. अलवर जिले में पिछले दशक में भू–जल स्तर की गिरावट की प्रवृत्ति (Trend) का अध्ययन करना।
2. जिले के विभिन्न ब्लॉकों के 'डार्क जोन' वर्गीकरण का मूल्यांकन करना।
3. घटते जल स्तर का स्थानीय फसलों के चयन और कृषि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।
4. क्षेत्र में जल संकट के समाधान हेतु भौगोलिक सुझाव प्रस्तुत करना।

3. डेटा और शोध कार्यप्रणाली (Data Base & Methodology)

प्रस्तुत शोध मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों (Secondary Data) पर आधारित है, जिसे विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक विधि से संसाधित किया गया है :

- **डेटा स्रोत :** आंकड़े केंद्रीय भू–जल बोर्ड (CGWB), राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग, तथा जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, अलवर से प्राप्त किए गए हैं।
- **विश्लेषण :** पिछले 10 वर्षों (2015–2025) के प्री–मानसून और पोस्ट–मानसून जल स्तर के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

4. विश्लेषण एवं विवेचना (Analysis and Discussion)

4.1 भू-जल स्तर की वर्तमान स्थिति और डार्क जोन :

केंद्रीय भू–जल बोर्ड की रिपोर्टों के अनुसार, अलवर जिले में भू–जल विकास का स्तर (Stage of Groundwater Development) 130% से अधिक हो चुका है, जिसका अर्थ है कि जितना पानी जमीन के अंदर रीचार्ज होता है, उससे कहीं अधिक बाहर निकाला जा रहा है।

जिले के अधिकांश ब्लॉकों की स्थिति चिंताजनक है :

- **अति-दोहित ब्लॉक (Over-Exploited / Dark Zone) :** बहरोड़, नीमराना, तिजारा, कोटकासिम, बानसूर, और लक्ष्मणगढ़। इन क्षेत्रों में जल स्तर प्रतिवर्ष 0.5 meter से 1.5 meter की दर से नीचे जा रहा है। यहाँ भू–जल स्तर कई स्थानों पर 100–150 meters से भी अधिक गहरा हो चुका है।
- **क्रिटिकल/सेमी-क्रिटिकल ब्लॉक :** अलवर, रामगढ़, और मालाखेड़ा।

4.2 कृषि प्रारूप पर प्रभाव (Impact on Cropping Pattern)

भू–जल के निरंतर गिरने का सीधा असर अलवर की कृषि पर पड़ा है :

- **फसल प्रतिस्थापन (Crop Substitution) :** पूर्व में जिन क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे गेहूं या कुछ मात्रा में अधिक पानी वाली फसलों की खेती होती थी, वहाँ अब किसान सरसों (Mustard) और बाजरा (Pearl Millet) जैसी शुष्क कृषि फसलों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अलवर जिला वर्तमान में राजस्थान में सरसों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है, जो यहाँ की अर्ध–शुष्क विवशता को भी दर्शाता है।
- **आर्थिक लागत में वृद्धि :** पानी का स्तर नीचे जाने के कारण पुराने कुएं सूख गए हैं। किसानों को अत्यधिक गहराई वाले सबमर्सिबल पंप लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी कृषि लागत (Input Cost) और बिजली / डीजल का खर्च लगातार बढ़ रहा है। छोटे और सीमांत किसान इस आर्थिक बोझ को उठाने में असमर्थ

हो रहे हैं।

4.3 भौगोलिक कारक (Geographical Factors)

- **अरावली का क्षरण :** अरावली की श्रेणियां वर्षा जल को रोककर भू–जल को रीचार्ज करने में प्राकृतिक अवरोधक का कार्य करती थीं। खनन गतिविधियों के कारण यह पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) प्रभावित हुआ है।
- **अनियमित वर्षा :** पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसूनी वर्षा के दिनों की संख्या घटी है। कम समय में तेज बारिश होने के कारण पानी जमीन में रिसने के बजाय सतह पर बहकर नष्ट हो जाता है।

5. निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion & Suggestions)

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि यदि अलवर जिले में भू–जल के दोहन की यही गति रही, तो आगामी वर्षों में यह क्षेत्र तीव्र मरुस्थलीकरण (Desertification) और गंभीर पेयजल संकट की चपेट में आ जाएगा। कृषि को सतत बनाए रखने के लिए भौगोलिक और नीतिगत स्तर पर निम्नलिखित कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं :

1. **पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनरूद्धार :** अलवर में तरुण भारत संघ जैसी संस्थाओं के सहयोग से पूर्व में निर्मित 'जोहड़' (Traditional Check Dams) और पोखरों को पुनर्जीवित किया जाए। जयसमंद और सिलीसेढ़ जैसे ऐतिहासिक जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों (Catchment Areas) को अतिक्रमण मुक्त किया जाना चाहिए।
2. **सूक्ष्म सिंचाई तकनीक (Micro-Irrigation) :** क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई (Sprinkler) और टपकन सिंचाई (Drip Irrigation) को अनिवार्य किया जाए, जिसके लिए राज्य सरकार को विशेष सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए।
3. **औद्योगिक जल पुनर्चक्रण :** भिवाड़ी और नीमराना के उद्योगों के लिए 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) नीति कड़ाई से लागू हो, ताकि वे भू–जल पर निर्भर रहने के बजाय उपचारित पानी (Treated Water) का पुनरुपयोग करें।

6. संदर्भ सूची (References)

1. केंद्रीय भू–जल बोर्ड (CGWB), भारत सरकार (2021). पश्चिमी क्षेत्र की भू–जल वार्षिक रिपोर्ट (राजस्थान).
2. सिंह, आर. (2018). राजस्थान का भूगोल. राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर.
3. शर्मा, बी.एल. एवं गुप्ता, एस.के. (2019). 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अलवर जिला) में भूमि उपयोग परिवर्तन और पर्यावरण संकट', भारतीय भौगोलिक पत्रिका, वॉल्यूम 42, पीपी. 112–125.
4. जिला सांख्यिकी रूपरेखा (2023). आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, अलवर सरकार.

subhashpaliwal40@gmail.com

Mob 9782607562

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 61-65

शिक्षक शिक्षकों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में व्यावसायिक दक्षता एवं व्यावसायिक संतुष्टि के मध्य संबंध का अध्ययन

डॉ. ज्ञान गांधी
सहायक प्रोफेसर, पाकुड़ बी.एड कॉलेज, पाकुड़, झारखंड।

सारांश :

वर्तमान युग में शैक्षिक प्रौद्योगिकी ने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली, नवाचारी तथा विद्यार्थी–केंद्रित बनाया है। शिक्षक–शिक्षकों (Teacher Educators) की भूमिका केवल ज्ञान के संप्रेषण तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वे भावी शिक्षकों को तकनीकी दक्षताओं से सुसज्जित करने के उत्तरदायी भी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक–शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता तथा व्यावसायिक संतुष्टि का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यावसायिक दक्षता से आशय शिक्षक–शिक्षकों के ज्ञान, कौशल, शिक्षण–रणनीतियों तथा तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग की क्षमता से है, जबकि व्यावसायिक संतुष्टि उनके कार्य के प्रति संतोष, प्रेरणा एवं सकारात्मक दृष्टिकोण को व्यक्त करती है। यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि व्यावसायिक दक्षता एवं व्यावसायिक संतुष्टि के मध्य सकारात्मक संबंध विद्यमान है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग शिक्षक–शिक्षकों की दक्षताओं को विकसित करने के साथ–साथ उनके कार्य–संतोष को भी बढ़ाता है। अतः शिक्षक–शिक्षा संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता तथा व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे शिक्षक–शिक्षकों की दक्षता और संतुष्टि दोनों में वृद्धि हो सके तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

मुख्य शब्द – शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षक शिक्षक, व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक संतुष्टि, शिक्षक शिक्षा, डिजिटल साक्षरता।

प्रस्तावना :

21वीं सदी को ज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के समावेश ने शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रोचक तथा परिणामोन्मुख बनाया है। शिक्षक शिक्षकों का उत्तरदायित्व केवल विषय–वस्तु का ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि भावी शिक्षकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना भी है।इन परिवर्तनों के सफल क्रियान्वयन में शिक्षक तथा शिक्षक शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शिक्षक शिक्षक (Teacher Educators) भावी शिक्षकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे न केवल विषय ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों में आवश्यक शिक्षण कौशल, व्यावसायिक मूल्य तथा तकनीकी दक्षताओं का भी विकास करते हैं। इसलिए शिक्षक शिक्षकों का व्यावसायिक रूप से दक्ष होना आवश्यक है। व्यावसायिक दक्षता से तात्पर्य उन ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों एवं क्षमताओं से है, जिनके माध्यम से शिक्षक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य का प्रभावी ढंग से निष्पादन करते हैं।

व्यावसायिक दक्षता शिक्षक शिक्षकों की उस क्षमता को व्यक्त करती है जिसके माध्यम से वे अपने कार्यों का सफल निष्पादन करते हैं। दूसरी ओर व्यावसायिक संतुष्टि उनके कार्य, संस्थागत वातावरण, सहकर्मियों एवं उपलब्ध सुविधाओं के प्रति संतोष की भावना को दर्शाती है। यदि शिक्षक शिक्षक अपने व्यवसाय से संतुष्ट होंगे तो उनकी कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग ने शिक्षक–शिक्षकों की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षण, स्मार्ट कक्षाएँ तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण प्रणालियाँ शिक्षक–शिक्षकों से नवीन दक्षताओं की अपेक्षा करती हैं। इसलिए व्यावसायिक दक्षता एवं व्यावसायिक संतुष्टि के मध्य संबंध का अध्ययन समकालीन शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, रोचक एवं छात्र–केंद्रित बनाने में तकनीकी संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में कार्यरत शिक्षक शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए भावी शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण कौशल प्रदान करें। इसके लिए उनका व्यावसायिक रूप से दक्ष होना आवश्यक है।

व्यावसायिक दक्षता शिक्षक शिक्षकों की कार्यकुशलता, शिक्षण कौशल, तकनीकी ज्ञान तथा समस्या समाधान क्षमता को प्रभावित करती है। दूसरी ओर व्यावसायिक संतुष्टि उनके कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, कार्यनिष्ठा एवं संस्थान के प्रति समर्पण को बढ़ाती है। यदि शिक्षक शिक्षक अपने व्यवसाय से संतुष्ट होंगे, तो वे नवीन तकनीकों को अपनाने और उनका प्रभावी उपयोग करने के प्रति अधिक प्रेरित होंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP–2020) में भी शिक्षण प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के समावेश तथा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता के विकास पर विशेष बल दिया गया है। ऐसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में शिक्षक शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता एवं व्यावसायिक संतुष्टि के मध्य किस प्रकार का संबंध विद्यमान है।

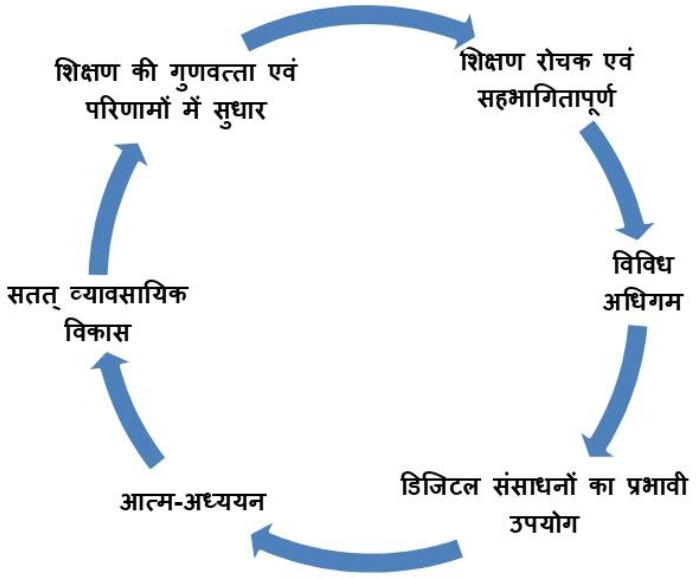
अतः शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास, तकनीकी दक्षता के संवर्धन तथा प्रभावी शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए इस अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की गई। यह अध्ययन शिक्षक शिक्षा संस्थानों, नीति–निर्माताओं एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षक-शिक्षा :

शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित तथा परिणामोन्मुख बनाने का साधन है। शिक्षक–शिक्षकों के लिए यह केवल तकनीकी उपकरणों के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षण

की नवीन रणनीतियों, डिजिटल सामग्री निर्माण तथा ऑनलाइन अधिगम वातावरण के विकास से भी संबंधित है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से शिक्षक-शिक्षा –



व्यावसायिक दक्षता और शिक्षक शिक्षा :

व्यावसायिक दक्षता (Professional Competency) शिक्षक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसका तात्पर्य उन ज्ञान, कौशलों, अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों से है जो एक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं। शिक्षक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो विषय ज्ञान के साथ–साथ शिक्षण–कौशल, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन तथा आधुनिक शैक्षिक तकनीकों के उपयोग में दक्ष हों। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम भावी शिक्षकों में व्यावसायिक दक्षताओं के विकास पर विशेष बल देते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षकों को शिक्षण–अधिगम सिद्धांतों, पाठ योजना निर्माण, शिक्षण विधियों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, संचार कौशल तथा विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली एवं परिणामोन्मुख बना पाते हैं।

वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक दक्षता का महत्व और अधिक बढ़ गया है क्योंकि शिक्षा प्रणाली निरंतर परिवर्तनशील है। नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षण, समावेशी शिक्षा तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में शिक्षकों का दक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। एक व्यावसायिक रूप से दक्ष शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं सृजनात्मकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अतः शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक दक्षता एक–दूसरे के पूरक हैं। प्रभावी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को विकसित करते हैं, जबकि उच्च व्यावसायिक दक्षता शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सक्षम, उत्तरदायी एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष शिक्षकों का निर्माण करना है।

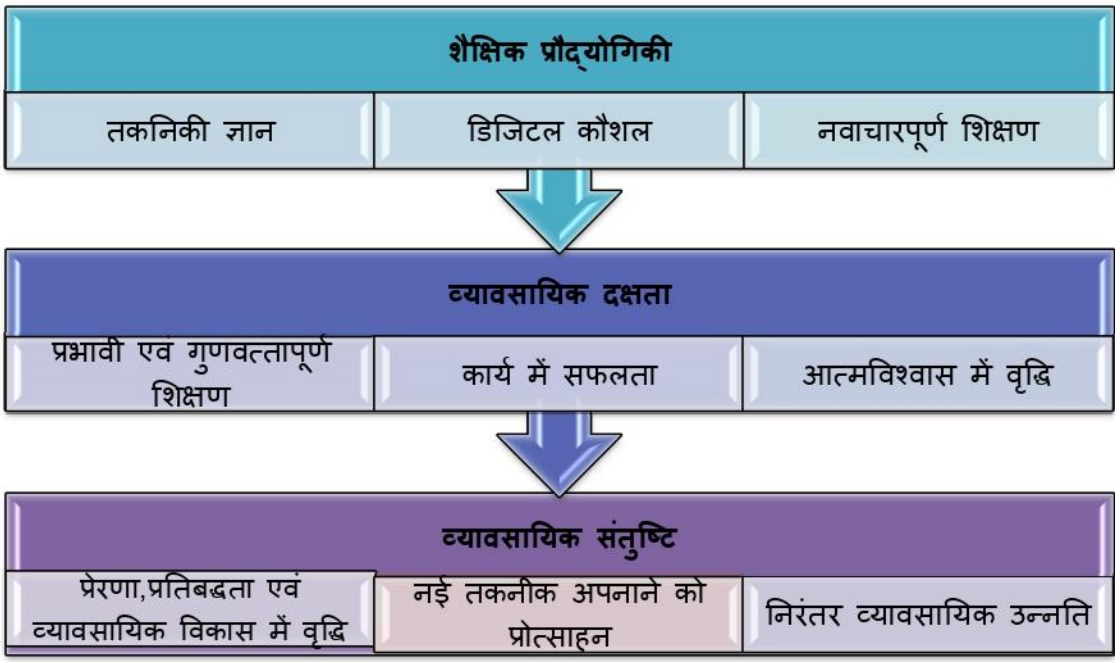
व्यावसायिक संतुष्टि और शिक्षक शिक्षा :

व्यावसायिक संतुष्टि (Professional Satisfaction) से आशय उस संतोष, प्रसन्नता एवं सकारात्मक अनुभूति से है जो किसी व्यक्ति को अपने कार्य, कार्य–परिस्थितियों तथा व्यावसायिक उपलब्धियों से प्राप्त होती

है। शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में व्यावसायिक संतुष्टि एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यह शिक्षक–शिक्षकों एवं शिक्षकों की कार्यक्षमता, प्रेरणा तथा शिक्षण की गुणवत्ता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब शिक्षक–शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण, अनुकूल कार्य वातावरण, व्यावसायिक विकास के अवसर, प्रशासनिक सहयोग तथा सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है, तब उनकी व्यावसायिक संतुष्टि में वृद्धि होती है। वर्तमान तकनीकी एवं वैश्विक परिवर्तनों के दौर में शिक्षक शिक्षा संस्थानों के लिए यह आवश्यक है कि वे शिक्षक–शिक्षकों की व्यावसायिक संतुष्टि को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, संसाधनों की उपलब्धता तथा सहयोगात्मक वातावरण प्रदान करें। इससे न केवल शिक्षकों का व्यावसायिक विकास होगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।

अतः शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक संतुष्टि का घनिष्ठ संबंध है। प्रभावी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों में संतुष्टि की भावना विकसित करते हैं, जबकि संतुष्ट शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक संतुष्टि शिक्षक शिक्षा की सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक दक्षता एवं व्यावसायिक संतुष्टि में संबंध :



अतः कहा जा सकता है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी व्यावसायिक दक्षता और व्यावसायिक संतुष्टि के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता तथा सतत् व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर शिक्षक–शिक्षकों की दक्षता और संतुष्टि दोनों में वृद्धि की जा सकती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है।

निष्कर्ष :

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में शिक्षक–शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता एवं व्यावसायिक संतुष्टि शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। दोनों के मध्य सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षक–शिक्षक अपने कार्य में अधिक सफलता एवं संतोष का अनुभव करते हैं, जबकि संतुष्ट शिक्षक–शिक्षक अपने व्यावसायिक विकास के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं। अतः शिक्षक शिक्षा संस्थानों

में तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों तथा अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षक–शिक्षकों की दक्षता एवं संतुष्टि दोनों में वृद्धि हो सके।

संदर्भ (References)

- Aggarwal, J. C. (2014). Essentials of Educational Technology. New Delhi: Vikas Publishing House.
- Panda, S. (2017). Educational Technology. New Delhi: Kanishka Publishers.
- Sharma, R. A. (2018). Teacher Education and Educational Technology. Meerut: R. Lall Book Depot.
- Mangal, S. K., & Mangal, U. (2019). Essentials of Educational Technology. New Delhi: PHI Learning.
- Singh, Y. K. (2019). Teacher Education. New Delhi: APH Publishing Corporation.
- NCERT (2020). National Education Policy 2020. New Delhi: Ministry of Education.
- UNESCO (2023). Technology in Education: A Tool on Whose Terms? Paris: UNESCO Publishing.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 66–70

भारतीय संसद एवं महिला सशक्तिकरण : झारखंड राज्य के संदर्भ में

वीरेन्द्र देव, शोधार्थी
डॉ० प्रीति कुमारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं शोध निर्देशिका
आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखण्ड।

सारांश :

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सामाजिक न्याय एवं समानता का महत्वपूर्ण आधार है। संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल राजनीतिक उपस्थिति नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम है। झारखंड जैसे आदिवासी एवं सामाजिक विविधता वाले राज्य में महिला प्रतिनिधित्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। प्रस्तुत शोध लेख में भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तिकरण की अवधारणा तथा झारखंड राज्य में महिला राजनीतिक सहभागिता की स्थिति का अध्ययन किया गया है। साथ ही महिला प्रतिनिधित्व में आने वाली चुनौतियों एवं सुधारात्मक उपायों पर भी विचार किया गया है।

मुख्य शब्द – महिला सशक्तिकरण, भारतीय संसद, महिला प्रतिनिधित्व, झारखंड, राजनीतिक सहभागिता।

प्रस्तावना –

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ महिलाओं को संविधान द्वारा समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त हों। महिला सशक्तिकरण इसी विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर, जागरूक एवं निर्णय लेने में सक्षम बनाना है।

भारतीय संसद महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करती रही है। संसद द्वारा समय–समय पर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं उनके विकास के लिए अनेक कानून, नीतियाँ एवं योजनाएँ लागू की गई हैं। दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोधक अधिनियम तथा पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण जैसे प्रावधान महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसके अतिरिक्त संसद द्वारा पारित "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा

है।

झारखंड में पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में आरक्षण के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। राज्य की कई संसदीय एवं जनजातीय क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जाती है, जो महिला राजनीतिक चेतना एवं सहभागिता को दर्शाती है। इसके बावजूद अशिक्षा, गरीबी, लैंगिक भेदभाव, मानव तस्करी एवं सामाजिक रूढ़िवादिता जैसी समस्याएँ महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं।

अतः "भारतीय संसद एवं महिला सशक्तिकरण रू झारखंड राज्य के संदर्भ में" विषय का अध्ययन अत्यंत प्रासंगिक है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा :

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना है ताकि वे स्वतंत्र निर्णय ले सकें और समाज में समान भागीदारी निभा सकें। राजनीतिक सशक्तिकरण इसके प्रमुख आयामों में से एक है, क्योंकि नीति निर्माण एवं निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से महिलाओं की स्थिति मजबूत होती है। झारखंड राज्य के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण का विषय विशेष महत्व रखता है। यह राज्य आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक संसाधनों एवं सामाजिक विविधताओं से समृद्ध है। यहाँ की महिलाएँ कृषि, वनोपज, पारिवारिक दायित्वों एवं सामाजिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेषकर आदिवासी समाज में महिलाओं की सहभागिता पारंपरिक रूप से अधिक रही है, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं राजनीतिक नेतृत्व के क्षेत्र में उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व :

भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी धीरे–धीरे बढ़ी है, किन्तु यह अभी भी संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुँच सकी है। पहली लोकसभा (1952) में महिला सांसदों का प्रतिशत लगभग 5% था, जबकि हाल के वर्षों में यह लगभग 14% के आसपास पहुँचा है।

महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रयास किए हैं। पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण ने महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान किया, जिससे अनेक महिलाएँ राजनीति की मुख्यधारा में आईं।

झारखंड राज्य के संदर्भ में महिला प्रतिनिधित्व :

झारखंड में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का स्वरूप विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। कई लोकसभा सीटों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक पाई गई है, जिससे उनकी राजनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है।

झारखंड विधानसभा एवं स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, किन्तु उच्च राजनीतिक पदों पर उनकी संख्या अभी भी सीमित है। पंचायत चुनावों में आरक्षण के कारण ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है। झारखंड राज्य महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा से संबंधित कार्य करता है तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है।

महिला सशक्तिकरण में संसद की भूमिका :

भारतीय संसद महिलाओं के अधिकारों एवं विकास के लिए नीतियाँ एवं कानून बनाकर महत्वपूर्ण भूमिका

निभाती है। संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम एवं योजनाएँ महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक रही हैं।

1. संवैधानिक अधिकार :

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 महिलाओं को समान अवसर सुनिश्चित करते हैं।

2. महिला सुरक्षा संबंधी कानून :

संसद द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, जैसे –

- दहेज निषेध अधिनियम, 1961
- घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005
- कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निरोधक अधिनियम, 2013
- बाल विवाह निषेध अधिनियम

इन कानूनों ने महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की है।

3. राजनीतिक सशक्तिकरण :

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत एवं नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इससे झारखंड की ग्रामीण महिलाओं को नेतृत्व एवं निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला।

4. शिक्षा एवं कल्याण योजनाएँ :

संसद एवं केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के विकास हेतु अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं, जैसे –

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
- उज्ज्वला योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- राष्ट्रीय महिला कोष योजना

इन योजनाओं ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया है।

झारखंड में महिला सशक्तिकरण की चुनौतियाँ :



झारखंड में महिला सशक्तिकरण उपाय और योजनाएं :

झारखंड सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास, विशेषकर महिलाओं, युवाओं, और आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए कई योजनाएं और सशक्तिकरण के उपाय लागू कर रही है। प्रमुख सशक्तिकरण उपायों और योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है :

महिला एवं बालिका सशक्तिकरण	**•मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना** **•सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना** **•सखी मंडल (JSLPS):**
आदिवासी एवं ग्रामीण विकास	**•झारखंड समावेशी आजीविका योजना (UPAJ):** **•आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना**
युवा रोजगार एवं कौशल विकास	**•झारखंड कौशल विकास मिशन सोसायटी (JSDM)**
कृषि एवं किसान सशक्तिकरण	**•झारखंड राज्य फसल राहत योजना** **•कृषि ऋण माफ़ी योजना**

सुधार हेतु सुझाव :

1. महिलाओं की शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई जाए।
2. संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रभावी आरक्षण लागू किया जाए।
3. ग्रामीण महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाए।
4. राजनीतिक दलों में अधिक अवसर देना चाहिए।
5. महिला सुरक्षा एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
6. आदिवासी महिलाओं के विकास हेतु विशेष योजनाएँ लागू की जाए।

निष्कर्ष :

भारतीय संसद महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। झारखंड राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बावजूद राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी सीमित है। वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब महिलाओं की भागीदारी समान एवं सार्थक हो। झारखंड राज्य के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ की महिलाएँ विशेषकर आदिवासी समाज में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा योजनाओं एवं सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया है।

अतः आवश्यक है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व को और अधिक बढ़ावा

दिया जाए। शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची :

- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-analysis/political-representation-of-women?utm_source=chatgpt.com
- https://www.sanskritiias.com/hindi/current-affairs/representation-of-women-in-indian-politics?utm_source=chatgpt.com
- https://www.orfonline.org/research/women-s-representation-in-india-s-parliament-measuring-progress-analysing-obstacles?utm_source=chatgpt.com)
- https://www.ifad.org/en/w/projects/1100001649
- https://jsdm.jharkhand.gov.in/jsdm/cms/en/vision/
- अग्रवाल, एस. पी. (2019). महिला सशक्तिकरण और भारतीय समाज। नई दिल्ली : राधा प्रकाशन।
- शर्मा, आर. एन. (2021). भारतीय राजनीति एवं महिला अध्ययन। आगरा : विनोद पुस्तक मंदिर।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 71-74

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की भूमिका

डॉ. स्वाति राय
सहायक व्याख्याता,
राजगंज इंटर महाविद्यालय, राजगंज, धनबाद।

सारांश (Abstract)

महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास का एक अनिवार्य आधार भी है। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना राष्ट्रीय प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में महिलाएँ शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता, कृषि, विज्ञान, तकनीक तथा प्रशासन जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। फिर भी लैंगिक असमानता, वेतन भेदभाव, सीमित अवसर एवं सामाजिक बाधाएँ महिला सशक्तिकरण के मार्ग में प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की भूमिका, उसकी आवश्यकता, वर्तमान स्थिति, चुनौतियाँ तथा संभावित समाधान पर विचार किया गया है।

मुख्य शब्द : महिला सशक्तिकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास, लैंगिक समानता, उद्यमिता।

प्रस्तावना :

किसी भी देश की प्रगति तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक वहाँ की महिलाएँ समान रूप से विकास प्रक्रिया में सहभागी न हों। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है, परंतु ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारणों से उन्हें लंबे समय तक सीमित अवसर प्राप्त हुए। वर्तमान में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, निर्णय–निर्माण तथा आर्थिक संसाधनों तक समान पहुँच प्रदान करने पर बल देती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महिलाओं की भूमिका बहुआयामी है। यदि महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाई जाए, तो भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा :

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं –



भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

1. श्रम शक्ति में योगदान :

महिलाएँ कृषि, उद्योग, सेवा एवं असंगठित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ग्रामीण भारत में कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत में बड़ी संख्या में महिलाएँ निम्न क्षेत्रों में सक्रिय हैं –

- कृषि एवं पशुपालन
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य
- बैंकिंग एवं प्रशासन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- लघु एवं मध्यम उद्योग

महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ने से उत्पादकता और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

2. उद्यमिता और स्वरोजगार :

आज अनेक महिलाएँ सफल उद्यमी बनकर भारतीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं।

स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, महिला ई–हाट जैसी सरकारी योजनाएँ महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रही हैं।

महिला उद्यमिता के लाभ –

- रोजगार सृजन
- पारिवारिक आय में वृद्धि
- आर्थिक आत्मनिर्भरता
- नवाचार और स्थानीय विकास

3. वित्तीय समावेशन :

जनधन योजना, स्वयं सहायता समूह (SHGs), माइक्रोफाइनेंस आदि योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इससे–

- बचत की आदत विकसित हुई।
- ऋण प्राप्ति आसान हुई।
- छोटे व्यवसायों का विस्तार संभव हुआ।

4. शिक्षा और मानव पूंजी निर्माण :

शिक्षित महिला परिवार और समाज दोनों के विकास में योगदान देती है। महिला शिक्षा से स्वास्थ्य, पोषण, बाल शिक्षा और सामाजिक चेतना में सुधार होता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास को मजबूत करता है।

महिला सशक्तिकरण में प्रमुख चुनौतियाँ :

1. लैंगिक असमानता :

लैंगिक असमानता से आशय महिलाओं और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, सम्मान तथा सुविधाओं में होने वाले भेदभाव से है। समाज में कई स्थानों पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर दिए जाते हैं, जिससे उनका विकास प्रभावित होता है। आज भी महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता।

2. शिक्षा में बाधाएँ :

ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा अभी भी प्रभावित है। अनेक लड़कियाँ शिक्षा से वंचित हैं। परिवारों में लड़कों की शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है। बाल विवाह, गरीबी तथा सामाजिक सोच के कारण लड़कियाँ उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पातीं।

3. सामाजिक रूढ़ियाँ :

पारंपरिक सोच महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित करती है। दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, लिंग भेद जैसी सामाजिक कुरीतियाँ आज भी महिलाओं के विकास में बाधा हैं। कई स्थानों पर महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित समझा जाता है।

4. कार्यस्थल पर सुरक्षा :

यौन उत्पीड़न एवं असुरक्षा महिलाओं की कार्य भागीदारी को प्रभावित करती है। यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, मानव तस्करी जैसी घटनाएँ उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। असुरक्षा की भावना उनके विकास को सीमित कर देती है।

5. डिजिटल विभाजन :

तकनीकी संसाधनों तक महिलाओं की सीमित पहुँच। आधुनिक युग में तकनीकी ज्ञान आवश्यक है, लेकिन अनेक महिलाएँ डिजिटल शिक्षा और इंटरनेट सुविधाओं से वंचित हैं। इससे वे नई संभावनाओं और रोजगार के अवसरों का लाभ नहीं उठा पातीं।

सरकारी पहल एवं योजनाएँ :

भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएँ लागू की हैं –



इन योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सुझाव एवं समाधान :

महिला सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने हेतु निम्न उपाय आवश्यक हैं –

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता।
- कौशल विकास प्रशिक्षण।
- समान वेतन और रोजगार अवसर।
- डिजिटल साक्षरता का विस्तार।
- सामाजिक जागरूकता अभियान।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

निष्कर्ष :

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और सतत विकास के लिए महिला सशक्तिकरण अनिवार्य है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी, तभी समाज में वास्तविक समानता स्थापित होगी। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति का आधार है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग है।

संदर्भ सूची :

- भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- नीति आयोग रिपोर्ट, महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक विकास।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) रिपोर्ट।
- UNESCO Report on Gender Equality.
- World Bank Report on Women and Economy.
- शर्मा, आर. (2022). भारतीय अर्थव्यवस्था और महिला विकास। नई दिल्ली : प्रकाशन संस्थान।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 58-6

माध्यमिक स्तर के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं नैतिक मूल्यों में संबंध का एक अध्ययन

कृष्ण बहादुर सिंह, शोधार्थी
शिक्षाशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
डॉ. राममणि द्विवेदी, प्राचार्य
एम.एल.चौरसीया शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश :

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य माध्यमिक स्तर के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं नैतिक मूल्यों के मध्य संबंध का अध्ययन करना है। किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार में मिलने वाला स्नेह, अनुशासन, सहयोग तथा नैतिक वातावरण विद्यार्थियों के व्यवहार एवं मूल्य प्रणाली को प्रभावित करता है।

इस अध्ययन में 10 माध्यमिक विद्यालयों से कुल 600 विद्यार्थियों को नमूने के रूप में चयनित किया गया, जिनमें 300 बालक तथा 300 बालिकाएं शामिल थे। अध्ययन में आंकड़ों के संकलन के लिए मधुलिका वर्मा एवं विन्देश्वरी वक्सर पवार द्वारा निर्मित Personal Values Scale *तथा बीना शाह द्वारा निर्मित* Family Climate Scale *का प्रयोग किया गया। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण माध्य* (Mean), *मानक विचलन* (SD) *तथा* t-test *के माध्यम से किया गया।*

अध्ययन के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों के बीच सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण संबंध पाया जाता है। जिन विद्यार्थियों का पारिवारिक वातावरण सकारात्मक पाया गया, उनमें नैतिक मूल्यों का स्तर भी अपेक्षाकृत अधिक पाया गया।

मुख्य शब्द : पारिवारिक वातावरण, नैतिक मूल्य, माध्यमिक शिक्षा, विद्यार्थी, पारिवारिक प्रभाव।

प्रस्तावना :

शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षा केवल ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और मूल्यों के निर्माण की प्रक्रिया भी है। किसी भी समाज की उन्नति उसके नागरिकों के नैतिक मूल्यों पर निर्भर करती है। यदि समाज में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और अनुशासन का अभाव हो जाए तो समाज का संतुलन

बिगड़ जाता है। विद्यालय शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है, वहीं परिवार उनके जीवन की आधारशिला रखता है। परिवार वह पहला सामाजिक संस्थान है जहाँ बालक जन्म से ही अपने जीवन के प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करता है। परिवार में मिलने वाला वातावरण बालक के व्यक्तित्व के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन के कारण पारिवारिक संरचना और पारिवारिक संबंधों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। संयुक्त परिवारों का स्थान धीरे-धीरे एकल परिवार लेते जा रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास पर भी पड़ रहा है।

नैतिक मूल्य जैसे– सत्य, ईमानदारी, अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता और सामाजिक उत्तरदायित्व किसी भी व्यक्ति के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। इन मूल्यों का विकास मुख्य रूप से परिवार और विद्यालय के संयुक्त प्रयास से होता है। यदि परिवार में सकारात्मक वातावरण हो तो बालक में अच्छे नैतिक मूल्यों का विकास होता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

वर्तमान समय में समाज में नैतिक मूल्यों के ह्रास की समस्या गंभीर रूप से उभर कर सामने आई है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, असहिष्णुता और सामाजिक जिम्मेदारी की कमी देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में यह समझना आवश्यक है कि विद्यार्थियों के नैतिक विकास में कौन-कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। इनमें परिवार का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि परिवार का वातावरण सहयोगपूर्ण, प्रेमपूर्ण और अनुशासित हो तो बालक में सकारात्मक गुणों का विकास होता है।

इस अध्ययन के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि पारिवारिक वातावरण का विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष अभिभावकों, शिक्षकों और शिक्षा नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

समस्या का कथन :

"माध्यमिक स्तर के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं नैतिक मूल्यों में संबंध का अध्ययन।"

अध्ययन के उद्देश्य :

- माध्यमिक स्तर के बालक एवं बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन करना।
- बालक एवं बालिकाओं के नैतिक मूल्यों में अंतर का अध्ययन करना।
- पारिवारिक वातावरण एवं नैतिक मूल्यों के मध्य संबंध का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :

Ho_1: बालक एवं बालिकाओं के नैतिक मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

Ho_2: बालक एवं बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

Ho_3: पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों के मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

अध्ययन की सीमाएं :

1. यह अध्ययन केवल 10 विद्यालयों तक सीमित है।
2. अध्ययन केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों पर किया गया।
3. समय और संसाधनों की सीमाओं के कारण न्यादर्श सीमित रखा गया।

संबंधित साहित्य की समीक्षा :

शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक शोधकर्ताओं ने पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों के संबंध का अध्ययन किया है।

खान, शबनम (2014), ने अपने शोध में पाया कि "पिता के सकारात्मक व्यवहार से आत्मविश्वास बढ़ता है एवं पिता का नकारात्मक व्यवहार बच्चों के आत्मविश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।"

अवस्थी, पूनम एवं खरे, ज्योत्सना (2018), नें "माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के नैतिक मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन" किया। इस अध्ययन में पाया कि माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के नैतिक मूल्य ईमानदारी, लगनशीलता, विनम्रता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया जबकि नैतिक मूल्य मानवता में सार्थक अंतर पाया गया तथा छात्राओं में नैतिक मूल्य मानवता छात्रों की तुलना में उच्च पाए गए ।

Balraj (2025) में पाया गया कि पारिवारिक वातावरण विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों एवं शैक्षिक उपलब्धि दोनों को प्रभावित करता है। जिन विद्यार्थियों का पारिवारिक वातावरण सकारात्मक एवं सहयोगपूर्ण था, उनके नैतिक मूल्य अधिक विकसित पाए गए।

अन्य शोधों में भी यह पाया गया है कि परिवार में माता-पिता का व्यवहार, पारिवारिक अनुशासन और पारिवारिक संबंध बच्चों के नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक वातावरण विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों का प्रमुख निर्धारक है। अधिकांश अध्ययन उच्च शिक्षा स्तर पर केंद्रित हैं। हिंदी माध्यम के माध्यमिक विद्यार्थियों पर विशेष रूप से सीमित शोध उपलब्ध हैं।

इसी कारण प्रस्तुत अध्ययन माध्यमिक स्तर के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों पर केंद्रित होकर इस शोध-अंतर (Research Gap) को पूर्ण करने का प्रयास करता है।

अनुसंधान पद्धति :

शोधार्थी ने अपने शोध कार्य के लिए वर्णनात्मक अनुसंधान विधि के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। सर्वेक्षण विधि का प्रयोग समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक होता है। इस पद्धति के माध्यम से विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण तथा नैतिक मूल्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई।

न्यादर्श :

करलिंगर (1986) ने न्यादर्श को परिभाषित करते हुए कहा कि, "किसी जीव संख्या या समष्टि से उस जीव संख्या के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्शन कहलाता है।"

इस अध्ययन में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों से कुल 400 विद्यार्थियों को नमूने के रूप में चयनित किया गया। जिसमें 200 बालक तथा 200 बालिकाएं हैं।

शोध उपकरण :

अध्ययन में निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया -

1. Personal Values Scale– मधुलिका वर्मा एवं विन्देश्वरी वक्सर पवार
2. Family Climate Scale– बीना शाह

इन उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता पहले से प्रमाणित है।

शोध विधि :

आंकड़ों के विश्लेषण के लिए निम्न सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया – माध्य (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation), टी-परीक्षण (t-test)।

आंकड़ों का संकलन :

शोधकर्ता ने विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों को दोनों स्केल प्रदान किए। विद्यार्थियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए और उनसे ईमानदारी से उत्तर देने का अनुरोध किया गया। सभी उत्तरों को एकत्रित कर सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए व्यवस्थित किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

Ho_1: बालक एवं बालिकाओं के नैतिक मूल्यों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1

नैतिक मूल्यों का माध्य, मानक विचलन एवं t-test

समूह	N	Mean	SD	t-value	सार्थकता स्तर
बालक	200	106.40	22.30	2.01	. 05=1.966
बालिकाएं	200	110.85	21.90		

(Df 398 t value, . 05=1.966, .01=2.587)

व्याख्या - उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालकों का माध्य 106.40 तथा बालिकाओं का माध्य 110.85 है। मानक विचलन क्रमश: 22.30 तथा 21.90 है। प्राप्त t-value 2.01 है, जो स्वतंत्रता की डिग्री मान 398 पर सारणी मान से बहुत ज्यादा है और 0.05 स्तर पर सार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है। यह स्पष्ट होता है कि बालक एवँ बालिकाओ के नैतिक मूल्य मे अंतर पाया जाता है।

Ho_2 : बालक एवं बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2

पारिवारिक वातावरण का विश्लेषण

समूह	N	Mean	SD	t-value	सार्थकता स्तर
बालक	200	98.50	18.75	1.45	. 05=1.966
बालिकाएं	200	101.20	19.10		

व्याख्या - उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बालकों का माध्य 106.40 तथा बालिकाओं का माध्य 110.85 है। मानक विचलन क्रमश: 22.30 तथा 21.90 है। प्राप्त t-value 1.45 है, जो स्वतंत्रता की डिग्री मान 398 पर सारणी मान से बहुत ज्यादा है और 0.05 स्तर पर असार्थक है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है और बालक एवं बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।

Ho_3: पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों के मध्य कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

तालिका 3

पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों के मध्य संबंध

चर	Mean	SD	सहसंबंध (r)
पारिवारिक वातावरण	100.10	18.90	0.62
नैतिक मूल्य	108.60	22.10	

व्याख्या - तालिका में प्राप्त मान r=0.62 यह दर्शाता है कि संबंध स्पष्ट और मजबूत है, पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों के मध्य, मध्यम से उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है। यदि एक चर बढ़ता है तो उसके प्रभाव से दूसरा चर भी बढ़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष :

- बालक एवं बालिकाओं के नैतिक मूल्यों में सार्थक अंतर पाया जाता है।
- बालक एवं बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया।
- पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों के मध्य उच्च स्तर का धनात्मक सहसंबंध है।

शैक्षिक निहितार्थ :

- ❖ अभिभावकों को सकारात्मक पारिवारिक वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- ❖ विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
- ❖ शिक्षक और अभिभावक मिलकर विद्यार्थियों के नैतिक विकास में योगदान दे सकते हैं।
- ❖ विद्यार्थियों के नैतिक विकास के लिए सह-शैक्षिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए।

सुझाव :

1. परिवार में संवाद और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जाए।
2. विद्यालयों में नैतिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
3. विद्यार्थियों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

भावी शोध हेतु सुझाव :

भविष्य में इस प्रकार के अध्ययन बड़े नमूने और विभिन्न क्षेत्रों में किए जा सकते हैं। साथ ही अन्य कारकों जैसे सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विद्यालय वातावरण आदि को भी शामिल किया जा सकता है।

a. ग्रामीण एवं शहरी बालकों के पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों का अध्ययन करना ।

b. ग्रामीण एवं शहरी बालिकाओं के पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों का अध्ययन करना।
c. हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण और नैतिक मूल्यों का अध्ययन करना।

निष्कर्ष :

अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के नैतिक मूल्यों के विकास में पारिवारिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नैतिक मूल्य की किसी व्यक्ति को समाज में एक योग्य नागरिक बना सकता है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है, जो जीवन में धन, स्वास्थ्य और चरित्र के महत्व को दर्शाती है: "धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया"। इसका अर्थ है कि मेहनत से धन और स्वास्थ्य दोबारा पाए जा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ चरित्र और सम्मान कभी वापस नहीं आता।

अतः विद्यार्थियों को उत्तम चरित्रवान बनाना चाहिए जिससे वे अपना अपने परिवार और समाज का विकास कर सके। यदि परिवार का वातावरण सहयोगात्मक, अनुशासित और प्रेमपूर्ण हो तो विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इसलिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए परिवार और विद्यालय दोनों का सहयोग आवश्यक है।

संदर्भ (References)

- कोठारी, सी.आर. (2009) Research Methodology. New Delhi
- सिंह, एस.पी. (2010) Educational Psychology.
- शर्मा, आर.ए. (2011) शिक्षा में अनुसंधान पद्धति. मेरठ.
- अग्रवाल, जे.सी. (2012) शैक्षिक अनुसंधान. नई दिल्ली.
- शर्मा, बी.एन. (2015) Educational Research Methods.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 82-87

National Education Policy 2020 & Experiential Learning in School Education

Dr. Giriraj Bhojak
Assistant Professor, Department of Education,
Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University), Ladnun.

Abstract :

The practical necessity of a child-centered education system has led to a major change in the education system all over the world. The curriculum is being presented to the children in line with real life, so that they can play an active role and participate in their own progress. Keeping this kind of modern education system in mind, the National Education Policy 2020 has emphasized hands-on practice from the foundation level of the education system. By prioritizing children's thinking, curiosity, creative exploration, interest, etc., elements like experiential learning and critical thinking have been given a place in the education policy.

In this study, an attempt has been made to explain how the child's spontaneous and active participation helps in cognitive development, reflective observation being one of the important elements of child-centered education. This study reveals that active engagement positively effect on the confidence, curiosity, and creativity of students. Hands-on activities make children possess the power of reflective observation. That is, active engagement directly and indirectly helps in acquiring problem-solving skills. Critical thinking is necessary to find multifaceted solutions to an incident or problem by delving deeply into it to identify a suitable solution. It is therefore advised that "pedagogy must evolve to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-based, competency-based, discussion-based, flexible and learner-centered." This article will look at different experiential learning methods, their numerous benefits for students, and how the National Education Policy (NEP) 2020 actively encourages their integration into the curriculum.

Key Words : NEP-2020, Experiential learning, critical thinking, rote learning, reflective observation, pedagogy.

Introduction :

In the 21st century, there has been a stir in education all over the world. Almost every country in the world is moving in the same direction, that is, from rote learning to experiential learning and critical thinking. This is a continuous attempt to make education self-sufficient. In the modernization of education, rote learning can never be considered a logical means. Through experiential learning, children acquire knowledge and competence and can reach multidimensional solutions through critical thinking. Experience and practical ideals are not reflected in one-way reading; students often feel frustrated. Experiential learning is an educational approach that emphasizes "learning by doing." It is based on the idea that students learn best when they actively participate in the learning process, which includes hands-on activities, direct experience, and reflection. This method enables students to connect theoretical concepts to real-world applications, thereby making learning more meaningful and effective. Experiential learning helps to decode all the talents that are in the child. According to Kolb (1984), this process is completed in a certain cycle. In the first stage, the student acquires ideas about a subject. In the next stage, reflective observation skills are developed about the subject from different perspectives with the acquired ideas, after which abstracting depends on the analysis and synthesis skills. Concepts are created, and in the final stage, the child applies all these abilities in real life to find solutions to problems.

The student will be able to put his experience into practice only when he is able to directly understand his problem deeply and apply the acquired skills positively. This will help him change his attitude and increase practical skills in real life (Umkabu & Lestari, 2023).

Through experiential learning, students can develop their critical thinking skills and gain a deeper understanding of the dynamics and underlying causes of complex situations and issues. This could lead to better decision-making, more effective problem-solving, and an increased ability to handle ambiguity and complexity in the external environment (Sachdeva & Latesh, 2023). It encourages adaptability, incorporates different learning modalities into full-cycle learning, and fosters the development of practical skills and meta-learning abilities (Kolb & Kolb, 2017).

The growing importance of experiential learning can be attributed to its ability to bridge the gap between theoretical knowledge and real-world application. Schools and educational institutions all over the world are increasingly using this approach to better prepare students for the challenges of the twenty-first century.

Review of Literature :

Golden, B. (2023) studied on "Enabling critical thinking development in higher education through the use of a structured planning tool" The researcher has emphasized on explaining the method

of developing critical thinking. Data has been collected through interviews, surveys, and class work. The information that emerges through data analysis through action research is that attention is a prerequisite for learning something, and critical thinking development of students is possible if the project is properly formulated by creating a suitable environment.

D'Northwood, G., & Rattray, J. (2025) examined "What is this thing called critical thinking? Perspectives from business school academics." in this research paper, the researcher wanted to see how critical thinking affects final year undergraduate students studying in business school. The research work is organized around 3 main themes, critical thinking as skills, critical thinking as dispositions and critical thinking as originality. It has been found that critical thinking skills enable students to make conflict-free, rational and credible decisions. They are inquisitive and take help of different perspectives while thinking about a topic and their principles and ideals will be innovative.

Loaiza Zuluaga, Gil Duque, and Narváez (2020) evaluated "A study of critical thinking in higher education students." The researchers used qualitative research to collect data to determine the level of critical thinking among higher education students. The study reveals that, critical thinking has a significant impact on student motivation and achievement, and students who have high academic achievement and a strong interest in reading have higher levels of critical thinking skills.

Fahim, M., & Ghamari, M. (2011) identified "Critical thinking in education: Globally developed and locally applied." This study was conducted to explore how teaching strategies can help to increase critical thinking and how teachers can apply them. Data was collected using conceptual and analytical research design from various teaching strategies and educational theories. The study revealed that critical thinking can be increased through reflective learning, discussion, questioning.
Experiential Learning and NEP 2020

The National Education Policy (NEP) 2020 has significantly altered the educational landscape in India. It promotes a comprehensive, student-centered method that goes beyond conventional memorization. NEP 2020's emphasis on experiential learning is one of its main features, establishing it as a pillar of contemporary education. NEP 2020 aims to create an educational system that fosters real-world skills and practical knowledge, preparing students for academic success as well as the challenges of life and work in the twenty-first century

To accomplish its objective of creating a comprehensive and diverse educational system, NEP 2020 highlights the importance of experiential learning. The policy places a strong emphasis on the value of giving students engaging, interactive, and practically applicable learning opportunities. NEP 2020 aims to integrate experiential learning into the curriculum and transform classrooms into dynamic spaces where students actively explore, experiment, and discover in order to make learning more

engaging and meaningful.

Curriculum Integration through Experiential Learning :

NEP 2020 supports a curriculum that prioritizes skills and practical knowledge over memorization. To encourage experiential learning, the policy supports field trips, internships, project work, and practical exercises in a range of subjects. For example, social studies classes might incorporate field-based activities.

Activity-Based Education and Principles of Experiential Learning :

Activity-based learning, which is encouraged by NEP 2020, closely resembles the tenets of experiential learning. It motivates teachers to create classes that include tasks that call for observation, introspection, and active participation from the students.It is advised that students engage in cooperative projects, role-plays, and simulations in order to better understand difficult ideas through real-world application as opposed to merely theoretical teaching.

Experience-Based Learning's Effect on Classroom activities :

School education is transformed by experiential learning. Experiential learning promotes a deeper understanding and long-term knowledge retention by involving students in meaningful, active experiences.

Beyond traditional lecture-based teaching methods, experiential learning provides a dynamic learning environment where students can connect abstract concepts to real-world applications, significantly advancing their academic careers.

Contextualizing Experiential Learning with NEP 2020 :

- **Holistic Development :** According to Sarkar (2022), it equips students for lifelong learning. A holistic approach to education fosters the growth of the mind, body, and spirit and is a blessing. NEP 2020 places a strong emphasis on students' overall development, encompassing not only academic performance but also life skills, creativity, critical thinking, problem-solving, and by allowing students to gain practical skills, develop their emotional intelligence, and learn how to apply theoretical knowledge in real-world situations. Experiential learning naturally promotes holistic development. "Holistic Education is the Soul of National Education Policy 2020" is the result.
- **Value of Experience-Based Education :** Experience-based learning makes learning more memorable and relevant by enabling students to interact with the material on a personal level. Experiential learning encourages students to actively participate by exploring, experimenting, and reflecting on their actions, in contrast to passive learning, which treats students as merely recipients of information.

Experiential learning has been found to increase retention rates by triggering several senses

and cognitive functions at once.

- **Multidisciplinary Approach :** By promoting a multidisciplinary approach to education, the policy enables students to investigate a wide range of topics and passions. This method is naturally supported by experiential learning, which gives students the chance to apply their knowledge from different fields in practical settings.
- **Critical Thinking and Problem Solving :** NEP 2020 places a strong emphasis on the value of developing critical thinking and problem-solving abilities. Through the use of real-world problems, situation analysis, and creative problem-solving, experiential learning aims to foster these abilities in students.
- **Teacher Training and Professional Development :** NEP 2020 emphasizes the necessity of ongoing professional development and training for teachers. A change in teaching approaches is necessary for experiential learning, and in order to successfully implement and support experiential learning activities in the classroom, teacher preparation becomes crucial.

Discussion and Conclusion :

According to the literature mentioned above, experiential learning is not a novel approach to teaching, but it does offer a fresh perspective on how our classrooms are set up. In order to engage students in field-based learning experiences, group projects, interdisciplinary research, reflection, and self-analysis, educators are using a growing number of strategies, which suggests that the student, not the teacher, should be at the center of classroom activities. According to Butler et al. (2019), experiential learning is a teaching approach that enables students to "Do, Reflect, Think, and Apply" as they learn. The study looked into a number of crucial areas for experiential learning in real classroom environments, which can undoubtedly aid students in growing in their capacity for creativity, critical thinking, engagement with real-world situations, and concept understanding. The importance of education is frequently questioned in the dynamic world of today. You can show that you can learn through experiential learning, which will improve your chances of finding employment. An innovative step toward a more complete and effective educational system is the inclusion of experiential learning in the National Education Policy (NEP) 2020. By emphasizing theoretical knowledge and practical skills, NEP 2020 recognizes the importance of people's overall development. Apart from enhancing scholastic understanding, experiential learning fosters critical thinking, creativity, and adaptability—qualities that are essential in today's fast-paced,

References :

1. D'Northwood, G., & Rattray, J. (2025). What is this thing called critical thinking? Perspectives

from business school academics. Innovations in Education and Teaching International, 62 (4), 1363–1376.
https://doi.org/10.1080/14703297.2024.2422310

2. Fahim, M., & Ghamari, M. (2011). Critical thinking in education: Globally developed and locally applied. Theory and Practice in Language Studies, 1(11), 1632-1638. https://doi.org/10.4304/tpls.1.11.1632-1638
3. Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906–911. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906
4. Golden, B. (2023). Enabling critical thinking development in higher education through the use of a structured planning tool. Irish Educational Studies, 42(4), 949–969. https://doi.org/10.1080/03323315.2023.2258497
5. Kolb, D. A. (1984). Experimental learning: Experience as the source of learning and development. Prentice-Hall
6. Loaiza Zuluaga, Y. E., Gil Duque, G. M., & Narváez, F. A. D. (2020). A study of critical thinking in higher education students. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos,16(2)
7. Ministry of Education, Government of India. (2020). National Education Policy 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
8. NCERT (2023). National Curriculum Framework for School Education. New Delhi.
9. Sarkar D. NEP 2020 holistic education to reboot society. The New Indian Express [Internet]. 2022 Jul 28 [cited 2025 Jun 28]. Available from: http://www.newindianexpress.com/opinions/2022/jul/28/ nep-2020-holistic-education-to-reboot-society-2481715.html
10. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press. https://www.scribd.com/document/845099157/Vygotsky-1978-Mind-in-Society-Development-of-Higher-Psycholo
11. Yusupaliyeva, I. (2024). Pedagogical conditions and need for the development of critical thinking in students. International Multidisciplinary Journal for Research & Development (IMJRD). https://www.academia.edu/121797306.

Email: drbhojakgiriraj@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 88-94

21वीं सदी की हिन्दी कहानियों में नारी चिन्तन व चुनौतियां

डॉ० कमलेश देवी
सह–प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
गुरु गोरखनाथ जी राजकीय महाविद्यालय, हिसार।

भारतीय संस्कृति के मूल में नारी को 'वामांगी' और 'शक्ति' का साक्षात स्वरूप माना गया है। प्राचीन वेदों और पुराणों के अध्ययन से यह साक्ष्य मिलते हैं कि उसे देवी का उच्चतम दर्जा प्राप्त था, जहाँ उसे पुरुषों के समान ही शिक्षा, उपनयन और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी के अधिकार प्राप्त थे । परंतु कालान्तर में पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने इन अधिकारों को संकुचित कर दिया। छायावाद और उत्तर-छायावाद काल के महान कहानीकारों जैसे जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और जैनेंद्र ने स्त्री के ममतामयी, त्यागी और करुणामयी रूपों को अपनी कालजयी रचनाओं का आधार बनाया। प्रसाद की सुप्रसिद्ध कहानी 'भिखारिन' में माँ का वह निर्मल और वात्सल्यपूर्ण स्वरूप प्रतिबिंबित होता है जो अपनी संतान के सुख के लिए अपना सर्वस्व सहर्ष न्यौछावर कर देता है । इसी प्रकार, प्रेमचंद के कथा-संसार में पत्नी के रूप में स्त्री अक्सर एक अत्यंत असहाय, परवश और मर्यादाओं में बंधी पात्र के रूप में चित्रित हुई है, जो समाज की कृत्रिम सीमाओं की वेदी पर अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की बलि दे देती है ।

परंतु 21वीं सदी की नारी अब केवल समर्पण और मूक सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनकर नहीं रहना चाहती। वह अब पुरुष से प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी के हक और सम्मान की आकांक्षा रखती है। समकालीन कहानियों में यह क्रांतिकारी बदलाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि आधुनिक स्त्री तभी तक पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है जब तक उसे वांछित सम्मान और गरिमा प्राप्त होती है, अन्यथा वह अपनी स्वतंत्र राह चुनने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करती । समाज के बदलते वैश्विक और स्थानीय मूल्यों ने नारी के भीतर एक ऐसी प्रखर चेतना को जन्म दिया है, जिसे अकादमिक जगत में 'स्त्री-विमर्श' के रूप में पहचाना जाता है। यह विमर्श केवल विधिक अधिकारों की प्राप्ति की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सदियों से आरोपित किए गए 'मौन' को तोड़ने का एक सामूहिक और सशक्त प्रयास है ।

मैत्रेयी पुष्पा का कथा-साहित्य 21वीं सदी के स्त्री विमर्श को एक नई दार्शनिक ऊंचाई और ठोस ग्रामीण

धरातल प्रदान करने के लिए जाना जाता है। उनकी कहानियों और उपन्यासों में विशेष रूप से बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचल की स्त्रियाँ अपने अस्तित्व और गरिमा के लिए व्यवस्था से लोहा लेती नजर आती हैं । पुष्पा की रचनाओं में 'अस्मिता' का अर्थ केवल जैविक रूप से जीवित रहना नहीं है, बल्कि अपनी एक स्वतंत्र पहचान और आवाज बनाना है। उनके मील के पत्थर माने जाने वाले उपन्यास 'इदन्नमम' (जिसका अर्थ है—'यह मेरा नहीं है') की मुख्य पात्र 'मंदा' के माध्यम से उन्होंने उस पारंपरिक पितृसत्तात्मक ढांचे को कड़ी चुनौती दी है जो स्त्री को मात्र एक संपत्ति के रूप में देखता है । ग्रामीण समाज में जहाँ स्त्री को प्रायः 'पैर की जूती' के समान निम्न समझा जाता है, वहाँ मंदा, कुसुमा भाभी और सारंग जैसे पात्र अपने मौलिक अधिकारों के लिए निर्भीकता से खड़े होते हैं। कुसुमा भाभी का चरित्र हिन्दी साहित्य में विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो यौन शुचिता के थोपे गए दोहरे मानकों को सिरे से नकारते हुए अपने प्रेम संबंधों और उससे उत्पन्न संतान को सामाजिक निंदा के भय के बिना गर्व से स्वीकार करती है । मैत्रेयी पुष्पा का यह दृढ़ विश्वास है कि नारी की चेतना ही उसे अपने हित और अहित के बीच सूक्ष्म अंतर को समझने की प्रेरणा प्रदान करती है। उनकी कहानियों में स्त्रियाँ केवल चौके-चूल्हे तक सीमित नहीं हैं; वे खेतों में कठोर श्रम करती हैं, पंचायतों की जटिल राजनीति में सक्रिय भाग लेती हैं और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर लेती हैं । 'अल्मा कबूतरी' उपन्यास में लेखिका ने कबूतरा जनजाति की स्त्रियों के बहुआयामी संघर्ष को स्वर दिया है। इस उपन्यास की नायिका 'अल्मा' अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए उस पुरुष प्रधान समाज द्वारा किए गए अवमूल्यन से सीधे टकराती है जो उसकी जाति को 'जन्मजात अपराधी' मानता है । अल्मा यह सिद्ध करती है कि उच्च शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन ही वे अमोघ अस्त्र हैं जिनके माध्यम से स्त्रियाँ अपनी सदियों पुरानी बेड़ियों को छिन्न-भिन्न कर सकती हैं। पुष्पा का संपूर्ण साहित्य यह सार्वभौमिक संदेश प्रसारित करता है कि संघर्षशील स्त्री का कोई संकुचित धर्म या जाति नहीं होती, वह केवल एक संकल्पवान व्यक्तित्व है जो समाज की सड़ी-गली और मृतप्राय परंपराओं के विरुद्ध निरंतर युद्धरत है ।

चित्रा मुद्गल 21वीं सदी की हिन्दी कथा साहित्य की एक ऐसी अत्यंत सशक्त और संवेदनशील हस्ताक्षर हैं जिन्होंने आधुनिक कामकाजी स्त्री के आंतरिक अंतर्द्वंद्व और बाह्य सामाजिक दबावों को अत्यंत सूक्ष्मता एवं

ईमानदारी से उकेरा है । आज की शिक्षित और महत्वाकांक्षी नारी घर की देहलीज़ को पार कर बाहर की दुनिया में तो निकल गई है, परंतु समाज की सामूहिक मानसिकता अभी भी उसे घर की चहारदीवारी के भीतर ही मानसिक रूप से कैद देखना चाहती है। मुद्गल जी की कहानियों में कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थलों पर व्याप्त असुरक्षा, लैंगिक भेदभाव और निरंतर मानसिक दबाव का सामना करते हुए दिखाया गया है । उनका उपन्यास 'एक जमीन अपनी' विज्ञापन और ग्लैमर जगत के उस कड़वे और स्याह सच को निर्दयता से उजागर करता है जहाँ महिलाओं का दैहिक और मानसिक शोषण एक सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया मान लिया गया है । उपन्यास की नायिका 'अंकिता' अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर करियर में शीर्ष पर पहुँचना चाहती है, परंतु पुरुष मानसिकता उसे हमेशा अपने अधीनस्थ एक 'वस्तु' या 'जिस्म' के रूप में ही देखना पसंद करती है । यहाँ स्त्री के लिए घर की शांति, संतान का सुख और सच्चा प्रेम एक धुंधले स्वप्न की भांति हैं, जिसे वह विज्ञापन की रंगीन, चकाचौंध भरी लेकिन खोखली दुनिया के बीच व्यग्रता से खोजने का असफल प्रयास करती है । कामकाजी स्त्री के लिए 'दोहरी जिम्मेदारी' का बोझ 21वीं सदी की सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती बनकर उभरा है। 'पाली का आदमी' जैसी मर्मस्पर्शी कहानियों में एक माँ अपनी नौकरी की व्यस्तता के कारण अपनी छोटी बेटी को पर्याप्त समय नहीं दे पाती, जिसके फलस्वरूप वह निरंतर आत्मग्लानि, अपराधबोध और तीव्र तनाव की स्थिति में रहती है । चित्रा मुद्गल का साहित्य निरंतर यह रेखांकित करता है कि जब स्त्री आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होती है, तो समाज में उसका आत्मसम्मान तो अवश्य बढ़ता है, परंतु अक्सर उसके जीवनसाथी का 'पुरुष अहम्' आहत हो जाता है, जिससे सुखी वैवाहिक जीवन में बिखराव और अलगाव की स्थितियाँ उत्पन्न होने लगती हैं ।

अलका सरावगी ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से मध्यम और उच्च-मध्यम वर्गीय मारवाड़ी समाज की महिलाओं के जटिल आंतरिक जीवन और बाह्य सामाजिक प्रतिबंधों को अत्यंत बारीकी से उद्घाटित किया है । उनके उपन्यासों में इतिहास की गूँज, परंपरा का मोह और आधुनिकता का संत्रास एक साथ गुंफित मिलता है। 'कलि-कथा : वाया बाइपास' में उन्होंने एक मारवाड़ी परिवार की छह पीढ़ियों की कथा के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे समय बदलने के बावजूद स्त्रियों की घुटनभरी अंधेरी दुनिया में विशेष परिवर्तन नहीं आया है । उनके पात्र अक्सर इतिहास और वर्तमान के बीच एक सेतु की भांति कार्य करते हैं, जो पुरानी रूढ़ियों को

तोड़कर एक नया 'बाइपास' या रास्ता खोजने की छटपटाहट महसूस करते हैं । 'शेष कादम्बरी' में सरावगी ने नारी मन की कोमल भावनाओं, पारिवारिक उपेक्षा और दमन की विभीषिका के बीच के संघर्ष को स्वर दिया है । उनकी नायिकाएं शिक्षित और बौद्धिक रूप से सक्षम हैं, फिर भी उन्हें पितृसत्तात्मक संरचनाओं के भीतर अपनी पहचान के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। सरावगी के उपन्यासों में 'समय' और 'स्मृति' के आयाम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं; वे पात्रों को उनकी जड़ों से जोड़ते हुए उन्हें भविष्य की अनिश्चितताओं से लड़ने का साहस प्रदान करते हैं । उनकी रचनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि 21वीं सदी की स्त्री अब अपनी देह और अपनी अस्मिता पर समाज द्वारा लगाए गए प्रश्नचिन्हों के उत्तर किसी अन्य से नहीं चाहती, बल्कि वह स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर इन्हें परिभाषित करना चाहती है ।

आज का मानव जीवन अत्यंत जटिल, यांत्रिक और उलझा हुआ हो गया है, जहाँ नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। रिश्तों में आने वाला अचानक बिखराव और दमित यौन कुंठाएँ समकालीन हिन्दी कहानियों के प्रमुख और अनिवार्य विषय बन गए हैं । 21वीं सदी की नारी अब अपने अधिकारों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक है, बल्कि वह उन सड़ी-गली परंपराओं के कारागार से निकलने की तीव्र छटपटाहट भी महसूस कर रही है जो उसे विकास की दौड़ में पीछे धकेलती रही हैं । यौन स्वायत्तता और देह विमर्श के संदर्भ में 21वीं सदी का साहित्य अत्यंत मुखर और बेबाक हुआ है। कृष्णा सोबती की 'मित्रो मरजानी' ने इस दिशा में दशकों पहले एक क्रांतिकारी नींव रख दी थी, लेकिन आज की कहानियों में यह विचार और भी अधिक स्पष्ट, तर्कसंगत और निर्भीक होकर उभरा है । सुधा अरोड़ा की कहानी 'मरी हुई चीज़', ममता कालिया की 'ज़िंदगी सात घंटे बाद की' और कृष्णा सोबती की रचनाएँ नारी के उस सबल रूप को चित्रित करती हैं जो अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं और अपनी देह पर केवल अपना ही संप्रभु अधिकार समझती हैं । 'खानाबदोश ख्वाहिशें' की नायिका 'निधि' जैसे पात्र अपनी शारीरिक जरूरतों और यौन इच्छाओं के बारे में बिना किसी हिचक के बात करते हैं और वे इसके लिए समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कृत्रिम अफसोस या ग्लानि महसूस नहीं करते ।

हालांकि, इस चेतना और जागरूकता के बीच एक अत्यंत कटु और भयावह यथार्थ यह भी है कि महिलाओं के प्रति होने वाले जघन्य अपराधों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है । कन्या भ्रूण हत्या जैसे क्रूर षड्यंत्र आज भी

समाज के शिक्षित और संपन्न वर्गों में रचे जा रहे हैं, जिसे अलका सरावगी ने अपनी कहानी 'आक एगारसी' में अत्यंत मर्मस्पर्शी और दहला देने वाले ढंग से चित्रित किया है । महादेवी वर्मा ने बहुत पहले यह भविष्यद्रष्टा कथन कहा था कि जिस दिन भारतीय नारी अपनी पूरी प्राण-शक्ति और चेतना से जाग उठेगी, उसकी प्रगति की गति को रोकना किसी भी सत्ता के लिए असंभव होगा । आज की हिन्दी कहानियाँ इसी महान जागृति का जीवंत प्रमाण हैं, जहाँ नारी ने अपनी कलम को एक धारदार हथियार बनाकर सामाजिक अन्याय और लिंग-भेद के विरुद्ध निर्णायक युद्ध छेड़ दिया है ।

21वीं सदी के तीसरे दशक में पदार्पण करते समय हिन्दी साहित्य का स्वरूप और उसकी पहुँच डिजिटल क्रांति के प्रभाव से पूरी तरह रूपांतरित हो गई है। डिजिटल माध्यमों, व्यक्तिगत ब्लॉग्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स) ने महिला लेखिकाओं को एक ऐसा नया, वैश्विक और स्वतंत्र मंच प्रदान किया है जहाँ वे बिना किसी सेंसरशिप, संपादकीय कैंची या पारंपरिक प्रकाशकों की बाधा के अपनी बात सीधे पाठकों के विशाल समुदाय तक पहुँचा रही हैं । डिजिटल युग ने साहित्य के सृजन और प्रकाशन का 'लोकतंत्रीकरण' कर दिया है । 'इन्स्टापोएट्री' और ऑनलाइन पत्रिकाओं के माध्यम से आज की नारी उन विषयों पर भी अत्यंत साहस के साथ लिख रही है जिन्हें पारंपरिक समाज में 'वर्जित' माना जाता था—जैसे मासिक धर्म, मानसिक स्वास्थ्य, वैवाहिक बलात्कार और यौन स्वायत्तता । सोशल मीडिया ने स्त्रियों को न केवल अभिव्यक्ति का अवसर दिया है, बल्कि उन्हें सामूहिक रूप से संगठित होने और अपनी मांगों को वैश्विक पटल पर रखने की शक्ति भी प्रदान की है। दिल्ली के 'निर्भया कांड' के बाद उभरा आक्रोश हो या 'पीरियड टैक्स' के विरुद्ध छेड़ा गया अभियान, ऑनलाइन मंचों ने शासन और प्रशासन को ठोस सामाजिक बदलावों और कानून निर्माण के लिए विवश किया है । परंतु, इस असीमित डिजिटल स्वतंत्रता के अपने अंतर्निहित खतरे और चुनौतियां भी हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय महिलाओं को अक्सर कुत्सित मानसिकता, संगठित ट्रोलिंग, बॉडी शेमिंग और साइबर-बुलिंग का शिकार होना पड़ता है । पुरुष प्रधान समाज का वह विद्वेष जो गलियों और चौराहों पर दिखता था, अब डिजिटल दुनिया के अदृश्य कोनों में अपनी जगह बना चुका है। इसके बावजूद, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि डिजिटल मीडिया ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं में आत्मविश्वास, विधिक जागरूकता और अपनी पहचान के प्रति स्वाभिमान को बढ़ाने में

युगांतरकारी भूमिका निभाई है ।

अत्यंत समीचीन होगा कि यद्यपि नर और नारी एक-दूसरे के नैसर्गिक पूरक हैं, परंतु आज की नारी अपनी इस पूरकता के साथ-साथ अपनी स्वतंत्र सत्ता, अपनी बुद्धि और अपने अस्तित्व के प्रति भी अत्यंत सचेत है । वह अब केवल दूसरों की इच्छाओं के सांचे में ढलने वाली मिट्टी का निर्जीव ढेला नहीं रह गई है, बल्कि वह स्वयं को गढ़ने वाली एक सजग मूर्तिकार बन गई है जो अपनी नियति के स्वर स्वयं लिखना जानती है । वर्तमान समाज के सम्मुख जो चुनौतियां उभर रही हैं, उनमें सबसे प्रमुख 'सामाजिक मानसिकता का धीमा परिवर्तन' है। भारतीय संविधान और विधिक तंत्र ने यद्यपि नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान कर दिए हैं, परंतु व्यवहारिक धरातल पर आज भी पितृसत्तात्मक ग्रंथियाँ उसे 'दोयम दर्जे का नागरिक' मानने की अपनी आदिम प्रवृत्ति को त्याग नहीं पाई हैं । विशेषकर उच्च शिक्षित और कामकाजी महिलाओं के संदर्भ में, घर के कार्यों में पुरुष का सहयोग आज भी केवल एक 'उपकार' के रूप में देखा जाता है, जबकि घर की संपूर्ण व्यवस्था और बच्चों की परवरिश का अंतिम उत्तरदायित्व आज भी महिला के कंधों पर ही टिका है । यह विडंबनापूर्ण स्थिति महिलाओं में निरंतर 'अपराधबोध' (Guilt) और गहराते 'मानसिक अवसाद' को जन्म दे रही है।

एक अन्य गंभीर चुनौती 'बाजारवाद' और 'उपभोक्ता संस्कृति' का वह प्रछन्न प्रभाव है जो स्वतंत्रता के नाम पर नारी को एक नए प्रकार के वैश्विक बाजारीकरण का शिकार बना रहा है। समकालीन कहानियों में इस कड़वे सच को भी दिखाया गया है कि कैसे विज्ञापन जगत और कॉर्पोरेट तंत्र स्त्री की मुक्ति को केवल उसके 'देह-प्रदर्शन' तक सीमित करने का कुचक्र रचते हैं । अति-आधुनिकता की अंधी दौड़ और पाश्चात्य संस्कृति के बिना सोचे-समझे अनुकरण के कारण पारिवारिक ढांचों में जो दरारें आ रही हैं और मानवीय मूल्यों का जो निरंतर क्षरण हो रहा है, वह भी 21वीं सदी की कहानी का एक चिंताजनक पक्ष है ।

नारी का सर्वांगीण उत्थान ही वास्तव में एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज का वास्तविक उत्थान है। हिन्दी कथा-साहित्य इस गौरवमयी और चुनौतीपूर्ण यात्रा का सबसे विश्वसनीय और निष्पक्ष गवाह है, जो आज यह सप्रमाण घोषित कर रहा है कि 21वीं सदी की नारी अब किसी पुरुष की प्रतिछाया बनकर रहने को तैयार नहीं है, बल्कि वह अपनी आंतरिक चमक से अपना मार्ग स्वयं प्रकाशित कर रही है । शोध और अकादमिक दृष्टि से ये कहानियाँ न केवल उच्च साहित्यिक मूल्य धारण करती हैं, बल्कि वे उस महान समाजशास्त्रीय परिवर्तन

की धारा को भी रेखांकित करती हैं जो भविष्य के एक अधिक समतामूलक, न्यायसंगत और गरिमापूर्ण वैश्विक समाज की आधारशिला रखेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. महाभारत आदिपर्व 74/41
2. महाभारत आदिपर्व 74/75
3. प्रसाद, भिखारिन, आकाशदीप, पृ० 67
4. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, गयारह वर्ष का समय (सम्पादक) देवेश ठाकुर कथाक्रम, भाग 1, पृ० 94
5. प्रसाद, चूड़ीवाली, आकाशदीप, पृ० 134
6. आचार्य चतुरसेन शास्त्री, "दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी", (सम्पादक) जैनेन्द्र कुमार तेईस हिन्दी कहानियाँ, पृ० 88
7. जनकृति ।.(2021, March 6). इक्कीसवीं सदी की हिंदी कहानियों में स्त्री की बदलती सामाजिक छवि. JANKRITI. https://jankriti.com/kahani-mein-stri/
8. मिश्रा, आर. (2023, June 28). इदन्नमम: तीन पीढ़ी की स्त्रियों का अंतर्विरोध और उनकी अस्मिता का संघर्ष दर्ज करता उपन्यास. फेमिनिज़म इन इंडिया. https://hindi.feminisminindia.com/2023/06/29/idannamam-by-maitreyi-pushpa-review-hindi/
9. उर्मिला भगत, अल्मा कबूतरी में चित्रित सामाजिक संस्थाएं : स्वरूप व कार्त्मकता, https://shikshansanshodhan.researchculturesociety.org/wp-content/uploads/SS202102003.pdf

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 95–98

ग्रामीण महिलाओं में महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

सुशीला, शोधकर्त्री
डॉ. रेखा खण्डेलवाल, सहायक आचार्या
श्री बालाजी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जयपुर।

1. **सारांश :**

भारतीय समाज में ग्रामीण महिलाएं सामाजिक और आर्थिक ताने–बाने की रीढ़ होने के बावजूद आज भी पितृसत्तात्मक मानसिकता, अशिक्षा और सदियों पुरानी सामाजिक कुरीतियों के कारण विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को समानता और गरिमा का अधिकार दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर ग्रामीण परिवेश में हालात अब भी चिंताजनक हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961 और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न सुसंगत धाराओं जैसे कई कड़े और प्रभावी कानून बनाए हैं। इन कानूनों के तहत न केवल अपराधियों को कड़े दंड का प्रावधान है, बल्कि राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता और परामर्श देने की व्यवस्था भी की गई है। इसके बावजूद, यह एक कड़वी सच्चाई है कि जब तक इन कानूनों के प्रावधानों के प्रति स्वयं ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता नहीं होगी, तब तक इन विधायी प्रयासों का वास्तविक और अपेक्षित लाभ उन तक नहीं पहुँच सकता। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए यह शोध पत्र ग्रामीण महिलाओं में कानूनी साक्षरता के वास्तविक स्तर को मापने, उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं को रेखांकित करने और इस स्थिति में सुधार के व्यावहारिक समाधान खोजने का प्रयास करता है।

तकनीकी शब्दावली :

ग्रामीण, महिला, महिला उत्पीड़न, संबंधित कानूनी प्रावधान, के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

1. **प्रस्तावना :**

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मानसिकता, अशिक्षा और सामाजिक कुरीतियों के कारण महिलाएं आज भी विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न (शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन) का सामना कर रही हैं। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन जब तक ग्रामीण महिलाओं में इन कानूनी प्रावधानों के प्रति

जागरूकता नहीं होगी, तब तक इन कानूनों का वास्तविक लाभ उन तक नहीं पहुँच सकता। यह शोध पत्र ग्रामीण महिलाओं में कानूनी जागरूकता के स्तर, उनके मार्ग में आने वाली बाधाओं और इसमें सुधार के उपायों का विश्लेषण करता है।

2. शोध के उद्देश्य :

- ग्रामीण महिलाओं में महिला उत्पीड़न रोधी कानूनों के प्रति जागरूकता के स्तर का मूल्यांकन करना।
- विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कारकों (जैसे शिक्षा, आयु, जाति) का जागरूकता पर प्रभाव जानना।
- ग्रामीण महिलाओं द्वारा कानूनी सहायता न ले पाने के प्रमुख कारणों (बाधाओं) की पहचान करना।
- कानूनी साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रभावी सुझाव प्रस्तुत करना।

3. प्रमुख कानूनी प्रावधान :

भारत में महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून लागू हैं, जिनकी जानकारी हर ग्रामीण महिला को होनी चाहिए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कानून निम्नलिखित है –

- **हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 :–** इस कानून के अन्तर्गत घरेलू दायरे में होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और निवास का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), पूर्व में IPC धारा 498 A :–** इस कानून के अन्तर्गत पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) :–** इस कानून के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने (यह असंगठित और कृषि क्षेत्र की महिलाओं पर भी लागू है) का प्रावधान किया गया है।
- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 :–** इस कानून के अन्तर्गत दहेज लेने, देने या इसके लिए उकसाने को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का प्रावधान किया गया है।
- **मुफ्त कानूनी सहायता (NALSA/SALSA) :–** इस कानून के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर या पीड़ित महिलाओं को सरकार की तरफ से मुफ्त वकील और कानूनी सलाह की सुविधा प्रदान किया गया है।

4. अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष :

ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षणों और अध्ययनों के आधार पर सामान्यतः निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आते हैं –

- **सीमित ज्ञान :–** अधिकांश ग्रामीण महिलाओं ने 'घरेलू हिंसा' या 'दहेज कानून' के बारे में सुन रखा है, लेकिन वे इसके तहत मिलने वाले अधिकारों (जैसे– शिकायत कहाँ करें, मुफ्त कानूनी सहायता) से पूरी तरह अनजान हैं।
- **शिक्षा का प्रभाव :–** साक्षर और युवा महिलाओं में निरक्षर या बुजुर्ग महिलाओं की तुलना में कानूनी जागरूकता का स्तर काफी बेहतर पाया गया।
- **शिकायत न करने के कारण :–** कानून की जानकारी होने पर भी महिलाएं सामाजिक बदनामी,

लोक–लाज, आर्थिक निर्भरता और पुलिस–अदालत के चक्कर काटने के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराती।

- **माध्यमों की कमी :–** ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविरों की भारी कमी है। सूचना का मुख्य स्रोत टीवी या मोबाइल हैं, जिनका उपयोग भी सीमित है।

5. कानूनी जागरूकता में प्रमुख बाधाएं :

- **अशिक्षा और सूचना का अभाव :–** कानूनी भाषा का जटिल होना और स्थानीय भाषा में सरल प्रचार सामग्री का न होना।
- **सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव :–** ''घर की बात घर में रहे'' वाली मानसिकता और समाज द्वारा पीड़िता को ही दोषी ठहराना।
- **प्रशासनिक उदासीनता :–** ग्रामीण स्तर पर पुलिस और पंचायत का रवैया कई बार संवेदनशील नहीं होता, जिससे महिलाएं मदद मांगने से कतराती हैं। आर्थिक निर्भरताः स्वयं आत्मनिर्भर न होने के कारण महिलाएं प्रताड़ना सहने को मजबूर हो जाती हैं।

6. सुझाव एवं समाधान :

ग्रामीण समाज में वास्तविक बदलाव लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने आवश्यक हैं :–

- **नियमित कानूनी साक्षरता शिविर :–** राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA/SALSA) द्वारा ग्राम पंचायतों के सहयोग से हर गाँव में नियमित अंतराल पर सरल भाषा में शिविर लगाए जाए।
- **आंगनवाड़ी और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका :–** ग्रामीण स्तर पर काम कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहुओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को कानूनी रूप से प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं इन पर आसानी से भरोसा करती हैं।
- **डिजिटल और दृश्य–श्रव्य माध्यम :–** नुक्कड़ नाटक, रेडियो, और मोबाइल कूट संदेशों के जरिए स्थानीय बोलियों में कानूनों का प्रचार–प्रसार हो।
- **पुलिस और प्रशासन का संवेदीकरण :–** ग्रामीण थानों में महिला हेल्प डेस्क को अधिक सक्रिय और संवेदनशील बनाया जाए ताकि पीड़ित महिला बिना किसी डर के अपनी बात कह सके।
- **आर्थिक सशक्तिकरण :–** महिलाओं को कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें।

निष्कर्ष :

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कागजों पर कड़े कानून होने के बावजूद ग्रामीण भारत में महिला उत्पीड़न पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जागरूकता की भारी कमी है। कानूनी अधिकार केवल अदालत की फाइलों तक सीमित न रहकर हर ग्रामीण महिला की जुबान और समझ में होने चाहिए। जब तक ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी रूप से सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक एक समतामूलक और सुरक्षित समाज की कल्पना अधूरी है।

''**सशक्त महिला, समर्थ समाज और सुरक्षित राष्ट्र की आधारशिला है।**''

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :

- अग्रवाल, जे. सी. (2018) : ''आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं'' विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
- अवस्थी, पी. (2021) : ''ग्रामीण भारत में महिला अधिकार और कानून'' कॉलेज बुक हाउस, जयपुर।
- कुमार, नरेंद्र (2019) : ''भारतीय समाज में महिला उत्पीड़न : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
- गुप्ता, आर. के. (2022) : ''घरेलू हिंसा और महिला संरक्षण कानून. विधि साहित्य प्रकाशन, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार।
- जैन, सुमिता (2020) : ''ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण'' शिक्षा प्रकाशन, जयपुर।

डॉ. मनोज कुमार
सहायक आचार्य
श्री बालाजी पी. जी. महाविद्यालय, जयपुर
Kumarmanoj381f@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 99-101

तारीख-ए-फिरोजशाही--जियाउद्दीन बरनी

आकाश गुप्ता
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

तुगलककालीन इतिहास लेखन में बरनी की व्यक्तिपरकता (Subjectivity) और रूढ़िवादिता (Orthodoxy) का समीक्षात्मक अध्ययन।

बरनी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं तथा इतिहास के महत्व, उसके लाभ, इतिहास की विशेषता, इतिहासकार के कर्तव्य और इतिहास की रचना की शर्तों का उल्लेख तारीख–ए–फिरोजशाही की भूमिका में स्वयं करते हुए लिखते हैं कि 'इतिहास की रचना करते समय सबसे बड़ी शर्त जो कि इतिहासकार के लिए उसकी धर्मनिष्ठता को देखते हुए आवश्यक है, यह है कि बादशाही की प्रतिष्ठा, गुणों, उत्तम बातों, न्याय और नीतियों का उल्लेख करें। उसे यह भी चाहिए कि उसकी बुरी बातों और अनाचार को ना छुपाए, इतिहास लिखते समय पक्षपात ना करें।'[1]

परंतु तुगलककालीन तीनों शासकों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर उनके इतिहास लेखन के यह विचार पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत नहीं होते। यदि हम इस पुस्तक का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि बरनी ने अपने विचार अनुकूल तथा रूढ़ीवादी विचारों से ग्रस्त होकर समय–समय पर राजाओं का अपने अनुसार पक्ष प्रस्तुत किया है, तथा कुछ तथ्यों को जानबूझकर छुपाने की कोशिश की है। जैसे कि जब भी कोई महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने की बात होती है, चाहे वह शासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित हो, वह यह कथन कहते हैं कि यदि 'मैं इस कार्य का सविस्तार उल्लेख करूं तो यह हाल बड़ा विस्तृत हो जाएगा और इससे मेरे उद्देश्यों की पूर्ति ना हो सकेगी'। उदाहरण स्वरूप मोहम्मद–बिन–तुगलक कि दान व्यवस्था का उल्लेख करते हुए जब बरनी दिल्ली के खजाने को होने वाली हानी की बात छुपाते हैं तब वह इस कथन का सहारा लेते हैं।[2]

इसके अतिरिक्त यदि सभी सुल्तानों की समान नीतियों के द्वारा उनके शासन प्रबंध पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाए, तब भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, किस प्रकार बरनी ने तथ्यों का इस्तेमाल त्रुटिपूर्ण रूप में किया है उदाहरण के लिए यदि हम तीनों शासकों द्वारा दिए गए दान व्यवस्था को आधार मानते हैं। तो यह निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि बर्नी ने गयासुद्दीन तुगलक तथा फिरोज तुगलक द्वारा दिए गए दान को आदर्शमय प्रस्तुत किया है। तथा उनके दान व्यवस्था कि बढ़–चढ़कर प्रशंसा की है। लेकिन मोहम्मद

---

1. सैयद अतहर अब्बास रिजवी, तुगलक कालीन भारत भाग 1, अनुवादित ग्रंथों की समीक्षा, P-x।
2. Ishtiyaq Ahmad Zilli, Tarikh_i_Firoz Shahi, P-289.

बिन तुगलक के लिए इसे विद्रोह के एक बहुत बड़े कारण के रूप में दर्शाया है।[3]

यदि सुल्तानों द्वारा दिए गए दंड को आधार बनाया जाए, तब भी इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल अभियान के विद्रोहियों को सूली पर चढ़ाया तथा उनके स्त्री और बच्चों को हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया। तब बरनी ने इसकी भर्त्सना नहीं की, परंतु मोहम्मद–बिन–तुगलक के समय होने वाले विद्रोह का विवरण देते हुए वह बताता है कि विद्रोह का एक मुख्य कारण मोहम्मद तुगलक द्वारा दिए जाने वाले कठोर दंड थे। जिससे प्रजा घृणा करने लगी थी और इस वजह से ज्यादा विद्रोह भड़क उठे थे। जबकि यदि फिरोज तुगलक के समय होने वाले लखनौती के विद्रोह के विवरण पर नजर डालें तो बरनी कहता है कि 'लखनौती के शासक इलियास की जिसके मस्तिष्क में सरदारी का अभिमान भरा था और जो, इस्लामी सेना से युद्ध करने निकला था। इस्लामी सेना ने उसके समस्त सहायकों, मित्रों, अश्वरोहियों, एंव पदातियों को पराजित तथा तहस–नहस कर डाला, विद्रोहियों तथा उपद्रवियों का अभिमान समाप्त कर दिया, रक्त की नदियां बहा दी।'[4] अर्थात यहां बरनी द्वारा इस कार्य की प्रशंसा की गई है।

एक अन्य अंतर प्रशासनिक नियुक्तियों के रूप में भी देखा जा सकता है। जब गयासुद्दीनतुगलक पुराने वज़ीर (ख्वाजा अतीक, मलिकुल जुनैदी तथा ख्वाजा मुहज़्जब बुजुर्ग) को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित करता है तथा नई नियुक्तियां करता है, जिसके लिए बरनी कहता है कि उसने ऐसे लोगों को अपने राज्य का सहायक तथा विश्वासपात्र बनाया एवं पद तथा इक्ता प्रदान की जिनके द्वारा राज्य व्यवस्था तथा शासन प्रबंध को शोभा प्राप्त हो सकती थी और सर्वसाधारण के हृदय में किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न ना हो सकती थी। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई नियुक्तियों के लिए वह कहता है कि वह जिस प्रकार बड़े–बड़े पद, बड़ी विलायतों तथा प्रदेशों का शासन प्रबंध कमीनों, तुच्छ लोगों को प्रदान करता था उससे प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य होता था। जबकि फिरोज तुगलक द्वारा की गई नियुक्तियों के लिए वह कहता है कि दरबार के सहायक विश्वासपात्र तथा पदाधिकारी और विलायतों के मुक्ते तथा वली सभी सदाचारी, परोपकारी, न्याय कार्य तथा इंसाफ पसंद चुने जाते थे और किसी भी दुष्ट अत्याचारी तथा ईश्वर का भय ना करने वाले को नेतृत्व एवं सम्मान ना प्रदान किया जाता था।[5]

अब यदि इस व्यक्तिपरकता की खोज की जाए तो हम इसे बरनी के रूढ़िवादी विचारों के निष्कर्ष के तौर पर देख सकते हैं कि क्यों बरनी अपने लेखन में इतनी विभिनता लिए हुए हैं, दरअसल गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल को महिमामंडित करने के पीछे मुख्य कारण खुसरो खाँ के शासन की समाप्ति है जो कि एक हिंदुस्तानी मुसलमान था और नस्लीय श्रेष्ठता के अनुकूल नहीं था। जिसके शासन समाप्ति से बरनी अत्यंत खुश था।[6]

मोहम्मद–बिन–तुगलक के कार्यकाल को अधिक प्रखरता से लिखने के पीछे मुख्य कारण उसकी मुसलमानों

---

3. Ibid, P-276.
4. bid, P-363.
5. Ibid, P-262.
6. Ibid, P-310-311.

को देने वाली मृत्यु दंड की सजा तथा हिंदुस्तानी और निम्न श्रेणी के लोगों को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त करना था। और इसके लिए वह साद मन्तकी, उबैद कवि, नज्मइनतेशार फलसफी को जिम्मेदार ठहरता है तथा लिखता है कि मौलाना अलीमुद्दीन जोकि बहुत बड़ा फलसफी (दार्शनिक) था। उसके साथ एकांत में रहा करता था।[7]

जबकि यदि फिरोज तुगलक के शासनकाल की बात की जाए तो बरनी द्वारा दिए गए सभी सुल्तानों के विवरणों में यह सबसे प्रशंसनीय तथा रोचक है। बरनी लिखता है कि सुल्तान मुइज़्जुद्दीन मोहम्मद साम के उपरांत समय तथा युग के बादशाह सुल्तान फिरोजा के समान कोई भी शिष्ट सज्जन, कृपालु, दयालु, दूसरों के अधिकार पहचानने वाला तथा कर्तव्यनिष्ठ इस्लाम के नियमों में दृढ़ तथा पवित्र विश्वास रखने वाला बादशाह दिल्ली के राज सिंहासन पर अरुण नहीं हुआ है। तथा इस पुस्तक के शीर्षक से भी यह बात स्पष्ट होती है। बरनी मुख्य रुप से फिरोज तुगलक के लिए ही अपना लेखन कार्य कर रहा था।[8]

इस प्रकार बरनी की तारीख–ए–फिरोजशाही का अध्ययन करते समय पाठकों को इस विचार से सतर्क रहना चाहिए कि, बरनी ने नस्लीय भेदभाव तथा इस्लामिक सर्वोच्चता को अपने लेखन कार्य में काफी स्थान दिया है। इसलिए कहीं कहीं यह बहुत अधिक कट्टरवादीता को प्रदर्शित कर देता है। परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि जिस समयकाल में यह रचना लिखी गई वह इसके स्वरुप के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था। इसलिये इसके अध्ययन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।[9]

BIBLIOGRAPHY :

1. Ishtiyaq Ahmad Zilli, Tarikh_i_Firoz Shahi.
2. सैयद अतहर अब्बास रिजवी, तुगलक कालीन भारत, भाग 1.
3. सैयद अतहर अब्बास रिजवी, तुगलक कालीन भारत, भाग 2.

---

7. Ibid, P-353.
8. Ibid, P-286.
9. Ibid, P-336.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 102–107

राजस्थान की जलवायु

हेमाराम जाट
सुपुत्र श्रवण राम
गांव नराधणा, तहसील जायल, जिला नागौर।

भूमिका :

राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का अधिकांश भाग थार मरुस्थल से आच्छादित है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु मुख्यतः शुष्क एवं अर्ध–शुष्क है। राजस्थान की जलवायु पर भौगोलिक स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला, थार मरुस्थल तथा दक्षिण–पश्चिम मानसून का विशेष प्रभाव पड़ता है। जलवायु किसी भी प्रदेश की कृषि, वनस्पति, पशुपालन, उद्योग, जनजीवन तथा आर्थिक विकास को प्रभावित करती है।

जलवायु का अर्थ :

किसी स्थान पर लगभग 30 वर्षों तक मौसम की औसत दशाओं का अध्ययन जलवायु कहलाता है। इसमें तापमान, वर्षा, वायु, आर्द्रता, वायुदाब तथा मौसम के अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं।

राजस्थान की जलवायु की प्रकृति :

राजस्थान की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय (Tropical Desert Climate) है। राज्य के पश्चिमी भाग में शुष्क मरुस्थलीय जलवायु तथा पूर्वी और दक्षिण–पूर्वी भागों में अर्ध–शुष्क से उप–आर्द्र जलवायु पाई जाती है।

राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक :

1. **भौगोलिक स्थिति :**

राजस्थान भारत के उत्तर–पश्चिम भाग में स्थित है। समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इसलिए गर्मियों में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है।

2. **अक्षांशीय स्थिति :**

राज्य का दक्षिणी भाग कर्क रेखा के निकट है। इसलिए सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं और तापमान अधिक रहता है।

3. **अरावली पर्वतमाला :**

अरावली पर्वतमाला दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व दिशा में फैली हुई है। इसकी दिशा मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण यह वर्षा कराने में अधिक सहायक नहीं होती। परिणामस्वरूप पश्चिमी राजस्थान में कम

वर्षा होती है।

4. थार मरूस्थल :

थार मरुस्थल के कारण गर्मियों में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा धूल भरी आँधियाँ और लू चलती है।

5. समुद्र से दूरी :

समुद्र से दूर होने के कारण समुद्री प्रभाव नहीं पहुँचता। इसी कारण यहाँ तापमान में अत्यधिक उतार–चढ़ाव पाया जाता है।

6. मानसूनी हवाएँ :

राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिण–पश्चिम मानसून है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखाओं से वर्षा होती है, परंतु पश्चिमी भाग तक पहुँचते–पहुँचते इनकी नमी कम हो जाती है।

राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएँ :

1. शुष्क एवं अर्ध–शुष्क जलवायु।
2. वर्षा का असमान वितरण।
3. पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में वृद्धि।
4. गर्मियों में अत्यधिक तापमान।
5. सर्दियों में पर्याप्त ठंड।
6. कम आर्द्रता।
7. दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर।
8. लू एवं धूल भरी आँधियाँ।
9. सूखे की बार–बार स्थिति।
10. जल की कमी तथा मरुस्थलीय परिस्थितियाँ।

राजस्थान की ऋतुएँ :

(1) ग्रीष्म ऋतु (मार्च-जून)

ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारंभ होकर जून तक रहती है। मई और जून सबसे गर्म महीने होते हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू आदि जिलों में तापमान 48-50°C तक पहुँच जाता है। इस समय तेज़ गर्म हवाएँ (लू) चलती हैं।

विशेषताएँ :

- अत्यधिक गर्मी।
- लू चलना।
- कम आर्द्रता।
- धूल भरी आँधियाँ।
- जल स्रोतों का सूखना।

(2) वर्षा ऋतु (जून-सितंबर)

दक्षिण–पश्चिम मानसून जून के अंत तक राजस्थान में प्रवेश करता है। अधिकांश वर्षा जुलाई और अगस्त में होती है।

विशेषताएँ :

- कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 90% इसी ऋतु में होता है।
- पश्चिमी भाग में कम वर्षा।
- दक्षिण–पूर्वी भाग में अधिक वर्षा।
- कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऋतु।

(3) शीत ऋतु (अक्टूबर-फरवरी)

अक्टूबर से तापमान कम होने लगता है। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं।

विशेषताएँ :

- शुष्क एवं ठंडा मौसम।
- कोहरा (पूर्वी राजस्थान में)
- पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा।
- रबी फसलों के लिए अनुकूल मौसम।

राजस्थान में वर्षा का वितरण

क्षेत्र	औसत वर्षा
पश्चिमी राजस्थान	100–300 मिमी
मध्य राजस्थान	300–500 मिमी
पूर्वी राजस्थान	500–800 मिमी
दक्षिण–पूर्वी राजस्थान	800–1000 मिमी या अधिक

सबसे कम वर्षा जैसलमेर में तथा सबसे अधिक वर्षा झालावाड़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ क्षेत्रों में होती है।

तापमान :

राजस्थान भारत के सबसे गर्म राज्यों में से एक है।

- ग्रीष्मकाल : 30° C से 50°C
- शीतकाल : 0° C से 25° C

मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है।

आर्द्रता :

राजस्थान में सामान्यतः आर्द्रता कम रहती है। वर्षा ऋतु में आर्द्रता बढ़ जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे कम तथा दक्षिण–पूर्वी भाग में अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता रहती है।

हवाएँ :

- ग्रीष्म ऋतु – लू।

- वर्षा ऋतु – दक्षिण–पश्चिम मानसून।
- शीत ऋतु – उत्तर–पश्चिमी ठंडी हवाएँ।

राजस्थान के जलवायु प्रदेश :

1. **शुष्क मरूस्थलीय प्रदेश :**
   जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू।
2. **अर्ध–शुष्क प्रदेश :**
   जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर।
3. **उप–आर्द्र प्रदेश :**
   जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा।
4. **आर्द्र प्रदेश :**
   कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़।

राजस्थान की जलवायु का कृषि पर प्रभाव

- सिंचाई की आवश्यकता अधिक।
- बाजरा, ज्वार, गेहूँ, चना, सरसों, मूंग, ग्वार प्रमुख फसलें।
- सूखे से उत्पादन प्रभावित।
- इंदिरा गांधी नहर ने पश्चिमी राजस्थान की कृषि में परिवर्तन किया।

पशुपालन पर प्रभाव :

कम वर्षा के कारण पशुपालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है।

मुख्य पशु :

- ऊँट
- भेड़
- बकरी
- गाय
- भैंस

राजस्थान ऊन उत्पादन में देश के प्रमुख राज्यों में से एक है।

वनस्पति पर प्रभाव :

कम वर्षा के कारण प्राकृतिक वनस्पति विरल है।

मुख्य वृक्ष :

- खेजड़ी
- बबूल
- रोहिड़ा
- बेर
- नीम

जनजीवन पर प्रभाव :

- मोटी दीवारों वाले घर।
- सफेद एवं हल्के रंग के वस्त्र।
- पानी का संरक्षण।
- गर्मी से बचने के लिए पारंपरिक जीवनशैली।
- मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या घनत्व।

उद्योगों पर प्रभाव :

- सीमेंट उद्योग।
- खनिज आधारित उद्योग।
- ऊन उद्योग।
- हस्तशिल्प।
- पर्यटन उद्योग।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव :

- तापमान में वृद्धि।
- सूखे की घटनाओं में वृद्धि।
- वर्षा का अनियमित वितरण।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- मरुस्थलीकरण का विस्तार।
- कृषि उत्पादन में कमी।

जल संरक्षण के उपाय :

- वर्षा जल संचयन।
- तालाबों एवं जोहड़ों का पुनर्जीवन।
- ड्रिप सिंचाई।
- स्प्रिंकलर सिंचाई।
- वृक्षारोपण।
- भूजल पुनर्भरण।
- जल का विवेकपूर्ण उपयोग।
- पर्यावरण संरक्षण।
- नदियों और जलाशयों का संरक्षण।
- जनजागरूकता।

राजस्थान की जलवायु का महत्व :

- कृषि का आधार।
- पशुपालन का विकास।

- पर्यटन को बढ़ावा।
- सौर एवं पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएँ।
- मरुस्थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण।

निष्कर्ष :

राजस्थान की जलवायु राज्य की प्राकृतिक एवं आर्थिक संरचना का आधार है। यहाँ शुष्क जलवायु, कम वर्षा, अत्यधिक तापमान तथा मरुस्थलीय परिस्थितियाँ प्रमुख विशेषताएँ हैं। इसके बावजूद राजस्थान ने जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भविष्य में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण तथा वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर जलवायु संबंधी चुनौतियों का प्रभाव कम किया जा सकता है। अतः राजस्थान की जलवायु राज्य के विकास, संस्कृति तथा जनजीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण प्राकृतिक तत्व है।

नाम – हेमाराम जाट
पिता – श्रवण राम
पता – गांव नराधणा तहसील जायल, जिला नागौर
मो. नं. 9667131109

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 108–112

Impact of Competency-Based Assessment under NEP 2020 on Classroom Engagement and Teaching Effectiveness among Secondary School Teachers

Pinky Agarwal, M.Ed. Scholar
Dr. Manju Devi, Research Supervisor (Assistant Professor)
Sri Balaji Teacher Training College, Jaipur.

Abstract :

The National Education Policy (NEP) 2020 has introduced revolutionary changes in the Indian educational landscape, most notably the implementation of Competency-Based Assessment (CBA). This research paper examines the profound impact of CBA under NEP 2020 on classroom engagement levels and overall teaching effectiveness among secondary school teachers. Transitioning away from a legacy rote-memorization paradigm, CBA prioritizes deep conceptual clarity, higher-order critical thinking, and continuous formative evaluation. Employing a rigorous descriptive survey research design, data was systematically gathered from 120 secondary school teachers across equally distributed government and private institutions utilizing validated, standardized instruments. The empirical findings reveal that teachers who fully incorporate competency-based frameworks demonstrate a highly statistically significant improvement ($t = 5.98$, $p < 0.05$) in pedagogical innovation, real-world application mapping, and active student participation metrics compared to their traditional assessment counterparts. The paper concludes with critical policy recommendations aimed at expanding continuous institutional training, scaling robust digital repository systems, and overcoming structural inertia to optimize classroom-level implementation outcomes.

Keywords : Competency-Based Assessment, National Education Policy 2020, Classroom Engagement, Teaching Effectiveness, Secondary Education, Pedagogical Shift.

1. Introduction :

For decades, the secondary educational framework within India has operated under an

examination-centric paradigm. This system disproportionately rewarded rote memorization, standardized test-taking speed, and surface-level replication of textbook data over deeper cognitive understanding. The formulation and enactment of the National Education Policy (NEP) 2020 sought to address this foundational flaw by introducing a modern skill-based framework designed to prepare learners for 21st-century global realities. At the absolute core of this institutional restructuring is Competency-Based Assessment (CBA), which shifts focus away from what a student can recall on exam day to what a student can execute, analyze, and apply in authentic life settings.

Because assessment and instruction exist within a tightly coupled systemic feedback loop, any modification in evaluation standards forces an immediate restructuring of classroom instruction. Secondary school teachers must transition away from standard, passive chalk-and-talk lecturing toward highly interactive, project-driven, and experiential pedagogy. While the programmatic vision of NEP 2020 is theoretically sound, the practical implementation within secondary classrooms presents multifaceted behavioral, infrastructural, and pedagogical challenges. Hence, this empirical investigation systematically analyzes the direct effect of implementing CBA workflows on classroom engagement metrics and systemic teaching effectiveness.

2. Review of Literature :

The conceptual foundation of competency-driven educational delivery traces closely to the foundational taxonomy of educational objectives established by Bloom (1956) and later refined by Anderson and Krathwohl (2001). These researchers argued that a balanced educational architecture must intentionally target higher-level cognitive operations, including synthesis, evaluation, and structural creation, rather than simple knowledge recall. Furthermore, the extensive analysis conducted by Black and Wiliam (1998) verified that regular formative assessment models, when integrated systematically with iterative feedback loops, yield substantial, documented gains in student mastery compared to isolated, high-stakes summative exams.

In modern contexts, Darling-Hammond (2006) emphasized that robust assessment frameworks serve as an analytical lens through which teachers evaluate the real-time efficacy of their own teaching methods. Despite these theoretical validations, local diagnostic reports from bodies such as NCERT (2021) and CBSE (2021) note that deep, classroom-level operationalization of competency-based criteria remains actively constrained by cultural habits of rote preparation, baseline gaps in teacher training, and localized assessment resource scarcities. This study aims to fill the gap by documenting the exact pedagogical shifts triggered when teachers cross over from traditional models into

competency-oriented assessment environments.

3. Research Methodology :

This research project used a descriptive survey research design to map out the current state of assessment practices and their corresponding impacts on teachers. The defined target population comprised all working secondary school teachers managing classes IX and X within the designated geographic region. To establish an unbiased, highly representative framework, a stratified random sampling technique was utilized, yielding a final sample of 120 teachers split evenly between government (n = 60) and private (n = 60) institutions.

Variables under Investigation :

- **Independent Variable :** Implementation of Competency-Based Assessment framework.
- **Dependent Variables :** Classroom Engagement Quality and Teaching Effectiveness Metrics.

Data collection was executed through the direct manual administration of standardized, pre-validated Likert-scale questionnaires assessing classroom engagement profiles, application-oriented question usage, formatting frequency, and technology deployment. Collected raw data matrices were cleaned, systematically coded, and processed via statistical tools to run Mean, Standard Deviation, and Independent Samples t-test calculations.

4. Data Analysis and Findings

Objective 1 : Evaluating CBA Implementation Levels Across Institutional Sectors

Table 1

CBA Implementation Profiles: Government vs. Private Schools

Institutional Cohort	N	Mean Score	Standard Deviation
Government Secondary Teachers	60	75.40	6.12
Private Secondary Teachers	60	78.25	5.98

The data in Table 1 indicates that both institutional sectors demonstrate moderate-to-high implementation profiles. Private school teachers exhibit a slightly higher mean score (78.25) relative to government school colleagues (75.40), likely supported by rapid digital infrastructure updates and localized teacher development workshops. Consequently, the baseline null hypothesis (H_{01}) predicting an absence of structured implementation is confidently rejected.

Objective 2 : Classroom Engagement and Teaching Effectiveness Discrepancies

Table 2

Pedagogical Profiles of CBA Adopters vs. Traditional Instructors

Methodological Grouping	N	Mean Score	Standard Deviation
CBA Framework Adopters	60	80.12	6.08
Traditional Assessment Users	60	72.35	7.21

As detailed in Table 2, teachers who anchor their instructional models around CBA principles achieve markedly higher pedagogical performance and student engagement levels (Mean = 80.12) than those continuing under conventional routines (Mean = 72.35). Qualitative survey parsing indicates that high CBA deployment corresponds with a dramatic increase in analytical questioning frequency, open-ended problem exploration, continuous feedback provision, and collaborative project assignments.

Objective 3 : Inferential Significance Testing of the Assessment Framework

Table 3

Independent Samples t-Test for Teaching Effectiveness Differences

Analytical Contrast	t-value	df	Significance Level (p)
CBA Cohort vs. Traditional Cohort	5.98	118	$p < 0.05$ (Highly Significant)

The inferential analysis in Table 3 confirms that the observed performance boost is highly statistically significant, with the calculated t-value of 5.98 comfortably exceeding critical distribution limits ($p < 0.05$). This result rejects the secondary null hypothesis (H_{02}), proving that CBA implementation fundamentally drives increased teaching effectiveness and sustained student classroom engagement.

5. Strategic Recommendations :

- **Institutionalized Professional Development :** Establish continuous, hands-on, case-study-driven teacher professional development modules to replace brief, superficial briefings, focusing

specifically on blueprinting original analytical questions.

- **Digital Resource Scaling :** Develop robust national and regional open-access item banks containing thoroughly vetted, high-quality, competency-mapped assessment tasks and interactive rubrics.
- **Administrative Alignment :** Readjust institutional reporting workflows, performance scorecards, and local board examination designs to reflect skill-centric outcomes, reducing systemic pressure to complete raw textbook coverage.

6. Conclusion :

This empirical research proves that competency-based assessment under NEP 2020 serves as a powerful catalyst for pedagogical innovation, classroom engagement, and teaching excellence. Moving beyond the historical limitations of rote learning frameworks, CBA naturally pushes secondary instructors toward highly dynamic, collaborative, and student-centered methodologies. To maximize these positive educational shifts across all regions, the educational ecosystem must actively cooperate to deliver systemic training infrastructure, provide well-aligned learning resources, and reduce structural resistance to change.

References :

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.
- Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7–74.
- Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Longman.
- Brookhart, S. M. (2013). How to create and use rubrics for formative assessment and grading. ASCD.
- CBSE. (2021). Competency-based education: Guidelines for schools. Central Board of Secondary Education, New Delhi.
- Darling-Hammond, L. (2006). Powerful teacher education: Lessons from exemplary programs. Jossey-Bass.
- Darling-Hammond, L., & Snyder, J. (2000). Authentic assessment of teaching in context. Teaching and Teacher Education, 16(5–6), 523–545.
- Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education, New Delhi.
- NCERT. (2021). Assessment reforms and competency-based education. National Council of Educational Research and Training, New Delhi.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
ਪ੍ਰਿਸ਼ਠ : 113–121

ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ

ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ, ਦਿਉਣ ਬੰਠਿਡਾ

ਸਾਰ :

ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹੱਥਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਲਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰ ਇਸ ਹੱਥਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਆਮਦਨ, ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ,ਰਹਿਣ–ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ : ਜੁੱਤੀ, ਕਾਰੀਗਰ, ਸ਼ਹਿਰ, ਚੰਮ, ਕਿੱਤਾ

ਭੂਮਿਕਾ :

ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੱਥਕਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਬਦਲਦਾ

ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਭਾਗ 'ਸਿਰ' ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ 'ਪੈਰ' ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 'ਜੁੱਤੀਆ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੁੱਤੀ' ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਸ਼ੂ' (shoe) ਦਾ ਸਮਾਨਾਅਰਥਕ ਹੈ। ਸ਼ੂ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਫੁਟਵੇਅਰ' 'ਬੂਟ' 'ਸਲੀਪਰ' ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਂ, ਰੂਪ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾਂ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਜੁੱਤੀ ਸ਼ਬਦ 'ਜੁੱਤ+ਈ' ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੁੱਤ ਦਾ ਅਰਥ 'ਯੁਕਤ' ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ, ਸ਼ਾਮਿਲ, ਸਾਥ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ 'ਜੁੱਤਣਾ' ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ 'ਜੋਇਆ ਜਾਣਾ' ਜੋਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਜਾਂ ਬਲਦ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੁੱਤਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤਣ ਵਰਗਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਸ਼ਾਂ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੱਟੀਆ, ਗੋਲੀਆ, ਰਾਏਗਰ, ਰੈਦਾਸੀ, ਰਾਈ , ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀਆ ਆਦਿ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਇਹ ਲੋ ਲੋਕ ਜੋ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਚਰਵਾਹੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਮਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਚੰਮ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਨੂੰ 'ਮੋਚੀ' ਦੀ ਸੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਚੀ ਸ਼ਬਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਸਿਊਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਚੀ ਵੀ ਆਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਬਿਹਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਮਦਰਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਦੀ ਵੱਧ

ਵਸੋਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮੋਜੂਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ- ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਹੰਬੜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। (ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ)

ਖੋਜ ਵਿਧੀ :

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਖੋਜ ਵਰਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ-ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ 80 ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਉਤਰਦਾਤਿਆ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਨਮੂਨਾ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਰਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖੋਜ ਵਿਧੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਹਿਤ ਸਰਵੇਖਣ :

1.ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਪੁਸਤਕ' 'ਜੁੱਤੀ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਤੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ, ਸੰਦਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਆਦਿ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਚਮਿਆਰ ਜਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕਾਰਨ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ।

2. ਰਾਉ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਯਾਦਵਪੁਰ' ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਤਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ, ਫੌਜੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਆਦਿ ।

3. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਾਰ ਜਾਤ ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਚਮਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਤ ਕਾਮੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਕੰਮ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ, ਖੱਲ ਲਾਹੁਣਾ, ਖੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿੱਤੇ ਅਪਨਾ ਲਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਉਦੇਸ਼ :

1. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ।
2. ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ (ਆਮਦਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ,) ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ।
3. ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਸੋਚਣ ਦੇ ਢੰਗ, ਰਹਿਣ–ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ–ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਮਰ : ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ ਨੂੰ:1 ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆ ਦੀ ਵੰਡ

ਲੜੀਨੰ.	ਉਮਰ	ਗਿਣਤੀ	ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
1	21ਸਾਲਤੋਂ 30ਸਾਲਤੱਕ	19	23.75
2	31ਸਾਲਤੋਂ40ਸਾਲਤੱਕ	29	36.25
3	41ਸਾਲਤੋਂ50ਸਾਲਤੱਕ	23	28.75
4	51ਸਾਲਤੋਂ60ਸਾਲਤੱਕ	9	11.25
	ਕੁਲ ਜੋੜ	**80**	**100**

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ 36.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, 28.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 41 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 23.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 11.25ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤੇ 51 ਸਾਲ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ।

ਜਾਤ : ਜਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ ਨੰਬਰ:2 ਜਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆ ਦੀ ਵੰਡ

ਲੜੀਨੰ.	ਜਾਤ	ਗਿਣਤੀ	ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
1.	ਰਵੀਦਾਸ	75	93.75
2.	ਹਰੀਜਨ	3	3.75
3.	ਖਟੀਕ	2	2.5
	ਕੁੱਲ ਜੋੜ	80	100

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ 93.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤੇ ਰਵੀਦਾਸ ਜਾਤ ਵਿਚੋਂ ਸਨ; 3.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤੇ ਹਰੀਜਨ ਜਾਤ ਵਿਚੋਂ, ਅਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤੇ ਖਟੀਕ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ

ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਦਾਤੇ ਜੋ ਕਿ ਰਵੀਦਾਸਿਆਂ ਜਾਤ ਵਿਚੋਂ ਸਨ।

ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ:- ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਂਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ ਨੰਬਰ:3 ਜੱਦੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆ ਦੀ ਵੰਡ

ਲੜੀਨੰ	ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ	ਗਿਣਤੀ	ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
1.	ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣਾ	73	91.25
2.	ਖੇਤੀ ਮਜਦੂਰ	3	3.75
3.	ਦਰਜੀ	4	5
	ਕੁੱਲ ਜੋੜ	**80**	**100**

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 91.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ; 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ: ਅਤੇ 3.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ : ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਕਾਰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ ਨੰਬਰ:4 ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆ ਦੀ ਵੰਡ

ਲੜੀ ਨੰ	ਆਮਦਨ	ਗਿਣਤੀ	ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
1.	1000ਰੁ:ਤੋ ਘੱਟ	27	33.75
2.	1001ਰੁ:ਤੋ5000	43	53.75
3.	5000ਰੁ:ਤੋ ਵੱਧ	10	12.5
	ਕੁੱਲ ਜੋੜ	80	100

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 53.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ; ਜਦੋਂ ਕਿ 33.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।

ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ : ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ ਨੰਬਰ:5 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆ ਦੀ ਵੰਡ

ਲੜੀਨੰ.	ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਹੈ	ਗਿਣਤੀ	ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
1.	ਹਾਂ	71	88.75
2.	ਨਹੀਂ	9	11.25
	ਕੁੱਲ ਜੋੜ	80	100

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 88.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ 11.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹੋਰਾਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ : ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰਣੀ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਰਣੀ ਨੰਬਰ:6 ਹੋਰਾਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆ ਦੀ ਵੰਡ

ਲੜੀਨੰ.	ਹੋਰਾਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ-ਨਾਤੇ	ਗਿਣਤੀ	ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ
1.	ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ	22	27.5
2.	ਵਧੀਆ	46	57.5
3.	ਠੀਕ-ਠੀਕ	12	15
	ਕੁੱਲ ਜੋੜ	**80**	**100**

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਣੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 57.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 27.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਨ; ਅਤੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਤਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਹੀ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ :

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ (31–50 ਸਾਲ) ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੀਗਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 1000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਤ੍ਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਦੇ ਹੋਣ; ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਇਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥਕਲਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ :

1. ਅਮੋਲ, ਐਸ.ਐਸ. "ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ", ਵਿਉਂਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

2. ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰਬੀਰ 2011,"ਜੁੱਤੀ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ" ਰਵੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

3. ਰਾਓ, ਐਮ.ਐਸ.ਏ. 1970, "ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ", ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

4. ਮੁਖਰਜੀ, ਏ. ਬੀ. 1980, "ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਮਾਰ", ਇੰਟਰ-ਇੰਡੀਆ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼, ਦਿੱਲੀ।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 122–135

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ : ਇਕ ਅਧਿਐਨ

Dr. Rajbinder Kaur
Assistant Professor, Baba Farid College Deon, Bathinda.

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ-ਲਿੰਗ ਭੇਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ – ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ :

ਨੀਚੀ ਹੁ ਅਤਿ ਨੀਚੁ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ।।

ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਚ।।[1]

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਇਕ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।

ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ

ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ।[2]

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਧਰਮਾ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ

ਸਿਧਾਂਤਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਤਰਸਮਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਨੀਚ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੰਡੀਆ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਘ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਛੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਵੇ :

ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ
ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ
ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗ ਉਪਜਿਆ
ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ।।[3]

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਇਕੋ ਜੇਹੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ

ਵੀ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ-ਕੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਦੀ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਭਰੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਵੰਡ ਛਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੱਥੀ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ ਦਸੌਂਧ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। ਜੋ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਤ ਨਸਲ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਂ, ਧਰਮ, ਕੁਚਲੇ ਲੋ-ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਬੇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਦਲਿਤ, ਭਗਤਾਂ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਿਲਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੀ- ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾ 'ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ' ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਕੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਞ ਵਿਅੰਗ ਕਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ:

ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੁ ਕਾਣਾ।

ਦੁਹਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ।।[4]

ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀਗਤ ਊਚ-ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ :

ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ।

ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮੁ ਜਪਉ ਦਿਨ ਰਾਤੀ।।[5]

ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਖੰਡਾਂ, ਕਾਡਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਲਈ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਬਾਣੀ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਖੰਡਾਂ ਕਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ :

ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ।
ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।।
ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ
ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ।।
ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੈ
ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ।।[6]

ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਰਭਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ :

ਕਬੀਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕਉ ਸਭ ਕੋ ਹਸਨੇਹਾਰ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤਿ ਕਉ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰ।।[7]

ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪਾਖੰਡੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ

ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਜਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਕਰੀਬ ਜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧੜਕ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜਾਤੀ ਜਮਾਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਸਾਨੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰਸਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਚ-ਨੀਂਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਊਚ-ਨੀਂਚ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਆਧਾਰਤ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਨਾਲ ਪੀ ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਅਮਾਨਵੀ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਚੱਜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਦਕਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਭਗਤ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵਰਭਾਗੀ ਜਾਤ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ :

ਜਾਤੀ ਓਛਾਪਾਤੀ ਓਛਾ ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ।

ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੇ ਸੇਟ ਨ ਕੀਨੀ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ।।[8]

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਦਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਲਾਸਾਨੀ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਸੰਗੀਤਮਈ ਧੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੌਣ? ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ :

ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟਬਾਂਢਿਲਾ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤਾ।

ਨਿਤਹਿ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ।।[9]

ਤਿਉ ਤਿਉ ਮੈਲ ਕਰਹਿ ਜਿਉ ਭਾਵੈ।

ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ।।

ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ।

ਜੋ ਹਮ ਸਹਰੀ ਸੁ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ।।[10]

ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਇਹ ਚੋਣਵੇ ਪਦ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ ਢੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਫ਼ਕਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਇਕ ਜਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਧ-ਵਿਧਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਉੱਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦਾਰਿਦ ਦੇਖਿ ਸਭ ਕੋ ਹਸੈ ਐਸੀ ਦਸਾ ਹਮਾਰੀ

ਅਸਟ ਦਸਾ ਸਿਧਿ ਕਰ ਤਲੈ

ਸਭ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਾਰੀ।।[11]

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ ਮੰਗੋਵਾਲੀ ਜੀ ਜੋ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਨਿਮਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਮਾਰੂ ਰਾਗ' ਅਤੇ 'ਸਾਗਰੁ ਸੁਰਤਰਿ ਚਿੰਤਾਸ ਬਿਨ ਕਉਨ ਕਰੈਨਿ' ਵਿਚ ਆਦਿ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਪਲ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸੁਰਤਰਿ ਚਿੰਤਾਮਨਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਸੋਰਨਿ ਤੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਗੂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਗੂ ਮਾਰੂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।[12]

ਰਵਿਦ 'ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਊ' ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਰਾਗ ਗਾਉੜੀ' ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਕ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੇਵੀ,

ਦੇਵਤੇ/ਰਿਸ਼ੀ-ਮੁਨੀ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।[13]

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਖੌਤੀ ਜਾਤ ਚਮਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਇਕਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ :

ਮੇਰੀ ਸੰਗਤਿ ਪੋਚਸੋਚ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ।
ਜਨਮੁ ਕਭਾਂਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮੁ ਕੁਟਿਲਤਾ
ਜੀਅ ਕੇ ਜੀਵਨਾ।। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ
ਮੈਂ ਜਨੁ ਤੇਰਾ।। ਮੋਹਿ ਨਾ ਬਿਸਾਰਹੁ।।[14]

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਇਸ ਤਿੱਖਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਸਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਵੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ-ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਰਣ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ 'ਹਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ' ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋੜੀ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਜਿਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ-ਜੋਲ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਦੂਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਕ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ

ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਛੂਤ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੜਾਂ ਵਾਲੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਦਿਆਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਜੋ ਹੋਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ।

ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਹਿਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ' ਦਰਜ ਬਣੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਢਲਾ ਮਾਰਗ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਜਾਤੀ, ਮੁਕਤੀ, ਵੰਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਜਾ ਉਹ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ. ਜੇ. ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ :

“ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਮਾਜੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਚਿਤਵਦੇਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੇ ਸਮਾਜੀ ਪਰਿਣਾਮ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਉਂਝ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ”

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ‘ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ’ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਇਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਰਲਾਉਣ ਪਿਛੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਬਲਯੂ ਮੈਕਲਾਇਡ ਐਸ. ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਥਿ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ’ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਉੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਮਣਵਾਦੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਈ ਆਧਾਰ ਹਿਤਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।[15]

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਸਮੂਹ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਬਰਿਕ ਔਰਤ ਵਰਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ

ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ :

"ਭੰਡਿ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡਿ ਨਿੰਮੀਐ
ਭੰਡਿ ਮੰਗਣ ਵੀਆਹੁ
ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ
ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ
ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ
ਭੰਡੁ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ
ਜਿਤੁ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ।।"

ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਕੁਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਨਵੀ ਜਾਤੀ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸੋਝੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਾਵ ਕਰਵਾਇਆ।

ਡਾ. ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ :

"ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ
ਅਪਣਾਈ ਜਿਸਨੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਕਹੀ (ਗੁਰੂਆਂ) ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ (ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ) ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ।"[17]

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਗਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕਰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ

ਵਿਰੋਧੀ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਗਲ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਖਾਸ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਲਈ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਜੁਮਾ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਈ: 1699 ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਕੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਦ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਛਕਣਾ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹਿੰਦੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਨੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਜਿਸ ਨੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦਲਿਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਣਾ 'ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ' ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰਤਨਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ

ਤੇ ਕਲਗੀ ਨਾਲ 'ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ' ਨੀਚ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸ-ਨਿਵਾਜਿਆ ਤਾਂ ਊਚ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧੱਕੜ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਗਰਜਾ ਸੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।[18]

ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਰੰਗਰੇਟੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮਦਾਸੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣਿਆਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਸਰ ਇਬਸਟਨ ਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਜਿਹਾ ਸੰਕਪਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਾਰਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ-ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ, ਨੀਵੇਂ, ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ

1. ਡਾ. ਰੰਣਕੀ ਰਾਮ, ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ : ਸਰੋਤ ਤੇ ਸਰੂਪ, ਪੰਨਾ-39
2. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-39

3. ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ-1349
4. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-875
5. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-485
6. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 324
7. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ- 1364
8. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-86
9. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-1293
10. ਪ੍ਰੋ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਪਨ, ਪੰਨਾ-345
11. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-858
12. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਗ-658
13. ਸੰਪਾ. ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, 'ਬੱਦਨ', ਰਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਇਕ ਵਿਵੇਚਨ, ਪੰਨਾ-169
14. ਡਾ. ਰੰਇਕੀ ਰਾਮ, ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ: ਸਰੋਰ ਤੇ ਸਰੂਪ, ਪੰਨਾ-37
15. ਉਹੀ, ਪੰਨਾ-39
16. ਪਰਮਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ, ਪੰਨਾ-19
17. ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਮਾਨਵ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ, ਪੰਨਾ-50
18. ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ-473

Dr. Rajbinder Kaur
Assistant Professor
Baba Farid College Deon,
Bathinda.
Mob No.: 97805-10956

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 136–139

संत कबीरदास के माया संबंधी विचार

डॉ. मनोज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी
चौधरी हरद्वारी लाल राजकीय महाविद्यालय, छारा, झज्जर।

संत कबीरदास का जन्म भक्ति काल के समय में हुआ था। कबीर के जन्म के समय भारतवर्ष के लोग सदियों से चली आ रही मोह माया के बंधन में बंधे हुए थे। हर व्यक्ति अपने जीवन में माया के पीछे दौड़ रहा था। किसी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं था। लोग विषय वासनाओं के साथ ही अगले जन्म में भी इसे पाने की इच्छा के साथ शरीर छोड़ रहे थे। ऐसे समय में इस धरती पर संत कबीरदास का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने समाज को आगे चल कर एक नई दिशा दिखाई।

कबीरदास ने इंसान को बताया कि माया ईश्वर द्वारा रची गई एक भ्रमपूर्ण शक्ति है। जो मनुष्य को सांसारिक मोह माया, धन और वासना में फंसाकर वास्तविक सत्य यानी ईश्वर से दूर रखती है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से उदाहरण देकर लोगों को माया से बचने की सलाह दी है।

कबीरदास ने माया को परछाई के समान बताया है। कोई भी व्यक्ति अपनी परछाई के कितने भी पीछे भाग ले लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता। जैसे–जैसे इंसान उसके पीछे भागता है वह उससे और दूर भागती है लेकिन जो इंसान अपनी परछाई से दूर भागता है वह उसके सामने आ जाती है।

माया छाया एक सी बिरला जाने कोय।
भगता के पीछे फिरे सनमुख भागे सोय।।[1]

कबीरदास ने माया को महाठगनी करार दिया है। कबीरदास माया को एक ऐसी स्त्री के समान मानते हैं जो अपनी विभिन्न अदाओं से ठगने का काम करती है। सारा जगत इस माया के फंदे में फंसा हुआ है। जो इसके जाल से बच जाता है उन पर इस माया का कोई असर नहीं होता।

माया तो ठगनी भई ठगत फिरें सब देस।
जा ठग या ठगनी ठगी ता ठग को आदेस।। [2]

कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से सांसारिक मोह माया की व्यर्थता को उजागर किया है। कबीर दास जी कहते हैं। इंसान सारी उम्र दिन रात दिन धन दौलत को इकट्ठा करने में लगा रहता है और इसी उधेड़बुन में अपने अंतिम सत्य यानी मृत्यु को भी भूल जाता है। जो संपत्ति इंसान सारी उम्र में बनाता है। वह नष्ट होने में एक पल का समय लेती है।

माया संचे संग्रहै वह दिन जाने नाहिं।

सहज बरस का सब करे मरे महरत माहि।। [3]

कबीर दास जी बताते हैं कि माया के अज्ञान को ज्ञान से दूर किया जा सकता है। केवल सच्चा ज्ञान ही अज्ञानता और भरम को दूर कर सकता है। ज्ञान रूपी आंधी के कारण माया रुपी पर्दा उड़ जाता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है।

आंधी आई ज्ञान की ढही भरम की भीति।

माया थाटी उड़ी गई लगो नाम से प्रीति।। [4]

माया को कबीरदास जी ने एक विषैले वृक्ष के समान माना है। जो माया रुपी तीन गुण सत्य (सत, रज और तमोगुण) से बना हुआ है। इस वृक्ष की शाखाएं केवल दुख और संताप यानी कष्ट देने वाली है। जैसे व्यक्ति किसी भी वृक्ष की छाया में बैठकर शांति और शीतलता पाता है लेकिन इस माया रूपी वृक्ष की छाया में उसे शांति और शीतलता सपने में भी नहीं मिलती। और इस माया रुपी पेड़ के फल फीके होते हैं। और उसे खाने से मनुष्य के शरीर में कष्ट और जलन ही होती है।

माया तरवार त्रिविधि का साख विषय सन्ताप।

सीतलता सपने नहीं फल फीका तन ताप।। [5]

कबीर जी ने विभिन्न उपमानों के द्वारा माया का भेद बताया है। दीपक और पतंगे का उदाहरण देकर कबीर ने माया का रूप इंसान को दिखाया है। कबीरदास जी ने माया की तुलना दीपक की लौ से तथा मनुष्य की तुलना अज्ञानी पतंगे से की हैं। जैसे पतंगा भी दीपक की तरफ आकर्षित होकर अपनी जीवन लीला खत्म कर लेता है। वैसे ही मनुष्य भी सांसारिक भ्रम और अज्ञान के वशीभूत होकर इस माया में बार–बार फसता है और अपना पतन कर लेता है। इस सांसारिक मोह माया से कोई विरला इंसान ही बच पाता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस इंसान को सद्गुरु का सच्चा ज्ञान मिल जाता है वही इस बंधन से मुक्ति पाता है।

माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि माहि परंत।

कोई एक गुरू ज्ञान ते उबरे साधू संत।। [6]

संसार जैसे दिखाई देता है। कबीर ने उसे असत्य माना है। उसे केवल माया की भ्रांति माना है। जो मनुष्य उसे इस माया को सच्चा मानकर उससे लिपट जाता है उसे कभी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती।

संसार ऐसा सुपिन जैसा जीव न सुपिन समान। [7]

कबीरदास जी बताते हैं कि जो मनुष्य हर वक्त माया में पड़ा रहता है वह सिर्फ अपनी ही बात सोचता रहता है। जिसके कारण वह परमात्मा को नहीं पा सकता। परमात्मा को पाने के लिए मोह माया को छोड़ना पड़ता है।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं।।[8]

माया को छोड़ना इतना आसान नहीं है। यह कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है। माया का बाहरी रूप इतना आकर्षक है कि उसे मनुष्य द्वारा छोड़े नहीं बनता। धीरे–धीरे माया अज्ञानी पुरुष को खाती जाती है अर्थात उसके पतन का कारण बनती है।

मीठी मीठी माया तजी न जाई।

आस्यानी पुरिष को भोली भोली खाई।। [9]

माया ही इंसान की विषय वासनाओं को जन्म देती है। कबीर दास ने माया को डायन की संज्ञा दी है। कबीरदास जी ने बताया है कि इस माया रुपी डायन के पांच पुत्र है। यह डायन मनुष्य के मन में बसती है। सुबह उठकर उसके हृदय को डसती है। हर दिन यह मनुष्य को नाच नचाती है।

एक डाइन मेरे मन बसे। नित उठि मेरे जिय को डसे।
या डाइन के लरिका पांच रे। निसि दिन मोहि नचावे नाचरे।।[10]

संसार में सर्वत्र पाखंडवाद का बोलबाला है। और इस पाखंड की जननी माया है। हत्या इस माया का उचित स्थान पाखंडियों के ही पास है। कबीरदास जी सांसारिक आडम्बरों जैसे रेशमी वस्त्र और चंदन को माया का प्रतीक मानकर उन पर तीखा प्रहार करते हैं। इसलिए माया को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं–

तहां जाऊं जह पार पटम्बर, अगर घसि लीना।[11]

माया का वजूद अज्ञानता के कारण बना रहता है। कबीर दास जी मनुष्य को समझाते हैं कि जिस प्रकार दर्पण पर काई लग जाती है उसी प्रकार आत्मा पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है। जिसके कारण आत्मज्ञान प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं। मनुष्य को आत्मारूपी दर्पण को निर्मल बनाए रखना चाहिए।

जो दरसन देख्या चाहिए, तो दरपन मंजत रहिए।
जब दरपन लागे काई, तब दरसन किया न जाई।। [12]

कबीर दास जी का कहना है कि दर्पण पर यही मांजना हरि भक्त करना है। भक्ति द्वारा ही माया रुपया ज्ञान दूर होता है और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अपने प्राय का भेद मिटता है।

उचित चेती च्यांति ले ताहि। जा च्यंत आपा पर नाहीं।
हरि हिरदे एक ग्यान उपाया। ताथे छूट गई सब माया।। [13]

संतों ने माया से बचने का एक उपाय जो भक्तों को बताया है। वह संसार से विमुख रहना है। कबीरदास जी घड़े के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जैसे उल्टा घड़ा कभी पानी में नहीं डूबता परंतु सीधा घड़ा पानी भरकर डूब जाता है। वैसे मनुष्य संसार के सामने होने से डूब जाता है परंतु संसार से विमुख होने से उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

औंधा घड़ा न जल में डूबे, सूधा सूभर भरिया।
जाको यह जग घिन करि चालें,ता प्रसादि निस्तरिया।। [14]

निष्कर्ष :-

कबीरदास ने माया को विभिन्न नामों से पुकारा है। कबीरदास इंसान को समझाते है कि माया उसे ईश्वर से दूर ले जाती है। वह एक सच्चे भक्त और भगवान के बीच में बाधक है। वह भक्त को भ्रमित रखती हैं। माया महाठगनी है। माया से विमुख होकर ही बचा जा सकता है। अतः कबीरदास जी ने माया के मायावी रूप को अपने दोहों के माध्यम से दिखाया है।

संदर्भ ग्रंथ :-

1. कबीर वचनावली, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध', पृष्ठ सं–108, वाणी प्रकाशन, 2011

2. वही, पृष्ठ सं– 108
3. वही, पृष्ठ सं– 108
4. वही, पृष्ठ सं– 108
5. वही, पृष्ठ सं– 108
6. वही, पृष्ठ सं– 109
7. कबीर ग्रंथावली, स०– डॉ श्याम सुंदरदास, एकांत पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, 2019 पृष्ठ सं० 29
8. वही, पृष्ठ सं० 29
9. वही, पृष्ठ सं० 29
10. वही, पृष्ठ सं० 29
11. वही, पृष्ठ सं० 29
12. वही, पृष्ठ सं० 30
13. वही, पृष्ठ सं० 30
14. वही, पृष्ठ सं० 30

Email : manojlohchab20@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 140–142

Impact of School Environment on Personality Development among Basketball Players : A Comparative Analysis of Government and Private Schools

Manish Kumar Sharma, Research Scholar
Dr. Surjeet Singh Kaswan (Professor) Research Supervisor
Faculty of Physical Education, Tantia University, Sri Ganganagar (Raj.)

Abstract :

The present study aimed to investigate the influence of school environment on personality development among basketball players belonging to government and private schools. Personality development is affected by coaching methods, peer interaction, educational facilities, competition exposure, and socio-economic conditions. A sample of 100 basketball players (50 government school and 50 private school players) aged 15–18 years participated in the study. Data were collected using a standardized personality questionnaire. Statistical analysis revealed significant differences in self-confidence, leadership, aggression control, and emotional maturity between both groups. Private school players exhibited higher confidence and leadership qualities, whereas government school players showed stronger emotional resilience and adjustment abilities. The study highlighted the importance of balanced sports environments in overall personality development.

Introduction :

Sports participation contributes significantly to personality development. Basketball particularly requires leadership, communication, teamwork, emotional control, and quick decision-making. School environment acts as a major factor influencing these traits.

Private schools generally provide advanced sports infrastructure, professional coaching, and exposure to competitions. Government schools, on the other hand, often develop adaptability and resilience due to limited resources. Such contrasting environments may influence the psychological

behavior of athletes differently.

Personality development among athletes is important not only for sports achievement but also for academic and social success.

Objectives :

- To study the effect of school environment on personality development.
- To compare self-confidence between government and private school basketball players.
- To compare leadership qualities among players.
- To analyze emotional maturity and aggression control.

Hypotheses :

- Significant differences would exist in personality development between government and private school basketball players.
- Private school players would demonstrate higher leadership qualities.
- Government school players would show better resilience.

Methodology :

Sample :

100 basketball players :

- Government School Players – 50
- Private School Players – 50

Tools Used :

- Personality Development Questionnaire
- Leadership Scale
- Emotional Maturity Scale

Statistical Techniques :

- Mean
- Standard Deviation
- t-test

Results and Discussion :

Personality Variable	Government School Mean	Private School Mean	t-value	Significance
Self-Confidence	18.21	21.45	2.82	Significant
Leadership	16.72	19.11	2.49	Significant
Emotional Maturity	20.34	18.29	2.17	Significant
Aggression Control	19.87	17.94	2.06	Significant

Discussion :

The findings suggest that private school players possess greater confidence and leadership due to advanced coaching and competitive opportunities. Government school players displayed better emotional maturity and aggression control because of exposure to challenging social conditions.

Major Findings :

- School environment significantly influences personality development.
- Private school basketball players scored higher in confidence and leadership.
- Government school players showed greater emotional maturity.
- Sports participation positively influenced overall personality in both groups.

Conclusion :

The study concluded that both government and private school environments contribute differently to personality development among basketball players. While private schools enhance leadership and confidence, government schools strengthen resilience and emotional adjustment.

Recommendations :

- Government schools should improve sports infrastructure.
- Private schools should focus on emotional development training.
- Sports psychologists should be appointed in schools.
- Equal competition exposure should be ensured.

Practical Applications :

- Coaches can use personality assessments during training.
- Schools may organize workshops on leadership and emotional control.
- Sports authorities can design balanced development programs.

References :

- Sports Psychology – Richard Cox
- Psychology Applied to Physical Education and Coaching – John Lawther
- Foundations of Sport Psychology – Weinberg & Gould
- Verma, P. (2019). Personality Development through Sports Participation.
- Kumar, S. (2021). Comparative Analysis of School Athletes.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 143-149
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

Women in Politics and Governance : Constitutional Empowerment and the Road to Viksit Bharat @ 2047

Kanika Thakur
Assistant Professor (Guest Faculty)
Deen Dayal Upadhyaya College NCWEB, University of Delhi.

ABSTRACT :

The role of women in politics is one of the key indicators of the strength and inclusiveness of a democracy, even after 75 years of the Indian constitution. Even though the constitution assures women of their equality, dignity, and political rights, there is still a gross under-representation of women in positions of power and in the higher echelons of most decision-making bodies. This paper will focus on the constitutive components of women's empowerment in the political sphere and will describe the changes in the roles and positions of women in the political and governance structures of the country.

The constitutional provisions such as articles 14, 15, and 16, and the 73rd and 74th amendments of the constitutions of India, have expanded the participatory rights of women as citizens in all the strata of democracy. The study also examines the various forms of barriers, such as the prevailing patriarchal structures, the hostile political environment, including political violence, and minimal representation, that limit women's leadership.

The leadership of women has contributed to inclusive growth, accountability in democracy and social justice. The study also links women's empowerment in politics to the country's aimed vision of Viksit Bharat @ 2047. This means that meaningful incorporation of women into governance is crucial for achieving sustainable development and democratic deepening.

The paper concludes that truly empowering the "daughters of the Bharatiya Constitution" requires moving beyond symbolic presence toward substantive participation, where women are recognized as equal partners in shaping India's democratic and developmental future.

Keywords : Women in Politics, Governance, Indian Constitution, Political Empowerment, Democracy, Viksit Bharat @ 2047

Introduction :

The participation of women in politics is widely recognised as a fundamental measure of democratic inclusiveness and political maturity. Democracies that fail to adequately represent women in decision-making institutions risk reproducing structural inequalities and undermining the principle of popular sovereignty. In India, the Constitution envisaged a democratic order based on equality, justice, and participation, granting women equal political rights from the very inception of the republic. However, the empirical reality of women's political representation presents a paradox. Despite constitutional guarantees and progressive legal frameworks, women continue to be grossly under-represented in legislatures, executive bodies, and leadership positions.

Scholars such as Beteille (2003) and Jayal (1999) have argued that Indian democracy has succeeded in institutionalising electoral participation but has been less effective in ensuring substantive social and political equality. Women's political marginalisation reflects deeper structural constraints rooted in patriarchal norms, socio-economic inequalities, and institutional biases. While women constitute nearly half of India's population, their representation in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies remains disproportionately low, raising critical questions about democratic legitimacy and inclusion.

The introduction of the 73rd and 74th Constitutional Amendments in the early 1990s marked a significant turning point by institutionalising women's participation at the grassroots level. These amendments mandated reservations for women in Panchayati Raj Institutions (PRIs) and Urban Local Bodies (ULBs), creating unprecedented opportunities for political engagement. Yet, concerns regarding tokenism, proxy representation, and limited decision-making power persist.

Against this backdrop, this paper seeks to examine the nature and extent of women's political empowerment in India. It explores constitutional provisions, institutional mechanisms, and socio-political barriers affecting women's leadership. Further, it situates women's political empowerment within the broader developmental vision of *Viksit Bharat @ 2047*, arguing that democratic deepening and sustainable development are inseparable from gender-inclusive governance.

Understanding Women's Political Empowerment :

Political empowerment is a multidimensional concept that extends beyond numerical representation to include agency, influence, and substantive participation. Kabeer (1999) conceptualises empowerment as the expansion of people's ability to make strategic life choices, articulated through the interrelated dimensions of resources, agency, and achievements. Applied to the political sphere, empowerment involves access to political institutions, the capacity to influence decision-making, and tangible outcomes that reflect women's interests and priorities.

Feminist political theorists have critically examined the gendered foundations of modern democracy. Pateman (1988), in *The Sexual Contract*, argues that democratic institutions are historically rooted in male dominance, systematically excluding women from the public sphere. This critique highlights the limitations of formal equality and underscores the need for structural transformation. Fraser (2009) further expands this perspective by emphasising justice as a combination of redistribution, recognition, and representation, all of which are central to women's political empowerment.

Amartya Sen's (1999) capability approach provides an important link between political participation and development. Sen views political freedom not merely as an instrument but as an intrinsic component of development. Women's participation in governance enhances democratic accountability and expands collective capabilities, thereby contributing to human development.

Agarwal's (1997) analysis of bargaining power within households and institutions underscores the importance of structural position in determining women's political agency. Without addressing underlying power asymmetries, formal inclusion may fail to translate into substantive empowerment. Thus, this paper adopts a framework that views women's political empowerment as a dynamic process shaped by legal provisions, institutional practices, and socio-cultural contexts.

Constitutional Foundation Of Women's Empowerment :

The Indian Constitution provides a robust legal foundation for gender equality and political participation. Article 14 guarantees equality before the law and equal protection of laws, establishing the principle of legal equality. Article 15 prohibits discrimination on grounds of sex and empowers the state to make special provisions for women. Article 16 ensures equality of opportunity in public employment, further reinforcing women's access to public institutions.

While these provisions established formal equality, their transformative potential remained limited in the absence of institutional mechanisms for participation. The 73rd and 74th Constitutional Amendments, enacted in 1992, marked a watershed moment by decentralising power and mandating reservations for women in local governance. These amendments reserved one-third of seats for women in PRIs and ULBs, including leadership positions, thereby institutionalising women's political participation at the grassroots level (Government of India, 1992).

Deshpande (2004) observes that these amendments significantly altered the landscape of local governance by bringing millions of women into formal political roles. The Ministry of Panchayati Raj has documented increased women's participation across rural India, making India one of the largest experiments in decentralised gender-inclusive governance globally.

However, the effectiveness of constitutional frameworks depends on its implementation and

socio-political context. While the Constitution provides enabling conditions, the translation of legal rights into substantive empowerment remains uneven. Nonetheless, constitutional provisions remain central to the project of democratic inclusion and gender justice.

Women In Political And Governance Structures In India :

The most visible impact of constitutional reforms is evident in local governance. Studies by Chattopadhyay and Duflo (2004) demonstrate that women leaders in PRIs tend to prioritise public goods such as water, sanitation, health, and education—areas directly affecting everyday life. Their presence has led to measurable changes in policy outcomes, challenging assumptions about women's leadership capabilities.

Beaman et al. (2009) further show that sustained exposure to women leaders reduces gender bias and alters voter perceptions, suggesting that representation has both immediate and long-term transformative effects. These findings underscore the importance of descriptive representation as a pathway to substantive change.

At the state and national levels, however, women's representation remains limited. Data from the Election Commission of India and the Inter-Parliamentary Union indicate that women's share in the Lok Sabha has remained well below global averages. Political parties continue to act as gatekeepers, often denying women tickets or relegating them to unwinnable constituencies.

Jayal (2006) notes that representation in India is shaped by complex intersections of caste, class, and gender, often disadvantaging women despite formal equality. While local governance has created a pipeline for political participation, upward mobility into higher political institutions remains constrained.

Gendered Constraints In Political Leadership :

Despite constitutional safeguards, women face multiple barriers to political leadership. Patriarchal social structures continue to assign women primary responsibility for unpaid care work, limiting their time, mobility, and access to political networks (Agarwal, 1997; John, 2005). These constraints are reinforced by cultural norms that view politics as a male domain.

The political environment itself often proves hostile to women. Hasan (2010) highlights how political violence, intimidation, and criminalisation disproportionately affect women candidates, discouraging their participation. The lack of institutional mechanisms to address gender-based political violence further exacerbates these challenges.

Tokenism and proxy representation remain persistent concerns, particularly at the local level. The phenomenon of "sarpanch pati" reflects how women's formal positions may be undermined by male relatives exercising de facto power. Jayal (2006) argues that such practices limit women's

agency and reduce representation to a symbolic gesture.

Institutional barriers within political parties also play a significant role. The absence of internal democracy, lack of leadership training, and resistance to gender quotas at higher levels constrain women's political advancement. The delayed implementation of women's reservation in legislatures reflects broader structural resistance to gender-inclusive power sharing

Gender Inclusive Leadership And Governance Outcomes :

Empirical evidence suggests that women's political leadership positively impacts governance and development outcomes. The World Bank (2012) and UNDP (2021) highlight strong correlations between women's participation in governance and improvements in human development indicators. Women leaders are often associated with greater transparency, accountability, and responsiveness to social needs.

Chattopadhyay and Duflo (2004) find lower levels of corruption and improved service delivery in areas governed by women leaders. These outcomes challenge stereotypes about women's leadership and underscore the democratic value of gender-inclusive governance.

Rai (2011) emphasises that women's political participation enhances social justice by amplifying marginalised voices and reshaping policy priorities. Fraser's (2009) framework of participatory parity further supports the argument that democracy cannot be truly inclusive without equal representation of women in decision-making processes.

Women's Political Empowerment and the Vision of Viksit Bharat @ 2047 :

The vision of *Viksit Bharat @ 2047* emphasises inclusive growth, social justice, and sustainable development. Achieving this vision requires recognising women as central agents of change rather than passive beneficiaries of development policies. Sen's (1999) conception of development as freedom underscores the intrinsic link between political participation and development outcomes. UN Women (2020) argues that women's political empowerment is essential for achieving the Sustainable Development Goals, particularly those related to gender equality, governance, and inclusive institutions. In the Indian context, strengthening women's political participation can enhance policy effectiveness, democratic legitimacy, and social cohesion.

Policy measures such as leadership training, capacity building, financial support, and safe political spaces are critical for translating formal rights into substantive empowerment. Integrating gender perspectives into governance is not merely a matter of justice but a strategic necessity for national development.

Conclusion :

This paper has examined political empowerment of women in India through constitutional,

institutional, and socio-political lenses. While the Indian Constitution provides a strong normative framework for gender equality, the gap between formal rights and substantive participation remains significant. Constitutional amendments have expanded women's access to political institutions, particularly at the grassroots level, yet structural barriers continue to limit their leadership potential. The analysis demonstrates that the political participation of women contributes to inclusive growth, democratic accountability, and social justice. Linking empowerment of women to the vision of *Viksit Bharat @ 2047* underscores the centrality of gender-inclusive governance in India's democratic and developmental future.

Ultimately, empowering the "daughters of the Bharatiya Constitution" requires moving beyond symbolic representation toward substantive participation, where women are recognised as equal partners in shaping India's democracy. Only through such transformation can Indian democracy achieve true deepening and inclusiveness.

REFERENCES :

- Agarwal, B. (1997). Bargaining and gender relations: Within and beyond the household. *World Development, 25*(1), 1–51.
- Beaman, L., Chattopadhyay, R., Duflo, E., Pande, R., & Topalova, P. (2009). Powerful women: Does exposure reduce bias? *Quarterly Journal of Economics, 124*(4), 1497–1540.
- Beteille, A. (2003). *Democracy and its institutions*. Oxford University Press.
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica, 72*(5), 1409–1443.
- Constitution of India. (1950). Government of India.
- Deshpande, R. (2004). How gendered is political participation? Women and politics in India. *Economic and Political Weekly, 39*(51), 5433–5439.
- Election Commission of India. (Various years). *Statistical reports on general elections*. Government of India.
- Fraser, N. (2009). *Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world*. Columbia University Press.
- Government of India. (1992). *The Constitution (Seventy-Third Amendment) Act, 1992*.
- Government of India. (1992). *The Constitution (Seventy-Fourth Amendment) Act, 1992*.
- Hasan, Z. (2010). *Politics of inclusion: Caste, minority and representation in India*. Oxford University Press.
- Inter-Parliamentary Union. (n.d.). *Women in national parliaments*.

- Jayal, N. G. (1999). *Democracy and the state: Welfare, secularism and development in contemporary India*. Oxford University Press.
- Jayal, N. G. (2006). *Representing India: Ethnic diversity and the governance of public institutions*. Palgrave Macmillan.
- John, M. E. (2005). *Women's studies in India: A reader*. Penguin Books.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change, 30*(3), 435–464.
- Ministry of Panchayati Raj. (Various years). *Reports on Panchayati Raj institutions*. Government of India.
- Pateman, C. (1988). *The sexual contract*. Stanford University Press.
- Rai, S. M. (2011). *Gender and the political economy of development: From nationalism to globalization*. Polity Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- UN Women. (2020). *Women's political participation and leadership*. United Nations.
- United Nations Development Programme. (2021). *Human development report 2021/2022*. UNDP.
- World Bank. (2012). *World development report 2012: Gender equality and development*. World Bank.

Email: kanikathakur101298@gmail.com

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 150–155

2014 के बाद भारत में राजनीतिक आख्यानों का निर्माण और विकास : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Dr. Ekta Chaudhary, Assistant Professor, Head of Department
Fatima Zohra, Research Scholar,
Department of Political Science, Ismail National Mahila PG College, Meerut.

सारांश :

2014 के बाद भारत के राजनीतिक परिदृश्य में संरचनात्मक, वैचारिक और संचारात्मक स्तर पर गहन परिवर्तन देखने को मिले हैं। इस अवधि को भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, जहाँ राजनीतिक आख्यान (Political Narratives) ने सत्ता, जनमत और राजनीतिक पहचान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभानी शुरू की। राजनीतिक आख्यान केवल सूचनाओं के प्रस्तुतीकरण का माध्यम नहीं रहे, बल्कि वे रणनीतिक रूप से निर्मित ऐसे संवाद बन गए हैं जो जनता की भावनाओं, अपेक्षाओं और विचारधाराओं को प्रभावित करते हैं।

इस अध्ययन में यह स्पष्ट होता है कि विकास, राष्ट्रवाद, डिजिटल शासन, कल्याणकारी नीतियाँ और नेतृत्व–केंद्रित राजनीति जैसे आख्यानों ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को नए आयाम प्रदान किए हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आधुनिक संचार तकनीकों ने इन आख्यानों के निर्माण और प्रसार को अत्यंत तीव्र, व्यापक और प्रभावशाली बना दिया है। परिणामस्वरूप, राजनीति अब केवल नीतिगत चर्चा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह भावनात्मक जुड़ाव, प्रतीकात्मक राजनीति और जनमत निर्माण की एक जटिल प्रक्रिया बन चुकी है।

1. प्रस्तावना :

भारतीय राजनीति में वर्ष 2014 को एक ऐतिहासिक और संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में देखा जाता है, जिसने न केवल सत्ता परिवर्तन को दर्शाया बल्कि राजनीतिक संवाद, जनमत निर्माण और राजनीतिक संचार की संपूर्ण प्रणाली को पुनर्परिभाषित किया। इस अवधि के बाद राजनीति एक बहुआयामी प्रक्रिया बन गई, जिसमें विचारधारा, भावनाएँ, प्रतीकात्मकता और डिजिटल संचार का अत्यधिक महत्व बढ़ गया। राजनीतिक प्रक्रिया अब केवल नीति निर्माण या शासन तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक व्यापक "आख्यान निर्माण प्रक्रिया" (Narrative Construction Process) में परिवर्तित हो गई है।

इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब राजनीतिक दल और नेतृत्व अपनी नीतियों एवं

विचारों को केवल तथ्यों या घोषणाओं के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि उन्हें एक संगठित कहानी (Storytelling Framework) के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे जनता उनके साथ भावनात्मक और वैचारिक रूप से जुड़ सके। इस प्रक्रिया में "विकास", "राष्ट्रीयता", "सुरक्षा", "सामाजिक न्याय" और "डिजिटल परिवर्तन" जैसे तत्व प्रमुख आख्यानात्मक आधार बनकर उभरे हैं।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल क्रांति ने राजनीतिक संवाद को अत्यधिक गतिशील बना दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर (X), फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप ने राजनीतिक संदेशों के प्रसार को तत्काल और व्यापक बना दिया है। अब राजनीतिक संवाद एकतरफा न होकर संवादात्मक (Interactive) बन गया है, जहाँ जनता न केवल संदेश प्राप्त करती है बल्कि उस पर प्रतिक्रिया देकर स्वयं आख्यान निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बन जाती है।

इस प्रकार, समकालीन भारतीय राजनीति में आख्यान केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि सत्ता, वैधता और जनसमर्थन प्राप्त करने का एक रणनीतिक उपकरण बन चुका है। यह अध्ययन इसी परिवर्तनशील राजनीतिक संरचना को समझने का प्रयास करता है।

2. ऐतिहासिक परिवर्तन और राजनीतिक संदर्भ :

वर्ष 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक गहरा वैचारिक, संगठनात्मक और संचारात्मक परिवर्तन देखा गया, जिसे केवल चुनावी परिवर्तन के रूप में नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचना (Political Restructuring) के रूप में देखा जाता है। इस अवधि में राजनीति का केंद्र बिंदु धीरे–धीरे पारंपरिक दलगत विचारधाराओं से हटकर नेतृत्व, विकास और संचार रणनीतियों की ओर स्थानांतरित हो गया।

इस परिवर्तन का एक प्रमुख पहलू नेतृत्व–केंद्रित राजनीति का उदय है, जहाँ राजनीतिक विमर्श अब केवल पार्टी नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत नेतृत्व की छवि, उसकी निर्णय क्षमता, उसकी कार्यशैली और उसकी संचार रणनीति पर आधारित हो गया। इसने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को अधिक व्यक्तिगत और भावनात्मक बना दिया है।

इसके साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने संदेशों को अधिक संगठित और रणनीतिक रूप से प्रस्तुत करना शुरू किया, जिसमें योजनाओं और नीतियों को एक बड़े "राष्ट्रीय विकास आख्यान" का हिस्सा बनाया गया। इस प्रकार राजनीति धीरे–धीरे "Policy-Based Governance" से "Narrative-Based Governance" की ओर बढ़ी है, जहाँ कथानक निर्माण शासन का एक आवश्यक तत्व बन गया है।

डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया का तीव्र विस्तार इस परिवर्तन का एक प्रमुख कारक रहा है। इंटरनेट और मोबाइल संचार के व्यापक प्रसार ने राजनीतिक संदेशों को सीधे जनता तक पहुँचाने की क्षमता को अत्यधिक बढ़ा दिया है। इसके परिणामस्वरूप पारंपरिक मीडिया की मध्यस्थ भूमिका कमजोर हुई है और राजनीतिक संचार अधिक प्रत्यक्ष और तेज हो गया है।

इस प्रकार 2014 के बाद का राजनीतिक परिदृश्य एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें राजनीति केवल शासन व्यवस्था नहीं रही, बल्कि यह संचार, प्रतीक, भावना और डिजिटल तकनीक पर आधारित एक जटिल और बहुस्तरीय प्रणाली बन गई है।

3. राजनीतिक आख्यानों का निर्माण :

राजनीतिक आख्यान एक संरचित वैचारिक ढांचा है, जिसमें घटनाओं, नीतियों और विचारों को एक संगठित कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं, बल्कि जनता की सोच, भावना और राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करना होता है।

3.1 विकास आख्यान :

विकास आख्यान 2014 के बाद भारतीय राजनीति का सबसे प्रभावशाली तत्व बन गया है। इसमें आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल तकनीक का उपयोग और औद्योगिक प्रगति को प्रमुखता दी जाती है। यह आख्यान यह स्थापित करता है कि राष्ट्र की प्रगति आर्थिक विकास के माध्यम से ही संभव है।

3.2 राष्ट्रवादी आख्यान :

राष्ट्रवादी आख्यान राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक गौरव पर आधारित है। यह आख्यान जनता में सामूहिक पहचान और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है तथा राजनीतिक विमर्श को भावनात्मक और प्रतीकात्मक स्तर पर प्रभावित करता है।

3.3 कल्याणकारी आख्यान :

कल्याणकारी आख्यान सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं पर केंद्रित है। इसमें उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास किया जाता है।

3.4 डिजिटल एवं तकनीकी आख्यान :

डिजिटल आख्यान भारत को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। ई–गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर बल दिया जाता है।

3.5 नेतृत्व आधारित आख्यान :

इस आख्यान में नेतृत्व को परिवर्तन और विकास का मुख्य प्रतीक माना जाता है। राजनीतिक नेतृत्व को एक मजबूत, निर्णायक और परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो जनता की अपेक्षाओं को दिशा देता है।

4. मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका :

2014 के बाद भारतीय राजनीति में मीडिया और विशेष रूप से सोशल मीडिया राजनीतिक आख्यानों के निर्माण, पुनर्निर्माण और प्रसार के सबसे शक्तिशाली माध्यमों में से एक बन गए हैं। पारंपरिक मीडिया जैसे समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो की भूमिका अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी व्याख्यात्मक शक्ति (Interpretative Power) को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने काफी हद तक पुनर्परिभाषित कर दिया है।

ट्विटर (X), फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म राजनीतिक संचार को केवल तेज ही नहीं बनाते, बल्कि इसे अत्यधिक इंटरैक्टिव और प्रतिक्रियात्मक (Interactive and Reactive) भी बनाते हैं। अब राजनीतिक संदेश केवल "प्रेषित" नहीं किए जाते, बल्कि वे तुरंत जनता की प्रतिक्रिया, शेयरिंग और बहस का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे एक सतत डिजिटल संवाद का निर्माण होता है।

इस परिवर्तन ने राजनीतिक आख्यानों को अधिक गतिशील और बहुस्तरीय बना दिया है। अब एक ही राजनीतिक घटना को अलग–अलग प्लेटफॉर्म पर भिन्न–भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे आख्यानों की विविधता (Narrative Plurality) बढ़ जाती है। साथ ही, एल्गोरिदम आधारित कंटेंट वितरण प्रणाली ने यह तय करना शुरू कर दिया है कि कौन सा राजनीतिक संदेश कितने लोगों तक पहुंचेगा, जिससे सूचना प्रसार की प्रकृति भी प्रभावित हुई है।

इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया ने जनता को केवल दर्शक (Audience) नहीं, बल्कि सक्रिय भागीदार (Active Participant) बना दिया है। लोग अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनकर स्वयं भी आख्यानों के निर्माण में योगदान दे रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक संवाद अधिक व्यापक, लेकिन कभी–कभी अधिक ध्रुवीकृत भी हो गया है।

5. राजनीतिक आख्यानों का प्रभाव :

राजनीतिक आख्यानों ने भारतीय लोकतंत्र में जनमत निर्माण की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया है। यह प्रक्रिया अब पहले की तुलना में अधिक तेज, डिजिटल और भावनात्मक रूप से संचालित हो गई है। राजनीतिक आख्यान केवल सूचना का माध्यम नहीं रहे, बल्कि वे नागरिकों की राजनीतिक समझ, धारणा और निर्णय निर्माण को भी प्रभावित करते हैं।

इन आख्यानों के माध्यम से जनता में राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लोग अब राजनीतिक घटनाओं पर अधिक सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देते हैं, ऑनलाइन चर्चाओं में भाग लेते हैं और नीति–निर्माण पर भी अपनी राय व्यक्त करते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक सहभागी (Participatory) हो गई है।

हालांकि, इसके साथ ही कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। राजनीतिक आख्यानों के तीव्र प्रसार ने वैचारिक ध्रुवीकरण (Ideological Polarization) को बढ़ावा दिया है। विभिन्न समूह अलग–अलग आख्यानों के प्रभाव में आकर एक–दूसरे से भिन्न राजनीतिक वास्तविकताएँ (Political Realities) विकसित कर लेते हैं। इससे सामाजिक एकता पर प्रभाव पड़ता है और संवाद की जगह टकराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त, भावनात्मक राजनीति (Emotional Politics) का प्रभाव भी बढ़ा है, जहाँ तर्क की तुलना में भावनाएँ अधिक प्रभावी हो जाती हैं। यह स्थिति लोकतांत्रिक विमर्श की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है।

6. प्रमुख अध्ययन :

उपलब्ध शोध यह स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल युग में राजनीतिक आख्यानों ने "डिजिटल पॉपुलिज्म" (Digital Populism) की एक नई अवधारणा को जन्म दिया है। इस अवधारणा के अनुसार राजनीतिक संचार अब पारंपरिक संस्थागत माध्यमों के बजाय सीधे नेता और जनता के बीच स्थापित हो जाता है, जिससे मध्यस्थ संस्थाओं की भूमिका कम हो जाती है।

शोध यह भी संकेत देते हैं कि यह प्रत्यक्ष संचार प्रणाली राजनीतिक संदेशों को अधिक प्रभावी और भावनात्मक बनाती है, लेकिन साथ ही यह सूचना की सत्यता (Information Authenticity), संतुलन और आलोचनात्मक विश्लेषण की क्षमता को प्रभावित कर सकती है।

इसके अतिरिक्त, अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिस्पर्धी आख्यान

(Competing Narratives) अक्सर समानांतर वास्तविकताओं (Parallel Realities) का निर्माण करते हैं, जिससे राजनीतिक समझ में विविधता के साथ–साथ भ्रम और अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

इस प्रकार, आधुनिक शोध यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक आख्यान लोकतंत्र को अधिक सक्रिय और संवादात्मक बनाते हैं, लेकिन साथ ही वे सूचना नियंत्रण, सत्यापन और संतुलन से जुड़ी नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न करते हैं।

7. निष्कर्ष :

2014 के बाद भारत में राजनीतिक आख्यानों का विकास भारतीय राजनीति के रूपांतरण का एक केंद्रीय और निर्णायक पहलू बन चुका है। इस अवधि में राजनीति केवल नीतिगत निर्णयों या चुनावी प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक व्यापक संचार–आधारित, भावनात्मक और डिजिटल रूप से संचालित प्रणाली में परिवर्तित हो गई है।

आज राजनीतिक आख्यान केवल सूचना प्रसारित करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे जनमत निर्माण, राजनीतिक पहचान निर्माण और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली उपकरण बन चुके हैं। ये आख्यान जनता की सोच, व्यवहार और राजनीतिक निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं।

हालांकि, इस विकास के साथ यह भी आवश्यक हो गया है कि राजनीतिक आख्यानों का उपयोग अधिक पारदर्शिता, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ किया जाए। यदि संतुलित और तथ्य–आधारित संवाद को प्राथमिकता दी जाए, तो यह प्रणाली लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बना सकती है।

भविष्य में भारतीय राजनीति की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि डिजिटल माध्यमों द्वारा निर्मित इन आख्यानों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है और वे समाज में किस प्रकार की राजनीतिक चेतना और समझ विकसित करते हैं।

संदर्भ सूची :

1. सर्देसाई, आर. (2015). 2014 : द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया. पेंगुइन बुक्स इंडिया।
2. सेन, अमर्त्य. (2005). द आर्ग्युमेंटेटिव इंडियन. एलन लेन पब्लिशर्स।
3. जाफ्रेलोट, सी. (2021). मोदी का भारत : हिंदू राष्ट्रवाद और जातीय लोकतंत्र. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. वैश्नव, एम. (2017). जब अपराध लाभ देता है : भारतीय राजनीति में धन और शक्ति. येल यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. चिब्बर, पी., एवं वर्मा, आर. (2018). भारतीय राजनीति में विचारधारा और पहचान. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. बानाजी, एस. (2018). भारत में डिजिटल प्रचार और मीडिया रणनीति. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स रिपोर्ट।
7. श्रीधरन, ई. (2019). 2014 के बाद भारतीय गठबंधन राजनीति. इंडिया रिव्यू।
8. राजन, आर. (2021). लोकलुभावन राजनीति और राजनीतिक आख्यान. जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी।
9. गुप्ता, ए. (2014). भारत में राजनीतिक अभियान और सोशल मीडिया रणनीति. आर्थिक एवं राजनीतिक

साप्ताहिक।

10. नायर, पी. (2020). भारत में सोशल मीडिया और राजनीतिक ध्रुवीकरण. मीडिया वॉच।
11. कुमार, एस., एवं सिंह, आर. (2023). 2014 के बाद भारत में डिजिटल राजनीतिक संचार. एशियन स्टडीज जर्नल।
12. चड्ढा, के., एवं गुहा, पी. (2016). भारत के 2014 चुनाव में डिजिटल प्रचार और नागरिक भागीदारी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिकेशन।
13. मैकॉम्स, एम. (2014). एजेंडा सेटिंग थ्योरी. पॉलिटी प्रेस।
14. लाक्लाउ, ई., एवं मौफ, सी. (2001). हेजेमनी और समाजवादी रणनीति. वर्सो पब्लिशिंग।
15. एंडरसन, सी. डब्ल्यू., एवं तूर, एस. (2020). डिजिटल मीडिया और राजनीतिक कथानक. न्यू मीडिया एंड सोसाइटी।
16. एलियाज, के., एवं स्पीगलर, आर. (2018). प्रतिस्पर्धी राजनीतिक आख्यानों का मॉडल. अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 156–161

समसामयिक चित्रकला में उभरता नया अध्याय

ध्रुव, शोधार्थी, चित्रकला विभाग,
डॉ. कृष्ण यादव, शोध निदेशक
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़।

भारत में जिस व्यापक स्तर पर कला का विकास (परम्परागत चित्र शैलियाँ) किसी जमाने में हुआ था, गत पांच से भी अधिक दशकों में उस निष्ठा के साथ कार्य नहीं हुआ है, लेकिन जिनकों आगे चलना होता है, वे चलते भी हैं तथा तात्कालिक समय से संघर्ष करके भी अभिव्यक्ति के स्तर पर अपनी बात कहते हैं। परिवर्तन की अपनी प्रक्रिया होती है। गत कुछ वर्षों से इसकी गति तेज हो रही है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक परिवर्तनों, वैज्ञानिक अनुसंधानों टैक्नोलोजी के विकास आदि क्षेत्रों में जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ है, उससे अनेक मान्यताओं, सामाजिक रीतिरिवाजों, सोचने समझने के तरीकों एवं रहन–सहन आदि की प्रणाली में बदलाव आया है, इन सब परिवर्तनों के बीच राजस्थान में कला सृजन की दिशा भी बदली है।

(क) इन्स्टॉलेशन आर्ट :–

इन्स्टॉलेशन जो आज यूरोप से आयायित होकर भारत में आ गयी है। इसके कारण कला वस्तु गैलरी की सीमाओं से निकलकर बाहर आ गई है। बिग ब्रदर अमेरिका में हर चीज को बड़ा दिखाने का रिवाज है। इस ख्याल ने यहाँ भी चित्रकारी से बड़े–बड़े इन्स्टॉलेशन या संपुजन पेश करने आरम्भ कर दिए हैं।

इन्स्टॉलेशन में कला की मात्रा कितनी है? कलाकार वक्तव्य को वह कितना स्पष्ट और व्यक्त कर पाता है उसमें मौलिकता कितनी है. उसकी सीमाएँ और सम्भावनाएं कितनी हैं? यह बहुत कुछ कलाकार और उसकी कृति पर निर्भर करती हैं, जैसे कि हुसैन ने कुछ वर्ष पहले पुरी गैलरी में फर्श पर मुड़े–तुड़े अखबार फैला दिए थे और ऊपर बिना किसी तादात्म्य से सफेद कपड़े के पूरे के पूरे थान टाँग दिए थे. इसका नाम रखा 'श्वेताम्बरी'। इस इन्स्टॉलेशन की बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। तब से अब तक नए–पुराने कई भारतीय चित्रकारों ने इन्स्टॉलेशन किए। एक कलाकार ने गैलरी के बीचों बीच साईकिल लाकर टांग दी और उसमें एक मोटर लगाकर निरन्तर उसे चलने दिया और नाम रखा 'जीवन चक्र'। इसी तरह से 1912 में मार्शल डुचौम ने किया था, एक 'यूरिनल' को आर्ट गैलरी में रख दिया और नाम दिया 'फव्वारा' 1912 में इन्स्टॉलेशन का जो बीज पड़ा था वो 60 के दशक में यूरोप में चलन में आया। इसके जरिये कोशिश की थी कि जो कुछ भी हम देखते हैं वह सब कला के रूप में माना जाना चाहिए।

भारत में इन्स्टॉलेशन आर्ट को हाल ही में कुछ कलाकारों ने अपनाना शुरू किया 'एम.एफ. हुसैन' ने 1990 में नई दिल्ली की श्री धराणी गैलरी में 'थियेटर ऑव दी एब्सर्ड' शीर्षक से एक नवप्रवर्तनकारी इन्स्टॉलेशन प्रस्तुत

किया। जिन अन्य कलाकारों ने इन्स्टॉलेशन आर्ट की दिशा में काम किया है वे है–

'अमरनाथ सहगल, सतीश गुजराल, विवान सुन्दरम्, वेदनायर, गोगी सरोज पाल और रतनावली कान्तं। सम्भवतः विवान सुन्दरम और वेद नायर इस कला क्षेत्र में नियमित रूप से साफतौर पर झलकते हैं। कुछ समय पहले शमशाद हसैन, लतिका कट्ट, एन. काम करते रहे हैं। इनकी इन्स्टॉलेशन में राजनीतिक और उत्तर–आधुनिक सरोकार पुष्पमाला, सोमन, राजेन्द्र टिक्कू, वाल्सन कोल्लेरी, एन.एन. सिमसन, शीला गौड़ा, नरेश कपूरिया, अपर्णा कौर जैसे अनुभवी कलाकारों ने भी इन्स्टॉलेशन की कृतियाँ बनाई हैं। वस्तुतः भारत में इन्स्टॉलेशन आर्ट का हाल ही में विकास हुआ है। कला के इस स्वरूप ने सृजनात्मक चाक्षुक अभिव्यक्ति के पारम्परिक रूप से मुक्ति पा ली है और उसमें प्रदर्शनकारी कलाओं यथा स्टूडियों तथा वीडियो कार्यक्रमों को भी शामिल कर लिया गया है इस तरह निर्मित बड़ी स्थापनाओं ने अब वास्तुकला, डिजाईन तथा ललित कला की सीमाओं को ही तोड़ डाला है। इसने ऐसी अभिव्यक्ति को जन्म दिया है जो संग्रहालय के बजाय थियेटर के अधिक निकट जान पड़ती है। समसामयिक संस्कृति की उपज होने के कारण यह अस्थायित्व तथा परिवर्तन पर बल देती है।

आज के दौर में निर्माण और इन्स्टॉलेशन कला का जो स्वरूप है, उसे हम पारम्परिक कला शैलियों में मिलने वाले चित्रोपम सौन्दर्य का अभाव ही पाते हैं। इसने तो हमारी कला की अवधारणा को ही बदल डाला है। पश्चिम की कला परम्परा में नितान्त निजी अभिव्यक्ति के रूप में 'इन्स्टॉलेशन आर्ट की एक विशिष्ट अवधारणा है। यह हमारे यहाँ की पारम्परिक इन्स्टॉलेशन की तुलना में जिनकी जड़ें लोक तथा आनुष्ठानिक संस्कारों में है, से भिन्न तरह की अभिव्यक्ति है–उदाहरण के लिए हमारे यहाँ दशहरे के समय रावण के पुतलों को जलाने की उत्सव धर्मिता की तुलना में भारत के हर प्रांत में होने वाली यह घटना प्रकाश ध्वनि तथा गति की एक असाधारण झांकी तो है ही, वरण इसमें नैतिक मूल्यों का शुमार भी रहता है ऐसा ही एक उदाहरण दर्गा–पूजा त्यौहार का दिया जा सकता है जब नवरात्रे के दिनों में दर्गा को महिषासुर मर्दिनीं के रूप में खूब सज्जित प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और दशहरे के दिन उसे किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है।

इन्स्टॉलेशन आर्ट शिल्प संबंधी सामग्री व अन्य माध्यमों का उस दिशा को सुधारने में प्रयोग करती है जिसमें कि हम विशेष स्थान का अनुभव करते हैं। यह कला केवल दीर्घा अवकाश तक ही सीमित नहीं होती बल्कि यह दैनिक, सार्वजनिक, व्यक्तिगत स्थान पर सामग्री व्यवधान भी हो सकता है। यह विशेष वातावरण में किसी एक अनुभव को स्थापित करने के लिए किसी भी माध्यम को संयुक्त करती है। समसामयिक इन्स्टॉलेशन आर्ट में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का विस्तार दैनिक और प्राकृतिक सामग्री से लेकर हुए माध्यमों जैसे कि दृश्य, ध्वनि, प्रस्तुति, कम्प्यूटर, इंटरनेट तक होता है। कुछ स्थापनाऐं स्थान विशेष होती है जिनका अस्तित्व उसी स्थान के लिए तैयार किया जाता है जिनके लिए वो उत्पन्न होती हैं। बहुत से लोग कला के इस रूप की जड़े प्रारम्भिक कलाकारों जैसे कि 'मार्शल डुचौम' को मानते हैं तथा मूर्तिकला पर आधारित पारम्परिक कला की अपेक्षा तैयार वस्तुओं के अधिक प्रयोग को मानते हैं, अपेक्षाकृत बाद की जो इन्स्टॉलेशन आर्ट है उसमें कलाकार का उद्देश्य सर्वोतम होता हैं जिसकी जड़े 60 के दशक की भाव सम्बंधी कला में निहित है। फिर से यह पारम्परिक मूर्तिकला से प्रस्थान करती है। प्रत्येक भारतीय इन्स्टॉलेशन आर्ट में वे धारणाएं शामिल होती है जैसे 1954 में जापान में शुरू हुए गुटल ग्रुप के द्वारा मंच पर की जाने वाली घटनाएँ शमिल हैं जिसने अमेरिकन इन्स्टॉलेशन आर्ट के एलन कप्रू जैसे पथ प्रदर्शक को भी प्रभावित किया।

आधुनिक कला का एक प्रकार जिसमें कि कलाकार विशेष व्यवस्था को जैसे कि दिवारें, फर्श, लाइट और फीटिंग विभिन्न सामग्री के साथ रचना के एक भाग के रूप में प्रयुक्त करता है। विशेष रूप से चुनी हुई सामग्री या स्थान को न्यूनाधिक बना देती है और दर्शक प्रायःचारों तरफ घूमने में समर्थ हो जाता है या फिर कार्य के साथ अन्तः क्रिया करता है ताकि वे समय के उस विशेष क्षण में उस कार्य का भाग बन सकें। कला के इस भाग के विभिन्न पूर्व भाग हैं परन्तु यह 80 के दशक तक सामने नहीं कला को इस भागल कारों ने इन्स्टॉलेशन आर्ट में विशेषज्ञता प्राप्त करना शुरू किया यह कार्य साधारणतः अस्थायी होते है परन्तु कई कार्य संरक्षित होते है। 1958 में एक कलाकार ने एक प्रदर्शनी आयोजित की जिसमें कि एक रिक्त कक्ष सम्मिलित था जिस भाव से स्थापना शब्द का प्रयोग होने लगा है। यह कई बार प्रथम स्थापना के रूप में सम्मानित की जाती है।

इसमें 'एट दिस मूमैन्ट' शब्दों को जोड़कर योग्य शीर्षक बनाया जा सकता हैं। मैं इस शब्द इन्स्टॉलेशन को प्रसारण भाव में भाव संबंधी कला, प्रकाश और स्थान पर्यावरण कला और वीडियों कला एवं प्रदर्शन कला को स्वीकार करने के लिए लेता हूँ, मैं मुहावरे के पूर्ण इतिहास को प्रकट नहीं कर सकता जैसा कि मेरा अनुमान है कि डुचौम के समय तक पीछे जाना चाहिए परन्तु मैं जोसेफ व्यूज के बारे में जरूर कहूंगा जिसनें वस्तुओं के असंगत संयोजन को और स्पष्टतः असंगत सामग्रियों के साथ संयुक्त किया उस कला की रचना करने के लिए जिसका प्रभाव सौन्दर्यात्मक न होकर प्रतीकात्मक था। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि जैसा कलाकार चाहता है वैसा ही वह किसी भी प्रकार की सामग्री का किसी भी प्रकार से प्रयोग करने में समर्थ है।

इस प्रकार इस कला की मुख्य विशेषता इसकी निरवता. अस्थायी भाव और इन्स्टॉलेशन आर्ट का महत्व कलाकार के वास्तविक सामग्री के साथ लगाव में है जिसने कि इसे गैर व्यवसायिक और विस्मरणीय बनाया। इन्स्टॉलेशन आर्ट में तेल, फल, तांबा, कीचड आदि पदार्थों का प्रयोग किया गया। शुरू में कुछ कलाकारों ने इन्स्टॉलेशन आर्ट को विरोध के रूप में प्रयोग किया। क्षणभंगुर मिगुर प्रकृति में हैफिर 90 के दशक में कैरन फिनले की इन्स्टॉलेशन की रचना हई जिसमें उसने एड्स पीडित लोगों के दुःख को वास्तविकता प्रदान की जैसे कि बोलेटेन्सकी सार्किस जो कि दिल्ली में आधुनिक कला की राष्ट्रीय दीर्घा में देखें जाते थे वो कई वर्षों पहले स्पष्ट अर्थ से वंचित थे। कलाकार की बढ़ती हुई श्रेष्ठता को पुनः बलित करते हुए प्रायः इन्स्टॉलेशन के लिए यह विशेष उद्देश्य के रूप में है।

(ख) डिजिटल आर्ट :

डिजिटल कला एक उभरता हुआ कलारूप हैं जिसमें कि पारम्परिक चित्रण तकनीकी (वॉटर, ऑयल) आदि का कम्प्यूटर, अंकन, सारणी और सॉफ्टवेयर के साधनों का प्रयोग करते हुए काम में ली जाती है। डिजिटल पेन्टिंग डिजिटल आहे के अन्य प्रकार से भिन्न है। विशेष रूप से कम्प्यूटर जनित कला। इसमें एक नमूने से बनाए गए कम्प्यूटर को शामिल नहीं किया जा सकता। कलाकार चित्रकला तकनीकी का कम्प्यूटर पर डिजिटल और पारम्परिक चित्रकला में मुख्य अन्तर अरेखीय प्रक्रिया है। एक कलाकार अपनी पेन्टिंग्स को सतहों में व्यवस्थित कर सकता है जिन्हें कि स्वतंत्र रूप से सम्पादित किया जा सकता है। स्ट्रॉक्स को नहीं करने और दोबारा करने की योग्यता कलाकार को रेखीय प्रक्रिया से मुक्त करती है। परन्तु डिजिटल पेन्टिंग यहां तक सीमित है कि किस प्रकार यह पारम्परिक चित्रकार के अध्ययन और तकनीकी का प्रयोग करती है डिजिटल कलाकार के पास ऐसे कई साधन होते हैं जो पारम्परिक कलाकार के पास नही होते इनमें से कुछ यह है– लोगों रंगों

से युक्त वरचुअल प्लेट, किसी भी प्रकार का कैनवास, गलतियों को सुधारने की योग्यता, द्विआयामी और त्रिआयामी साधन। डिजिटल पेन्टिंग अधिकांशतः उत्पादन कला में पनपती है यह अधिकतर फिल्म, टी.वी. या वीडियों के उपचारात्मक नमूनों के लिए प्रयोग की जाती है। डिजिटल पेन्टिंग, सॉफ्टवेयर जैसे कि कोरल पेन्टर, एडोब फोटोशॉप, आर्ट रेंज, जी.आई.एम.पी. और कैनवास कलाकार को भौतिक चित्रकार के समान वातावरण प्रदान करता है। एक कैनवास, चित्रकला के साधन, मिक्सिंग प्लेट, रंग विकल्प की अधिकता डिजिटल पेन्टिंग के विभिन्न प्रकार हैं।

सामान्य रूप से कम्प्यूटर तकनीक का प्रयोग करके रचित कार्य डिजिटल आर्ट के नाम से जाना जाता है। कला का यह युग कथित रूप से 1970 में प्रारम्भहुआ जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है। परन्तु वास्तव में इसने अपने पैरों पर खड़ा होना 20 वी शताब्दी के अन्त तक शुरू किया जब कम्प्यूटर का हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाने लगा यह एक ऐसा काल था जब आधुनिक डिजिटल साधन जैसे सॉफ्टवेयर तथा अधिक फंक्शन वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण विशेषतः भारत में प्रयोग किए गए। नियोग्राफी और त्रिआयामी कला जो इस विशाल कला क्षेत्र में विभिन्न उपखंडों में से केवल दो है जो वस्तुओं को अकाल्पनिक बना सकते हैं। हर प्रदर्शनकारी की तरह डिजिटल आर्ट भी विवाद का विषय रहा है और अपने लिए अच्छी और बुरी भावनाएं आकर्षित करता है। डिजिटल आर्ट के विरूद्ध जो कलाएं है वो अपने अंक बनाती है। जैसे कम्प्यूटर कलाकार का कार्य करता है और यह कार्य बहुत बार पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। जो इसे अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण बना देता है। परन्तु यदि कलाकार अपने कार्य को अद्वितीय ओर अनुत्पादक बना देता है। इस प्रकार की कला का एक निश्चित लाभ यह है कि आधुनिक प्रिन्टिंग तकनीकी होने के कारण इन प्रिन्ट के रंग एक शताब्दी तक धूमिल नहीं पड़ते। डिजिटल रूपान्तरण एवं म्यूजिक और वीडियों तथा डिजिटल फोटोग्राफी एवं स्केनिंग ने भी कला संसार में स्वीकृति प्राप्त की है और अपनी जड़े मजबूत की है।

ब्रश, फिल्टर ओर एनलॉर्जर के विद्युत रूपों का प्रयोग करके यह नियोग्राफर्स एवं डिजिटल कलाकार–ऐसी आकृतियाँ उत्पन्न करते है जिन्हें पारम्परिक फोटोग्राफिक साधनों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त डिजिटल आर्टिस्ट–पेन्टिंग, ड्राइंग, कोलाज और लिथोग्राफ को कुशलता से कर सकते हैं। साथ ही ऊपर दी गई तकनीकों में से किसी भी तकनीक सयोजन का प्रयोग कर सकते है। कलाकार अपने कार्य की रचना करने के लिए सूचना और कार्यक्रम के बहुत से साधनों का प्रयोग करते हैं। डिजिटल आर्टिस्ट को डिजिटल ग्राफिक्स आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल आर्टिस्ट को डिजिटल ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, डिजिटल फोटोग्राफी तकनीक और कम्प्यूटर असिस्टिड पेन्टिंग को नवीन कला रचित करने के लिए उत्पन्न किया जाता है यह नवाचार केवल तकनीकी रूप में ही नहीं हैं परन्तु उनके कार्य के सहयोगी पहलुओं में भी है। डिजिटल मीडिया एक रचनात्मक प्रयास के द्वारा साधन (उपकरण) आंदोलन को तर्क देता है। जिसमें कि प्रयोगकर्ता अद्वितीयक कलाकृतियों को सृजन करने के लिए एक प्रोजक्ट में सहयोग दे सकता है।

डिजिटल आर्ट आजकल मुख्य धारा बन गई है इसका एक मुख्य कारण है कि इमेज को परिक्षित करने वाला पकाया पहले की अपेक्षा अधिक डिजिटल है जैसे डिजिटल कैमरा डिजिटल माइक्रोस्कॉप। ये सब आज विस्तृत रूप से उपलब्ध हैं और इसका विस्तृत रूप में प्रयोग किया जाता है। इमेज का डिजिटल परिरक्षण प्रयोगकर्ता को एनालॉग मैटीरियल की अपेक्षा अधिक आसानी से वितरित करने की अनुमति देता है। कला इन

प्रगतियों के साथ गति बनाये रखते हुए नए रिव्यू सिस्टम को पूर्णतः डिजिटल समीक्षक इस सिस्टम की प्रशंसा करते है जो उनके कार्यों को अधिक तेजी से और अधिक प्रभावशाली तरीके से करते है। इन सभी तकनीकों का प्रयोग इकटठा किया जाना चाहिए, ताकि यह अधिकतम् लाभ दे सके।

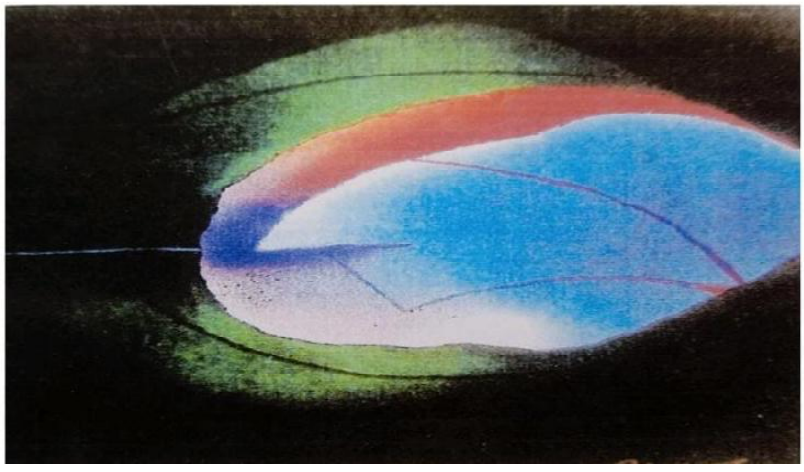
डिजिटल आर्ट को अभी सम्मान और स्वीकृति जो कि गम्भीर कला रूपों जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, और आरेखन कला के लिए आरक्षित है, मिलना बाकी है। यह कार्य करने में कम्प्यूटर हमारी सबसे अधिक मदद करता है। कम्प्यूटर का प्रयोग संगीत बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि कम्प्यूटर ध्वनि नमूनों को पैदा करने और व्यवस्थित करने का शक्तिशाली तरीका प्रस्तुत करता है। यह सम्भव है कि डिजिटल आर्ट के महत्तव की सामान्य स्वीकृति उसी तरीके से विकास को प्राप्त होगी जिस प्रकार पिछले दशकों में विद्युत जनित म्यूजिक की स्वीकृति बढ़ी है।

कुछ लोग कहते हैं कि हम उत्तर डिजिटल युग में हैं जहां कला संसार में डिजिटल तकनीकी कोई नयी बात नही हैं। डिजिटल साधन निर्माण कला की प्रक्रिया का एक सम्पूर्ण भाग बन गए हैं। रॉय एस्कॉर्ट ने 21वीं शताब्दी की कला के लिए 'मोस्ट मीडिया' आधार को उत्पति की तरफ इशारा किया। डिजिटल फोटोग्रॉफी और डिजिटल प्रिन्टिंग आजकल मुख्य संग्रहालयों और गैलरी के द्वारा रचना और प्रस्तुति का संतोषजनक माध्यम है। डिजिटल कलाकारों का कार्य 'रोबोटिक इन्स्टॉलेशन' और नेट आर्ट तथा सॉफ्टवेयर आर्ट के द्वारा आधार प्राप्त कर रहा हैं परन्तु डिजिटल पेन्टर और प्रिन्ट मेकर के कार्य ने स्वीकृति प्राप्त करना अभी शुरू किया है। जैसे–जैसे योग्यताएँ आगे बढ़ती है तथा गुणवता बढ़ती है।

अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संग्रहालयों ने डिजिटल आर्ट का संग्रह करना आरम्भ किया है। सेन्ट जॉन्स म्यूजियम ऑफ आर्ट विक्टोरिया और अल्बर्ट म्यूजियम प्रिन्ट डिपार्टमेंट में भी डिजिटल आर्ट का संग्रह है। साथ ही ऑन लाईन कला दीर्घाएं भी लोकप्रिय हो रही हैं। आर्ट ओवर अमेरिका जैसे स्थल भी डिजिटल आर्ट की रचनाओं को प्रोत्साहित करने के तरीके ढूँढ रहे हैं। कला समुदाय डिजिटल आर्ट को स्वीकार करने में कठिनाई समझता है। इसका एक कारण डिजिटल प्रिन्ट के अशुद्ध ज्ञान का लगातार पूर्व उत्पादन होना है। इसका कारण दीघो है। आज की डिजिटल प्रिन्टिग धीमें रंगों या हल्के रंगों वाली 60–100 वर्षो तक घटित नहीं होगी।

चित्रः-

चित्र संख्या 1 **शीर्षक विहीन**



चित्र संख्या 2 शीर्षक विहीन



सन्दर्भ ग्रन्थ सूचि/पत्र-पत्रिकाएं :

1. शुक्ल रामचन्द्र, कला अथवा आधुनिक प्रवर्तक राजश्री पुरूषोत्तम दास टंडन हिन्दी भवन, लखनऊ।
2. गौतम आर. बी., राजस्थान की समसामयिक कला राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर।
3. भारद्वाज विनोद, संप्रदाय समकालीन भारतीय कला राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. कुमार सुनील, भारतीय छपा चित्रकला आदि से आधुनिक काल तक भारतीय कला प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. साखलाकर आर. वी., आधुनिक चित्रकला का इतिहास राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
6. गोस्वामी प्रेमचन्द, आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तम्भ राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर।
7. बोहल शोध मंजूषा, संपादक डॉक्टर नरेश सिहाग एडवोकेट।

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 162-167

संस्कृत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग : संभावनाएँ, उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ



डॉ. वर्षा रानी
असि. प्रो. संस्कृत विभाग,
डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence—AI) वर्तमान युग की सबसे प्रभावशाली तकनीकों में से एक है, जिसने भाषा, शिक्षा, चिकित्सा, संचार तथा अनुसंधान के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन किए हैं। संस्कृत, जो विश्व की सर्वाधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक भाषाओं में मानी जाती है, AI अनुसंधान के लिए विशेष महत्त्व रखती है। पाणिनीय व्याकरण की नियमबद्ध संरचना, शब्द–निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया तथा अर्थ–संबंधों की स्पष्टता के कारण संस्कृत भाषा प्राकृतिक भाषा संसाधन (Natural Language Processing—NLP) के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। वर्तमान समय में संस्कृत के लिए रूपविश्लेषण (Morphological Analysis), सन्धि–विच्छेद, समास विश्लेषण, मशीन अनुवाद, वाक्य विश्लेषण, ज्ञान–आधारित प्रणालियाँ तथा बड़े भाषा मॉडल (Large Language Models) विकसित किए जा रहे हैं। SanskritShala और SansGPT जैसे आधुनिक उपकरण संस्कृत एवं AI के समन्वय के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रस्तुत शोध आलेख में संस्कृत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्संबंध ा, विभिन्न अनुप्रयोगों, वर्तमान उपलब्धियों, चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

1. प्रस्तावना :

वर्तमान युग सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। भाषा विज्ञान भी इससे अछूता नहीं रहा। मशीनों को मानव भाषा समझाने और उसका विश्लेषण कराने की प्रक्रिया को प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP) कहा जाता है।

संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसकी व्याकरणिक संरचना अत्यंत व्यवस्थित, तार्किक तथा नियमाधारित है। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी को विश्व का पहला औपचारिक व्याकरण माना जाता है। अनेक भाषाविद् एवं कम्प्यूटर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि पाणिनीय व्याकरण की संरचना आधुनिक एल्गोरिद्म और औपचारिक भाषा सिद्धांतों से साम्य रखती है। इसी कारण संस्कृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं संगणकीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में विशेष आकर्षण का विषय बनी हुई है।

2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता : अवधारणा एवं स्वरूप :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) वह तकनीक है जिसके माध्यम से कम्प्यूटर या मशीनें

मानव–सदृश बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य कर सकती हैं। इसमें सीखना, तर्क करना, समस्या–समाधान, निर्णय लेना तथा भाषा को समझना शामिल है।

AI के प्रमुख क्षेत्र हैं –

1. मशीन लर्निंग (Machine Learning)
2. डीप लर्निंग (Deep Learning)
3. प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP)
4. कंप्यूटर विजन
5. विशेषज्ञ प्रणाली (Expert Systems)
6. रोबोटिक्स।

भाषा से संबंधित AI अनुप्रयोगों में NLP की विशेष भूमिका है। संस्कृत भाषा में AI का अधिकांश कार्य NLP पर आधारित है।

3. संस्कृत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध :

संस्कृत की संरचना अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक नियमबद्ध है। प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति, धातु, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक का स्पष्ट निर्धारण किया जा सकता है। यह विशेषता कम्प्यूटर द्वारा भाषा के विश्लेषण को अपेक्षाकृत सरल बनाती है।

संस्कृत की AI-अनुकूल विशेषताएँ :

- व्याकरणिक नियमों की स्पष्टता।
- पाणिनीय सूत्रों की तार्किक संरचना।
- शब्द निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया।
- अर्थ की अपेक्षाकृत कम अस्पष्टता।
- औपचारिक भाषा के रूप में उपयोगिता।

इन्हीं कारणों से संस्कृत को संगणकीय भाषाविज्ञान में एक महत्त्वपूर्ण भाषा माना जाता है।

4. प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP) में संस्कृत :

प्राकृतिक भाषा संसाधन AI का वह क्षेत्र है जिसमें कम्प्यूटर मानव भाषा को समझने, विश्लेषित करने तथा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं।

संस्कृत में NLP के निम्न प्रमुख अनुप्रयोग विकसित किए जा रहे हैं –

4.1 शब्द विभाजन (Word Segmentation)

संस्कृत में सन्धि के कारण अनेक शब्द मिलकर एक रूप धारण कर लेते हैं। AI आधारित प्रणालियाँ इन संयुक्त शब्दों को पृथक करने का कार्य करती हैं।

उदाहरण :

रामोऽस्ति ऊँ रामः + अस्ति।

इस प्रकार की तकनीकें संस्कृत पाठों को मशीन द्वारा समझने में सहायक हैं।

4.2 रूपविश्लेषण (Morphological Analysis)

संस्कृत शब्दों की जटिल संरचना को समझने हेतु AI आधारित रूपविश्लेषक विकसित किए गए हैं। ये किसी शब्द की धातु, विभक्ति, लिंग, वचन तथा प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं।

4.3 समास विश्लेषण :

संस्कृत में समासों का अत्यधिक प्रयोग होता है। AI आधारित प्रणालियाँ समस्तपदों के घटकों तथा उनके संबंधों का विश्लेषण करने में सक्षम हो रही हैं।

5. मशीन अनुवाद में संस्कृत :

मशीन अनुवाद (Machine Translation) AI का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

संस्कृत से हिन्दी, अंग्रेजी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में स्वचालित अनुवाद हेतु अनेक शोध परियोजनाएँ चल रही हैं। इन प्रणालियों के माध्यम से विशाल संस्कृत साहित्य को आधुनिक भाषाओं में उपलब्ध कराया जा सकता है।

मशीन अनुवाद के प्रमुख लाभ –

- प्राचीन ग्रन्थों की व्यापक पहुँच।
- शोध कार्य में सुविधा।
- भाषा अध्ययन को सरल बनाना।
- भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक प्रसार।

6. संस्कृत आधारित AI उपकरण

6.1 SanskritShala :

IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित SanskritShala संस्कृत NLP का एक उन्नत मंच है। यह शब्द विभाजन, रूपविश्लेषण, निर्भरता विश्लेषण (Dependency Parsing) तथा समास वर्गीकरण जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। यह संस्कृत के लिए उपलब्ध प्रमुख न्यूरल NLP टूलकिटों में से एक है।

6.2 SansGPT :

SansGPT संस्कृत भाषा के लिए विकसित एक जनरेटिव प्री–ट्रेंड मॉडल है। यह संस्कृत पाठों के विशाल संकलन पर प्रशिक्षित है तथा अर्थ–विश्लेषण, नामित इकाई पहचान (NER), उपमा विश्लेषण एवं अन्य NLP कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है। शोध में इस मॉडल ने कई कार्यों में उच्च सटीकता प्रदर्शित की है।

6.3 भाषा विश्लेषक और व्याकरण परीक्षक :

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों द्वारा संस्कृत भाषा विश्लेषक, व्याकरण परीक्षक तथा स्पीच–टू–टेक्स्ट उपकरण विकसित किए जा रहे हैं।

7. संस्कृत पाण्डुलिपियों के संरक्षण में AI :

भारत में लाखों संस्कृत पाण्डुलिपियाँ विभिन्न पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इनमें से अनेक पाण्डुलिपियाँ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं।

AI आधारित तकनीकों का उपयोग –

- OCR (Optical Character Recognition)

- डिजिटल पुनर्निर्माण।
- पाठ पुर्नस्थापन।
- स्वचालित अनुक्रमण
- पाठ खोज (Text Search)

जैसे कार्यों में किया जा रहा है।

इससे दुर्लभ ग्रन्थों का संरक्षण एवं अध्ययन संभव हो रहा है।

8. संस्कृत एवं ज्ञान-आधारित AI

संस्कृत साहित्य केवल भाषा नहीं, बल्कि ज्ञान का विशाल भंडार है। वेद, उपनिषद्, आयुर्वेद, योग, न्याय, मीमांसा तथा दर्शन में निहित ज्ञान को **AI** प्रणालियों में समाहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ज्ञान-आधारित AI के संभावित क्षेत्र –

- वैदिक ज्ञान प्रणाली।
- आयुर्वेदिक विशेषज्ञ प्रणाली।
- योग परामर्श प्रणाली।
- दार्शनिक प्रश्नोत्तर प्रणाली।
- संस्कृत ज्ञान ग्राफ (Knowledge Graph)

कुछ शोधकर्ता वैदिक ग्रन्थों के लिए AI आधारित खोज प्रणालियाँ विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं।

9. संस्कृत शिक्षण में AI का योगदान :

AI ने संस्कृत शिक्षण को अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाया है।

प्रमुख नवाचार :

1. AI चैटबॉट।
2. वर्चुअल शिक्षक।
3. गेम आधारित शिक्षण।
4. व्यक्तिगत अधिगम प्रणाली।
5. उच्चारण विश्लेषण उपकरण।

हाल में AI एवं गेमिंग आधारित संस्कृत शिक्षण मॉडल विकसित किए गए हैं जो विद्यार्थियों को संवादात्मक तरीके से संस्कृत सिखाते हैं।

10. पाणिनीय व्याकरण और AI

महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों का अत्यंत सुव्यवस्थित व्याकरणिक तंत्र है।

AI शोधकर्ताओं के लिए पाणिनीय व्याकरण महत्त्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि –

- यह नियम आधारित (Rule-Based) प्रणाली है।
- इसमें औपचारिक निरूपण मिलता है।
- व्याकरणिक निर्णय क्रमबद्ध हैं।
- भाषा–प्रसंस्करण के लिए स्पष्ट निर्देश उपलब्ध हैं।

आधुनिक NLP मॉडल पाणिनीय सिद्धांतों का उपयोग करके अधिक सटीक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं।

11. संस्कृत और बड़े भाषा मॉडल (LLMs)

ChatGPT, Gemini तथा अन्य बड़े भाषा मॉडल भाषा समझने एवं उत्पन्न करने में सक्षम हैं।

संस्कृत के लिए विशेष LLM विकसित करने के प्रयास जारी हैं। हाल के शोध यह भी संकेत देते हैं कि संस्कृत की संक्षिप्त अभिव्यक्ति और समृद्ध व्याकरणिक संरचना भाषा मॉडल अनुसंधान में नए अवसर प्रदान कर सकती है।

12. चुनौतियाँ :

संस्कृत में AI के विकास के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं –

12.1 डेटा की कमी :

आधुनिक भाषाओं की तुलना में संस्कृत के डिजिटाइज्ड कॉर्पस सीमित हैं।

12.2 जटिल व्याकरण :

संस्कृत की समृद्ध रूपात्मक संरचना मशीनों के लिए चुनौती प्रस्तुत करती है।

12.3 विशेषज्ञों का अभाव :

संस्कृत एवं AI दोनों क्षेत्रों में दक्ष शोधकर्ताओं की संख्या अभी सीमित है।

12.4 मानकीकरण की समस्या :

विभिन्न ग्रन्थों में भिन्न पाठ एवं लेखन पद्धतियाँ मिलती हैं, जिससे डेटा निर्माण कठिन हो जाता है।

13. भविष्य की संभावनाएँ :

भविष्य में संस्कृत और AI का समन्वय निम्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है–

- संस्कृत आधारित डिजिटल सहायक।
- स्वचालित संस्कृत अनुवादक।
- वैदिक ज्ञान खोज प्रणाली।
- आयुर्वेदिक विशेषज्ञ प्रणाली।
- संस्कृत वाणी पहचान (Speech Recognition)
- संस्कृत आधारित ज्ञान ग्राफ।
- भारतीय ज्ञान परम्परा के AI मॉडल।

IIT खड़गपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थानों के शोध यह संकेत देते हैं कि संस्कृत AI अनुसंधान का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन सकती है।

उपसंहार :

संस्कृत और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध केवल एक भाषाई प्रयोग नहीं, बल्कि परम्परा और आधुनिकता का अद्‌भुत समन्वय है। पाणिनीय व्याकरण की वैज्ञानिकता, संस्कृत की संरचनात्मक स्पष्टता तथा आधुनिक AI तकनीकों का संयोजन भविष्य में भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई संभावनाएँ खोल सकता है। संस्कृत के लिए विकसित NLP उपकरण, मशीन अनुवाद प्रणालियाँ, AI मॉडल तथा डिजिटल शिक्षण मंच इस दिशा में महत्त्वपूर्ण

उपलब्धियाँ हैं। यदि पर्याप्त अनुसंधान, संसाधन और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाए, तो संस्कृत न केवल भारतीय ज्ञान परम्परा के संरक्षण का माध्यम बनेगी, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

पुस्तकें :

1. पाणिनि – अष्टाध्यायी, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।
2. पतञ्जलि – महाभाष्य।
3. बलदेव उपाध्याय – संस्कृत साहित्य का इतिहास।
4. कपिलदेव द्विवेदी – संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास।
5. George Cardona – Panini : A Survey of Research.
6. Sheldon Pollock – The Language of the Gods in the World of Men.

शोध-पत्र एवं ऑनलाइन स्रोत :

7. Sandhan, J. et al. **SanskritShala: A Neural Sanskrit NLP Toolkit with Web-Based Interface for Pedagogical and Annotation Purposes.** ACL 2023.
8. Chaudhari, **R. et al. SansGPT: Advancing Generative Pre-Training in Sanskrit.** ICON 2024.
9. Pathak, Vivek. **Artificial Intelligence and Sanskrit: The Role of Computational Linguistics.** Journal of Asiatic Society for Social Science Research, 2025.
10. IIT Kharagpur, **Sanganaka Sanskrit Computational Research Lab.**
11. Delhi University, **Computer Applications for Sanskrit and Computational Linguistics Initiatives.**
12. Sandhan, J. **Linguistically-Informed Neural Architectures for Lexical, Syntactic and Semantic** Tasks in Sanskrit.
13. Kumar, **Anshul. Is Sanskrit the Most Token-Efficient Language?** 2026.
14. Built in a Lab : Bhopal Teacher Gives AI Gaming Makeover to Sanskrit Learning. Times of India, 2026.
15. Aesthetics of Sanskrit Poetry from the Perspective of Computational Linguistics.

Mail : vasu14rani@gmail.com

Mob – 9671904323

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 168–174

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में आपदा प्रबन्धन हेतु शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

Study of Awareness of Disaster Management Education Among Secondary Level Students

डॉ. नुपूर अग्रवाल
सहायक आचार्य,
जवाहर लाल नेहरू टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कोटा (राजस्थान)



सार :

आपदा प्रबन्धन प्राकृतिक या मानव निर्मित खतरों के प्रभावों को कम करने, उनकी तैयारी, तत्काल प्रतिक्रिया और पुर्ननिर्माण की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य जान–माल की रक्षा करना, जोखिम को कम करना और सामान्य जीवन को जल्द से जल्द बहाल करना है।

सूखा, बाढ़, चक्रवर्ती तूफानों, भूकम्प, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग और ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक कम किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए माध्यमिक स्तर से ही आपदा प्रबन्ध की शिक्षा सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। प्रस्तुत शोध हेतु कोटा जिले के सरकारी एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों के कुल 60 विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।

निष्कर्ष रूप में सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी, निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में कुछ अधिक जागरूक पाये गये हैं।

1. प्रस्तावना –

भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक–सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। वृहद् भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधताओं और सांस्कृतिक बहुलता तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण अनेक प्रकार की घटनाएँ घटित होती है जिनमें आपदा भी प्रमुख है। आपदा किसी समाज को कार्य करने की क्षमता को बाधित करती है, जिसके परिणामस्वरूप मानव जीवन को व्यापक क्षति पहुँचती है।

इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एण्ड रेड क्रिसेट सोसाइटीज के अनुसार प्राकृतिक आपदाएँ (भूकम्प, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, बाढ़, सूखा, जंगल में आग, चक्रवात, तूफान, महामारी इत्यादि) प्राकृतिक रूप से होने वाली शारीरिक घटनाएँ है जिनका प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर तत्काल पड़ता है

और आगे चलकर मृत्यु और पीड़ा का कारण बन सकता है। वहीं मानव निर्मित आपराएँ (प्रदूषण, दुर्घटनाएँ) मनुष्यों द्वारा होने वाली घटनाएँ है जो मानव बस्तियों में या उसके करीब घटित होती है जो अक्सर पर्यावरणीय या तकनीकी आपात स्थितियों के परिणामस्वरूप होती है।

प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों के एक जटिल संयोजन से जटिल आपात स्थितियों (भोजन को असुरक्षा, सशस्त्र, संघर्ष, विस्थापित, आबादी, सुरक्षा जोखिम में वृद्धि) का निर्माण होता है।

उपरोक्त वर्णित आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबन्धन की आवश्यकता है।

आपदा प्रबन्धन में किसी आपदा के दौरान या उसके तुरन्त बाद जीवन बचाने, स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों की बुनियादी निर्वाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन सेवाओं और सार्वजनिक सहायता शामिल है। सभी को विदित है कि आज के विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आगे चलकर देश के युवा बनेंगे। अतः इन आपदाओं से बचाव हेतु आपदा शिक्षा की आवश्यकता है।

2. समस्या का औचित्य –

माध्यमिक स्तर से ही आपदा प्रबंधन हेतु शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। सूखा, बाढ़, चक्रवर्ती तूफानों, भूकम्प, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग और ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है लेकिन इनके प्रभाव को एक सीमा तक जरूर कम किया जा सकता है जब तक सक्षम रूप से आपदा प्रबन्धन का सहयोग न मिले प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं से अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। अतः यह जानने का प्रयास किया जाना चाहिए कि आखिर सरकार आपदा शिक्षा के प्रति जागरूक क्यों नहीं है।

3. समस्या कथन –

''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में आपदा प्रबन्धन हेतु शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन।''

"Study of Awareness of Disaster Management Education among Secondary Level Students."

4. शोध अध्ययन के उद्देश्य –

1. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्रों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्राओं की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

5. शोध परिकल्पनाएँ –

1. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्रों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

3. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्राओं की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

6. अनुसंधान में प्रयुक्त विधि, प्रविधि एवं उपकरण –

1. प्रस्तुत शोध वर्तमान की आवश्यकता से सम्बन्धित है तथा यह शोध कार्य व्यक्ति विशेष से संबंधित ना होकर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। इस शोध कार्य में सर्वेक्षण दत्तों का संकलन किया गया है। अतः शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।
2. इस शोध हेतु अमानीकृत उपकरण (स्वनिर्मित उपकरण) ''माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में आपदा प्रबन्धन हेतु शिक्षा के प्रति जागरूकता हेतु प्रमापनी का प्रयोग किया गया है।
3. सांख्यिकी – आँकडों के विश्लेषण हेतु आवृत्ति, मध्यमान, मानक विचलन व टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया है।
4. न्यादर्श – प्रस्तुत शोध कार्य हेतु यादृच्छिक विधि से कोटा जिले के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के कुल 60 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है जिसमें 30 (15+15 छात्र व छात्राएँ) सरकारी तथा 30 (15+15 छात्र व छात्राएँ) निजी विद्यालय है।

7. तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण –

- **आपदा प्रबन्धन** – यह एक प्रक्रिया है जिसमें सरकार, संगठन और समुदायों के संयोजन द्वारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं से होने वाली हानि को न्यायसंगत रूप से प्रबंधित और कम किया जाता है। इसका उद्देश्य जीवन, सम्पत्ति और पर्यावरण को सुरक्षा निश्चित करना है।
- **सरकारी विद्यालय** – ये स्कूल केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित स्वायत्त संगठनों द्वारा चलाए जाते है।
- **निजी विद्यालय** – सरकार के बजाय एक निजी समूह द्वारा स्थापित, संचालित और रखरखाव किया जाने वाला स्कूल जो अक्सर एक विशेष दर्शन, दृष्टिकोण आदि का पालन करता है।
- **महामारी** – बीमारी का प्रकोप जो तेजी से फैलता है।

8. शोध परिसीमन –

प्रस्तुत शोधकार्य हेतु कोटा शहर को चुना गया है जिसमें माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं निजी विद्यालय के छात्र–छात्राओं को शामिल किया गया है।

9. व्याख्या एवं विश्लेषण –

परिकल्पना 1. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सारणी संख्या 1

माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता का मध्यमान व प्रमाणिक विचलन।

समूह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	टी–मूल्य (t-value)	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी	30	28.5	29.39	0.38	स्वीकृत
सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राएँ	30	25.66	27.22		

$df = N_1 + N_2 - 2 = 30 + 30 - 2 = 58$

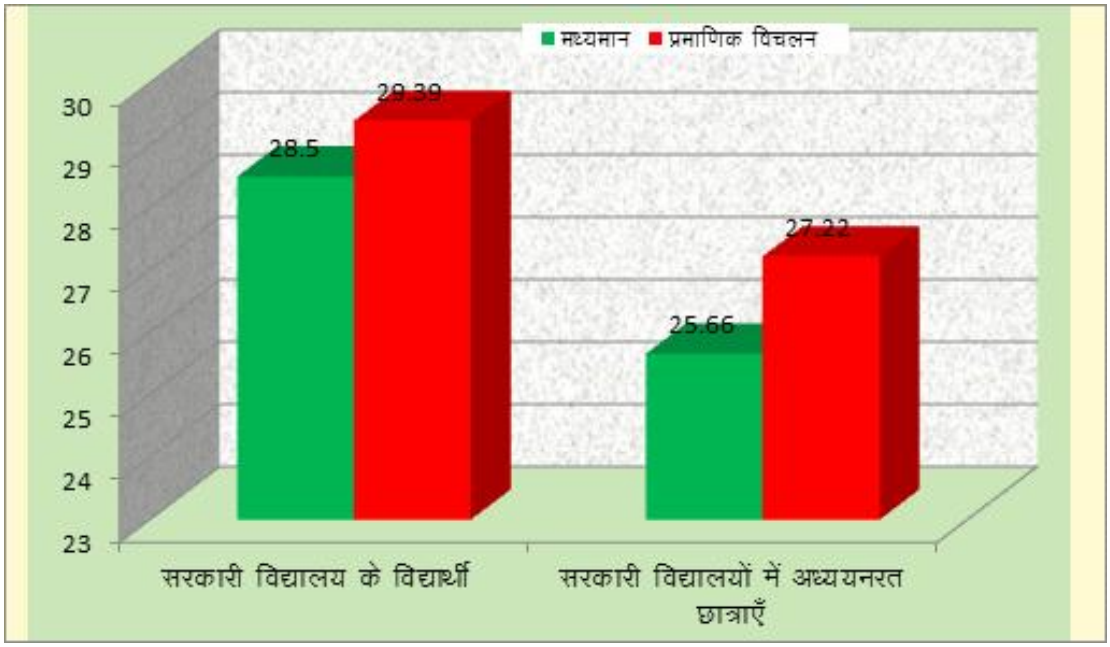
df = 58 पर 0.05 पर टी सारणी मान = 1.676

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उपर्युक्त सारणी के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की आपदा षिक्षा के प्रति जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 28.5 व 25.66 प्राप्त हुआ है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमशः 29.39 व 27.22 प्राप्त हुआ है। इनसे प्राप्त टी मूल्य का मान 0.38 प्राप्त हुआ है जो स्वतंत्रता की कोटि (df) 58 पर सार्थकता स्तर सारणी से कम है। इसलिए शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

आरेख संख्या 1

माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन आरेख द्वारा प्रदर्शित।



परिकल्पना 2. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्रों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सारणी संख्या 2

माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्रों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन।

समूह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	टी–मूल्य (t-value)	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के छात्र	15	29.5	16.24	0.05	स्वीकृत
निजी विद्यालन के छात्र	15	25.16	13.19		

$df = N_1 + N_2 - 2 = 15 + 15 - 2 = 28$

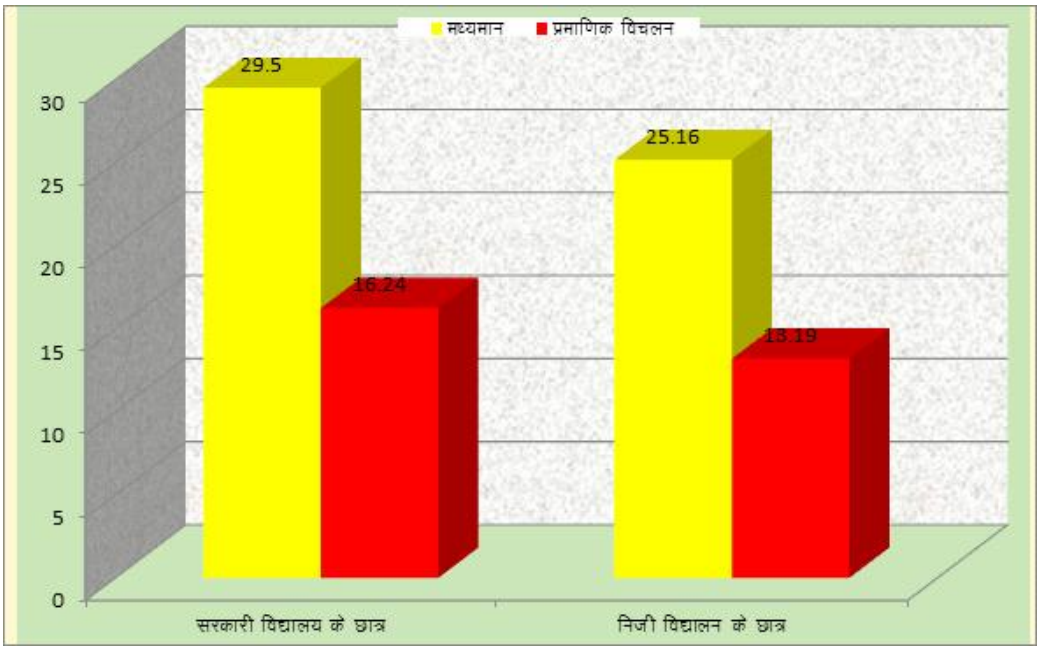
df = 28 पर 0.05 पर टी सारणी मान = 1.701

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उपर्युक्त सारणी के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्रों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 29.5 व 25.16 प्राप्त हुआ है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमशः 16.24 व 13.19 प्राप्त हुआ है। इनसे प्राप्त टी मूल्य का मान 0.05 प्राप्त हुआ है जो स्वतंत्रता की कोटि (df) 28 पर सार्थकता स्तर सारणी से कम है। इसलिए शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्रों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

आरेख संख्या 2

माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्रों की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन आरेख द्वारा प्रदर्शित।



परिकल्पना 3. माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्राओं की आपदा शिक्षा के प्रति

जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सारणी संख्या 3

माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्राओं की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता का मध्यमान व प्रमाणिक विचलन।

समूह	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	प्रमाणिक विचलन (SD)	टी–मूल्य (t-value)	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय की छात्राएँ	15	27.5	10.95	0.29	स्वीकृत
निजी विद्यालन की छात्राएँ	15	26.16	13.59		

$df = N_1 + N_2 - 2 = 15 + 15 - 2 = 28$

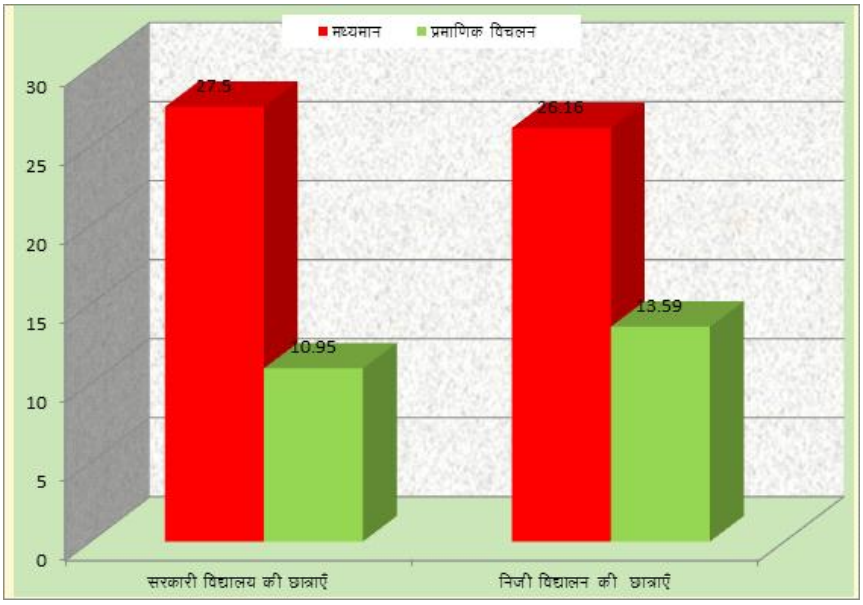
df = 28 पर 0.05 पर टी सारणी मान = 1.701

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उपर्युक्त सारणी के अनुसार माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्राओं की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता का मध्यमान क्रमशः 27.5 व 26.16 प्राप्त हुआ है तथा प्रमाणिक विचलन क्रमशः 10.95 व 13.59 प्राप्त हुआ है। इनसे प्राप्त टी मूल्य का मान 0.29 प्राप्त हुआ है जो स्वतंत्रता की कोटि (df) 28 पर सार्थकता स्तर सारणी से कम है। इसलिए शून्य परिकल्पना माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्राओं की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। इसलिए शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

आरेख संख्या 3

माध्यमिक स्तर पर सरकारी एवं निजी विद्यालयों के छात्राओं की आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता के मध्यमान व प्रमाणिक विचलन आरेख द्वारा प्रदर्शित।



10. शोध निष्कर्ष –

प्रस्तुत शोध में सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों में आपदा शिक्षा के प्रति जागरूकता में बहुत अधिक अंतर पाया गया है। सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी (छात्र एवं छात्राऐं) निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में कुछ अधिक जागरूक पाए गए।

11. शैक्षिक निहितार्थ –

- आपदा प्रबन्धन शिक्षा के प्रति जागरूकता के माध्यम से किशोर विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किया जा सकेगा।
- आपदा प्रबन्धन शिक्षा के प्रति उत्पन्न भय को दूर किया जा सकेगा।
- इससे सम्बन्धित विषय सामग्री का समायोजन किसी भी रूप में (यथा अनिवार्य या वैकल्पिक) पाठ्यक्रम में किया जा सकेगा।

12. भावी शोध हेतु सुझाव –

- प्रस्तुत शोध महाविद्यालय के विद्यार्थियों, बी.एड. प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षकों, व्यावसायिक प्रशिक्षणार्थियों पर भी किया जा सकता है।
- इस शोध कार्य में आपदा प्रबन्धन शिक्षा के प्रति जागरूकता के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोणों को आधार मानकर शोधकार्य किया जा सकता है।
- आपदा प्रबन्धन शिक्षा के प्रति जागरूकता द्वारा विद्यार्थियों के समायोजन, आत्मचिंतन, आत्मसंतुष्टि व आत्म प्रत्यय पर पड़ने वाले प्रभावों आदि चरों को आधार बनाकर शोधकार्य किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

- अग्रवाल, आर. (2018), भारतीय संकट प्रबंधन शिक्षा : समस्याएँ और संभावनाएँ आपदा अनुसंधान एवं प्रबंधन जर्नल, 3(1), 45–58.
- दास, एस. के. (2019), भारतीय आपदा प्रबंधन में शिक्षा की भूमिका आपदा विज्ञान और प्रबंधन, 15(2), 78–89.
- गुप्ता, ए. (2016), आपदा प्रबंधन शिक्षाः भारतीय स्थिति विज्ञान और प्रौद्योगिकी पत्रिका, 30(3), 210–225.
- जैन, आर. (2018), भारत में आपदा प्रबंधन शिक्षा : समस्याएँ और समाधान आपदा अध्ययन संग्रह, 7(1), 34–47.
- कुमार, वी. (2017), भारत में आपदा प्रबंधन शिक्षा : स्थिति और दिशाएँ. शोध पत्र, 12, 89–102.
- मिश्रा, एस. (2020), आपदा प्रबंधन शिक्षा के लिए नई प्राथमिकताएँ, अध्ययन संग्रह, 18(3), 145–158.
- पटेल, ए. (2019), भारतीय आपदा प्रबंधन शिक्षा : स्वरूप, समस्याएँ और समाधान आपदा विज्ञान और प्रबंधन, 21 (4), 200–215.

Websites -

- www. the freedictionary.com
- https//books.google.co.in
- nttutorial.wordppess.com
- https://www. sbistudy.com
- https://www. shodhaganga.inflibnet.ac.in

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 175–192

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी : ऐतिहासिक विकास, संस्थागत चुनौतियां और भविष्य के नीतिगत आयाम

डॉ. एस.पी. शुक्ला प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
अंजुलि शुक्ला, शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र)

सारांश :

किसी भी जीवंत, प्रगतिशील और समावेशी लोकतंत्र की सफलता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि उसके नागरिक शासन, निर्णय लेने और नीति-निर्माण की प्रक्रिया में कितनी सक्रियता, स्वतंत्रता और समानता के साथ भाग लेते हैं। राजनीतिक भागीदारी एक अत्यंत व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें केवल मतदान करने का अधिकार ही शामिल नहीं है, बल्कि चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद धारण करना, राजनीतिक दलों का सक्रिय हिस्सा बनना, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करना, राजनीतिक अभियानों का नेतृत्व करना और व्यापक राजनीतिक चेतना विकसित करना भी शामिल है । महिलाओं के संदर्भ में, राजनीतिक भागीदारी केवल एक संवैधानिक या लोकतांत्रिक अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि यह लैंगिक समानता, सामाजिक सशक्तिकरण और राष्ट्र के समग्र समावेशी विकास को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य मार्ग है ।

राजनीतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अक्सर दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: 'वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व' (Descriptive Representation), जिसका अर्थ है विधायी और कार्यकारी निकायों में महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति, और 'मौलिक या वास्तविक प्रतिनिधित्व' (Substantive Representation), जिसका अर्थ है महिलाओं द्वारा सार्वजनिक नीति और शासन के एजेंडे को इस तरह से प्रभावित करना जो महिलाओं के विशिष्ट हितों और कल्याण को बढ़ावा दे । भारत में पिछले सात दशकों का अनुभव इन दोनों प्रकार के प्रतिनिधित्वों के बीच एक जटिल संबंध को दर्शाता है।

वैश्विक स्तर पर, यद्यपि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में प्रगति हुई है, फिर भी गहरे सामाजिक मानदंड, संरचनात्मक असमानताएं और संसाधनों तक सीमित पहुंच उनकी पूर्ण भागीदारी के मार्ग में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करती हैं । अंतर-संसदीय संघ (IPU) की एक विस्तृत रिपोर्ट दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 1995 के 11.3 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 27.2 प्रतिशत हो गया है । इसकी तुलना में भारत की स्थिति चिंताजनक है। यद्यपि भारतीय महिलाओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री (जैसे 1966 में इंदिरा गांधी) और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री (जैसे उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती) जैसे शीर्ष पदों को सुशोभित किया है, फिर भी समग्र राजनीतिक भागीदारी के मामले में 183 देशों की वैश्विक रैंकिंग में भारत 143वें स्थान पर रहा है ।

जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विश्व में एक अद्वितीय और अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां 14.5 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि शासन की कमान संभाल रही हैं । यह कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों का 46 प्रतिशत है । लेकिन इसके विपरीत, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। हाल ही में 18वीं लोकसभा (2024) में महिलाओं की भागीदारी केवल 14 प्रतिशत रही, जो यह स्पष्ट करता है कि भारत के नीति-निर्माण के शीर्ष स्तरों पर संरचनात्मक अवरोध अभी भी मजबूती से कायम हैं ।

यह विस्तृत शोध रिपोर्ट भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, मतदाता मतदान में अभिसरण (convergence) के रुझानों, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सांख्यिकीय विश्लेषण, पंचायती राज व्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, 'सरपंच पति' जैसी संस्थागत चुनौतियों और हाल ही में पारित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के दूरगामी निहितार्थों का एक सूक्ष्म और विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।

मूल शब्द : राजनीतिक भागीदारी,समानता, राजनीतिक विकास, महिला,

प्रस्तावना : ऐतिहासिक विकास और मताधिकार का विस्तार

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का आधार आधुनिक स्वतंत्र भारत के निर्माण से बहुत पहले, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक अभूतपूर्व मंच प्रदान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे व्यापक जन-आंदोलनों में सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू और अरुणा आसफ अली जैसी नेत्रियों ने न केवल प्रमुख भूमिका निभाई, बल्कि बड़े पैमाने पर सामान्य महिलाओं को भी घरों से बाहर निकालकर सड़कों पर ला खड़ा किया । उनके योगदान और बलिदानों ने महिलाओं की मजबूत नेतृत्व क्षमता को प्रमाणित किया और औपनिवेशिक काल के सख्त पितृसत्तात्मक और पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को गहरी चुनौती दी ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही एक क्रांतिकारी

कदम उठाया गया, जिसने भारतीय लोकतंत्र को पश्चिमी देशों के लोकतंत्रों से अलग और प्रगतिशील बना दिया। जहां ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त करने के लिए दशकों तक 'सफ्रेजेट' (Suffragette) जैसे हिंसक और लंबे आंदोलन करने पड़े थे, वहीं भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 326 के तहत बिना किसी लैंगिक, जातीय, धार्मिक या वर्गीय भेदभाव के पहले ही दिन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage) की गारंटी दी । यह अधिकार भारतीय महिलाओं के लिए राजनीतिक समानता की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण संस्थागत कदम था।

महिला मतदाता मतदान (Voter Turnout) में ऐतिहासिक अभिसरण

कानूनी रूप से मताधिकार प्राप्त होने के बावजूद, वास्तविक राजनीतिक भागीदारी में इसका पूर्ण रूप से परिलक्षित होना एक लंबी प्रक्रिया रही है। दशकों तक भारतीय चुनावों में एक स्पष्ट लैंगिक अंतर (Gender Gap) देखा गया, जहां मतदान के दिन पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत काफी कम रहता था । चुनाव आयोग और राजनीतिक शोधकर्ताओं के अनुसार, 1970 और 1980 के दशक के आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं में राजनीतिक प्रभावोत्पादकता (political efficacy) की भावना बहुत कम थी। 1971 के एक चुनाव-उपरांत सर्वेक्षण में पाया गया कि आधे से अधिक पुरुषों का मानना था कि चुनाव सरकार को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि एक-तिहाई से भी कम महिलाएं ऐसा मानती थीं; साथ ही, महिलाओं ने यह भी महसूस किया कि सरकार के निर्णयों में उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है ।

हालांकि, भारत के चुनाव आयोग (ECI) की 'व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी' (SVEEP) जैसी संस्थागत पहलों, साक्षरता दर में वृद्धि और महिलाओं में बढ़ती राजनीतिक चेतना के कारण यह खाई धीरे-धीरे कम होती गई । 2014 के आम चुनावों में, यह अंतर काफी कम हो गया था, जहां महिला मतदान प्रतिशत 65.63 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो पुरुषों के 67.09 प्रतिशत से थोड़ा ही कम था ।

वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव इस दिशा में एक ऐतिहासिक और जनसांख्यिकीय मोड़ साबित हुआ, जब भारतीय चुनावी इतिहास में पहली बार महिला मतदाताओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक दर्ज किया गया । यह अभिसरण (convergence) 2024 के आम चुनावों में भी मजबूती से कायम रहा। 2024 में, महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में थोड़ा अधिक रहा, जहां 65.8 प्रतिशत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 65.6 प्रतिशत दर्ज किया गया । चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा और चार राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए 42 विस्तृत सांख्यिकीय रिपोर्टें जारी की हैं, जो चुनाव प्रक्रिया में अधिकतम प्रकटीकरण (maximum disclosure), पारदर्शिता और लिंग-आधारित मतदान व्यवहार (gender-based voting behaviour) के विश्लेषण को बढ़ावा देती हैं ।

हालांकि, मतदाता भागीदारी में यह अभिसरण जितना उल्लेखनीय है, इसके कुछ अंतर्निहित

विरोधाभास भी हैं। राजनीतिक वैज्ञानिकों जैसे सोलेदाद प्रिलमन (Soledad Prillaman) और गैब्रिएल क्रुक्स-विस्नर (Gabrielle Kruks-Wisner) द्वारा क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश में किए गए प्राथमिक सर्वेक्षणों और 'नेशनल इलेक्शन स्टडी' (NES) के आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मतदान के दिन लैंगिक अंतर समाप्त हो गया है, लेकिन अन्य सभी प्रकार की निरंतर राजनीतिक सक्रियता में महिलाएं आज भी पुरुषों से काफी पीछे हैं । उदाहरण के लिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों से संपर्क करना, सार्वजनिक बैठकों में भाग लेना, राजनीतिक रैलियों का हिस्सा बनना या राजनीतिक दलों का औपचारिक सदस्य बनना—इन सभी गैर-चुनावी राजनीतिक गतिविधियों में लैंगिक खाई पूरी तरह से दिखाई देती है । यह दर्शाता है कि महिलाओं को 'मतदाता' के रूप में तो स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन 'राजनीतिक कार्यकर्ता' या 'नीति-निर्माता' के रूप में उनकी पूर्ण स्वीकार्यता अभी भी बाकी है।

सर्वोच्च विधायिका में प्रतिनिधित्व: लोकसभा का सांख्यिकीय और जनसांख्यिकीय विश्लेषण

राष्ट्रीय स्तर पर नीति-निर्माण और शासन में महिलाओं की प्रत्यक्ष और प्रभावशाली भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण सूचक लोकसभा में उनकी उपस्थिति है। 1952 में गठित पहली लोकसभा से लेकर 2024 में चुनी गई 18वीं लोकसभा तक, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि तो हुई है, लेकिन यह विकास न तो रैखिक (linear) रहा है और न ही इसकी गति संतोषजनक रही है।

प्रतिनिधित्व के ऐतिहासिक रुझान और क्रमिक प्रगति :

दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर, 1952 की पहली लोकसभा में केवल 22 महिला सांसद (कुल क्षमता का 4.5 प्रतिशत) चुनी गई थीं । सात दशकों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी, पूर्ण समानता का लक्ष्य बहुत दूर है। यह वृद्धि एक जटिल प्रक्षेपवक्र (trajectory) का अनुसरण करती है। 1970 के दशक में प्रतिनिधित्व में अप्रत्याशित गिरावट आई थी, जिसके बाद 1980 और 1990 के दशक में इसमें सुधार के संकेत मिले ।

यह एक विडंबना ही है कि भारतीय लोकतंत्र को लोकसभा में महिला सांसदों के अनुपात को 10 प्रतिशत के दहाई अंक तक पहुंचाने में आधी सदी से अधिक का समय लग गया। 2009 की 15वीं लोकसभा में पहली बार यह आंकड़ा 10 प्रतिशत को पार कर पाया, जब 59 महिला सांसद (10.9 प्रतिशत) निर्वाचित हुईं । इसके एक दशक बाद, 2019 की 17वीं लोकसभा में यह संख्या अपने ऐतिहासिक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई, जब 78 महिलाओं (14.4 प्रतिशत) ने संसद के निचले सदन में प्रवेश किया ।

लोकसभा सत्र	चुनाव वर्ष	महिला सांसदों की संख्या	कुल प्रतिशत (%)
पहली	1952	22	4.5%
दूसरी	1957	27	~5.4%
आठवीं	1985	42	7.7%
पंद्रहवीं	2009	59	10.9%

सत्रहवीं	2019	78	14.4%
अठारहवीं	2024	74	13.6% - 14.0%

(स्रोत: PRS Legislative Research एवं Dataful के ऐतिहासिक आंकड़े)

राज्यसभा में भी स्थिति लगभग समान है। 1952 में राज्यसभा में 15 महिला सदस्य थीं, जो वर्तमान में बढ़कर 42 हो गई हैं (कुल सदस्यों का लगभग 17 प्रतिशत)।

18वीं लोकसभा (2024) का जनसांख्यिकीय और शैक्षिक प्रोफाइल :

2024 के आम चुनावों के उपरांत गठित 18वीं लोकसभा में कुल 543 सीटों में से 74 सीटों (लगभग 13.6 से 14 प्रतिशत) पर महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है। 2019 (78 सांसद) की तुलना में इस बार 0.8 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है।

इन निर्वाचित 74 महिला प्रतिनिधियों का विस्तृत प्रोफाइल उनके जनसांख्यिकीय और राजनीतिक अनुभव के बारे में कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है:

- **आयु संरचना:** 18वीं लोकसभा में महिला सांसद सदन की अपेक्षाकृत युवा जनसांख्यिकी का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुल निर्वाचित महिला सांसदों में से 16 प्रतिशत 40 वर्ष से कम आयु की हैं, जो युवा महिला नेतृत्व के उदय का एक सकारात्मक संकेत है।
- **शैक्षिक योग्यता:** शैक्षिक स्तर के मामले में महिला सांसद समग्र सदन के उच्च औसत के बिल्कुल समतुल्य हैं। नवनिर्वाचित महिला सांसदों में से 78 प्रतिशत ने कम से कम स्नातक (Undergraduate) स्तर की शिक्षा पूरी कर ली है। यह आंकड़ा समग्र लोकसभा के 78 प्रतिशत स्नातक औसत के बराबर है। इसके अतिरिक्त, सदन में डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले कुल 5 प्रतिशत सांसदों में तीन महिला सांसद भी शामिल हैं।
- **राजनीतिक अनुभव और सत्ता में वापसी:** राजनीतिक स्थायित्व के दृष्टिकोण से, निर्वाचित 74 महिला सांसदों में से 41 प्रतिशत (30 सांसद) पूर्व में भी लोकसभा की सदस्य रह चुकी हैं। इसके अलावा, एक महिला सांसद पूर्व में राज्यसभा की सदस्य रही हैं। यह प्रदर्शित करता है कि राजनीतिक दलों में एक बार स्थापित होने के बाद, महिलाओं की स्वीकार्यता और उनका राजनीतिक 'कैपिटल' (Political Capital) बना रहता है।
- **गठबंधन और दलों की स्थिति:** ब्लॉक-वार विश्लेषण से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में ऐतिहासिक रूप से महिला सांसदों की संख्या अधिक रही है (17वीं लोकसभा में 47)। 18वीं लोकसभा में, NDA के पास 37 महिला सांसद हैं, जबकि 'INDIA' गठबंधन के पास 34 महिला सांसद हैं, जो कि 2024 में विपक्षी गठबंधन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारी उछाल को दर्शाता है।

प्रतिनिधित्व का 'विनेबिलिटी' (Winnability) विरोधाभास और राजनीतिक दलों की भूमिका :

राजनीतिक दलों द्वारा अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि चुनाव में महिलाओं को कम टिकट देने

का मुख्य कारण उनकी चुनाव जीतने की कम संभावना (winnability) है। हालांकि, चुनाव आयोग और 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' (ADR) के 2024 के चुनाव के आंकड़े इस पितृसत्तात्मक धारणा का पूर्णतः खंडन करते हैं।

आंकड़ों के अनुसार, 18वीं लोकसभा चुनाव में विश्लेषण किए गए कुल 8,360 उम्मीदवारों में से केवल 800 (9.6 प्रतिशत) उम्मीदवार महिलाएं थीं । भारत के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से 152 निर्वाचन क्षेत्र (28 प्रतिशत) ऐसे थे जहां से एक भी महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं थी । यदि हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह समस्या पुरानी है; अध्ययनों से पता चलता है कि दशकों तक 70 प्रतिशत से अधिक चुनावी दौड़ में कोई महिला उम्मीदवार ही नहीं होती थी और कुल उम्मीदवारों में उनका हिस्सा बमुश्किल 4.3 प्रतिशत रहता था ।

परंतु, विनेबिलिटी का वास्तविक सांख्यिकीय प्रमाण कुछ और ही कहानी बयां करता है। 2024 के चुनावों में, 800 महिला उम्मीदवारों में से 74 ने चुनाव जीता, जो कि लगभग 9 प्रतिशत की सफलता दर (Strike Rate) को दर्शाता है । यह सफलता दर समग्र पुरुष उम्मीदवारों की जीत दर की तुलना में अधिक है। यह सांख्यिकीय विरोधाभास स्पष्ट करता है कि समस्या महिलाओं की चुनाव जीतने की क्षमता या जनता द्वारा उनकी स्वीकार्यता में नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों की टिकट वितरण प्रणाली के भीतर अंतर्निहित पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों में है ।

विभिन्न दलों की बात करें तो, राष्ट्रीय दलों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सबसे अधिक 16 प्रतिशत महिला उम्मीदवार उतारे, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने 13-13 प्रतिशत, और बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने 8 प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया । निर्वाचित 74 महिला सांसदों में से भाजपा के पास सबसे अधिक 31 महिला सांसद हैं, उसके बाद कांग्रेस के पास 13 और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के पास 11 महिला सांसद हैं । राज्य-वार बात करें तो पश्चिम बंगाल ने सबसे अधिक 11 महिला सांसदों को चुना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 7-7, तथा मध्य प्रदेश से 6 महिला सांसद संसद पहुंची हैं ।

अंतरराष्ट्रीय तुलना और वैश्विक परिदृश्य :

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भारतीय संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कई विकासशील और विकसित देशों की तुलना में काफी निराशाजनक है। जब 'अंतर-संसदीय संघ' (IPU) का डेटा दर्शाता है कि 1995 से 2025 के बीच वैश्विक संसदों में महिलाओं का औसत 11.3 प्रतिशत से छलांग लगाकर 27.2 प्रतिशत तक पहुंच गया है , तब भारत का 14 प्रतिशत पर स्थिर रहना कई सवाल खड़े करता है।

अन्य देशों के साथ तुलना इस अंतर को और स्पष्ट करती है:

देश	संसद में महिलाओं का प्रतिशत
दक्षिण अफ्रीका	46%
यूनाइटेड किंगडम (UK)	35%

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)	29%
वैश्विक औसत (2025)	27.2%
भारत (18वीं लोकसभा)	14%

(स्रोतः PRS रिपोर्ट और IPU डेटा)

विशेषज्ञों का अनुमान है कि परिवर्तन की वर्तमान अत्यंत धीमी गति को देखते हुए, भारत को बिना किसी संस्थागत या संरचनात्मक हस्तक्षेप के 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व के लक्ष्य तक पहुंचने में भी कई और दशक लग जाएंगे ।

राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति और क्षेत्रीय विसंगतियां :

राष्ट्रीय राजनीति की तरह ही, भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं (State Legislative Assemblies) में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यधिक असंतुलित और अपर्याप्त है। राज्य विधानसभाएं राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मैदान और पाइपलाइन के रूप में कार्य करती हैं। जब इस पाइपलाइन में ही महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

राज्य स्तरीय सांख्यिकी और 'स्पिल-ओवर' (Spill-over) प्रभाव :

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के देशव्यापी विश्लेषण के अनुसार, वर्तमान में भारत भर की विधानसभाओं में कुल 4,123 विधायकों (MLAs) में से केवल 390 महिलाएं हैं, जो कुल संख्या का मात्र 9 से 10 प्रतिशत है । राज्य विधानसभा चुनावों में 39,033 पुरुष उम्मीदवारों में से 3,733 (10 प्रतिशत) पुरुष जीते, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह अवसर बहुत सीमित रहा ।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि राजनीतिक दलों में राज्य स्तर पर महिलाओं की उपस्थिति राष्ट्रीय राजनीति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। एक महत्वपूर्ण शोध के अनुसार, जब कोई महिला किसी क्षेत्र से राज्य विधानसभा का चुनाव जीतती है, तो बाद के राष्ट्रीय (लोकसभा) चुनावों में उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या में 34 प्रतिशत की भारी वृद्धि होती है । इसके साथ ही, प्रति महिला उम्मीदवार औसत वोट शेयर में 2.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखी गई है । यह तथाकथित 'स्पिल-ओवर इफेक्ट' (Spill-over effect) इस बात को प्रमाणित करता है कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रवेश न केवल उनके लिए, बल्कि अन्य नई महिला राजनेताओं के लिए भी राष्ट्रीय राजनीति के द्वार खोलता है ।

अग्रणी राज्य	महिला विधायकों की संख्या (वर्तमान)
उत्तर प्रदेश	47
पश्चिम बंगाल	40
बिहार	29
मध्य प्रदेश	27

(स्रोतः ADR रिपोर्ट)

दलों के स्तर पर राज्य विधानसभाओं में भाजपा के पास सबसे अधिक 163 महिला विधायक हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पास 59 और एआईटीसी (AITC) के पास 34 महिला विधायक हैं ।

केस स्टडी : मध्य प्रदेश विधानसभा और क्षेत्रीय गतिशीलता :

मध्य प्रदेश का सांख्यिकीय विश्लेषण राज्य स्तरीय राजनीति की व्यावहारिक वास्तविकताओं को गहराई से समझने में मदद करता है। ऐतिहासिक रूप से, 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में महिलाओं का अनुपात आज तक कभी भी 13 प्रतिशत के आंकड़े को पार नहीं कर पाया है ।

2013 के विधानसभा चुनावों में राज्य ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 30 महिलाओं (13 प्रतिशत) को चुना था । हालांकि, 2023 के हालिया विधानसभा चुनावों में यह संख्या घटकर 27 रह गई है (कुल 27 निर्वाचन क्षेत्रों से एक महिला विधायक चुनी गई है) । इन चुनावों में प्रतिमा बागरी (रैगांव - SC), रीति पाठक (सीधी), अर्चना चिटनिस (बुरहानपुर), और मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ (इंदौर-4) जैसी प्रमुख महिला नेताओं ने जीत दर्ज की है ।

2023 के चुनाव परिणामों का शैक्षिक जनसांख्यिकीय विश्लेषण एक अत्यंत रोचक तथ्य सामने लाता है। 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनी गई महिलाओं की शैक्षिक पृष्ठभूमि पुरुष विधायकों की तुलना में अधिक मजबूत है। जहां 69 प्रतिशत पुरुष विधायकों के पास कम से कम स्नातक (Graduate) की डिग्री है, वहीं 78 प्रतिशत महिला विधायकों ने कम से कम स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त की है ।

मध्य प्रदेश विधानसभा हाल ही में महिला आरक्षण को लेकर तीखी राजनीतिक बहसों का केंद्र भी रही है। 27 अप्रैल 2026 को, मध्य प्रदेश विधानसभा ने परिसीमन (Delimitation) अभ्यास के पूरा होने के बाद महिलाओं के लिए तत्काल एक तिहाई सीटों के आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया । मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि उमंग सिंघार के नेतृत्व में विपक्ष ने इस बात पर कड़ा विरोध जताया कि आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर इसे अनिश्चित काल के लिए टाला जा रहा है, और उन्होंने इसे वर्तमान विधानसभा शक्ति पर तत्काल लागू करने की मांग की ।

जमीनी लोकतंत्र और पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में क्रांति :

राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निराशाजनक आंकड़ों के पूर्ण विपरीत, भारत के जमीनी स्तर के शासन (Grassroots Governance) में महिलाओं की भागीदारी एक अभूतपूर्व वैश्विक सफलता की कहानी है। यह जनसांख्यिकीय क्रांति 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों के पारित होने के साथ शुरू हुई, जिसने भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई (33 प्रतिशत) सीटों के आरक्षण को अनिवार्य कर दिया था ।

33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की ओर: संवैधानिक जनादेश और राज्यों की पहल :

विकेंद्रीकृत संघीय ढांचे के सिद्धांतों के अनुरूप, भारत के कई राज्यों ने 33 प्रतिशत के न्यूनतम संवैधानिक जनादेश से एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत तक विस्तारित कर दिया है ।

वर्ष 2006 में, बिहार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत कानूनी आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना । इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद से अब तक 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने राज्य पंचायती राज अधिनियमों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया है । मध्य प्रदेश में यह प्रावधान 'मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2007' के माध्यम से लागू किया गया । 50% आरक्षण देने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं ।

संसद में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कोटा के क्रियान्वयन में कुछ राज्यों में विविधताएं भी मौजूद हैं। जहां आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, और सिक्किम जैसे राज्य 50 प्रतिशत कोटा को ठीक से पूरा कर रहे हैं; वहीं अरुणाचल प्रदेश (33% कोटा के मुकाबले 38% महिलाएं), अंडमान और निकोबार (35.6%), केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्य अपने निर्धारित कोटा से 0 से 5 प्रतिशत अधिक महिलाओं को चुन रहे हैं । इसके विपरीत, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां 50% का प्रावधान होने के बावजूद लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे गुजरात (49.9%), हरियाणा (42.12%), त्रिपुरा (45.25%), और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (31.97%) ।

इस आक्रामक सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action) का समग्र राष्ट्रीय परिणाम यह है कि आज देश भर में स्थानीय सरकारों में लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से लगभग 46 प्रतिशत—अर्थात 14.5 लाख से अधिक—महिला निर्वाचित प्रतिनिधि (EWRs) हैं । यह प्रतिनिधित्व का एक ऐसा विशाल पैमाना है जो दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है ।

शासन और नीति-निर्माण पर महिला नेतृत्व का प्रभाव: प्रयोगात्मक साक्ष्य :

स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रवेश ने केवल सांख्यिकीय उपस्थिति नहीं बढ़ाई है, बल्कि इसने ग्रामीण विकास के एजेंडे और नीति-निर्माण की प्राथमिकताओं को मौलिक रूप से बदल दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो (Esther Duflo) और राघबेंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा पश्चिम बंगाल और राजस्थान के 265 ग्राम परिषदों (Village Councils) में किए गए 'रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल' (RCT) शोध ने इस प्रभाव को प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया है ।

इस अत्यंत महत्वपूर्ण शोध से यह स्पष्ट हुआ कि आरक्षण के कारण बनी महिला सरपंचों (ग्राम प्रधानों) ने उन बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक वस्तुओं (Public Goods) में अधिक निवेश किया जो सीधे तौर पर उनकी अपनी आवश्यकताओं और उनके जेंडर की दैनिक चुनौतियों से संबंधित थे । महिला

निर्वाचित अधिकारियों द्वारा सबसे अधिक उठाए गए मुद्दों में सुरक्षित पेयजल की सुविधा, सड़कों का निर्माण, और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल थीं; जबकि पुरुष नेताओं की प्राथमिकताएं अक्सर सिंचाई और शिक्षा तक सीमित रहती थीं।

डुफ्लो के व्यापक अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन गांवों को महिला नेतृत्व के लिए आरक्षित किया गया था, वहां सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता और मात्रा गैर-आरक्षित गांवों की तुलना में अधिक थी, और इन वस्तुओं की मापी गई गुणवत्ता (Quality) भी कम से कम उतनी ही अच्छी या उससे बेहतर थी। शासन में पारदर्शिता के मोर्चे पर भी महिलाओं ने बेहतर प्रदर्शन किया; आंकड़ों ने साबित किया कि महिलाओं के नेतृत्व वाले गांवों में निवासियों द्वारा रिश्वत (Bribes) देने की संभावना काफी कम थी, जिससे यह सिद्ध हुआ कि महिलाएं कम भ्रष्ट शासन प्रदान करती हैं।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और उनके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए निरंतर शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। इन अध्ययनों से यह स्थापित हुआ है कि महिला नेता अक्सर मातृ स्वास्थ्य, बच्चों की देखभाल (Childcare), और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे महत्वपूर्ण कल्याणकारी मुद्दों को विचार-विमर्श के केंद्र में लाती हैं।

'रोल मॉडल' प्रभाव (Role Model Effect) और सामाजिक परिवर्तन :

संभवतः महिला सरपंचों का सबसे दूरगामी और परिवर्तनकारी प्रभाव समाज की गहरी मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संरचना पर पड़ता है। 495 गांवों में 11 से 15 वर्ष की आयु के 8,453 किशोरों और उनके माता-पिता पर किए गए एक सर्वेक्षण ने 'रोल मॉडल प्रभाव' (Role Model Effect) की शक्ति को स्पष्ट रूप से मापा है।

शोध के अनुसार, जिन गांवों में लगातार दो चुनाव चक्रों (Election Cycles) तक महिला सरपंच रही हैं, वहां माता-पिता की अपनी बेटियों के प्रति आकांक्षाओं में लैंगिक अंतर (Gender Gap in Aspirations) 25 प्रतिशत तक कम हो गया। स्वयं किशोरियों की महत्वाकांक्षाओं में यह अंतर 32 प्रतिशत तक कम हुआ। महिला नेताओं को शासन करते देखकर युवा लड़कियों की शैक्षिक प्राप्ति में लैंगिक अंतर पूरी तरह से मिट गया (और कुछ मामलों में उलट गया), और सबसे महत्वपूर्ण बात, किशोरियों द्वारा घरेलू कार्यों (Household Chores) में बिताए जाने वाले समय में गैर-आरक्षित परिषदों की तुलना में प्रतिदिन 18 मिनट की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई। यद्यपि श्रम बाजार के अवसरों में कोई तत्काल परिवर्तन नहीं देखा गया, फिर भी सामाजिक धारणा में यह बदलाव सिद्ध करता है कि राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण का सीधा पूर्वगामी (precursor) है।

सफलता की कहानियां: जमीनी स्तर से राष्ट्रीय पटल तक :

भारत के विभिन्न राज्यों—विशेषकर मध्य प्रदेश—से कई महिला सरपंचों ने अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किए हैं जो इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि सही अवसर मिलने पर महिलाएं शासन की तस्वीर

बदल सकती हैं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित बरखेड़ी अब्दुल्ला ग्राम पंचायत की सरपंच भक्ति शर्मा एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी हैं । विदेश से लौटकर सरपंच का चुनाव लड़ने वाली भक्ति ने घर-घर जाकर ग्रामीणों का विश्वास जीता और एक भारी बहुमत से जीत दर्ज की । उन्होंने अपनी पंचायत को 'गरीबी रेखा से नीचे' (BPL) के दर्जे से निकालकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक सेवाओं के मानकों पर एक 'मॉडल पंचायत' में बदल दिया । उनके प्रयासों ने पूरे राज्य के लिए एक प्रतिमान (benchmark) स्थापित किया। इसी तरह, प्रतिभा तिवारी जैसी महिलाओं ने जैविक खेती के क्षेत्र में सैकड़ों किसानों को सशक्त बनाया, और छात्रा नवश्री ने घरेलू कार्यों को सरल बनाने वाले उपकरणों का नवाचार किया, जो एक व्यापक महिला सशक्तिकरण परिदृश्य का हिस्सा हैं ।

एक अन्य प्रेरक उदाहरण मंडला जिले (मध्य प्रदेश) के टिकरवाड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच संपतिया उइके का है । आदिवासी बहुल और रानी दुर्गावती के शौर्य के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में, संपतिया उइके ने एक ग्राम सरपंच के रूप में अपनी नेतृत्व यात्रा शुरू की। अपनी प्रशासनिक क्षमता के बल पर वह जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं, और अंततः मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद के उच्च सदन तक पहुंचीं । 'ग्लास सीलिंग' (Glass Ceiling) को तोड़ने वाली यह यात्रा दर्शाती है कि पंचायती राज संस्थाएं महिलाओं के लिए शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व तक पहुंचने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी 'प्रशिक्षण मैदान' बन सकती हैं ।

इन जमीनी सफलताओं की गूंज वैश्विक मंचों पर भी सुनाई दी है। भारत के स्थायी मिशन, पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) ने "Localizing the SDGs: Women in Local Governance in India Lead the Way" नामक कार्यक्रम के तहत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय (न्यूयॉर्क) में सुप्रिया दास दत्ता (त्रिपुरा), कुनुकु हेमा कुमारी (आंध्र प्रदेश) और नीरू यादव (राजस्थान) जैसी महिला सरपंचों की उपलब्धियों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है ।

संरचनात्मक चुनौतियां और संस्थागत अवरोध :

यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं ने एक मूक क्रांति को जन्म दिया है, और संवैधानिक रूप से महिलाओं को समानता प्रदान की गई है, फिर भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कई गहरी सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बाधाओं के चक्रव्यूह में फंसी हुई है।

'सरपंच पति' सिंड्रोम : पितृसत्तात्मक छद्म प्रतिनिधित्व और मानवाधिकार चिंताएं :

स्थानीय स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी, प्रत्यक्ष और विडंबनापूर्ण चुनौती 'सरपंच पति' (Proxy Representation) की असंवैधानिक प्रथा है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां आरक्षण के माध्यम से चुनी गई महिला प्रतिनिधि केवल एक नाममात्र की या प्रतीकात्मक प्रमुख (Symbolic Figurehead) बनकर रह जाती है, जबकि वास्तविक प्रशासनिक, वित्तीय और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग उसके पति या अन्य पुरुष रिश्तेदारों (जिन्हें आम बोलचाल में 'प्रधान पति',

'मुखिया पति' या 'सरपंच पति' कहा जाता है) द्वारा किया जाता है ।

यह प्रथा आरक्षण के मूल उद्देश्य और महिलाओं को दिए गए लोकतांत्रिक जनादेश को पूरी तरह से खोखला कर देती है। समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक संरचनाएं, निर्वाचित महिलाओं में शिक्षा और अनुभव की कमी, और पर्याप्त संस्थागत समर्थन का अभाव महिलाओं को प्रशासनिक कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और आधारभूत संरचना की परियोजनाओं के लिए अपने पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर होने के लिए मजबूर कर देता है । यह भी एक मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है कि एस्थर डुफ्लो के शोध में पाया गया था कि यद्यपि महिला सरपंचों ने अधिक सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान कीं और कम भ्रष्टाचार किया, फिर भी पुरुष नेतृत्व वाले गांवों की तुलना में ग्रामीण (विशेषकर पुरुष) महिला सरपंचों के प्रशासन से कम संतुष्ट थे। यह मतदाताओं के भीतर गहराई तक बैठे लैंगिक पूर्वाग्रह (Gender Bias) को उजागर करता है, जहां महिलाएं भले ही कुशल हों, उन्हें एक सक्षम नेता के रूप में स्वीकार करने में सामाजिक झिझक मौजूद है।
इस असंवैधानिक प्रथा की गंभीरता पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने इसे संवैधानिक जनादेश और मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है । NHRC ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि सहित 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज विभागों के प्रमुख सचिवों को सशर्त समन (Conditional Summons) जारी किया है । उन्हें 30 दिसंबर 2025 तक 'सरपंच पति' प्रथा को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों पर 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है (हालांकि आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कर दी हैं) ।

सरकार ने भी इसके खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 18 मार्च तक चलने वाला "प्रॉक्सी सरपंच को ना कहें" (Say No To Proxy Sarpanch) नामक एक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है । मंत्रालय की एक सलाहकार समिति ने ऐसे मामलों में जहां पुरुष रिश्तेदार महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर अधिकार का प्रयोग करते पाए जाते हैं, वहां सख्त दंड की सिफारिश की है, और 'व्हिसलब्लोअर' (Whistleblowers) की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन और 'महिला निगरानी समितियों' की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया है ।

इसके साथ ही, सरकार 'सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान' नामक एक लक्षित क्षमता-निर्माण पहल के माध्यम से महिला पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और शासन भूमिकाओं को मजबूत करने का प्रयास कर रही है । इसके अतिरिक्त, 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (SHGs) से जोड़ना और 'मॉडल महिला-हितैषी ग्राम पंचायत' (Model Women-Friendly Gram Panchayats) पहल जैसी नीतियां जमीनी स्तर पर महिलाओं के आर्थिक और राजनीतिक आधार को मजबूत कर रही हैं ।

मीडिया का पूर्वाग्रह, हिंसा और आईसीडब्ल्यूआर (ICRW) अध्ययन :

प्रख्यात दार्शनिक मार्था नुसबाम (Martha Nussbaum) ने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश

के लिए यौन हिंसा और शारीरिक खतरे को एक अत्यंत महत्वपूर्ण बाधा के रूप में रेखांकित किया है । चुनाव अभियान के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा (Violence against Women in Politics) केवल शारीरिक नहीं होती; यह डराने-धमकाने, दुर्व्यवहार, और चारित्रिक लांछन लगाने वाले अभियानों का रूप ले लेती है । यह एक वैश्विक घटना है, जिसका उदाहरण 2012 में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड (Julia Gillard) द्वारा दिया गया प्रसिद्ध "मिसोगिनी स्पीच" (Misogyny Speech) है, जिसने विश्व राजनीति में महिलाओं के खिलाफ मौजूद सेक्सिज्म (sexism) और रूढ़िवादी दृष्टिकोण को बेनकाब किया था । इसी प्रकार 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में भी महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह स्पष्ट रूप से देखे गए थे । भारतीय संदर्भ में, मीडिया द्वारा महिलाओं का रूढ़िवादी चित्रण उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाता है, जो मतदाताओं की धारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है ।

अंतर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान केंद्र (ICRW) और 'यूएन वीमेन' (UN Women) के एक अत्यंत महत्वपूर्ण संयुक्त अध्ययन ने स्थानीय शासन में जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को लेकर एक गंभीर विरोधाभास को उजागर किया है । भारत और दक्षिण एशिया में 3,000 से अधिक निर्वाचित पुरुष और महिला पंचायत नेताओं के सर्वेक्षण पर आधारित इस अध्ययन में पाया गया कि यद्यपि महिलाएं अक्सर अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के पास 'घरेलू हिंसा' (Domestic Violence) जैसे गंभीर लैंगिक मुद्दों को व्यक्तिगत या निजी तौर पर उठाती हैं, लेकिन पंचायत की औपचारिक बैठकों (Gram Sabha) में इन मुद्दों पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है ।

यह 'सार्वजनिक' बनाम 'निजी' का एक कृत्रिम विभाजन है। निर्वाचित प्रतिनिधियों (जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं) के बीच मौजूद पारंपरिक और रूढ़िवादी दृष्टिकोण घरेलू हिंसा को एक ऐसा 'पारिवारिक मामला' मानता है जो सार्वजनिक नीति या राजनीतिक विमर्श के दायरे से बाहर है । जब तक 'जेंडर-उत्तरदायी शासन' (Gender Responsive Governance) के ढांचे के भीतर इन निजी माने जाने वाले मुद्दों को राजनीतिक मंचों पर सार्वजनिक नीति का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रहेगा।

राजनीतिक दलों की पितृसत्तात्मक संरचना और डिजिटल डिवाइड :

राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र के मुख्य द्वारपाल (Gatekeepers) होते हैं, जो यह तय करते हैं कि सत्ता के गलियारों में कौन प्रवेश करेगा। शोधकर्ताओं (जैसे चिब्बर और वर्मा, 2014) के अनुसार, भारतीय राजनीतिक दलों का आंतरिक ढांचा अत्यधिक पितृसत्तात्मक है । यद्यपि दल महिलाओं को निचले स्तर पर काम करने और रैलियों में जनसमर्थन जुटाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन जब टिकट वितरण या पार्टी पदानुक्रम (Party hierarchy) के भीतर प्रमुख निर्णय लेने वाले पदों की बात आती है, तो महिलाओं को व्यवस्थित रूप से दूर रखा जाता है । 1990 के दशक से लेकर अब तक, राजनीतिक दलों में महिलाओं की कुल सदस्यता 10 से 12 प्रतिशत के बीच ही स्थिर रही है, और भारत में मुश्किल से चार राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका नेतृत्व महिलाओं के हाथ में है । इसी संरचनात्मक हताशा के कारण 2007 में

महिलाओं ने 'यूनाइटेड वीमेन फ्रंट' (United Women Front) जैसी अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई थी, जिसने संसद में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की वकालत की।

इसके अतिरिक्त, 21वीं सदी के 'ई-गवर्नेंस' (E-governance) युग में, 'डिजिटल डिवाइड' (Digital Divide) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में एक नई और जटिल बाधा बनकर उभरा है। गुरुमूर्ति और चामी (Gurumurthy and Chami, 2016) के अध्ययन के अनुसार, यह डिजिटल डिवाइड केवल प्रौद्योगिकी की कमी नहीं है, बल्कि यह गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और लैंगिक मानदंडों का परिणाम है । ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव, डिजिटल साक्षरता की कमी, और स्मार्टफोन जैसे तकनीकी उपकरणों तक सीमित पहुंच के कारण महिला पंचायत प्रतिनिधि सरकारी पोर्टल्स नेविगेट करने, कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंचने और वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने में भारी कठिनाई महसूस करती हैं । समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध और गतिशीलता पर पितृसत्तात्मक सीमाएं महिलाओं को तकनीक का उपयोग करने से हतोत्साहित करती हैं, जो डिजिटल शासन प्रक्रियाओं से उनके बहिष्कार को और अधिक मजबूत करता है ।

भविष्य का मार्ग: 106वां संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) :

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में मौजूद भारी और निराशाजनक अंतराल को पाटने के लिए, दशकों के राजनीतिक संघर्ष और कई विफल प्रयासों (जैसे 1996 का 81वां संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा भंग होने के कारण लैप्स हो गया था) के बाद, अंततः 2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम—जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' कहा जाता है—पारित किया गया । यह भारत की विधायी संरचना में लैंगिक समानता स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और 'गेम-चेंजर' (Game-changer) कदम है।

संवैधानिक प्रावधान और उनका महत्व :

इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में तीन महत्वपूर्ण नए अनुच्छेद और कुछ उप-खंड जोड़े गए हैं, जो भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देंगे :

- **अनुच्छेद 330A:** यह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली लोकसभा की कुल सीटों में से यथाशक्य एक-तिहाई (33 प्रतिशत) सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी उन वर्गों की महिलाओं के लिए एक-तिहाई 'उप-आरक्षण' (Sub-quota) का प्रावधान किया गया है ।
- **अनुच्छेद 332A:** यह प्रावधान ठीक इसी 33 प्रतिशत आरक्षण के ढांचे को भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं में लागू करता है । इसके साथ ही अनुच्छेद 239AA में संशोधन करके इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi) की विधानसभा पर भी लागू किया गया है ।
- **अनुच्छेद 334A (कार्यान्वयन का तंत्र):** यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि यह आरक्षण

अधिनियम के लागू होने के बाद प्रकाशित होने वाली पहली जनगणना (Census) के आधार पर किए गए परिसीमन (Delimitation) अभ्यास के बाद ही प्रभावी होगा । यह आरक्षण 15 वर्षों की अवधि (Sunset Clause) के लिए लागू रहेगा, जिसे संसद द्वारा कानून बनाकर आगे भी बढ़ाया जा सकता है ।

इस अधिनियम का घोषित लक्ष्य 2024 की लोकसभा में मौजूद 74 महिला सांसदों की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 181 तक ले जाना है ।

परिसीमन, जनसंख्या गतिशीलता और संघीय चिंताएं :

यद्यपि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा ने कई संवैधानिक, जनसांख्यिकीय और संघीय (Federal) प्रश्न खड़े कर दिए हैं। 'विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' (Vidhi Centre for Legal Policy) और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि आरक्षण को जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन से जोड़ना इस प्रक्रिया को अत्यधिक और अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर सकता है । इसके अतिरिक्त, यदि परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना के पुराने और कालबाह्य जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, तो यह निर्वाचन क्षेत्रों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व को बुरी तरह बिगाड़ सकता है, जो अनुच्छेद 81 और 82 की मूल भावना के विरुद्ध होगा ।

सबसे गंभीर चिंता भारत के संघीय ढांचे (Cooperative Federalism) और उत्तर बनाम दक्षिण भारत के राजनीतिक तनाव से जुड़ी है। यदि नई जनगणना के बाद परिसीमन अभ्यास के साथ लोकसभा की कुल सीटों (वर्तमान 543 से बढ़ाकर अनुमानित रूप से 816 सीटों तक) का विस्तार किया जाता है, तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे । केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों ने पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण में अपार सफलता प्राप्त की है, जिसका परिणाम यह होगा कि नई विस्तारित लोकसभा में उनका सापेक्ष राजनीतिक प्रभाव और शक्ति (Relative influence) काफी कम हो जाएगी । इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों (जहां जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही है) का राजनीतिक वर्चस्व अत्यधिक बढ़ जाएगा (अनुमानित रूप से इन दो राज्यों के पास ही संयुक्त रूप से लगभग 180 सीटें होंगी) ।

इस प्रकार, महिलाओं के आरक्षण का महान उद्देश्य भारत के संस्थागत डिजाइन, जनसांख्यिकीय दंड (Demographic penalty on performing states), और क्षेत्रीय संतुलन के अत्यंत संवेदनशील और जटिल मुद्दों के साथ उलझ गया है।

निष्कर्ष :

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का गहन मूल्यांकन इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकता के बीच कितना गहरा और जटिल अंतर मौजूद है। एक ओर, पंचायत और स्थानीय शासन के स्तर पर 14.5 लाख से अधिक निर्वाचित महिला

प्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति एक अभूतपूर्व और अकल्पनीय उपलब्धि है। महिला सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने एस्थर डुफ्लो के प्रयोगात्मक साक्ष्यों को सही साबित करते हुए यह प्रदर्शित किया है कि जब महिलाओं के हाथों में सत्ता आती है, तो शासन का मॉडल अधिक मानवीय, पारदर्शी और समावेशी हो जाता है। जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके निर्णय न केवल वर्तमान पीढ़ियों को लाभान्वित कर रहे हैं, बल्कि भविष्य की किशोरियों के लिए 'रोल मॉडल' बनकर लैंगिक आकांक्षाओं की खाई को भी पाट रहे हैं।

दूसरी ओर, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विधायिकाओं (लोकसभा और विधानसभाओं) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10 से 14 प्रतिशत की संकीर्ण सीमा के भीतर फंसा रहना, भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष स्तरों पर मौजूद एक अदृश्य लेकिन अभेद्य 'ग्लास सीलिंग' (Glass Ceiling) को प्रमाणित करता है। महिलाओं को सिर्फ चुनाव के दिन 'मतदाता' के रूप में देखना और टिकट वितरण के समय उन्हें 'जीतने में अक्षम' (winnability myth) मानकर नेतृत्व के पदों से दूर रखना राजनीतिक दलों की एक बड़ी रणनीतिक विफलता और पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रह है। सांख्यिकीय आंकड़े स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि महिला उम्मीदवारों की सफलता दर पुरुषों से कहीं अधिक है।

'सरपंच पति' जैसी असंवैधानिक प्रथाएं, घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों को सार्वजनिक नीति विमर्श से बाहर रखना, और डिजिटल डिवाइड जैसी नई सदी की चुनौतियां यह स्पष्ट करती हैं कि केवल 'वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व' (Descriptive Representation) यानी कानूनों के माध्यम से पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। भारत को अब 'मौलिक प्रतिनिधित्व' (Substantive Representation) की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जहां महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें और नीति-निर्माण के एजेंडे को आकार दे सकें।

106वां संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) भारत के राजनीतिक और लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक 'पैराडाइम शिफ्ट' (Paradigm Shift) और आशा की सबसे मजबूत किरण है। 33 प्रतिशत आरक्षण निश्चित रूप से संसद और विधानसभाओं की संरचना को बदल देगा। हालांकि, इस ऐतिहासिक सुधार को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए न केवल परिसीमन और संघीय तनावों जैसी प्रशासनिक बाधाओं को पार करना होगा, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर गहरे बैठे सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों को भी तोड़ना होगा।

अंततः, भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण तभी अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करेगा जब संस्थागत कानूनी सुधारों (जैसे 33% आरक्षण), लक्षित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों (जैसे सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान), और समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता में व्यापक सांस्कृतिक परिवर्तन का त्रिस्तरीय संगम होगा। एक 'विकसित' और वास्तव में समावेशी भारत के निर्माण के लिए महिलाओं की समान और स्वतंत्र राजनीतिक भागीदारी कोई वैकल्पिक नीति नहीं, बल्कि लोकतंत्र के अस्तित्व और सफलता की एक अनिवार्य शर्त है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Women's political participation in India - Wikipedia,
2. Opportunities and Challenges of Women s Political Participation in India.
3. Women in parliament 1995-2025 | Inter-Parliamentary Union,
4. Government is promoting greater participation of women in local governance and political leadership roles - PIB,
5. Government adopts comprehensive strategy for Women's ... - PIB,
6. Profile of the 18th Lok Sabha - Vital Stats.
7. Vital Stats: Profile of the 18th Lok Sabha - PRS India,
8. Women's Political Participation in India: - ijrti.
9. Women's Political Participation In India - RJPN,
10. What Lies Behind India's Rising Female Voter Turnout,
11. Women and Panchayat Elections - Berkeley Political Science,
12. Proactive Disclosure of Extensive Data sets of the world's Largest Election - Press Release: Press Information Bureau,
13. Women in Lok Sabha at 13.8%: Slow Gains, Persistent Gaps - Insights - Dataful,
14. Women's Political Participation and Representation in India,
15. Women in Indian Politics: Challenges, Progress, and Future Prospects - IJNRD.org,
16. Does Local Female Political Representation Empower Women to Run for Higher Office? Evidence from State and National Legislatures in India,
17. Profile of the 16th Madhya Pradesh Legislative Assembly - Vital Stats,
18. Vital Stats - Profile of the 16th Madhya Pradesh Legislative Assembly - PRS India,
19. Total women winners:Madhya Pradesh 2023 Election - MyNeta.
20. M.P. Assembly passes resolution to implement women's reservation after delimitation amid uproar by Opposition - The Hindu,
21. Women Panchayats And Digital Inclusion: Transforming Local Governance,
22. GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF PANCHAYATIRAJ LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO - 2550 ANSWERED ON- 05.08.2025 RESERVATION FOR WOM.
23. Name of the Nation - India or Bharat - Cloudfront.net,
24. Women empowerment issues - Jobs,Reservation and education - CivilsDaily,
25. Status of Representation of Women in Panchayati Raj Institutions (PRIs) - ArcGIS Online,
26. 50% reservation for women in PRI has been provided as per 'The Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007' which has been incorporated in the Principal Act. | Ministry Of Panchayati Raj, 27. Govt claims women winning unreserved panchayat seats in 'significant numbers',
28. Unappreciated Service: Performance, Perceptions, and Women Leaders in India | IPA,
29. Unappreciated Service: Performance, Perceptions, and Women Leaders in India,
30. WOMEN AS POLICY MAKERS: EVIDENCE FROM A RANDOMIZED POLICY EXPERIMENT IN INDIA sented in all political positions. In June 2000, w - MIT Economics,

31. Strengthening Capacity of Women Leaders in Rural India: Evaluating the Impact of Training on the Effectiveness of Elected Women Representatives (EWR) to Village Councils in Bihar,
32. Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India - PMC,
33. Women Leadership In Panchayati Raj Institutions (PRI) At The Gram Panchayat Level: Review,
34. Advancing the Rights of Women and Girls Panchayats Leading the Way - UNFPA India,
35. Iron-Willed Sarpanch Returned From the US to Transform Villages in India! - The Better India.
36. Documentation of Success stories of Women Panchayat Representative Of Madhya Pradesh On Women's Leadership Zilla Panchayat.
37. Elected Women Representatives of Panchayati Raj Institutions to Participate in CPD57 Side Event “Localizing the SDGs: Women in Local Governance in India Lead the Way” on 3rd May 2024 at United Nations Headquarters in New York - Press Release Page | Press Information Bureau,
38. Government Launches Campaign Against 'Sarpanch Pati' Practice - GKToday,
39. Breaking 'Sarpanch Pati Raj' - MillenniumPost.
40. NHRC Initiates Action Against 'Proxy Governance' In Women-Reserved Local Bodies; Issues Summons To Senior Officials Of 32 States & UTs - Verdictum,
41. From Proxy to Power: Eliminating the 'Sarpanch Pati' Practice in Rural Governance,
42. Government launches campaign against 'Sarpanch Pati' practice - The Times of India,
43. ELECTORAL RIGHTS OF WOMEN IN INDIAN DEMOCRACY,
44. (PDF) Challenges Faced by Women in the Political Sector - ResearchGate,
45. Opportunities and Challenges of Women's Political Participation in India 2012 - ICRW,
46. Opportunities and challenges of women's political participation in India - ICRW,
47. art and culture (12-27),
48. International Women's Day 2026 - PIB,
49. One Hundred and Sixth Amendment of the Constitution of India - Wikipedia,
50. Ratifying Reservation - PRS India,
51. THE CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND SIXTH AMENDMENT) ACT, 2023 An Act further to amend the Constitution of India. vlk/kkj.k izkf/k - eGazette.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
ISSN : 2321-8037
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 193–201

अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का छात्रों की समग्र व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया पर प्रभाव का अध्ययन

लवनीश कुमार, शोधार्थी
डॉ. रजनीश कुमार कारवारिया, शोध निर्देशक
सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग,
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीली बंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान–335801

शोध सार :

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा का उद्देश्य केवल संज्ञानात्मक विकास तक सीमित न रहकर छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास की ओर उन्मुख हो गया है। समग्र व्यक्तित्व में बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक तथा व्यवहारिक आयाम सम्मिलित होते हैं। पारंपरिक सैद्धांतिक शिक्षण पद्धतियाँ छात्रों में व्यावहारिक दक्षताओं, आत्मविश्वास एवं जीवन कौशलों के विकास में अपेक्षित प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पा रही हैं। इस संदर्भ में अभ्यास आधारित प्रशिक्षण एक प्रभावी शैक्षिक दृष्टिकोण के रूप में उभरकर सामने आया है। शिक्षा को सदैव मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मूल आधार माना गया है। यह केवल ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण, व्यवहार और मूल्यों को आकार देने का माध्यम भी है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से सक्षम बनाती है तथा उसे समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करती है। मानव विकास की प्रक्रिया में शिक्षा व्यक्ति की तार्किक क्षमता, समस्या–समाधान योग्यता, नैतिक चेतना तथा आत्मनिर्भरता को विकसित करती है। इस प्रकार शिक्षा न केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन है, बल्कि राष्ट्रीय विकास की भी आधारशिला है। 21वीं सदी के ज्ञान–आधारित और वैश्वीकृत समाज में शिक्षा की भूमिका में मौलिक परिवर्तन आया है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली मुख्यतः पुस्तकीय ज्ञान, स्मरण शक्ति और परीक्षा–उन्मुख अधिगम पर आधारित रही है, जो आधुनिक जीवन की जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रही है। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को केवल सूचनाओं से लैस करना नहीं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान, नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान कौशल से सुसज्जित करना है। अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका निभाता है।

कुंजी शब्द :– अभ्यास आधारित प्रशिक्षण, समग्र व्यक्तित्व विकास, जीवन कौशल, व्यावहारिक अधिगम, छात्र विकास।

प्रस्तावना –

शिक्षा को मानव विकास का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। 21वीं सदी में शिक्षा की अवधारणा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर व्यावहारिक अनुभव, कौशल विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण पर केंद्रित हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी अनुभवात्मक अधिगम, कौशल आधारित शिक्षा और जीवनोपयोगी दक्षताओं पर बल देती है। छात्रों का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है, जिसमें बौद्धिक क्षमता के साथ–साथ भावनात्मक स्थिरता, सामाजिक सहभागिता, नैतिक मूल्यों तथा व्यवहारिक दक्षताओं का समन्वय आवश्यक है। अभ्यास आधारित प्रशिक्षण–जैसे परियोजना कार्य, समूह चर्चा, भूमिका निर्वाह, प्रयोगात्मक गतिविधियाँ, सामुदायिक सेवा छात्रों को वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़कर उनके सर्वांगीण विकास को सशक्त बनाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल आधारित शिक्षा, बहुविषयक दृष्टिकोण तथा जीवनोपयोगी दक्षताओं जैसे संप्रेषण, सहयोग, नेतृत्व, नैतिकता और डिजिटल साक्षरता पर विशेष बल देती है। इस नीति के माध्यम से शिक्षा को जीवन और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया है, जिससे छात्रों का व्यक्तित्व संतुलित एवं व्यावहारिक रूप से सक्षम बन सके। अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों को कक्षा की सीमाओं से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ता है। इससे छात्र न केवल अकादमिक रूप से दक्ष बनते हैं, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक संवेदनशीलता एवं व्यावहारिक समझ विकसित होती है। इस प्रकार यह प्रशिक्षण छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण तीनों को प्रभावित करता है और उनके समग्र व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को सशक्त एवं सार्थक बनाता है।

व्यक्तित्व को एक समग्र, गतिशील और बहुआयामी संरचना के रूप में समझा जाता है, जिसमें व्यक्ति के विचार, भावनाएँ, व्यवहार, मूल्य तथा सामाजिक अंतःक्रियाएँ एक–दूसरे से गहराई से जुड़ी होती हैं। केवल बौद्धिक विकास किसी छात्र को पूर्ण रूप से सक्षम नहीं बना सकता, क्योंकि जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में सफलता के लिए भावनात्मक संतुलन, सामाजिक समझ, नैतिक दृढ़ता और व्यवहारिक दक्षताओं की भी समान रूप से आवश्यकता होती है। इसी कारण व्यक्तित्व विकास को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखा जाना आवश्यक है।

बौद्धिक आयाम व्यक्तित्व का वह पक्ष है जो व्यक्ति की सोचने, समझने और सीखने की क्षमता से संबंधित होता है। इसमें तर्कशक्ति, विश्लेषण क्षमता तथा सृजनात्मक सोच का विशेष महत्व होता है। छात्रों में बौद्धिक विकास के माध्यम से तथ्यों को समझने, समस्याओं का तार्किक विश्लेषण करने और नवीन विचारों का सृजन करने की क्षमता विकसित होती है। यह आयाम शैक्षणिक उपलब्धि के साथ–साथ निर्णय लेने की योग्यता और आलोचनात्मक चिंतन को भी सुदृढ़ करता है। किंतु केवल बौद्धिक दक्षता होने से ही छात्र जीवन की जटिलताओं का सामना नहीं कर सकता, जब तक अन्य आयामों का भी विकास न हो।

भावनात्मक आयाम व्यक्तित्व का वह महत्वपूर्ण पक्ष है जो व्यक्ति की भावनाओं की समझ, नियंत्रण और अभिव्यक्ति से संबंधित होता है। आत्मनियंत्रण व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों में संतुलित रहने में सहायता करता है, जबकि सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक होती है। आत्मविश्वास भावनात्मक आयाम का एक प्रमुख तत्व है, जो छात्रों को अपने निर्णयों पर विश्वास करने, चुनौतियों का सामना करने और असफलताओं से सीखने की प्रेरणा देता है। भावनात्मक रूप

से सशक्त छात्र न केवल मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन करता है।

सामाजिक आयाम व्यक्ति के समाज के साथ संबंधों और अंतःक्रियाओं को दर्शाता है। सहयोग की भावना छात्रों को समूह में कार्य करना सिखाती है, जिससे उनमें टीम भावना और पारस्परिक सम्मान का विकास होता है। नेतृत्व क्षमता सामाजिक आयाम का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसके माध्यम से छात्र दूसरों को मार्गदर्शन देने, जिम्मेदारी लेने और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना सीखता है। सामाजिक समायोजन व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विविधताओं और विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम बनाता है। सामाजिक रूप से विकसित छात्र समाज में सक्रिय, उत्तरदायी और सकारात्मक भूमिका निभाने में सक्षम होता है।

नैतिक आयाम व्यक्तित्व का वह आधार है जो व्यक्ति के आचरण, मूल्यों और नैतिक दृष्टिकोण को दिशा प्रदान करता है। मूल्यबोध व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता देता है, जबकि ईमानदारी उसके व्यवहार में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को दर्शाती है। उत्तरदायित्व की भावना व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और कार्यों के प्रति सजग बनाती है। छात्रों में नैतिक आयाम का विकास उन्हें न केवल एक अच्छा विद्यार्थी, बल्कि एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। नैतिक मूल्यों के अभाव में बौद्धिक और सामाजिक विकास भी दिशाहीन हो सकता है।[1]

इन सभी आयामों का संतुलित और समन्वित विकास ही समग्र व्यक्तित्व विकास कहलाता है। जब बौद्धिक क्षमता भावनात्मक संतुलन, सामाजिक समझ, नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक दक्षताओं के साथ विकसित होती है, तब छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से सफल होता है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मविश्वास, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ता है। यही समग्र व्यक्तित्व विकास शिक्षा का अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

अभ्यास आधारित प्रशिक्षण को एक ऐसी प्रभावी शिक्षण पद्धति के रूप में देखा जाता है, जिसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता न रहकर अधिगम प्रक्रिया के सक्रिय सहभागी बनते हैं। इस पद्धति का मूल उद्देश्य छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक अनुभवों के माध्यम से ज्ञान और कौशल अर्जित करने का अवसर प्रदान करना है। जब छात्र स्वयं गतिविधियों में भाग लेते हैं, प्रयोग करते हैं और अपने अनुभवों पर चिंतन करते हैं, तब उनका अधिगम अधिक गहरा, स्थायी और अर्थपूर्ण बन जाता है। इस प्रक्रिया में आत्म मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके माध्यम से छात्र अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और सुधार की संभावनाओं को पहचान पाते हैं।

अभ्यास आधारित प्रशिक्षण में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में सम्मिलित होता है। परियोजना कार्य के माध्यम से छात्रों को किसी वास्तविक समस्या की पहचान करने, उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करने, योजना बनाने और अंततः समाधान प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है। यह प्रक्रिया छात्रों में अनुसंधान दृष्टिकोण, तार्किक सोच, रचनात्मकता और उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करती है। परियोजना कार्य छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के साथ–साथ सहयोगात्मक अधिगम की भी शिक्षा देता है, जिससे उनका आत्मविश्वास और समस्या समाधान क्षमता सुदृढ़ होती है।

समूह चर्चा अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का एक अन्य प्रभावी माध्यम है, जिसके द्वारा छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का अवसर मिलता है। समूह चर्चा के दौरान विचारों का आदान–प्रदान होता है, जिससे छात्रों की तर्क क्षमता, संप्रेषण कौशल और आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। यह प्रक्रिया छात्रों को अपने विचारों को स्पष्ट, संगठित और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना सिखाती है तथा उनमें सहिष्णुता और परस्पर सम्मान की भावना को भी प्रोत्साहित करती है।

भूमिका निर्वाह अथवा रोल प्ले गतिविधि के माध्यम से छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अनुभव कराया जाता है। इस प्रक्रिया में छात्र विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए सामाजिक, व्यावसायिक या नैतिक स्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। भूमिका निर्वाह से छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता, भावनात्मक समझ और सामाजिक संवेदनशीलता का विकास होता है। इसके माध्यम से वे दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाकर सोचने लगते हैं, जिससे सहानुभूति और आत्मनियंत्रण जैसे गुण विकसित होते हैं।

प्रयोगात्मक गतिविधियाँ अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का वह पक्ष हैं, जो सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी को कम करती हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से छात्र कक्षा में पढ़े गए सिद्धांतों को प्रयोगशाला या वास्तविक परिस्थितियों में लागू करते हैं। इससे उनके ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है और अधिगम अधिक ठोस तथा विश्वसनीय बनता है। प्रयोगात्मक गतिविधियाँ छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना को प्रोत्साहित करती हैं, जो उच्च स्तरीय अधिगम के लिए आवश्यक है।

सामुदायिक सेवा को भी अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। इसके माध्यम से छात्र समाज की वास्तविक समस्याओं से परिचित होते हैं और उनके समाधान में सक्रिय योगदान देते हैं। सामुदायिक सेवा छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व, सहानुभूति, सहयोग और मानवीय मूल्यों का विकास करती है। जब छात्र समाज के विभिन्न वर्गों के साथ कार्य करते हैं, तब उनमें सामाजिक संवेदनशीलता और नागरिक चेतना का विकास होता है, जो उन्हें एक जिम्मेदार और सजग नागरिक बनने में सहायता करता है।

इस प्रकार अभ्यास आधारित प्रशिक्षण की ये सभी गतिविधियाँ छात्रों को ज्ञान, कौशल और मूल्यों का समन्वित अनुभव प्रदान करती हैं। परिणामस्वरूप छात्र न केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम बनते हैं, बल्कि जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से तैयार होते हैं।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. अभ्यास आधारित प्रशिक्षण की अवधारणा का विश्लेषण करना।
2. छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों का अध्ययन करना।
3. अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का आत्मविश्वास पर प्रभाव ज्ञात करना।
4. अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का संप्रेषण एवं सामाजिक कौशल पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
5. अभ्यास आधारित प्रशिक्षण एवं समग्र व्यक्तित्व विकास के मध्य संबंध स्थापित करना।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या :

अध्ययन के इस चरण में अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयामों पर पड़ने वाले प्रभाव का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया। इसके अंतर्गत आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल

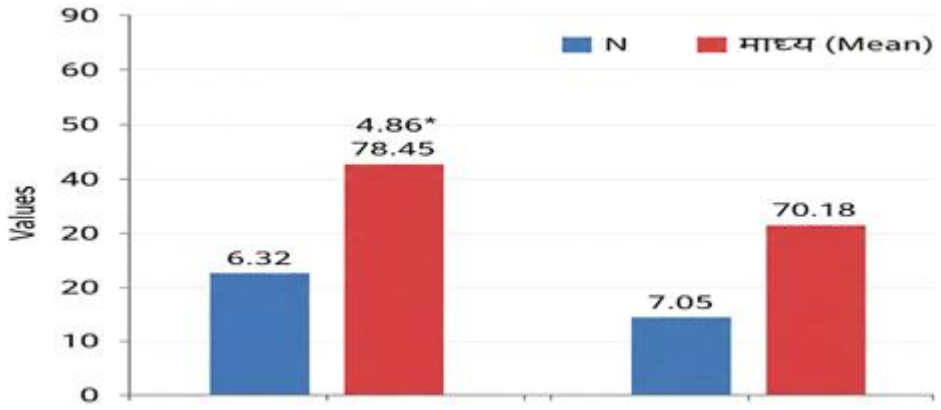
तथा सामाजिक समायोजन जैसे प्रमुख आयामों का परीक्षण किया गया। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु माध्य, मानक विचलन तथा 't' परीक्षण का प्रयोग किया गया, जिससे निष्कर्षों की वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित की जा सके।

तालिका :- 1 अभ्यास आधारित प्रशिक्षण एवं आत्मविश्वास

समूह	N	माध्य (Mean)	मानक विचलन SD	t-मान
अभ्यास आधारित प्रशिक्षण प्राप्त छात्र	100	78.45	6.32	4.86
प्रशिक्षण न प्राप्त छात्र	100	70.18	7.05	

0.05 स्तर पर सार्थक।

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों का आत्मविश्वास स्तर, प्रशिक्षण न प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में अधिक पाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त समूह का माध्य आत्मविश्वास स्कोर 78.45 है, जबकि अन्य समूह का माध्य 70.18 है। दोनों समूहों के मध्य प्राप्त 't' मान 4.86 है, जो 0.05 स्तर पर सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

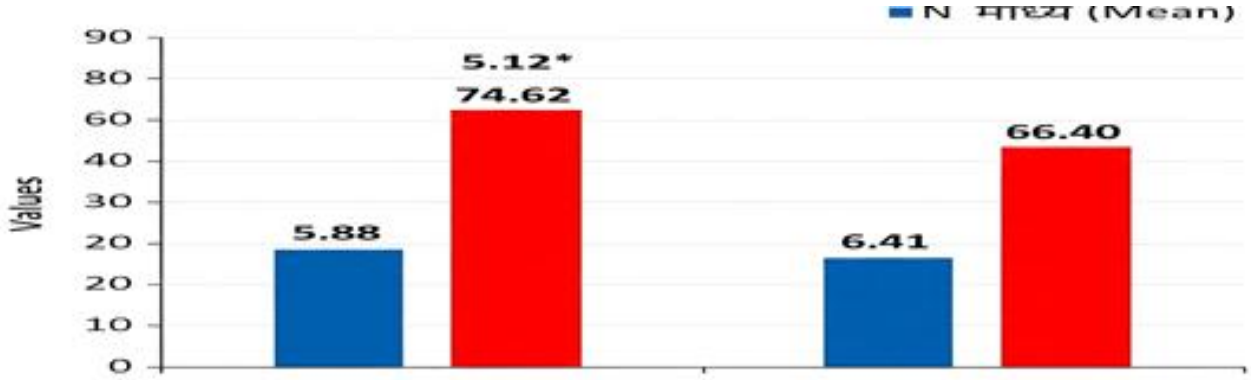


तालिका :-2 अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का संप्रेषण कौशल पर प्रभाव

समूह	N	माध्य (Mean)	मानक विचलन (SD)	t-मान
अभ्यास आधारित गतिविधियों में सम्मिलित छात्र :	100	74.62	5.88	5.12
न्यून सहभागिता वाले छात्र	100	66.40	6.41	

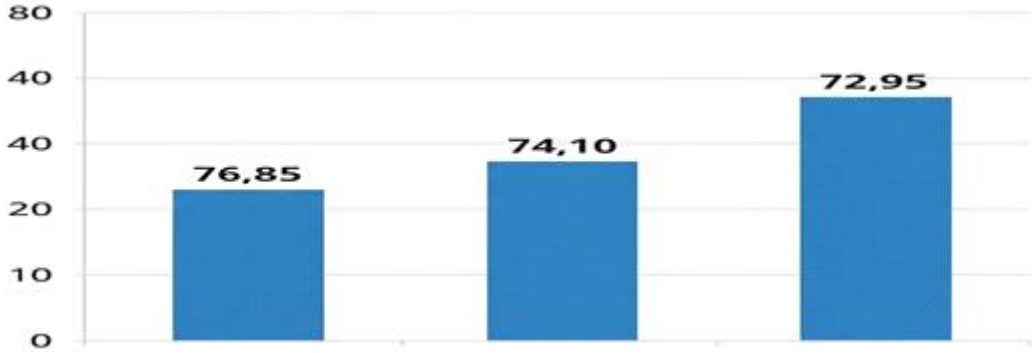
0.05 स्तर पर सार्थक।

तालिका 2 के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यास आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित छात्रों के संप्रेषण कौशल में उल्लेखनीय वृद्धि पाई गई। सक्रिय सहभागिता वाले छात्रों का माध्य स्कोर 74.62 है, जबकि न्यून सहभागिता वाले छात्रों का माध्य 66.40 पाया गया। प्राप्त 't' मान 5.12 है, जो यह दर्शाता है कि दोनों समूहों के बीच का अंतर सांख्यिकीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।



तालिका 3 :- अभ्यास आधारित प्रशिक्षण एवं सामाजिक समायोजन

आयाम	माध्य स्कोर
सहयोग भावना	76.85
सहानुभूति	74.10
नेतृत्व क्षमता	72.95



तालिका 3 से यह स्पष्ट होता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों के सामाजिक समायोजन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सहयोग भावना का माध्य स्कोर सर्वाधिक पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभ्यास आधारित गतिविधियाँ छात्रों में टीम भावना और सामूहिक उत्तरदायित्व को विकसित करती हैं। सहानुभूति और नेतृत्व क्षमता के उच्च स्कोर यह दर्शाते हैं कि ऐसे प्रशिक्षण से छात्र न केवल दूसरों की भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं, बल्कि समूह का मार्गदर्शन करने की क्षमता भी विकसित करते हैं।

व्याख्या एवं समग्र विश्लेषण :

सभी सांख्यिकीय परीक्षणों में प्राप्त 't' मान निर्धारित सार्थक स्तर से अधिक पाए गए, जिससे यह सिद्ध होता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का छात्रों के आत्मविश्वास, संप्रेषण कौशल तथा सामाजिक समायोजन पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आँकड़ों का विश्लेषण यह संकेत देता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों को केवल अकादमिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी सशक्त बनाता है।

इस प्रकार आँकड़ों की व्याख्या से यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकलता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण

छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को प्रभावी, सुदृढ़ और उद्देश्यपूर्ण बनाता है।

चर्चा–प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष यह स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह परिणाम न केवल अध्ययन की परिकल्पनाओं की पुष्टि करते हैं, बल्कि पूर्ववर्ती शोधों से भी पूर्णतः सामंजस्य रखते हैं। अनुभवात्मक अधिगम से संबंधित डेवी, कोल्ब तथा समकालीन भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों में यह प्रतिपादित किया गया है कि जब छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, तब उनका अधिगम अधिक गहरा, स्थायी और व्यवहारोन्मुख हो जाता है। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष इन्हीं सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से प्रमाणित करते हैं।

अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों को निष्क्रिय श्रोता की भूमिका से बाहर निकालकर सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में स्थापित करता है। जब छात्र परियोजना कार्य, समूह चर्चा, भूमिका निर्वाह अथवा प्रयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं, तब वे ज्ञान को केवल ग्रहण नहीं करते, बल्कि उसका विश्लेषण, प्रयोग और मूल्यांकन भी करते हैं। यह सक्रिय सहभागिता छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करती है, क्योंकि वे स्वयं समस्याओं की पहचान करना, समाधान ढूँढना और निर्णय लेना सीखते हैं। आत्मनिर्भरता का यह विकास उन्हें शैक्षणिक ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी सक्षम बनाता है।

अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। विभिन्न गतिविधियों के दौरान छात्रों को अनेक विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करना होता है, जिसके लिए तर्क, विवेक और अनुभव का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में छात्र अपनी गलतियों से सीखते हैं और भविष्य में अधिक विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। यह निर्णय क्षमता व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो छात्रों को जटिल जीवन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है।

इसके अतिरिक्त अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों में सामाजिक चेतना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समूह कार्य और सामुदायिक सेवा जैसी गतिविधियों के माध्यम से छात्र समाज की वास्तविक समस्याओं से परिचित होते हैं और उनके समाधान में सहभागिता करते हैं। इससे उनमें सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। सामाजिक चेतना का यह विकास छात्रों को केवल अपने व्यक्तिगत हितों तक सीमित न रखकर समाज के प्रति सजग और उत्तरदायी नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करता है।

वर्तमान अध्ययन की चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों के व्यवहारिक पक्ष को सुदृढ़ करता है। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियाँ प्रायः सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित होती हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जूझने में कठिनाई होती है। इसके विपरीत अभ्यास आधारित प्रशिक्षण सिद्धांत और व्यवहार के बीच सेतु का कार्य करता है। यह छात्रों को ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे जीवन की वास्तविक चुनौतियों के लिए मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से तैयार होते हैं।

समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि अध्ययन के निष्कर्ष अभ्यास आधारित प्रशिक्षण को एक प्रभावी शिक्षण पद्धति के रूप में स्थापित करते हैं, जो छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

यह न केवल पूर्ववर्ती शोधों की पुष्टि करता है, बल्कि भारतीय शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इसके महत्व को भी रेखांकित करता है, जिससे भविष्य में इस दिशा में और अधिक अनुसंधान की संभावनाएँ सुदृढ़ होती हैं।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध के विश्लेषण एवं प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास में अत्यंत प्रभावी भूमिका निभाता है। यह प्रशिक्षण छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें सक्रिय सहभागिता के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है, जिससे उनके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम संतुलित रूप से विकसित होते हैं।अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण छात्रों के संज्ञानात्मक विकास को सुदृढ़ करता है। इसके माध्यम से उनमें समस्या–समाधान, विश्लेषण, तार्किक चिंतन तथा सृजनात्मक सोच जैसी उच्च स्तरीय क्षमताओं का विकास होता है। साथ ही, यह प्रशिक्षण उनके भावनात्मक विकास में भी सहायक सिद्ध होता है। विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने से छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति तथा तनाव से निपटने की क्षमता विकसित होती है, जिससे उनका मानसिक संतुलन मजबूत होता है। सामाजिक विकास की दृष्टि से भी अभ्यास आधारित प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है। समूह कार्य, सहयोगात्मक गतिविधियों तथा नेतृत्व के अवसरों के माध्यम से छात्रों में सहयोग, संचार, नेतृत्व तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक जीवन से जुड़ी गतिविधियाँ छात्रों में ईमानदारी, उत्तरदायित्व, नैतिक मूल्यों तथा उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती हैं, जिससे नैतिक शिक्षा व्यवहारिक रूप में स्थापित होती है।

अतः कहा जा सकता है कि अभ्यास आधारित प्रशिक्षण को शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। पारंपरिक शिक्षण पद्धतियों के साथ इसके समन्वय से शिक्षा अधिक प्रभावी, जीवनोपयोगी एवं व्यवहारिक बन सकती है तथा छात्र शैक्षणिक सफलता के साथ–साथ जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम बन सकते हैं।

संदर्भ सूची :

1. Dewey. J. (2022). E-perience and Education. New York : Macmillan.
2. Kolb. D. A. (2022). E-periential Learning. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
3. शर्मा, आर. (2022). आधुनिक शिक्षण विधियाँ. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन।
4. पटेल, एस., एवं सिंह, के. (2022). अभ्यास आधारित शिक्षण का प्रभाव. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, 7(2), 45–52.
5. National Education Policy (2020). Government of India.
6. Malik, P. & Behera, S. (2024). The Transformative Power of E-periential Learning : Bridging Theory and Practice.
7. Henriquez. V. V. (2025). Applying Kolb's E-periential Learning Cycle for Deep Learning.
8. Coleman, B. M. (2025). Effects of Experiential Learning on Students' Transfer Skills.
9. K. A. A. K. Putri & N. L. P. E. S. Dewi (2025). The Impact of E-periential Learning on Student

Engagement and Outcomes. Singh. T. P.. & Rao.T. K. (2024).
10. E-periential Learning : A Systematic Review of Approach and Learning Models. EdukAsia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. 4(3), 1403–1411.
11. Ainiyah. M. U.. Subroto. W. T.. & Hakim. L. (2023). E-periential Learning Research Trends Through Bibliometric Analysi 2019-2023.

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
SANGAM
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 202-205

Medicinal Plants in Indian Traditional Knowledge

Kamini Kumari
Principal in-charge
M.Sc, B.Ed, M.phil, (Chemistry)

Abstract :

India possesses one of the world's richest traditions of medicinal plant knowledge, developed over thousands of years through careful observation, practical experience, and scholarly documentation. Ancient systems such as Ayurveda, Siddha, and Unani recognize the healing properties of numerous plants and emphasize maintaining health through a balance of body, mind, and environment. Even today, medicinal plants continue to play a significant role in primary healthcare, pharmaceutical research, and preventive medicine. This article explores the importance of medicinal plants in Indian traditional knowledge, highlights commonly used species, discusses their therapeutic benefits, and examines their relevance in modern healthcare.

Introduction :

India is widely recognized as the "land of medicinal plants" because of its remarkable biodiversity and long history of traditional medicine. For centuries, Indian communities have relied on herbs, shrubs, trees, and climbers to treat diseases and promote overall well-being. The knowledge of these plants has been preserved in ancient texts such as the Charaka Samhita, Sushruta Samhita, and Ashtanga Hridaya, as well as through oral traditions passed down from one generation to another.

Medicinal plants are natural sources of bioactive compounds that possess therapeutic properties. Unlike many synthetic drugs, they are often used as part of a holistic approach that considers diet, lifestyle, and mental well-being alongside treatment.

Indian Traditional Knowledge and Medicinal Plants :

The Indian Knowledge System (IKS) integrates medicine with philosophy, ecology, ethics, and sustainable living. Traditional healing systems believe that maintaining harmony between humans and nature is essential for good health. Plants are selected based on their taste (Rasa), qualities (Guna), potency (Virya), post-digestive effect (Vipaka), and specific therapeutic action (Prabhava).

Medicinal plants are used in various forms, including powders, decoctions, juices, oils, pastes, and herbal formulations. Their use is often complemented by yoga, meditation, dietary regulation, and healthy daily routines.

Important Medicinal Plants in Indian Traditional Knowledge :

1. Tulsi (Ocimum sanctum)

Tulsi, also known as Holy Basil, is regarded as one of the most sacred medicinal plants in India. It possesses antimicrobial, anti-inflammatory, antioxidant, and immunomodulatory properties. Tulsi is commonly used to treat cough, cold, fever, respiratory disorders, digestive problems, and stress. Regular consumption is believed to strengthen immunity and improve overall health.

2. Neem (Azadirachta indica)

Neem has been valued for centuries because of its antibacterial, antifungal, antiviral, and antiparasitic properties. Different parts of the tree—including leaves, bark, flowers, fruits, and seeds—are used in traditional medicine. Neem is effective in managing skin disorders, dental problems, wound healing, diabetes, and certain infections.

3. Turmeric (Curcuma longa)

Turmeric is one of the most extensively used medicinal spices in India. Its active compound, curcumin, exhibits powerful anti-inflammatory and antioxidant effects. Traditionally, turmeric has been used for wound healing, digestive disorders, joint pain, skin diseases, and boosting immunity. Modern research also explores its role in managing chronic inflammatory conditions.

4. Ashwagandha (Withania somnifera)

Ashwagandha is an important rejuvenating herb in Ayurveda. It is classified as a Rasayana, meaning it promotes vitality and longevity. It is commonly used to reduce stress, improve physical endurance, enhance cognitive function, strengthen immunity, and support healthy aging.

5. Amla (Phyllanthus emblica)

Amla, or Indian gooseberry, is one of the richest natural sources of vitamin C and antioxidants. It supports digestion, liver function, immunity, eye health, and cardiovascular health. Amla is also a major ingredient in many classical Ayurvedic formulations.

6. Giloy (Tinospora cordifolia)

Giloy is known as the "herb of immortality" in Ayurveda. It is traditionally used to enhance immunity, reduce fever, improve digestion, support liver function, and manage chronic illnesses. Its immunomodulatory properties have attracted increasing scientific attention.

7. Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller)

Aloe vera is widely used for treating burns, wounds, skin disorders, and digestive complaints.

Its soothing gel promote tissue healing and skin hydration while also possessing antimicrobial properties.

Scientific Validation of Traditional Knowledge :

Modern scientific research has confirmed many therapeutic properties of medicinal plants described in traditional Indian literature. Advanced techniques in pharmacology, phytochemistry, and biotechnology have identified numerous active compounds responsible for their medicinal effects. Several modern medicines have originated from or been inspired by plant-derived compounds.

Scientific validation strengthens confidence in traditional medicine while encouraging evidencebased integration into modern healthcare systems.

Importance of Conservation :

India's medicinal plant wealth faces challenges such as habitat destruction, climate change, overharvesting, and loss of traditional knowledge. Sustainable cultivation, conservation of biodiversity, documentation of indigenous knowledge, and community participation are essential for preserving this valuable heritage.

Government initiatives, research institutions, medicinal plant boards, and educational programs play a crucial role in promoting conservation and responsible utilization of medicinal plant resources.

Relevance in the Modern World :

The growing interest in natural products, preventive healthcare, and holistic medicine has increased global recognition of Indian medicinal plants. Herbal medicines, nutraceuticals, cosmetics, and wellness products derived from traditional knowledge are now widely used across the world. The integration of traditional wisdom with scientific research offers promising opportunities for affordable, sustainable, and patient-centered healthcare.

Conclusion :

Medicinal plants represent one of the greatest strengths of the Indian Knowledge System. They embody centuries of accumulated wisdom that combines careful observation, practical experience, and holistic health principles.While modern science continues to validate many traditional claims, these plants remain valuable not only as therapeutic resources but also as symbols of India's rich cultural and scientific heritage. Preserving medicinal plant diversity, promoting evidence-based research, and integrating traditional knowledge with contemporary healthcare will ensure that this invaluable legacy continues to benefit future generations.

References :

1. Charaka Samhita.

2. Sushruta Samhita.
3. Ministry of AYUSH, Government of India.
4. WHO Traditional Medicine Strategy.
5. National Medicinal Plants Board (Government of India).
6. Kirtikar, K. R., & Basu, B. D. Indian Medicinal Plants.
7. Browser of national children's science congress, 2026

Mob No. 9135266489
Regional Resource Person, Escort, Mentor and Guide Teacher of National Children's Science Congress From 2012 Till Present.
Medicinal Plants in Indian Traditional Knowledge

संगम Impact Factor : 7.834
Website : www.ginajournal.com
ISSN : 2321-8037
गीना देवी शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित बहुभाषिक–बहुविषयक शोध को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय मासिक
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY MONTHLY MULTI LANGUAGE
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL
SANGAM
Vol. 14, Issue 5-6
पृष्ठ : 206–213

निर्गुण संत कबीर : युवा–वर्ग के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा–स्त्रोत

डॉ. सुधा
सहायक आचार्य, हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ. प्रदेश–226007

जीवन में नित नए परिवर्तन एवं बदलाव होते हैं, कभी भी जिन्दगी एक समान नहीं रह सकती है। हमारी आयु, विचार-बुद्धि, रुचि और दिनचर्या सब धीरे-धीरे शाश्वत् रूप से बदलते और नए रूप-रंग में ढलते हैं। यह होना स्वाभाविक और अति महत्त्वपूर्ण है। वरना जीवन में एकरसता और एकाकीपन विद्यमान हो जाएगा।

युवा वर्ग इस परिवर्तन के दौर में सर्वाधिक ऊर्जावान, उत्साहित एवं आनंदित रहता है। मनुष्य के जीवन का बसंत है- युवावस्था, जीवन के निर्माण का स्वर्णिम काल है-युवावस्था, निर्माण के साथ ही भटकाव और विचलन का समय भी है यही ऊर्जावान युवावस्था अर्थात् अगर अपनी युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन एवं प्रेरणा ना मिले तब उनकी दिशा और दशा दोनों ही दिग्भ्रमित हो सकती है।

भक्ति आन्दोलन के अन्तर्गत निर्गुण पंथी, ज्ञानमार्गी शाखा के प्रसिद्ध और महान संत कबीरदास ने अपनी वाणी के द्वारा भारतीय जन-मानस के लिए बेहद सुन्दर, सार्थक एवं प्रेरणादायक उक्ति कही। कबीर के वचन हमारे लिए अति अनमोल और अद्वितीय हैं। भावी पीढ़ी के लिए यदि सही समय पर इसका चिन्तन-मनन एवं आत्मसात् करने का प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति, समाज और सम्पूर्ण मानवता का कल्याण एवं सुखद अनुभूति होगी।

कबीर हमेशा कहते हैं कि गुरु के आशीर्वाद, प्रेम और मार्गदर्शन से शिष्य का भला होता है। गुरु की महिमा अनंत मानी है। कबीर कहते है -

"सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार।
लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखांवनहार।।→

(1) (सतगुरु महिमा कौ अंग)

अर्थात् सच्चे गुरु की महिमा का गुण-गान नहीं किया जा सकता है, वे अनंत उपकार करते है। हमें देखने के लिए ज्ञान द्वारा आँखें खोल देते है। जिससे मैं प्रभु के दर्शन कर सकता हूँ।

कबीर का ही प्रसिद्ध दोहा है:

"कबीर ग्यान प्रकास्या गुरु मिल्या, सो जिनि बीसरि जाइ।
जब गोब्यंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई।।→

(गुरु गोविन्द के विषय में)

युवा पीढ़ी को भी सही एवं उचित मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु की शरण लेनी चाहिए। उनके बताए रास्ते पर चलकर सदैव जीवन सत्-मार्ग की ओर बढ़ता है।

वर्तमान दौर में युवा-वर्ग ऊपरी चमक-दमक के कारण कभी-कभार अच्छे गुरु की संगति नहीं कर पाता है। नई तकनीकी एवं मीडिया के जमाने में किसी को भी अपना प्रेरणास्त्रोत एवं मार्गदर्शक बना लेता है। जिसकी सज़ा गुरु-शिष्य दोनों को मिल जाती है। सचेत करते हुए संत कबीर ने बताया है-

"जाका गुरु है आंधरा, चेला है जाचंध।
अंधै-अंधा ठेलिया, दोन्यूं कूप परंत।।→ (2)

भाव यही है कि जब गुरु अंधा होगा स्वार्थ और लोभ से भरा होगा, तो शिष्य को क्या बताएगा। दोनों ही अँधे की तरह एक-दूसरे को ठेलकर

कूप (कुंए) अवनति के मार्ग पर ही प्रशस्त करेंगे। इसके लिए सावधानी पूर्वक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए।

युवा पीढ़ी प्रेम के प्रति बेहद आकर्षित एवं प्रेरित होती है। आज के समय सच्चे प्रेम की प्राप्ति बेहद कठिन और दुर्लभ जान पड़ती है। प्रेम के लिए कबीरदास समस्त प्राणी एवं मनुष्य को बताते हैं। विशेष रूप से बड़े उत्साही जवान लोग (युवा-वर्ग) प्रेम में शीघ्रता चाहते हैं। जबकि इसमें गहराई और त्याग परम आवश्यक तत्त्व है। संत कबीर कहते हैं-

"प्रेम ना बाड़ी ऊपजे, प्रेम न हाट बिकाय।
राजा परजा जेहि रुचे, सीस देई ले जाय।।→

"पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय।
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।।→

प्रेम (प्यार) की अनुभूति हृदय में तभी संभव है जब अहम् (गर्व) को चूर (समाप्त) कर दिया जाए। प्रेम खेत में उगने वाली या बाज़ार में बिकने वाली वस्तु नहीं है।

भले ही कितना भी पढ़े-लिखे विद्वान हैं, अगर हमने प्रेम की भावना नहीं तो व्यर्थ है। प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है।

इस तरह आज हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से युवाओं में दिखावटी और ऊपरी प्रेम का फैशन (आँधी) चारों ओर दिखाई देती है। किन्तु अल्प समय में उनका प्रेम गानो खत्म हो जाता है। कई अपराध और अपहरण केवल झूठे प्रेग के कारण होते रहते हैं। यदि कबीर की बात समझें तो प्रेम की महिमा जान सकते हैं।
कबीरदास ने सदैव साहस, निर्भीकता, बेहद प्रखर स्वर में समाज के आडम्बर, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, मंदिर-मस्जिद आदि के विषय में विरोधी भाव प्रकट किए हैं। वे भ्रमित युवा पीढ़ी कर्म की ओर झुकाव बढ़ा सकती है। जो अब मानो अंध भक्ति और अंध श्रद्धा के पथ पर चलकर समय और श्रम व्यर्थ करते हैं। युवा देश और समाज के मजबूत आधार हैं जिन पर आने वाला भविष्य तय होगा। उन्हें सचेत और जागरूक करते हैं कबीर के पद :-

"चलन-चलन सब कोई कहत है। ना जानौ बैकुंठ कहाँ है।
जोजन एक परमिति नहिं जाने। बातन ही बैकुंठ बखानै।

कहें सुनें कैसे पतिअइजै। जब लग तहाँ आप नहीं जइहै।
कहै कबीर यह कहिओं काहि। साधु संगति बैकुंठहि आहि।।→ -----(3)

साधु-संतों की संगति का असर हमारे जीवन पर इस प्रकार पड़ता है कि हृदय सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। युवा शक्ति के लिए सही मार्गदर्शन एवं प्रेरणा ही सही रास्ते पर चलने की दृढ़ता प्रदान करती है। कबीर का बेहद जरूरी सुझाव यही दिखाई पड़ता है-

"बोलना का कहिए रे भाई। बोलत-बोलत तत्त नसाई। बोलत-बोलत बदै बिकाए। बिनु बोलें क्या करहि किचाएं। संत मिलहिं कुछ सुनि कहिये। मिलहिं असंत मस्टि करि रहिये। →

अर्थात् बोलना तभी सार्थक है, जब समझवाले हों वरना मौन रहना ही उत्तम है। -----(4)

कबीर अपने समय और परिस्थितियों से ऊपर और आगे की सोच रखने वाले महान व्यक्ति थे। उनकी शिक्षा एवं उपदेश आज भी प्रासंगिक एवं आवश्यक जान पड़ते हैं। भारतीय ज्ञान परम्परा के इस कवि व्यक्तित्व के प्रति सच्चे मन से आदर भाव जागृत होते हैं। युवाओं को इनके व्यक्तित्व से भी प्रेरणा मिलती है।

"सच्ची बात यह है कि हिन्दी साहित्य में कबीर से बड़ा मानवतावादी कोई नहीं हुआ। उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज में प्रचलित समस्त विश्वासों, रूढ़ियों तथा मिथ्या सिद्धान्तों द्वारा प्रचारित सामाजिक विषमताओं का मूलोच्छेद करने का बीड़ा उठाया और निर्ममतापूर्वक सभी पाखण्डों पर प्रहार किया। ----------(5) (कबीर-वाणी सुधा पृष्ठ-62)

सामाजिक शोषण, अनाचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में आज भी कबीर का काव्य एक तीखा अस्त्र है। कबीर से हम रूढ़िगत सामन्ती दुराचार और अन्यायी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध उठ कर लड़ना सीखते हैं और यह भी सीखते हैं कि विद्रोही कवि किस प्रकार अंत तक शोषण के दुर्ग के सामने अपना माथा ऊंचा रखता है।"-------(6)

(श्री प्रकाश गुप्त, हिन्दी साहित्य
की जनवादी परम्परा
डॉ० राम जी सहायक,
कबीर दर्शन, पृ-435)

युवा वर्ग अक्सर अपनी अवस्था, सुन्दरता और ताकत पर मुग्ध और आकर्षित होते हैं। कभी-कभार वे वृद्ध-जनों का मजाक एवं तिरस्कार तक करने में नहीं चूकते। उनका मान-सम्मान ना करना संस्कारहीनता है। ऐसी भावनाओं पर लगाम लगाते हुए कबीर दास जी हकीकत बयान करते हैं-

"झूठे तन को क्या गरबावे। मेरे तो पल भरी रहन न पावै।
हाड़ जरै जैसे लकड़ी झूरी केस जरै जैसे तिन के कूरी।
कहै कबीर नर अजहुं न जागे। जम का डंड मूड़ महि लागे।।→

-------(7) (कबीर-वाणी सुधा पृष्ठ-62)

कबीर ने वैसे तो पद में सभी को संबोधित किया था। किन्तु यदि युवा-अवस्था में इस प्रकार सचेत किया जाए तो मिथ्या गरूर नहीं पनप सकता। जीवन की सच्चाई सदैव याद रहेगी।

शिकायत और पर-निन्दा की भी अधिकांश लोगों को आदत पड़ जाती है। इसके विपरीत उनके पास अवकाश नहीं होता कि स्वयं के लिए आत्ममंथन करें। इसके लिए कबीर वाणी के स्वर याद आते हैं-

"कबीर दोष पराये देखि करि, चल्या हसंत हसंत।
अपने याद न आवहीं, जिनकी आदि न अंत।।→

----------(8)(कबीर ग्रंथावली पृष्ठ-132)

युवा भी अक्सर दूसरों को दोषी मानकर अपनी असफलता और स्थिति का कारण मानते हैं, जबकि स्वयं वह अपने लिए सर्वाधिक जिम्मेदार होते हैं। इस प्रवृत्ति से बचना हितकारी होता ही है।

कबीर दास के विषय में "हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास→, संप० बच्चन सिंह ने वर्णित है- "किसी समय की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव पड़ा हो या न पड़ा हो, इस पर परस्पर विरोधी रायें हो सकती हैं। किन्तु अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि आज की शिष्ट और शिक्षित जनता पर कबीर का प्रभाव किसी भी अन्य कवि के प्रभाव से अधिक ही पड़ा है। →

---------(9)(हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास पृष्ठ- 87)

कबीर अपने समय-समाज और परिस्थितियों के आगे की सोच रखने वाली महान हस्ती हैं। जितनी बातें उस वक्त भी चुनौती देती थीं आज भी उतनी ही धारदार साबित होती हैं। भाषा, भाव अभिव्यक्ति, साधना और सिद्धि सभी में अत्यंत उच्च कोटि के साधक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें "वाणी का डिक्टेटर→ कहा है।

युवाओं में भी यदि सम्प्रेषण शक्ति (communication skill) प्रखर और प्रभावशाली सक्षमता और सामर्थ्य प्राप्त कर लें तो वास्तव में उनके व्यक्तित्व और भावाभिव्यक्ति सशक्त एवं सहज रूप में आविर्भूत हो सकेंगे।

कबीर के दोहों में कहा गया है-

"ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय।
औरन को शीतल करै, आपहु शीतल होय।। →

भारतीय समाज में समन्वय एवं सामंजस्य पूर्वक जीवन जीने की कला को बहुत महत्त्व दिया जाता है। युवा पीढ़ी से यही उम्मीद की जाती है कि उनकी शक्ति तथा सफलता अवश्य ही परोपकार और परहित का कार्य स्वीकार करेगी। जिससे आशा की ज्योति, सद्भाव के गुण निरन्तर प्रकाशित होते रहें।

"बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।। →

या

"कबीरा खड़ा बाज़ार में, सबकी माँगे खैर।।→

सबका कल्याण हो, यही सात्विक भावना का मनन करना युवाओं को श्रेष्ठ नागरिक बनने और अच्छे इन्सान में ढालने में सहायक होगा।

अंत में हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कबीर के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं आदर्शों में वास्तविक रूप से ऊर्जा से भरपूर युवा-वर्ग को सीखने-सिखाने के लिए बहुत ही जीवंत एवं प्रभावशाली विचारधारा समाहित एवं प्रवाहित है। जिसकी ताकत को यदि युवा पीढ़ी दिल से स्वीकार कर प्रेरणा तथा मार्गदर्शक मान सके तो कोई शंका नहीं कि उनका सन्तुलित एवं उच्च स्तर का आनंदित जीवन दृष्टिगत होगा। कबीर का साहित्य आज भी समय-सीमा लाँघ कर सर्वाधिक प्रासंगिक तथा प्रेरणास्त्रोत बना हुआ है। वैसे तो सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, भाषायी अनेक स्तर पर कबीर की कोई तुलना नहीं। फिर भी युवाओं के पास जो तेवर एवं जुनून होता है, वैसी ही ललकार कबीर के ही पास सुनाई देती है। जिस निर्भीकता और अखंड़ता से वे अपनी बात कबीरदास कहते हैं, वैसा कोई कहीं नहीं मिलता है।

"भाषा-संवेदना, विचार-प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देसीपन को महत्त्व देते हैं। "संसकिरित के कूप-जल→ को छोड़कर वे भाषा के बहते नीर तक स्वयं पहुँचते हैं और सबको पहुँचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक-संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों एक साथ अप्रासंगिक करार दिए जाते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अपने अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। भाषा के पहले कड़े कवि होने के नाते वे युगीन संवेदना की इस माँग को पूरा करते हैं।"----------(10)

निष्कर्षतः कबीर सच्चे अर्थों में युवा-वर्ग के सच्चे प्रेरणास्त्रोत एवं मार्गदर्शक साबित होते हैं।

संदर्भ सूची

1. "सतगुरु महिमा कौ अंग"- 'कबीर-वाणी सुधा'- डॉ० पारसनाथ तिवारी, रका प्रकाशन, 2003, पृ-185
2. सतगुरु महिमा कौ अंग- 'कबीर-वाणी सुधा', वही पृ-184
3. कबीर-वाणी-सुधा, पृ-165
4. कबीर-वाणी सुधा - पृ 166
5. वही पृ - 61
6. श्री प्रकाश गुप्त, (हिन्दी साहित्य की जनवादी परम्परा), डॉ० रामजी सहायक, कबीर दर्शन पृ-435
7. कबीर वाणी सुधा - पृ-167
8. कबीर ग्रंथावली, संपा- डॉ० माताप्रसाद गुप्त पृ-132, साहित्य भवन प्रा० लि०, इलाहाबाद (2001)
9. हिन्दी का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, राधाकृष्ण प्रकाशन (2006) नई दिल्ली (पृ-87)
10. हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास - रामस्वरूप चतुर्वेदी, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद (2007) (पृ-31)

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor : 8.642

बोहल शोध मंजूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES
PEER REVIEWED, REFREED RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 2018)

Website :
www.bohalshodhmanjusha.com
Email : grsbohal@gmail.com

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Adv.
M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित

ISSN : 2321-8037
Impact Factor : 7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : www.ginajournal.com
Email : grngobwn@gmail.com
Office : 8708822674

Editor :
Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tantia University
M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ
द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639
Impact Factor : 6.521

SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Executive Editor : Dr. Varsha Rani M. 9671904323
Managing Editor : Dr. Mukesh Verma M. 9627912535

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गीना देवी शोध संस्थान भिवानी के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज भिवानी से छपवाकर कार्यालय #202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा) से वितरित की।

ISSN 2321:8037

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों में मजदूरों के संघर्ष

Authored by

डॉ. आलपाटि भानु प्रसाद

हिन्दी प्राध्यापक,

यस.आर.आर–सी.वी.आर शासकीय महाविद्यालय (स्वा),

विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 08-10

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

समस तालाब (झुंझुनूं शहर) के जल की गुणवत्ता का WQI आधारित मूल्यांकन

Authored by

डॉ. धर्मेन्द्र सिंह

सह–आचार्य (भूगोल)

आई.ए.एस.ई. (डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय), सरदारशहर, चूरू।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 11-15

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

साम्प्रदायिक सद्भाव की कहानियाँ – हिन्दी कथासाहित्य में मानवीय मूल्यों की अभिव्यक्ति

Authored by

डॉ. तरूण कुमार साहू
अतिथि प्राध्यापक
शा. रा.लो. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजिम (छ.ग)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 16-19

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

पर्यावरणीय न्याय और मानव अधिकार : भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

Authored by

डॉ. धर्मेंद्र सिंह

सह –आचार्य (भूगोल),
आई.ए.एस.ई. (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), सरदारशहर, चूरू।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 20-26

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

माधव नागदा की कहानियों में सामाजिक परिवर्तन, वर्ग–संघर्ष और मानवीय संवेदना

Authored by

श्रीमती संगीता देवी, शोद्यार्थी,

डॉ. राजेश शर्मा, सहायक आचार्य

हिन्दी विभाग, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ
(डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय) उदयपुर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 27-34

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

कोरगर जनजाति : परंपरा, संस्कृति और समकालीन चुनौतियाँ

Authored by

डॉ. संजीव कुमार. के

एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदी विभाग

एम.इ.एस कल्लडी. कॉलेज (ओटोणमस) मन्नाटकाड,

पालकाड, केरल–678583

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 35-37

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

माधव नागदा की कहानियों का कथा–शिल्प – भाषा, संरचना और दृष्टि बिंदु का विवेचन

Authored by

श्रीमती संगीता देवी, शोद्यार्थी,

डॉ. राजेश शर्मा, सहायक आचार्य

हिन्दी विभाग, जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ,
(डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय) उदयपुर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 38-44

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

रामचरित मानस में मानव मूल्य

Authored by

डॉ. रीनू चतुर्वेदी

207 भाटागांव सिटी होंडा शोरूम के पास
रायपुर छत्तीसगढ़।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 45-48

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

हिंदी कहानी समीक्षा में सुरेंद्र चौधरी का योगदान : एक आलोचनात्मक अध्ययन

Authored by

भोली रानी

शोधार्थी, हिंदी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 49-53

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

दलित विमर्श के संदर्भ में 'जूठन' आत्मकथा

Authored by

डॉ. दर्शना धवल

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वूमेंस,
नई दिल्ली।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 54-57

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

अलवर जिले में गिरता भू-जल स्तर और कृषि प्रारूप पर उसका प्रभाव : एक भौगोलिक विश्लेषण

Authored by

डॉ. सुभाष चंद खटीक

सहायक आचार्य (भूगोल विभाग)

बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 58-60

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

शिक्षक शिक्षकों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में व्यावसायिक दक्षता एवं व्यावसायिक संतुष्टि के मध्य संबंध का अध्ययन

Authored by

डॉ. ज्ञान गांधी

सहायक प्रोफेसर,

पाकुड़ बी.एड कॉलेज, पाकुड़, झारखंड।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 61-65

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

भारतीय संसद एवं महिला सशक्तिकरण : झारखंड राज्य के संदर्भ में

Authored by

वीरेन्द्र देव, शोधार्थी

डॉ० प्रीति कुमारी, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं शोध निर्देशिका
आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग, झारखण्ड।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 66-70

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की भूमिका

Authored by

डॉ. स्वाति राय

सहायक व्याख्याता,
राजगंज इंटर महाविद्यालय, राजगंज, धनबाद।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 71-74

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

माध्यमिक स्तर के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण एवं नैतिक मूल्यों में संबंध का एक अध्ययन

Authored by

कृष्ण बहादुर सिंह, शोधार्थी

शिक्षाशास्त्र विभाग, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. राममणि द्विवेदी, प्राचार्य

एम.एल.चौरसीया शिक्षा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 75-81

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

National Education Policy 2020 & Experiential Learning in School Education

Authored by

Dr. Giriraj Bhojak
Assistant Professor, Department of Education,
Jain Vishva Bharati Institute (Deemed University),
Ladnun

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 82-87

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

21वीं सदी की हिन्दी कहानियों में नारी चिन्तन व चुनौतियां

Authored by

.डॉ० कमलेश देवी

सह–प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)

गुरु गोरखनाथ जी राजकीय महाविद्यालय, हिसार।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 88-94

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

ग्रामीण महिलाओं में महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का अध्ययन

Authored by

सुशीला, शोधकर्त्री
डॉ. रेखा खण्डेलवाल, सहायक आचार्या
श्री बालाजी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जयपुर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 95-98

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

तारीख–ए–फिरोजशाही––जियाउद्दीन बरनी

Authored by

आकाश गुप्ता

दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 99-101

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

राजस्थान की जलवायु

Authored by

हेमाराम जाट

सुपुत्र श्रवण राम

गांव नराधणा, तहसील जायल, जिला नागौर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 102-107

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

Impact of Competency-Based Assessment under NEP 2020 on Classroom Engagement and Teaching Effectiveness among Secondary School Teachers

Authored by

Pinky Agarwal, M.Ed. Scholar
Dr. Manju Devi, Research Supervisor
(Assistant Professor)
Sri Balaji Teacher Training College, Jaipur.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 108-112

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ : ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ

Authored by

ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ

ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਕਾਲਜ, ਦਿਉਣ ਬੰਠਿਡਾ

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 113-121

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਲਿਤ ਚੇਤਨਾ : ਇਕ ਅਧਿਐਨ

Authored by

Dr. Rajbinder Kaur
Assistant Professor,
Baba Farid College Deon, Bathinda.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 122-135

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

संत कबीरदास के माया संबंधी विचार

Authored by

डॉ. मनोज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी
चौधरी हरद्वारी लाल राजकीय महाविद्यालय, छारा, झज्जर।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 136-139

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Impact of School Environment on Personality Development among Basketball Players : A Comparative Analysis of Government and Private Schools

Authored by

Manish Kumar Sharma, Research Scholar

Dr. Surjeet Singh Kaswan (Professor) Research Supervisor

Faculty of Physical Education, Tantia University,
Sri Ganganagar (Raj.)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 140-142

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Women in Politics and Governance : Constitutional Empowerment and the Road to Viksit Bharat @ 2047

Authored by

Kanika Thakur

Assistant Professor (Guest Faculty)
Deen Dayal Upadhyaya College NCWEB,
University of Delhi.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 143-149

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

2014 के बाद भारत में राजनीतिक आख्यानों का निर्माण और विकास : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

Authored by

Dr. Ekta Chaudhary,
Assistant Professor, Head of Department
Fatima Zohra, Research Scholar,
Department of Political Science, Ismail National Mahila PG College, Meerut.

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 150-155

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

समसामयिक चित्रकला में उभरता नया अध्याय

Authored by

ध्रुव, शोधार्थी, चित्रकला विभाग,
डॉ. कृष्ण यादव, शोध निदेशक
श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 156-161

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

संस्कृत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग : संभावनाएँ, उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

Authored by

डॉ. वर्षा रानी

असि. प्रो. संस्कृत विभाग,
डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 162-167

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate of Publication for the paper titled*

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में आपदा प्रबन्धन हेतु शिक्षा के प्रति जागरूकता का अध्ययन

Study of Awareness of Disaster Management Education Among Secondary Level Students

Authored by

डॉ. नुपूर अग्रवाल

सहायक आचार्य,

जवाहर लाल नेहरू टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कोटा (राजस्थान)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 168-174

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी : ऐतिहासिक विकास, संस्थागत चुनौतियां और भविष्य के नीतिगत आयाम

Authored by

डॉ. एस.पी. शुक्ला प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
अंजुलि शुक्ला, शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 175-192

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

अभ्यास आधारित प्रशिक्षण का छात्रों की समग्र व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया पर प्रभाव का अध्ययन

Authored by

लवनीश कुमार, शोधार्थी

डॉ. रजनीश कुमार कारवारिया, शोध निर्देशक

सहायक आचार्य, शारीरिक शिक्षा विभाग,

श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीली बंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान–335801

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037

Impact Factor 7.834, May-June 2026,

Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 193-201

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

8708822674
9466532152

https://ginajournal.com/

grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

Medicinal Plants in Indian Traditional Knowledge

Authored by

Kamini Kumari

Principal in-charge
M.Sc, B.Ed, M.phil, (Chemistry)

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 202-205

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com

गीना देवी शोध संस्थान
Gina Devi Research Institute

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL
UGC Valid Journal (The Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, Dated July 18, 2018)

Run by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Certificate* of Publication for the paper titled

निर्गुण संत कबीर : युवा–वर्ग के मार्गदर्शक एवं प्रेरणा–स्त्रोत

Authored by

डॉ. सुधा

सहायक आचार्य, हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ. प्रदेश–226007

Published in SANGAM ISSN : 2321-8037
Impact Factor 7.834, May-June 2026,
Vol. 14, Issue 5-6, Part-4, Page No. 206-213

Director/Editor :
Dr. Rekha Soni

Secretary/Editor-in-Chief :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

*This Certificate is only Valid with the Presentation of the Research Paper/Topic.

202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021
8708822674
9466532152
https://ginajournal.com/
grngobwn@gmail.com